वही संकल्प लें जो आप पूरे कर सकें

विचार

धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक् वक्ता ततोऽपि च।
श्रोता ततोऽपि श्रद्धावान् कर्ता कोऽपि तत: सुधी:।।

भावार्थ : धर्म को जानने वाला दुर्लभ होता है, उसे श्रेष्ठ तरीके से बताने वाला उससे भी दुर्लभ, श्रद्धा से सुनने वाला उससे दुर्लभ और धर्म का आचरण करने वाला सुबुद्धिमान सबसे दुर्लभ है।

ट्रंप की दादागीरी

अमेरिकी सेनाएं वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत जिस तरह उठा लाईं, वह राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी की पराकाष्ठा है। ट्रंप ने सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के मामले में अमेरिका के मुकाबले कहीं अधिक कमजोर देश में दादागीरी दिखाकर यही साबित किया कि उनका जोर दुर्बल देशों पर ही चलता है। उन्होंने यह आरोप लगाकर वेनेजुएला पर हमला किया कि वहां से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी और निकोलस मादुरो की दमनकारी नीतियों से इस देश के लोग अवैध तरीके से उनके यहां आ रहे थे। यह एक बहाना ही अधिक है, क्योंकि अमेरिका में न तो नशीले पदार्थ केवल वेनेजुएला से आते हैं और न ही वहां के लोग। यह भी ध्यान रहे कि ट्रंप ने इसके प्रमाण नहीं दिए कि वेनेजुएला के अपराधियों के गिरोह मादुरो की शह पर अमेरिका के खिलाफ आतंकियों की तरह काम कर रहे थे। इस बारे में मादुरो ने ट्रंप से वार्ता का प्रस्ताव भी रखा था, पर उन्होंने उसकी अनदेखी कर दी। ऐसे में यही लगता है कि ट्रंप इससे चिढ़े हुए थे कि सबसे अधिक तेल भंडार वाले देश का राष्ट्रपति उनके मनमाने रवैये के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका और वेनुजएला के संबंध तबसे बिगड़े, जब वहां वामपंथी रुझान वाले शासक सत्ता में आए और उन्होंने कच्चे तेल और खनिज के स्त्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। इससे अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर होना पड़ा।

ट्रंप मादुरो से इसलिए और भी खार खाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रूस और चीन से संबंध प्रगाढ़ कर लिए थे। चूंकि ट्रंप का रूस और चीन पर जोर नहीं, इसलिए उन्होंने वेनेजुएला को निशाना बना लिया। यह सही है कि निकोलस मादुरो चुनावों में धांधली करके सत्ता में आए और एक तरह से तानाशाही शासन चला रहे थे, लेकिन क्या वे ऐसे इकलौते शासक हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ट्रंप किस्म-किस्म के तानाशाहों और यहां तक सीरिया में काबिज हुए आतंकी सरगना को भी गले लगा रहे हैं। वे पाकिस्तान के अघोषित तानाशाह आसिम मुनीर की भी पीठ थपथपा रहे हैं और वह भी इसके बावजूद कि वे आतंकी संगठनों को पाल रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को धोखा तो देता ही रहा है, वह उन देशों में भी प्रमुख है, जहां से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी होती है। यह तस्करी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी की शह से होती है, लेकिन ट्रंप की नजर में पाकिस्तान महान देश है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद बेलगाम होकर विश्व व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर रहे ट्रंप अपने साथ अमेरिका की भी फजीहत करा रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला कर उन्होंने बची-खुची नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता की ओर धकेल दिया है।

डिजिटल क्रांति की राह

छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से डिजिटल कनेक्टिविटी के अभाव की खबरें अक्सर आती रही हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केंद्र को डिजिटल भारत निधि के माध्यम से पांच हजार नए मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव भेजना दूरगामी और सकारात्मक कदम है। विशेषकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां माओवाद की छाया अब कम हो रही है, वहां 'डिजिटल इंडिया' की पहुंच केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक आवश्यकता है।

बस्तर, सरगुजा और जशपुर के दुर्गम गांवों में मोबाइल नेटवर्क का नहीं होना विकास के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है। जब हम ई-गवर्नेंस, आनलाइन बैंकिंग और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो नेटवर्क विहीन गांवों का उल्लेख हमारी प्रगति पर सवाल खड़े करता है।

> जब हम ई-गवर्नेंस, आनलाइन बैंकिंग और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो नेटवर्क विहीन गांवों का उल्लेख हमारी प्रगति पर सवाल खड़े करता है।

भरतपुर-सोनहत और कांकेर के दबेना जैसे गांवों के उदाहरण यह बताते हैं कि टावर न होने से एंबुलेंस बुलाने जैसी आपातकालीन सेवाएं भी बाधित होती हैं। ऐसे में केंद्र का मार्च 2026 तक राज्य को माओवाद मुक्त करने का लक्ष्य और राज्य की 'मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना' का तालमेल सराहनीय है। 'पीएम जनमन' और 'नियद नेल्ला नार' जैसी योजनाओं के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना अत्यंत सामयिक है। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये टावर केवल कागजों पर न लगें, बल्कि धरातल पर आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाएं। जब गांव-गांव तक फोर-जी और फाइव-जी की लहर पहुंचेगी, तभी बस्तर का युवा मुख्यधारा से जुड़ पाएगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत

कल का परिणाम

क्या इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से हुई मौतों के मामले में पर्याप्त कार्रवाई की गई है?

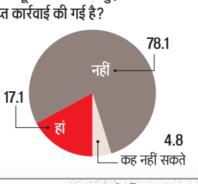

आज का सवाल
क्या वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला ट्रंप की दादागीरी का प्रमाण है?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विकसित भारत की राह के रोड़े

संजय गुप्त

जब सरकारी कामकाज दोयम दर्जे का होता है, तब उसका दुष्प्रभाव कहीं अधिक होता है, क्योंकि सरकारी दखल हर कहीं है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नव वर्ष के आगमन के ठीक पहले पिछले वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश अब रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। इसके उपरांत उन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच 'प्रगति' की बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों की पांच महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार, प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक परिवर्तन बेहद जरूरी बताए। प्रधानमंत्री ने 2025 में किए गए जिन महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया था, उनमें जीएसटी में व्यापक बदलाव, बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति, ग्रामीण रोजगार कानून मनेरगा में आमूलचूल परिवर्तन और श्रम संहिताओं को लागू करने और परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधारों का उल्लेख किया। निःसंदेह जीएसटी में सुधार से आम आदमी को लाभ मिला है, लेकिन अन्य सुधारों का लाभ मिलने में समय लगेगा। मोदी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सुधार करने के साथ नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करती रही है। इनके जरिये उसने सुशासन स्थापित करने की कोशिश की है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो और देश तेजी के साथ आगे बढ़े।

इसमें संदेह नही कि प्रशासनिक कामकाज में सरकारी नियंत्रण कम होने और विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से आम जनता को लाभ मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी देश सरकारी नियंत्रण के बिना नहीं चलता, लेकिन यह नियंत्रण एक सीमा तक ही होना चाहिए। अपने देश में सरकारी नियंत्रण कम करने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखता और इसीलिए पश्चिमी देश अभी भी यह शिकायत करते हैं कि भारत में सरकारी नियंत्रण अधिक है। वे इस नियंत्रण को सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। इसी तरह विदेशी निवेशक भी कारोबारी सुगमता में तमाम सुधार होने के बाद भी भारत में काम करने में बाधाएं देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह शिकायत करती ही रहती हैं कि भारत में कोई उद्योग-व्यापार स्थापित करना अभी भी कठिन बना हुआ है, क्योंकि कदम-कदम पर सरकारी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है।

मोदी सरकार की ओर से पिछले 11 सालों में उद्योग-व्यापार स्थापित और उन्हें संचालित करने में सरकारी दखल को कम करने के तमाम कदम उठाए जाने के बाद भी स्थितियां वैसी नहीं बन सकी हैं, जैसी बननी चाहिए। इस मामले में बात केवल केंद्र सरकार की ही नहीं, राज्य सरकारों की भी है। देश के सभी राज्यों का रवैया उद्योग एवं व्यापार के बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता और इसीलिए विकसित भारत के लक्ष्य में बाधाएं खड़ी हुई दिखती हैं। यह एक तथ्य है कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए देश में जैसी कारोबारी सुगमता होनी चाहिए, वैसी नहीं है। कारोबारी सुगमता केवल होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि वह दिखनी भी चाहिए- खास तौर पर कारोबारियों को। इसी तरह सरकारी तंत्र को जन समस्याओं के समाधान में तत्पर दिखना चाहिए। अधिकांश मामले में इस तत्परता का अभाव ही दिखता है।

अवधेश राजपूत

निःसंदेह यह आशा की जा रही है कि इस नए वर्ष में भी सुधारों का सिलसिला कायम रहेगा। जनता और उद्योग-व्यापार जगत उन क्षेत्रों में सुधार की खास तौर पर उम्मीद कर रहा है, जहां उनकी गति धीमी है। बतौर उदाहरण शहरी ढांचे को ठीक करने के लिए जैसे कदम उठाए जाने आवश्यक हो गए हैं, उनमें देरी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि नगर निकायों के कामकाज में अपेक्षित सुधार न होने से शहरी नागरिकों की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे शहर आबादी के बोझ तले दब रहे हैं और उनका ढांचा चरमरा रहा है। बात चाहे सीपीडब्ल्यूडी की हो या पीडब्ल्यूडी की, वे ढंग की सड़कें भी नहीं बना पा रहे हैं। यही स्थिति नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य विभागों की भी है। उनकी ओर से किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं हो पा रही है। उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव भी व्याप्त है। यह तब है, जब सब जानते हैं कि शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं।

अपने देश में समस्या केवल सरकारी कामकाज में गुणवत्ता के अभाव की ही नहीं है। यह अभाव उद्योग-व्यापार जगत में भी देखने को मिलता है। यह समझा जाना चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की कामकाज की गुणवत्ता ठीक करके ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जा सकता है। जब सरकारी कामकाज दोयम दर्जे का होता है, तब उसका दुष्प्रभाव कहीं अधिक होता है, क्योंकि हर कहीं सरकारी दखल है और सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं। विडंबना यह है कि औसत सरकारी कर्मियों का काम न तो पारदर्शी ढंग से होता है और न ही जवाबदेही के साथ। गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के बजाय जुगाड़ संस्कृति पर जोर दिया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि देश में कम ही निजी उद्योग हैं, जहां गुणवत्ता और उत्पादकता को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक तथ्य है कि भारत के बहुत कम उत्पाद विश्वस्तरीय गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। यदि सरकार अपने हर काम की गुणवत्ता ठीक करने को प्राथमिकता दे तो उसका प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र में अपेक्षित बदलाव तभी संभव है, जब देश की नौकरशाही के सोच में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। समस्या यह है कि फिलहाल सरकार के एजेंडे पर यह दिख नहीं रहा है। नौकरशाही में सुधार की जो प्रतीक्षा की जा रही है, वह इस नए वर्ष पूरी होनी चाहिए। नौकरशाही को अपने कामकाज के तौर-तरीकों के साथ अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि भी अपने काम का तरीका और सोच बदलें। यह भी समय की मांग है कि आम जनता भी अपना कार्य-व्यवहार बदले। उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना चाहिए। क्या कभी इसकी चर्चा होती है कि एक नागरिक के तौर पर हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं? देश के हर व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर कारोबारी या फिर श्रमिक अथवा अन्य कोई, अपना काम इस तरह करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो।

response@jagran.com

ताजा हवा के झोंके की तरह अपराध कथा

अनंत विजय

वेब सीरीज पर किसी प्रकार के सेंसर या प्रमाणन की व्यवस्था नहीं है, इस कारण वहां अराजकता जारी है

ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म्स पर चलने वाली वेब सीरीज की बात आते ही पहली प्रतिक्रिया होती है- गालियों की भरमार होगी। जबरदस्ती ठूंसी गई यौनिकता या न्यूडिटी होगी। जबरदस्त हिंसा होगी। प्रश्न आता है कि कोई अच्छी और साफ-सुथरी वेब सीरीज बताइए। उत्तर मिलता है- पंचायत और गुल्लक। अच्छी कहानी, साफ सुथरी प्रस्तुति, कम गाली-गलौच और न्यूनतम हिंसा जिन वेब सीरीज में हो, उनकी संख्या कम है। हमारे देश में विशेषकर हिंदी में बनने वाली वेब सीरीज एक ऐसी राह पर चली गईं, जिनमें निर्माता और निर्देशकों को लगता है कि बगैर गालियों के, बिना यौनिकता और हिंसक दृश्यों के वेब सीरीज लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लिहाजा सफलता के लिए ये तीन अवयव जबरदस्ती कहानी में ठूंसे जाते हैं। अपराध कथा हो तो यह तो आवश्यक ही होते हैं। भले ही कहानी का सत्यानाश क्यों न हो जाए। इस तरह से भारतीय दर्शकों की मानसिकता को विश्लेषित करने वाले निर्देशकों को पता नहीं यह बात कब समझ में आएगी कि दर्शकों को कहानी चाहिए। बेहतर कहानी और बेहतर ट्रीटमेंट ही किसी वेब सीरीज को दर्शकों की पसंद बना सकती है। एक जमाने में इसी तरह से हिंदी फिल्मों में अश्लीलता दिखाने के लिए तर्क गढ़े जाते थे। कई ऐसी फिल्में दर्शकों ने पसंद भी की थीं लेकिन ये ट्रेंड लंबे समय नहीं चल सका और दर्शक जबरदस्ती ठूंसी गई नग्नता से ऊब गए। फिर हिंदी फिल्मों ने अपनी राह बदली। आज वेब सीरीज के निर्माताओं को इस पर विचार करने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए।

वेब सीरीज पर चूंकि किसी प्रकार के सेंसर या प्रमाणन की व्यवस्था नहीं है, इस कारण वहां अराजकता जारी है। स्वनियंत्रण और स्वनियमन की आड़ में प्रमाणन को रोका गया है। सरकार इस कारण से इस दिशा में गति से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर प्रसारण पूर्व प्रमाणन का निर्णय होता है तो एक अलग संस्था बनानी होगी। सरकार ने एक व्यवस्था जरूर बनाई है, जब किसी वेब सीरीज को लेकर अधिक विवाद होता है तो सूचना-प्रसारण मंत्रालय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके मामले को सुलझा देता है।

आज चर्चा एक ऐसी वेब सीरीज की करनी है, जो बहुत ही साफ-सुथरी, न्यूनतम गाली-गलौच के साथ और बगैर किसी अश्लीलता और जुगुप्साजनक हिंसा के बनाई गई है। यह वेब सीरीज अपराध कथा है, उसमें मर्डर है, ग्लैमर और लड़कियां हैं, प्रेम-प्रसंग हैं, अश्लीलता दिखाने का अवसर भी है, लेकिन अश्लीलता या नग्नता कम से कम है। इस वेब सीरीज को परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। रोचकता अपने चरम पर है और दर्शकों के दिमाग में इसको देखते हुए बस यही चलता रहता है कि आगे क्या? यही तो निर्माता निर्देशक की सफलता है। बात हो रही है- वेब सीरीज मिसेज देशपांडे की। छह एपिसोड की यह सीरीज एक सीरियल किलर को पकड़ने की कथा है। कहा गया है कि यह किसी फ्रेंच कहानी पर आधारित है, लेकिन इसके निर्देशक और लेखक नागेश कुकनूर ने जिस प्रकार से कहानी को भारतीय पुट दिया है, वो प्रशंसनीय है। अपने जमाने की सुपर स्टार रहीं माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं। उन्होंने अपने अभिनय कला से दर्शकों को बांधे रखा है। माधुरी ने जिस तरह से मिसेज देशपांडे के पात्र को पर्दे पर जीवंत किया है, वो उल्लेखनीय है। माधुरी अपनी परिस्थितियों के कारण सीरियल किलर बन जाती हैं। पकड़ ली जाती हैं और मिसेज देशपांडे को जेल में जीनत का नाम मिलता है। वो इस पहचान के साथ जेल में सूर्य नमस्कार करती हैं और साथी कैदियों को भोजन बनाकर खिलाती हैं। यह सीरियल किलिंग पुणे में हुई थी। मिसेज देशपांडे के केस की फाइल किसी एक लड़की के हाथ लग जाती है। यहां भी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, वो लड़की पहले लड़का होती है लेकिन अपनी मानसिक स्थिति के कारण वो चिकित्सकीय रास्ते से लड़की बनती है। यह लड़की पुणे की सीरियल किलर मिसेज देशपांडे की कापीकैट किलर बनती है। उसके ही अंदाज में अपने शिकार का नायलान की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करती है और उसकी आंख खोल देती है। जब कापीकैट किलर ने मुंबई में कत्ल करना आरंभ किया तो पुलिस कमिश्नर ने मिसेज देशपांडे यानी जीनत की मदद लेना तय किया। कहानी में इतने चक्करदार घुमाव हैं कि मिसेज देशपांडे इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की मां होती है और कापीकैट किलर जांच अधिकारी की पत्नी की दोस्त है। जब दर्शकों को लगता है कि पुलिस किलर के पास पहुंच गई है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है और किलर की नए सिरे से तलाश आरंभ हो जाती है। कोई नया क्लू मिलता है। जिस पर किलर होने का शक होता है या जिसको किलर की तरह पेश किया जाता है वो तो किसी और ही मानसिक स्थिति में होता है। दर्शक जब उसकी सचाई जानता है तो उसके प्रति संवेदना से भर उठता है। प्रश्न उठता है कि किलर कौन? निर्देशक ने कहानी को किसी तरह से लाउड नहीं होने दिया है। न ही किसी प्रकार का छद्म वातावरण तैयार करके अपराध कथा को तिलस्मी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। बगैर लाउड हुए कहानी का ट्रीटमेंट बेहतरीन है। बस कहानी में एक ही चीज खटकती है- अंत में भेद खुलता है कि मिसेज देशपांडे को उसके पिता ने ही सेक्सुअली अबयूज किया था। वो अपने पिता की हत्या के लिए पहुंचती है। वो छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस तरह की वेब सीरीज से एक उम्मीद जगती है कि ओटीटी प्लेटफार्म पर चलने वाली सामग्री में परिपक्वता आनी आरंभ हो गई है। दूसरे निर्माता भी इसको देखकर प्रेरित होंगे और कहानी का इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। मिसेज देशपांडे को एक शुभ संकेत की तरह लिया जाना चाहिए। इसकी सफलता ने यह संकेत भी दिया है कि साफ सुथरी वेब सीरीज दर्शकों को भाती है। मिसेज देशपांडे उन निर्देशकों के लिए मिसाल है, जो सेक्स और हिंसा दिखाकर सफल होना चाहते हैं।

anant@nda.jagran.com

ऊर्जा

गतिशील जीवन

जीवन स्थिर नहीं सतत प्रवाह है। जीवन का मूल स्वर ही गति है। गर्भ में पहली धड़कन से लेकर अंतिम श्वास तक जो चलता है, वही जीवित है। ठहराव, चाहे वह शरीर का हो या विचारों का, जीवन की नहीं, जड़ता की पहचान है। प्रकृति स्वयं हमें यही सिखाती है। सूर्य का रथ निरंतर चलता है, नदियां बिना थके बहती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। ऐसे में मनुष्य यदि जीवन को प्रमाद, संतुष्टि और लक्ष्यहीनता में गंवा दे तो यह उस उपहार का अवमूल्यन है। ऐसा जीवन न स्वयं के लिए प्रेरक बनता है और न ही समाज के लिए।

फिर भी, गति का अर्थ अंधी दौड़ नहीं है। अतिशय वेग में बहती धारा भी विनाश ला सकती है। इसलिए जीवन की गति विवेकपूर्ण होनी चाहिए। ऐसी गति जो स्वयं को आगे बढ़ाए, पर दूसरों को कुचले नहीं। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यह स्मरण आवश्यक है कि सीमाओं का ज्ञान ही संतुलन देता है। जीवन का सौंदर्य उसी संतुलन में है, जहां कर्म निरंतर है, पर अहंकार नहीं। उपनिषद का सूत्र-चरैवेति चरैवेति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक गति की भी प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि ठोकरें आएंगी, गिरना होगा, पर रुकना विकल्प नहीं है। गिरकर उठना और फिर आगे बढ़ना ही जीवन का धर्म है।

आज का विश्व जिस अनिश्चितता, हिंसा और असंतुलन से जूझ रहा है, उसका कारण भी नकारात्मक गतिशीलता है। ऐसी गति जो शक्ति तो बढ़ाती है, पर करुणा नहीं। ऐसे समय में आवश्यकता है सकारात्मक, शांतिप्रिय और मानवोन्मुख गतिशीलता की। वही गतिशीलता जो विकास को विनाश नहीं बनने दे। अंततः जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम हर क्षण किसी सकारात्मक प्रयोजन से जुड़े रहें। गति रुके नहीं, पर दिशा न भूले। क्योंकि जीवन वही है जो चलता है और सही दिशा में चलता है।

– छाया श्रीवास्तव

पाठकनामा

letter@naidunia.com

हिंदुओं से हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय चुप्पी

बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर लगभग प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। वहां न केवल हिंदुओं की हत्या की जा रही है, बल्कि उनकी बेटियों और महिलाओं की अस्मिता भी बेखौफ लूटी जा रही है। इन दोनों इस्लामिक देशों में यदि कोई अल्पसंख्यक हिंदू-सिख व्यक्ति अपनी बहन-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आवाज उठाता है, तो कट्टरपंथी और नफरती हिंसक भीड़ द्वारा उसका सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है। आज चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इन देशों में बहुसंख्यक वर्ग के कट्टरपंथी तत्वों ने भारत और हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते अपने ही देश में रह रहे हिंदू परिवारों की स्थिति को नारकीय बना दिया है, लेकिन भारत में किसी अल्पसंख्यक पर जरा भी आंच आने की स्थिति में शांति और सद्भाव की दुहाई व नसीहत देने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकारों की बात करने वाले वैश्विक संगठन और अमेरिका को बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की चीखें सुनाई नहीं देना बेहद चिंताजनक है।

– **अरविंद रावल,** गोपाल कालोनी, झाबुआ

दूषित पानी का संकट, समाधान जरूरी

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से कई लोगों की जान चली गई। इससे कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए और अनेकों लोग दूषित पानी के सेवन से अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की नर्मदा, चंबल, कालीसिंध, क्षिप्रा आदि नदियों में उनके किनारे बसे गांवों, कस्बों, नगरों और शहरों का सड़ांधयुक्त मटमैला और अत्यंत बदबूदार गंदा पानी बरसों से विलीन हो रहा है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक है। भोपाल के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद डा. एसके राजन इस संबंध में प्रदेश सरकार को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, फिर भी प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया है। अभी भी समय है कि हम सब इंदौर की घटना से सबक लेकर चैतन्य हो जाएं।

– **दिनेश तिवारी उपवन,** बड़नगर, इंदौर

शुद्ध जल ही जीवन है

समाचार : दूषित पेयजल से इंदौर में अब तक 16 नागरिकों की मृत्यु, एक हजार से अधिक अस्वस्थ।

टिप्पणी : कहावत- 'जल ही जीवन है' को इंदौर की घटना के बाद बदलकर अब 'शुद्ध जल ही जीवन है, दूषित जल मृत्यु है' कर देना चाहिए।

– **आशीष सकलेचा,** जावरा

छेरछेरा परंपरा का संरक्षण आवश्यक

छत्तीसगढ़ की प्राचीन छेरछेरा परंपरा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सहयोग और दान की भावना का जीवंत उदाहरण है। पौष पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली छेरछेरा परंपरा में लोग घर-घर जाकर अन्न, चावल या दान एकत्र करते हैं। इसका उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि समाज में कोई भी भूखा न रहे। यह परंपरा हमें समानता, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का संस्कार सिखाती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाती है। हालांकि आधुनिकता और शहरीकरण के कारण युवा पीढ़ी इससे धीरे-धीरे दूर होती जा रही है। आवश्यकता है कि स्कूलों, सांस्कृतिक मंचों और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से इस परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ा जाए। यदि शासन और समाज मिलकर प्रयास करें तो छेरछेरा जैसी लोक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती हैं। आशा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देते हुए समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं पीढ़ी-दर पीढ़ा परंपरा का निर्वाहन होता रहेगा।

–योगेश कौशिक , बिलासपुर

X पोस्ट

किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लेना और उसके बाद नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दुहाई बस पाखंड की पराकाष्ठा ही है।

नवरूप सिंह@TheNavroopSingh

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति दुनिया भर को शांति का उपदेश देते रहते हैं और युद्ध रोकने की वकालत करते हैं, मगर खुद किसी दूसरे देश पर हमला करने से हिचकिचाते नहीं। ऐसा लगता है कि शेष विश्व और अपने लिए उनके अलग ही प्रतिमान हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

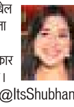

तो क्या यही कारण रहा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतनी व्यग्रता दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि इसके बाद तो शांति पुरस्कार का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा।

शुभांगी शर्मा@ItsShubhangi

शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली वेनेजुएला में विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार ट्रंप को समर्पित किया था। उनकी गतिविधियां देखें तो उन्होंने ट्रंप को अपने देश पर हमले के लिए आमंत्रित किया।

श्रीमय तालुकदार@sreemoytalukdar

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/19437 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस सेक्टर 1, प्लॉट नं 12, 13 एवं 14 सिरगिट्टी, बिलासपुर से मुद्रित एवं 2वीं मंजिल, महिमा ट्रेड सेंटर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर से प्रकाशित, इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com, संपादक : सद्गुरु शरण * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

साल 2026 के लिए संकल्प कीजिए कि इसे युद्धों का नहीं, बल्कि गरीबी से लड़ने का वर्ष बनाएंगे; इसे धरती पर शांति और न्याय सुनिश्चित करने का साल बनाएंगे- एंटोनियो गुटेरस /संयुक्त राष्ट्र महासचिव

जंग की आहटें और यह नया साल

वर्ष 2025 ने अगर बहुत कुछ दिया है, तो साल 2026 के समक्ष युद्धों की नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हर रोज जंग की ज्वाला की ओर घिसट रही हमारी दुनिया में अब भी शांति और सहमति के नए सूत्र तलाशने की कुव्वत शेष है? इस सवाल का जवाब ही घातकतम हथियारों से बजबजाती धरती का भविष्य तय करेगा।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

क्या आपने अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों की गिरफ्त में जंजीरों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फोटो देखा? क्या यह तस्वीर आपको दिसंबर 2003 में छपे एक और दर्दनाक चित्र की याद नहीं दिला गई?

उस फोटो में सद्दाम हुसैन थे, इसी तरह जकड़े हुए, हतप्रभ और हताश। मादुरो भी सद्दाम की तरह एक संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी हुक्मरानों की सनक के गुलाम हैं? जॉर्ज डब्ल्यू बुश सद्दाम को सूली पर चढ़ाने के बावजूद अपना एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए थे, क्या मादुरो झूठ की इस परंपरा की अगली कड़ी साबित होने जा रहे हैं?

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप का यह कारनामा आशंकाओं का भरा-पूरा महाकाव्य रचने की कुव्वत रखता है। दशकों से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए साल के पहले हफ्ते में दुनिया को जंग की ऐसी सौगात नहीं दी थी। वेनेजुएला की यह वारदात डरावनी है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप की तरह ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने यूक्रेनियाई समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अभी तक वह अपने मकसद में भले सफल न हो सके हों, लेकिन उनकी फौज ने यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। सोवियत फौजियों का यूक्रेन की धरती में धंसाव जारी है और हर पल कीव की स्थिति नाजुक होती जा रही है।

साल के पहले दिन मॉस्को के आला अधिकारियों ने एक वीडियो जारी कर घोषणा की कि यूक्रेन के 91 ड्रोन हमारे हुक्मरां पुतिन के आधिकारिक आवास पर दागे गए। इस हमले का मकसद पुतिन को सांघातिक नुकसान पहुंचाना था। कीव ने इसका खंडन किया है, मगर मॉस्को बदला लेने के 'हक' पर अड़ा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजधानी कराकस जैसी या उससे मिलती-जुलती कोई घटना कीव में घटती देखें।

यहां एक और त्रासद तथ्य की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में हमला इस बिना पर किया कि वहां के राष्ट्रपति नशीले पदार्थों के तस्करों को पनाह देते हैं, जिनमें से कई तो दहशतगर्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसा कहते वक्त वह सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि उनके परम मित्र पाकिस्तान के हुक्मरां तो ओसामा बिन लादेन से लेकर अजहर मसूद तक को न केवल पनाह देते आए हैं, बल्कि उन जैसों को जनने में भी उन्हें महारत हासिल है। उधर, पुतिन ने हमले के वक्त दावा किया था कि जेलेंस्की फासिस्ट हैं। दुनिया पर सबसे बड़ा असर डालने वाली घटनाओं के मूल में इसी तरीके के कुतर्क पाए जाते हैं।

दुनिया की मौजूदा अशांति इन्हीं असत्यों की देन है।

'ग्लोबल पीस इंडेक्स' (जीपीआई) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 78 इस समय किसी न किसी रूप में जंग से जूझ रहे हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यह पहला अवसर है, जब इतनी बड़ी संख्या में संप्रभु राष्ट्र एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। 17 दुर्भाग्यशाली देश तो ऐसे हैं, जिनके एक हजार से अधिक नागरिक 2025 में मारे गए।

मैं जान-बूझकर यहां पश्चिमी अफ्रीकी माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड आदि देशों की बात नहीं कर रहा। वे बरसों से इस प्राणलेवा बला की चपेट में हैं। अब तो थाईलैंड और कंबोडिया जैसे शांत समझे जाने वाले देश भी गुत्थमगुत्था हो रहे हैं। पिछले महीने की 13 तारीख को थाईलैंड ने अमेरिका के दिए हुए एफ-16 बमवर्षक का उपयोग करते हुए कंबोडिया पर बम बरसाए। इससे 11 लोग मारे गए। अकाल काल के गाल में समाए लोग वहां मनोरंजन के लिए जुटे थे। युद्ध उनके ख्वाबों-ख्यालों से परे था।

हथियारों के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनका संग्रह करता है, वह इसका शिकार जरूर बनता है।

जीपीआई की ही रिपोर्ट बताती है कि संसार के 84 देश ऐसे हैं, जो पिछले छह साल से निरंतर अपना रक्षा व्यय बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र भी हैं। सन् 2023 में इनका कुल रक्षा व्यय विश्व जीडीपी का 11.6 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। इसी का नतीजा है कि समूची धरती पर शांति-कामना में 0.3 प्रतिशत की और गिरावट आई है। अपने में सिकुड़ते-सिमटते देशों के बाशिंदे भला किस मुंह से नई और भली 21वीं सदी की सरंचना करेंगे?

इसी बीच रूस और यूक्रेन की जंग चौथे साल की दहलीज पर पहुंच चुकी है। इसके चलते अब तक 53 हजार के करीब लोग मारे जा चुके हैं और एक करोड़ से अधिक विस्थापित हो चुके हैं। इस युद्ध ने न केवल इन दो देशों को प्रभावित किया है, बल्कि पिछले 50 सालों में सर्वाधिक शांत माने जाने वाले यूरोप को भीतर से झिंझोड़ दिया है। डेनमार्क न केवल द्वितीय विश्व-युद्ध में बनाई उन सुरंगों की सफाई करा चुका है, जिनमें हमला होने की स्थिति में सामान्य लोग छिप सकते थे, बल्कि उसने नए मारक हथियारों के सौदे भी शुरू कर दिए हैं। पड़ोसी स्वीडन की भी यही स्थिति है। यूरोप में ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब कोई बड़ा नेता या जनरल रूस के आक्रमण की आशंका नहीं दोहरा देता।

डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नाटो से अधिक रक्षा शुल्क वसूलने की जद्दोजहद शुरू की है, तब से यूरोपीय देश अपने रक्षा व्यय में और बढ़ोतरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका असर संसार की माली हालत पर पड़ रहा है और विश्व की कल्याणकारी योजनाएं शिथिल पड़ रही हैं।

क्या 1991 से 2019 के बीच रची गई विकास-गाथा अतीत बन चली है?

हमारे यहां भी सत्ता-प्रतिष्ठान और सैन्य प्रशासन रह-रहकर ऑपरेशन सिंदूर-02 की आशंकाएं जताता रहता है। पाकिस्तान तो पहले से इस आपदा का शिकार था, लेकिन उसके द्वारा आरोपित हालात ने हमें बड़ी जंग की तैयारी पर मजबूर कर दिया है। हमारी एक चुनौती यह भी है कि दूसरा पड़ोसी चीन, जिसकी आर्थिक और सैन्य भुजाएं हमसे कहीं बलवान हैं, शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। आपको देश के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' जनरल विपिन रावत का वह बयान याद होगा कि हमें एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

यही नहीं। पिछले एक साल से बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनको इस्लामाबाद के साथ बीजिंग से जैसा समर्थन हासिल हो रहा है, वह कुछ नई चिंताएं जनता है। बांग्लादेश आंतरिक हिंसा के दावानल से झुलस रहा है। वहां अब तक महत्वपूर्ण छात्र नेताओं की रहस्यपूर्ण तरीके से हत्या हो चुकी है। हर हत्या के बाद वहां बदअमनी का आकार बढ़ जाता है और भारत विरोध का शोर भी। सवाल उठता है कि हमारे इस पड़ोसी को भड़काने की साजिश कर कौन रहा है?

वर्ष 2025 ने अगर बहुत कुछ दिया है, तो साल 2026 के समक्ष युद्धों की नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हर रोज जंग की ज्वाला की ओर घिसट रही हमारी दुनिया में अब भी शांति और सहमति के नए सूत्र तलाशने की कुव्वत शेष है? इस सवाल का जवाब ही घातकतम हथियारों से बजबजाती धरती का भविष्य तय करेगा।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

चेतना गाला सिन्हा
बैंकर, समाजसेवी

लाखों ग्रामीण औरतों की सहारा बनी एक चेतना

चेतना चाहतीं, तो वह मुंबई में एक आरामदेह जिंदगी जी सकती थीं, मगर गांधी-जेपी के दर्शन ने उन पर कुछ ऐसा जादू किया था कि वह महाराष्ट्र के गांवों में पहुंच वहां के भूमि अधिकार आंदोलनों, कृषि आंदोलनों और महिला सशक्तीकरण की मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगीं।

हमारे देश में बहुत सारे लोगों, खासकर राजनेताओं को इस बात का बड़ा गुमान रहता है कि उन्होंने न जाने कितने भारतीयों की जिंदगी संवार दी। दर-हकीकत, वे समूचे सिस्टम के काम का सेहरा अपने सिर सजाने की कोशिश करते रहते हैं और सरमायेदारों की एक पूरी फौज उनके दावों की मुनादी करती रहती है। ऐसे में, जब चेतना गाला सिन्हा जैसे जमीनी लोगों के काम सामने आते हैं, तब यह एहसास होता है कि हमारे सियासतदां इन लोगों के आगे कितने बौने हैं!

आज से करीब 68 साल पहले मुंबई के एक सुशिक्षित, आर्थिक रूप से सक्षम परिवार में चेतना पैदा हुईं। महानगरीय सुविधाओं के बीच पली-बढ़ी चेतना को बचपन से ही बेहतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला। 1980 के दशक की शुरुआत में जब वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी की कॉमर्स स्नातक की छात्रा थीं, तभी उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण से हुई। उस मुलाकात ने चेतना की पूरी चेतना बदल डाली। दरअसल, जेपी उन दिनों देश भर के कॉलेजों-यूनिवर्सिटियों में जा-जाकर नौजवानों का आह्वान कर रहे थे कि वे गांवों में जाकर काम करें।

चेतना चाहतीं, तो उन्हें मुंबई (तब बॉम्बे) में अच्छी नौकरी मिल सकती थी और वह एक आरामदेह जिंदगी भी जी सकती थीं, मगर गांधी-जेपी के दर्शन ने कुछ ऐसा जादू किया था कि वह महाराष्ट्र के गांवों में पहुंच वहां के भूमि अधिकार आंदोलनों, कृषि आंदोलनों व महिला सशक्तीकरण की मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। इसी क्रम में चेतना सूखा प्रभावित गांव मसवाड़ पहुंचीं। वहां के युवा किसान नेता विजय सिन्हा से वह बहुत प्रभावित हुईं। विजय बहुत पढ़े-लिखे तो नहीं थे, मगर एक प्रखर वक्ता थे। उनकी बातें लोगों पर खूब असर करतीं। उन्हें सुनने बड़ी भीड़ जुटती। आहिस्ता-आहिस्ता चेतना और विजय एक-दूसरे से प्यार करने लगे और अंततः उन्होंने विवाह करने का फैसला किया।

घरवाले और कॉलेज के तमाम साथी चेतना के इस फैसले से हैरान थे। उनका चौंकना स्वाभाविक भी था। कहां देश के सबसे महंगे, सुविधायुक्त महानगर में पली-बढ़ी लड़की और कहां एक सूखाग्रस्त गांव, जहां बुनियादी सुविधाएं तक न थीं। चेतना का परिवार चिंतित था कि वह निबाह कैसे करेंगी, उस गांव में तो शौचालय तक नहीं था! नैतिक आदर्शों और प्रेम ने सभी चिंताओं व नसीहतों पर विजय पाई थी। चेतना ने विजय से विवाह भी किया और सन् 1987 में वह अपने ससुराल मसवाड़ आ बसीं।

मसवाड़ में रचे-बसे चेतना को कई वर्ष बीत चुके थे। वह तीन बेटों की मां बन चुकी थीं। एक दिन कांताबाई नाम की गांव की एक महिला चेतना से मिलने आईं और उनसे कहा कि वह बचत खाता खुलवाना चाहती हैं। चेतना ने कांताबाई से पूछा,

क्या आपके पास इतने पैसे होते भी हैं कि आप बचा सको? आप तो फुटपाथ पर रहती हो? कांताबाई ने कहा, मैं पैसे बचाना चाहती हूं, ताकि मानसून के आने तक इतने रुपये जमा कर सकूं कि प्लास्टिक शीट खरीद पाऊं। वह अपने परिवार को बारिश की मार से बचाना चाहती थीं।

कांताबाई को लेकर चेतना बैंक पहुंचीं, मगर बैंक मैनेजर ने छोटी रकम का हवाला देते हुए खाता खोलने से साफ इनकार कर दिया। चेतना को यह बात बुरी तरह चुभी। कांताबाई कर्ज मांगने तो बैंक नहीं गई थीं, वह तो इतना भर चाहती थीं कि मेहनत से कमाई गई उनकी छोटी रकम भी सुरक्षित रहे। चेतना ने सोचा कि यदि बैंक यह काम नहीं कर रहा, तो क्यों न एक कॉपरेटिव बैंक शुरू किया जाए, ताकि कांताबाई जैसी औरतों को बचत का मौका मिले। साल 1996 में उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए चेतना का आवेदन खारिज कर दिया कि आरबीआई ऐसे बैंक की इजाजत नहीं दे सकता, जिसके प्रमोटर्स अशिक्षित हों।

चेतना लगभग रोती हुई गांव लौटीं और कांताबाई व दूसरी औरतों को बताया कि वह लाइसेंस नहीं हासिल कर सकीं, क्योंकि आप लोग पढ़ी-लिखी नहीं हो। औरतों ने कहा, आप मत रोइए, हम लिखना-पढ़ना सीखेंगे और फिर से लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे। छह महीने में चेतना की मेहनत ने रंग दिखाया, मसवाड़ की महिलाओं ने लिखना-पढ़ना, दस्तखत करना सीख लिया। सन् 1997 में चेतना 15 महिलाओं को साथ लेकर आरबीआई की दहलीज पर पहुंचीं। आरबीआई ने चेतना व उनके गांव की महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए लाइसेंस जारी कर दिया और इस तरह देश का पहला महिला ग्रामीण बैंक (मान देशी महिला बैंक) वजूद में आया।

यह महिलाओं का अपना बैंक था। उनके हितों की खैरख्वाह चेतना ने एक और कमाल किया। चूंकि गरीब महिलाएं बैंक नहीं आ सकती थीं, क्योंकि इससे उनकी मजदूरी या काम का नुकसान होता, इसलिए बैंक उनके घर तक पहुंचा। महिलाओं का महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित इस बैंक ने कांताबाई को पक्का मकान बनाने में ही मदद नहीं की, बल्कि इसने महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं की जिंदगी को रोशन किया। यह बैंक बेटियों को साइकिल, महिलाओं को सिलाई मशीन से लेकर दूसरे उपकरण खरीदने या कोई कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देता है। बीते वर्षों में मान देशी महिला बैंक का कारवां बढ़ता गया। आज दस लाख से

साल 1997 में चेतना 15 महिलाओं को साथ लेकर आरबीआई की दहलीज पर पहुंचीं। आरबीआई ने चेतना व उनके गांव की महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए लाइसेंस जारी कर दिया और इस तरह देश का पहला महिला ग्रामीण बैंक (मान देशी महिला बैंक) वजूद में आया।

अधिक महिलाएं इसकी खाता धारक हैं और इस बैंक की बाजार-कीमत 200 करोड़ रुपये की है। चेतना की इस खामोश क्रांति को पूरी दुनिया ने सराहा। उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 2018 में वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सह-अध्यक्षता करने वाली हिन्दुस्तान की पहली महिला बनीं।

बगैर किसी गुरूर के दूसरे के काम आना गांधी ने सिखाया, जेपी ने अपनाया और चेतना सिन्हा उसे आगे बढ़ा रही हैं। ऐसी जिंदगी से भला किसे रश्क न होगा?

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

लुई ब्रेल
ब्रेल लिपि के आविष्कारक

घने अंधेरों में उभरे अक्षरों का आलोक

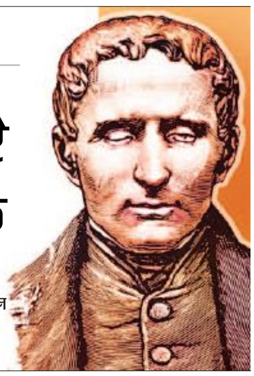

दृष्टिबाधितों के उस विद्यालय में पढ़ाई नाममात्र की थी, क्योंकि उभरे अक्षरों वाली किताबें न के बराबर थीं। ऐसे बच्चों को कोई न कोई काम सिखा दिया जाता था, ताकि जिंदगी कट जाए। उस बालक को भी बक्से और चप्पलें बनाना सिखा दिया गया था।

असंख्य ऐसे इंसान होते हैं, जिनकी जिंदगी में रात कभी नहीं ढलती। हमेशा अंधेरा छाया रहता है। उस 12 वर्षीय बालक का भी यही हाल था। वह टटोलते हुए ही सब कुछ करता था। उसकी पढ़ाई भी सिर्फ थोड़ा टटोलने और कुछ समझ जाने तक महदूद थी, लिखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।

वह बीते दो वर्ष से पेरिस में दृष्टिबाधित बच्चों के विशेष स्कूल 'रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ' में पढ़ रहा था। पढ़ाई तो नाममात्र की थी, क्योंकि उभरे अक्षरों वाली किताबें न के बराबर थीं। ऐसे बच्चों को कोई न कोई काम सिखा दिया जाता था, ताकि जिंदगी कट जाए। उस बालक को भी बक्से और चप्पलें बनाना सिखा दिया गया था। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, पर वह अक्सर याद करता था कि कभी उसकी आंखें ठीक थीं। तीन साल की उम्र रही होगी, वह घर-दरवाजे पर खूब दौड़ता-भागता था। एक दिन खेल-खेल में पिता का कोई औजार उसकी दायीं आंख में जा लगा। तब अच्छी चिकित्सा के दिन नहीं आए थे। बायीं आंख में भी संक्रमण फैला और कुछ ही दिनों में दोनों आंखों ने देखना बंद कर दिया। तब वह लाचार बच्चा जिससे भी मिलता था, यही पूछता था कि यहां इतना अंधेरा क्यों है?

उस अंधेरे ने ही उसे अपने गांव से दूर पेरिस के उस खास स्कूल तक पहुंचाया था। किसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन स्कूल में एक खास हस्ती का आगमन हुआ। पूर्व सैन्य कप्तान चार्ल्स बार्बियर ने विशेष छात्रों को बताया कि हम सैनिक रात के अंधेरे में कहीं संदेश भेजने या संदेश पढ़ने के लिए एक खास लिपि या शैली का उपयोग करते हैं। इस लिपि में उभरे हुए कुछ संदेशों का उस बालक ने भी पूरे मनोयोग से स्पर्श किया और उसका रोम-रोम हर्षित हो उठा। उसने इस विशेष विधि को तत्काल प्रयोग में लाने का फैसला कर लिया।

अब क्या था, कक्षा में कोई पाठ सुनने और चप्पलें बनाने के काम के बाद जैसे ही मौका मिलता, वह अंधेरे में लिखने की उस विधि पर काम शुरू कर देता। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इस विधि को और कारगर बनाया जा सकता है। सैनिक अपनी कूट लिपि के लिए 12 डॉट के ढांचे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस किशोर ने केवल छह डॉट वाला ढांचा बनाया। उसने एक विशेष स्लेट या स्केल तैयार किया। डॉट बनाने के लिए एक औजार बनाया, जिसे स्टाइलस नाम दिया। यह पूरी विधि बनाने में तीन वर्ष का समय लगा। अब अपने नए काम को साबित करने की बारी थी। पेरिस में तब प्रचंड ठंड के दिन चल रहे थे। साल चल रहा 1824, उस रॉयल इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर डॉक्टर अलेक्जेंडर रेने पिग्नियर बहुत चकित भाव से आए। उन्हें बताया गया कि आपके संस्थान के छात्र लुई ब्रेल एक लिपि का प्रदर्शन करेंगे। 15 वर्षीय लुई ब्रेल ने हेडमास्टर साहब से कहा, सर, आप किताब में से कोई लेख पढ़िए और मैं सुनकर लिखता जाऊंगा।

हेडमास्टर साहब ने बोलना शुरू किया और ब्रेल स्टाइलस, रूलर-स्केल के सहारे कागज पर निशान बनाते चले गए। हेडमास्टर साहब धीरे-धीरे पढ़ रहे थे, तब खुद ब्रेल ने कहा कि सर, आप और तेजी से पढ़िए, मैं लिख रहा हूं।

हेडमास्टर साहब तेजी से पढ़ते गए और ब्रेल ने उस पूरे लेख को निशान बना-बनाकर उकेर दिया। जब हेडमास्टर साहब ने लेख पढ़ना समाप्त किया, तब ब्रेल ने अपने लेखन की शुरुआत में वापस जाकर, अपनी उंगलियों को उभरे हुए बिंदुओं पर फेरा और पूरा पाठ शब्दशः सुना दिया। वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए। खुशी से भाव-विभोर हेडमास्टर साहब ने वहीं घोषणा कर दी कि जो लोग देख नहीं पाते, आज उनकी दुनिया में क्रांति का आगाज हो गया है। स्कूल ने अगले ही दिन ब्रेल की उभरे बिंदुओं वाली प्रणाली को पढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रेल कागज पर स्टाइलस को इतनी तेजी से चलाते थे, मानो उनके हाथ में कोई मशीन लगी हो। पेरिस की एक प्रदर्शनी में ब्रेल को प्रति मिनट 2,500 बिंदु या डॉट बनाते हुए देखा गया। वह एक के बाद एक उपयोगी किताबों की रचना ब्रेल में किए जा रहे थे, ताकि उन जैसों के संसार में भी अक्षरों का आलोक अच्छे से फैल जाए। उनकी दुनिया के लोग न केवल पढ़ सकें, मनचाहा लिख भी सकें।

धीरे-धीरे पूरी दुनिया ने लुई ब्रेल की लिपि को अपना लिया। ब्रेल के निधन की 100वीं बरसी पर आयोजित एक समारोह में विश्वप्रसिद्ध लेखिका व दृष्टिबाधितों की दुनिया की सबसे खास मिसाल हेलेन केलर ने कहा था, हम तमाम दृष्टिबाधित लोग लुई ब्रेल के ऋणी हैं। हमारी उंगलियों के नीचे उभरे हुए अक्षर अनमोल बीज हैं, जिनसे हमारी बौद्धिक संपदा का अंकुर फूटा है।

4 जनवरी को जन्मे लुई ब्रेल (1809-1852) फ्रांस ही नहीं, दुनिया के महानतम नायकों में शुमार हैं। दुनिया उनकी ऋणी है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

ताकि साइबर लोक भी सधता रहे

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

लगता है, नया बरस मेरे ऊपर कुछ अतिरिक्त कृपालु है। एक वाट्सएप संदेश कह रहा है कि 'सर जी, नववर्ष मंगलमय हो'... मोबाइल नंबर...! दूसरा वाट्सएप संदेश कह रहा है, 'नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए', साथ में दो इमोजी गुलदस्ते... मोबाइल नंबर...! तीसरा कह रहा है कि 'यह वर्ष आपके पूरे परिवार और आपके लिए सदैव मंगलमय रहे'... दो इमोजी गुलाब... मोबाइल नंबर!

कोई-कोई तो अपने फोटो की जगह अपनी बिल्ली की तस्वीर चेप देता है और लिख देता है- नया बरस मंगलमय हो... फिर मोबाइल नंबर! बताइए, मैं बिल्ली को धन्यवाद भेजूं कि बिल्ली वाले को? दो दिन में कोई साठ-सत्तर शुभ संदेश मिले हैं। किसी में सिर्फ शुभकामनाएं थीं, तो किसी में भेजने वाले ने किसी की कविता ही मार दी थी। किसी की काव्यात्मक प्रतिभा नए बरस पर अचानक जाग गई थी और उसने अपनी शैली में चार लाइनें लिख भेजी थीं।

मेरे तईं यह एक रिकॉर्ड है। जितने आए हैं, उतने ही भेज चुका हूं। जिस-जिस ने मुझे 'विश' किया है, मैं उस-उस को 'विश' कर चुका हूं। मेरा मन हल्का है, उदात्त भाव से भरा है, गद्गद है। फिर भी संदेश भेजने वालों से कहना चाहता हूं कि हे फोन नंबर जी! आप एक लेखक हैं। आपका व्यक्तित्व है। फिर आप अपने को एक मोबाइल नंबर में क्यों 'रिड्यूस' किए जाते हैं? जिन दिनों एआई (बनावटी बुद्धि) लेखक को ही मिटाने पर तुली हो, उन दिनों उसके नाम को 'इरेज' करना (मिटाना) क्या ठीक है? आप जब भी संदेश भेजें, अपना नाम जरूर लिखें, अपने को 'बिल्ली' न बनाएं।

इतनी मंगलकामनाओं को देख मैं *लीडर* के दिलीप कुमार की तरह गाने लगता हूं- *मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है!* जरा सोचिए, जिस बंदे को पूरे बरस कोई दमड़ी का न पूछता हो, न कोई 'हलो-हाय' करता हो, न कोई यह पूछता हो कि क्या लिख-पढ़ रहे हो? ऐसे दो टके के लेखक को नया बरस जब इतने शुभ-शुभ व मंगल-मंगल, इतने गुलाबों, पुष्पगुच्छों और कुत्ते-बिल्लियों से भर दे, तो उसका मन क्यों न उड़े?

सच! उस दिन मैं सातवें आसमान पर था कि मैं कहीं किसी सरकारी कमेटी में तो नहीं जा रहा? वह दल मुझे राज्यसभा तो नहीं भेज रहा? कहीं कोई मुझे 'छद्मश्री' तो नहीं बनाने जा रहा? कहीं बुकर वाले मुझे अगले पांच बरस के लिए जज तो नहीं बनाने जा रहे? नोबेल कमेटी वाले अपनी कमेटी में पहली बार किसी हिंदी वाले को, यानी मुझे तो नहीं चुनने जा रहे?

बार-बार फड़कती मेरी दाईं आंख यह कहती हुई लगी कि तेरे दिन अब बहुरे, जबकि डॉक्टर कह चुका है कि आंख का चेक-अप जल्दी करा लें-ब्लड प्रेशर हो सकता है, आंख की नसें कमजोर हो सकती हैं। पब्लिक प्लेस में किसी के आगे फड़क गई, तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं!

अब आप ही बताएं, राज्यसभा का सपना देखूं कि अस्पताल का? वह तो भला हो वाट्सएप, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का कि उन्होंने नए बरस के पहले दिन ही मेरे जैसे मनहूस को इतना आनंदमय कर दिया!

कुछ कहते हैं कि वाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ बोलती है। तो भैया जी, यह बता दें कि सच कौन बोलता है? ऐसे में, अगर वाट्सएप के जरिये किसी ने फ्री में सबका एक दिन मंगलमय बना दिया, तो किसी का क्या गया? मैं वाट्सएप भगवान को धन्यवाद देता हूं कि 'सर जी! आप हमेशा यूं ही फ्री में सबका मंगल करते रहें जी!'

कुछ देर से ही सही, इस अवसर पर मैं अपने पीएम, सीएम, सभी विपक्षी नेताओं, कम्यूनलों व सेक्युलरों को भी नए वर्ष की 'वाट्सएपी मंगलकामनाएं विद पुष्पगुच्छ' भेजना चाहता हूं, ताकि पक्ष भी सधा रहे और विपक्ष भी सधा रहे। यह लोक भी सधा रहे, वह लोक भी सधा रहे। इस सबके लिए जरूरी है कि वाट्सएप का साइबर लोक भी सधा रहे!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

मैंने उस शहर का कर्ज उतारा

'जिस लाहौर नइ देख्या ओ जम्याइ नइ' जैसे बहुचर्चित नाटक के लेखक असगर वजाहत ने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन के साथ-साथ फिल्म लेखन और चित्रकला के क्षेत्र में भी खासी ख्याति अर्जित की है। हिंदी साहित्य में साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के महत्वपूर्ण कहानीकार एवं नाटककार। हिंदी अकादमी के शलाका और व्यास सम्मान से सम्मानित असगर वजाहत के यात्रा-संस्मरण 'अतीत का दरवाजा' से प्रस्तुत है संपादित अंश...

इलस्ट्रेशन: यशवंत नामदेव

अद्भुत यात्रा संस्मरण-41

असगर वजाहत
जन्म: 05 जुलाई, 1946

लगता है मेरे ऊपर उनका कर्ज है, भारी देनदारी है, जिन्होंने ईसा से लगभग दो सौ वर्ष पहले सीरिया में पेत्रा नाम का शहर बसाया था। उन कलाकारों के ऋण से मैं उस वक्त तक मुक्त नहीं हो सकता, जब तक उनकी महानता का गुणगान न कर लूं। वर्तमान में पेत्रा, जॉर्डन देश की सीमा में है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 245 किलोमीटर दूर है। कई जगह लिखा गया है कि मरने से पहले आदमी को जो कुछ जगहें देख लेनी चाहिए, उनमें 'पेत्रा' भी एक है। अकल्पनीय सौंदर्य और महानतम प्रतिभा का अनोखा मिश्रण पेत्रा को मनुष्य की कला प्रतिभा के उच्चतम शिखर पर स्थापित करता है।

पेत्रा तक आने की यात्रा जॉर्डन की राजधानी अम्मान से शुरू हुई थी। जॉर्डन यात्रा की प्रेरणा डॉ. दिनेश शर्मा से मिली थी। डॉ. शर्मा एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री और चिकित्सक होने के साथ-साथ घुमक्कड़, शौकीन तबीयत, मस्तमौला, साहित्य और सौंदर्य प्रेमी हैं। वे अपने किसी काम से जॉर्डन जा रहे थे। जॉर्डन मेरी भी यात्रा-सूची में था। इस तरह हम साथ हो गए, लेकिन कार्यक्रम यह बना था कि डॉ. शर्मा अपना काम खत्म करके दो दिन बाद मुझे ज्वॉइन करेंगे। तब तक मैं अकेला अम्मान का मजा लेता रहूंगा।

सुबह-सवेरे बाजार बंद थे और मैं सड़क पर था। होटल से नीचे उतरा, तो मुख्य सड़क पर आ गया। बिना मकसद एक तरफ चलना शुरू कर दिया। सभी दुकानें बंद थीं, लेकिन चाय-कॉफी की दुकानें खुली थीं। एक चाय की दुकान में चला गया। वहां दो लड़के बैठे थे। अब सवाल पैदा हुआ कि किस जुबान में बात की जाए? हिंदी-अंग्रेजी वे क्यों जानते। अरबी मुझे नहीं आती। 'कॉफी' कहकर खामोश हो गया। वे समझ गए कि मैं विदेशी हूं। अब टूटी-फूटी अंग्रेजी और अरबी के कुछ शब्दों के माध्यम से संवाद आगे बढ़ने लगा। पता चला उनमें से एक लड़का सीरिया के गृहयुद्ध के कारण यहां आ गया है। दूसरा स्थानीय है। सीरिया पर बात होने लगी कि शिआ-सुन्नी आपस में लड़ते हैं। उनके पीछे क्षेत्र के दो बड़े देश हैं और जनता मरती-खपती है, जिसे क्षेत्रीय राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। दोनों लड़के एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहे थे। मैंने सिगरेट का पैकेट उठाया, उस पर अरबी में लिखी इबारत के कुछ शब्द मैंने पढ़ लिए। लड़के हैरान हुए कि मैं अरबी पढ़ सकता हूं।

आगे बढ़ा तो फुटपाथ पर एक गरीब बुढ़िया दो बिल्लियों को दूध पिला रही थी। जॉर्डन में गरीबी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष रूप से बेरोजगारी और गरीबी है, जिसे हमने गांवों में जाकर देखा था। आमतौर पर लोग राज व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि देश में भारी असमानता है, लेकिन राज विरोध का स्वर बहुत दबा हुआ है। हो सकता है, इसका कारण राजशाही का आतंक या धर्म की अफीम हो।

होटल में नाश्ता करने के बाद फिर सड़क पर आ गया। मेरे खयाल से किसी देश को देखने और समाज को समझने का सड़कों पर घूमने से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सड़क किताब होती है। बाजार खुल गया था। मैं दुकानों और लोगों को देखता आगे बढ़ने लगा। खयाल यह था कि मुहाजिरों के बस अड्डे जाकर कोई ऐसी बस पकडूंगा, जो एक-दो घंटे में किसी दूसरे कस्बे या शहर ले जाएगी। वहां घूमूंगा और शाम तक वापसी हो जाएगी।

बाजार का रंग बदल गया था। दुकानों के अलावा फुटपाथ पर सामान फैला पड़ा था। फुटपथिया दुकानें बता रही थीं कि उनके ग्राहक भी बड़ी संख्या में हैं। फुटपाथ पर लगी दुकानें देखते-देखते अचानक मैंने फुटपाथ पर बच्चों के पुराने खिलौनों की दुकान देखी और डर गया। एक अजीब तरह का डर लगने लगा। मैं उस दुकान के सामने ठहर गया। लोग, मतलब गरीब लोग अपने बच्चों के लिए दूसरे बच्चों द्वारा खेले गए पुराने खिलौने खरीद रहे थे।

मैंने यह भी देखा कि पुराने खिलौने खरीदने वालों के साथ बच्चे नहीं हैं। पुराने खिलौने देखकर बच्चे मां-बाप से क्या यह न पूछते होंगे कि खिलौने पुराने क्यों हैं? ये भी पूछते होंगे कि उन्हें किन बच्चों ने खेल कर पुराना या गंदा कर दिया है। बच्चों के मन में यह भी आता होगा कि वे बच्चे कैसे होंगे, जो नए खिलौनों से खेलते होंगे। मां-बाप के लिए बच्चों को यह समझाना मुश्किल हो जाता होगा।

> कॉफी पीकर फिर टहलने लगा। मिठाई की एक दुकान दिखाई पड़ी और कुछ अपने यहां जैसी मिठाइयों की शक्लें थीं। बड़ी-बड़ी रंग-बिरंगी जलेबियां और कुछ रसगुल्ले जैसा दिखाई पड़ा। सोचा, 'ट्राई किया जाए।' मिठाई खानी नहीं चखनी थी। यह बात दुकानदार को समझाने में वक्त लगा। मिठाई खाई, तो कुछ खास नहीं लगी। आगे बढ़ा। घूमते-घूमते दोपहर हो गई थी और खाने का मसला सामने था। दो-तीन खाने के होटलों में से एक चुना और खाने बैठ गया।

इधर, जिस बस अड्डे की तलाश थी, वहां तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक ऐसी जगह आ गया, जहां से मिनी बसें कहीं या कई तरफ जा रही थीं। पूछने पर पता चला कि मैं मिनी बस में बैठकर वादिए-मूसा नामक कस्बे तक जा सकता हूं और शाम तक वापस आ सकता हूं।

शहर से निकलने का अच्छा तरीका था। जल्दी ही शहर की चमक-दमक से दूर उजाड़ पहाड़ों और सूखे इलाकों से गुजरती मिनी बस कस्बे में आ गई। देखकर अच्छा लगा कि यही यथार्थ है, सच्चाई है, देश यही है, यही असली लोग हैं। उतर कर कस्बे के बाजार में घूमने लगा। सफाई-व्यवस्था अच्छी लगी। बहुत अधिक भीड़-भाड़ भी नजर नहीं आई। हां, थोड़ी पस्ती जरूर दिखाई पड़ी। एक गली में चाय-कॉफी की दुकान नजर आई, वहां दो लड़के बैठे थे। मैं वहीं बैठ गया। उम्मीद थी कि वे शायद अंग्रेजी जानते होंगे पर अनुमान गलत निकला।

कॉफी पीकर फिर टहलने लगा। मिठाई की एक दुकान दिखाई पड़ी और कुछ अपने यहां जैसी मिठाइयों की शक्लें थीं। बड़ी-बड़ी रंग-बिरंगी जलेबियां और कुछ रसगुल्ले जैसा दिखाई पड़ा। सोचा, 'ट्राई किया जाए।' मिठाई खानी नहीं, चखनी थी। यह बात दुकानदार को समझाने में वक्त लगा। मिठाई खाई, तो कुछ खास नहीं लगी।

आगे बढ़ा। घूमते-घूमते दोपहर हो गई थी और खाने का मसला सामने था। दो-तीन खाने के होटलों में से एक चुना और खाने बैठ गया। बड़ी-सी रोटी, कबाब और दही के रायते का 'कॉम्बिनेशन' मजेदार था। खाकर पैसे पूछे, उसने तीस रियाल बताए। मैंने गलती से उसे तीन सौ दे दिए। उसने फौरन मेरी गलती की तरफ इशारा किया और आसमान की तरफ उंगली उठाकर कुछ कहा, जिसका मतलब साफ था।

होटल के नीचे वाली मुख्य सड़क पर प्राचीन रोमन थिएटर के विशाल खंडहर हैं। इस प्रांगण में शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पहले दिन ही शाम को घूमता-घामता यहां पहुंचा और अरब नर्तकों का नृत्य देखा। परंपरागत वेशभूषा में दस-पंद्रह आदमी नाच रहे थे। उनका नाच कुछ मार्शल आर्ट जैसा था। कुछ ऐसा नृत्य था, जो युद्ध के बाद या पहले किया जाता रहा होगा। यह अजीब लगा कि दो-तीन नृत्य जो वहां देखे उनमें सभी आदमी थे, कोई महिला नहीं थी, जबकि अरब की महिला नर्तकियां बहुत विख्यात रही हैं। हो सकता है, वर्तमान समय की कट्टरवादिता ने महिलाओं को नृत्य के हाशिये पर डाल दिया हो।

रोमन थिएटर के प्रांगण में मैंने ऊपर से नीचे तक काले बुर्कों में ढंकी सात-आठ महिलाओं को एक साथ बैठे देखकर उनका फोटो ले लिया। मुझे लगा और दूसरे लोग भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज ने महिलाओं के पर्दे के प्रति कुछ ज्यादा ही कड़ा रवैया अपनाया हुआ है। यह प्रायः अरब देशों में देखा जा सकता है।

(साभार: 'अतीत का दरवाजा', राजपाल एंड संज, दिल्ली से संपादित अंश)

पुस्तक अंश

दुष्यंत की गजलों के साये में पचास साल

आपातकाल के दौर में दुष्यंत कुमार के पहले और इकलौते गजल-संग्रह 'साये में धूप' के प्रकाशन ने धूम मचा दी थी। इसके बाद हिंदी में लिखी जा रही गजलों को 'हिंदी गजल' नाम मिला। इस संग्रह के 50वें प्रकाशन वर्ष में आई पुस्तक 'हिंदी गजल की सृजन-यात्रा' से प्रस्तुत है एक अंश...

हिंदी गजल की सृजन-यात्रा
(हिंदी गजल के पांच दशक)
संपादक: कमलेश भट्ट कमल
प्रकाशक: हिंदी अकादमी, दिल्ली
मूल्य: ₹400

हिंदी गजल में विपुल लेखन भी आलोचना की राह के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। यह किसी भी आलोचक के बस का नहीं है कि एक साथ सारी रचनात्मकता पर ध्यान दे पाए। जाहिर है किसी को भी चयन करना ही पड़ेगा। ऐसे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर हमेशा बना ही रहता है।

यदि हम इतिहास में जाएं, तो हिंदी गजल के बीज हमें अमीर खुसरो से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। बाद में गजल कबीर फिर भारतेंदु और उसके आगे के रचनाकारों में धीरे-धीरे प्रकट होती हुई दुष्यंत कुमार तक आती है। दुष्यंत कुमार और उनके बाद की गजल की दुनिया जिसे हम सही अर्थों में हिंदी गजल की दुनिया कह सकते हैं, हम लोगों के सामने की और काफी कुछ जानी-पहचानी दुनिया है।

दुष्यंत कुमार के बाद का हिंदी गजल का यह पांच दशकों का सफर कोई बहुत आसान नहीं रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि इसके रास्ते लगातार कंटकाकीर्ण रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की रोटी खाने वाले एक आलोचक ने पिछले दिनों एक गजलकार से यह तक कह दिया कि गजल के साथ हिंदी शब्द का प्रयोग सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है।

इसी प्रकार हिंदी की ही पृष्ठभूमि से उभरे एक गजल-गुरु ने यह कहकर अपनी कुंठा मिटाई कि दुष्यंत के पास भी दो-चार शेर के अलावा और क्या है? हिंदी का ही कोई रचनाकार हिंदी गजल से कब अपना दामन छुड़ाकर परायेपन का व्यवहार करने लगे या उर्दू गजल के पाले में खड़ा हो जाए, यह भी आशंका बराबर बनी ही रहती है।

जीवन भर हिंदी गजल की ही खाने वाले एक वरिष्ठ गजलकार जब अचानक यह कह बैठें कि क्या हिंदी गजल कोई अलग विधा है, तो भटकाव की स्थितियों को समझा जा सकता है। बावजूद ऐसे आरोपों, उपेक्षाओं, तिरस्कारों के, हिंदी गजल का पिछले पांच दशकों का यह सफर शानदार, बहुआयामी और सुदृढ़ रहा है।

हिंदी गजल के इतिहास पर बात करते हुए हम प्रायः दक्खिनी हिंदी में गजल की महत्वपूर्ण उपस्थिति का संज्ञान नहीं लेते हैं। जबकि दक्खिनी हिंदी को भी हिंदी भाषा के विद्वानों ने हिंदी भाषा का ही एक अंग माना है।

दक्खिनी हिंदी में ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज (1312-1421 ई.) से ही गजलें मिलनी शुरू हो जाती हैं। यह सिलसिला वली दकनी (1687-1840 ई.) तक चलता है। इस बीच में लुत्फी, शेख हसन, कुली कुतुब शाह, शेख अहमद शरीफ, इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय 'जगतगुरु', काजी महमूद 'बहरी', मलिक खुशनूद, अली आदिल शाह, रुस्तमी, इश्रती, सुल्तान अब्दुल हसन 'तानाशाह' जैसे कितने ही गजलकार आते हैं।

बीसवीं सदी की तीसरे-चौथे दशक में लिखी गई बहुत सारी गजलें ही नहीं, बल्कि बहुत सारा साहित्य अंग्रेज सरकार द्वारा लिखे जाने के तुरंत बाद ही जब्त कर लिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित ऐसी गजलों का भी एक कालखंड इतिहास का ही हिस्सा है। विगत पांच दशकों की हिंदी गजल की उपलब्धियां आश्वस्तकारी ही नहीं, अपूर्व भी हैं। ये उपलब्धियां आने वाले सालों की हिंदी गजल को महत्वपूर्ण आधार और पृष्ठभूमि प्रदान करेंगी तथा हिंदी कविता में गजल की उपस्थिति को और भी स्थायित्व प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

पुस्तकें आई हैं

प्रतिनिधि कविताएं
(कविता-संग्रह)
लेखक: पवन करण
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य: ₹199

वरिष्ठ कवि पवन करण के पिछले दिनों आए काव्य-संग्रह 'प्रतिनिधि कविताएं' की रचनाएं अदृश्य लोक से कोसों दूर अपने आसपास की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बावजूद इन कविताओं का अपना अलग ही स्वाद और तेवर है। ये कविताएं किसी तयशुदा फार्मेट में बंधी नजर नहीं आतीं। 'रिश्तेदार', 'दूल्हे के दोस्त', 'स्कूटर', 'चौथी बहन' जैसी तमाम कविताएं इसकी हामी हैं।

हिंदी कविता के समकाल का सम
(आलोचना)
लेखक: शिरीष कुमार मौर्य
प्रकाशक: राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य: ₹350

'**हिंदी** कविता के समकाल का सम' पुस्तक के केंद्र में हिंदी के उन हस्ताक्षरों को रखा है, जिनकी कविता ने मनुष्य और उसके दुख के अंतर्बाह्य आयामों को अपने-अपने ढंग से पकड़ा है। जनपक्षधरता को एक मूल्य की तरह बरता है। सच कहने का साहस दिखाया है और भाषा को, उसकी अर्थ-व्याप्ति को वृहत्तर किया है। पुस्तक में विवेचित कवियों में मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय आदि प्रमुख हैं।

गोलियों के सामने अडिग कलम
(छतरपुर की साहसिक पत्रकारिता का दस्तावेज)
लेखक: राजेश बादल
प्रकाशक: प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग, गाजियाबाद
मूल्य: ₹375

आजादी के आंदोलन से लेकर और उसके बाद भी पत्रकारिता ने समय-समय पर समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई, 1980 में छतरपुर में एक युवती और बच्ची के खिलाफ दो जघन्य अपराध हुए, जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। इस घटना के दौरान छतरपुर के पत्रकारों ने संघर्ष की जो मिसाल पेश की, उसका जीवंत दस्तावेज है पुस्तक 'गोलियों के सामने अडिग कलम।'

नदी सी मैं
(कविता-संग्रह)
लेखिका: डॉ. कुसुम मानसी द्विवेदी
प्रकाशक: अनामिका प्रकाशन, प्रयागराज
मूल्य: ₹350

'**मुझको** मेरा गुरूर प्यारा था, उसको बस जी हुजूर प्यारा था। उसकी जिद थी किसी टुकड़े पे सुलह कर लूं मैं, मुझको पूरे का बस पूरा फितूर प्यारा था।' जैसे तेवर से लैस 'नदी सी मैं' काव्य-संग्रह की कविताएं सिर्फ शब्दों की यात्रा नहीं है। यह एक स्त्री की भी यात्रा है। कुल मिलाकर कहा जाए, तो स्त्री-विमर्श इन कविताओं में सामाजिक विडंबनाओं को जागरूक होकर देखने की दृष्टि भी है।

रोजनामचा

साप्ताहिक भविष्यफल

(04 जनवरी से 10 जनवरी 2026)

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष (21 मार्च-20 अप्रैल)
मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आय के साधन बन सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष (21 अप्रैल-20 मई)
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। संतान की सेहत का भी ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं।

मिथुन (21 मई-21 जून)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा।

कर्क (22 जून-23 जुलाई)
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह (24 जुलाई-22 अगस्त)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी।

कन्या (23 अगस्त-22 सितंबर)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला (23 सितंबर-23 अक्तूबर)
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। मित्र के सहयोग से नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

वृश्चिक (24 अक्तूबर-21 नवंबर)
मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। किसी मित्र के सहयोग कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के विस्तार के लिए किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

धनु (22 नवंबर-21 दिसंबर)
आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य सुख में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मकर (22 दिसंबर-19 जनवरी)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है।

कुंभ (20 जनवरी-18 फरवरी)
मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

मीन (19 फरवरी-20 मार्च)
मन परेशान हो सकता है, परंतु आत्मविश्वास बहुत रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। परिवार व मित्रों का साथ मिलेगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

04 जनवरी, रविवार, **शक संवत्**: 14 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग**: 21, पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम**: 14 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत्**: माघ कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 12.31 मिनट तक। पुष्य नक्षत्र, वैधृति योग रात्रि 01.48 मिनट तक पश्चात विष्कुंभ योग, कौलव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रातः 09.43 मिनट तक उपरांत कर्क राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। माघ कृष्ण पक्ष प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरा शोरूम तीन फ्लोर का है। ऊपर-नीचे के फ्लोर तो ठीक हैं पर बीच वाला नहीं चलता। कोई उपाय बताएं।
-हजारीमल व्यास, जयपुर

- आपने बीच वाले फ्लोर में ब्रह्मस्थान पर दो बड़े स्टेचू खड़े किए हैं। इससे आपके उस फ्लोर का ब्रह्मस्थान बाधित हो गया है। उन्हें वहां से हटा दें।
- इस फ्लोर पर जो मिरर दक्षिण दिशा में लगे हुए हैं, उन्हें भी हटा दीजिए।
- इस फ्लोर की उत्तर दिशा में थोड़े छुआरे रख दें, जिन्हें तीन दिन बाद बदल दें।
- इस फ्लोर की दक्षिण पश्चिम दिशा में गुलाब जल रख दीजिए। कुछ दिन लगातार चारों कोनों में तीन-तीन तेजपत्ते रखिए। उत्तर दिशा में एक हरे रंग का बल्ब लगाएं।

वर्ग पहेली: 8199

बाएं से दाएं
2. याद न रहना; विस्मृत होना; अच्छा न लगना; तिरस्कृत हो जाना (2,1,4)
5. प्रकाशित; चमकीला (4)
6. अनुचित प्रयोग; गलत इस्तेमाल (5)
8. धन; राशि; संपत्ति(3)
9. देवी-देवता के प्रति विनय, श्रद्धा और समर्पण भाव प्रकट किया जाना; अर्चना; आराधना (2)
10. ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा के ऊपर समकोण बनाए; नीचे की ओर झूलता हुआ; नीचे की ओर लटकता हुआ (2)
12. ऊपर सामान रखना; ढोने के लिए सामान भरना; भार रखना (3)
14. कड़क होना; कड़ा होना; सख्त होना; निष्ठुर होना; श्रुतिकटु होना (3,2)
15. पापपूर्ण आचरण; पापकार्य; दुराचार (4)
16. झरने से गिरते जल का मधुर स्वर करना; मधुर ध्वनि करना (4,3)

ऊपर से नीचे
1. सतर्कता के साथ; सावधानी से; होशियारी के साथ (7)
2. अपनी कमाई हुई संपत्ति; वैयक्तिक संपत्ति; मेरा (4)
3. पर्वत; नगीना; मणि; अदद (2)
4. छटपटाना; दर्द से व्याकुल होना; गरजना (4)
6. अधीनता प्रकट करना; दीनतापूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना (2,3)
7. अव्यवस्था फैलाना; क्रम भंग करना; खराबी करना; भूल करना (4,3)
11. आरक्षी; पहरेदार; प्रहरी; रक्षक; सिपाही (4)
13. प्रसिद्धि प्राप्त करना; मशहूर होना (2,2)
15. दूसरा किनारा; अंत; छोर; सिरा (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली 8198 का उत्तर

सुडोकू: 8181

*कठिन

			3			6	9	
	3	8			9	2		
	6				2	4		
5			1				2	
	9				3			4
		4	6				8	
		5	8			1	7	
	8	6			1			

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। तर्क से इसे हल कर सकते हैं। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

हल: सुडोकू नं. 8180

3	9	5	7	8	1	2	4	6
7	8	2	3	6	4	5	9	1
4	1	6	5	9	2	8	3	7
2	4	3	9	5	6	7	1	8
8	5	1	4	7	3	9	6	2
9	6	7	2	1	8	3	5	4
5	2	9	6	4	7	1	8	3
6	7	8	1	3	9	4	2	5
1	3	4	8	2	5	6	7	9

जनसत्ता सरोकार | सम-सामयिक | एक
जनसत्ता | 4 जनवरी, 2026

नीदो से एंजेल तक, कुछ भी नहीं बदला

नस्लवाद, घृणास्पद भाषणों और बयानों पर क्या किसी समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों से लगाम लगाई जा सकती है? अगर ऐसा होता तो नस्ली घृणा अपराध में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की उत्तराखंड में जान नहीं जाती। साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीदो तानिया की दिल्ली में नस्ली घृणा के कारण हुई मौत के 11 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है, जबकि उस वारदात के कारण सरकार ने बेजबरुआ समिति बनाई थी। उस समिति की सिफारिशें शायद देश की राजधानी तक ही सीमित रह गईं। नीदो के बाद एंजेल की मौत ने व्यवस्था के खोखलेपन को जगजाहिर कर दिया है। इस घटना ने चेतावनी दी है कि देश में रंग-रूप, जाति, नस्ल और धर्म को लेकर नफरती बर्ताव गहरे तक पैठा हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि से लेकर मजहबी नेता तक नस्ली नफरत की मानसिकता के शिकार हैं। लिहाजा घृणा के खिलाफ कानून बनना ही चाहिए। मसले पर सरोकार की पड़ताल।

नफरती माहौल है कानून बनना चाहिए

जनसत्ता सरोकार

उत्तराखंड में एंजेल चकमा की हत्या ने देश में नस्लीय भेदभाव और कानूनी खालीपन को फिर उजागर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीदो तानिया की हत्या के बाद 2014 में गठित बेजबरुआ समिति को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। उत्तर-पूर्व भारत के विद्यार्थियों और संगठनों का कहना है कि इसकी प्रमुख सिफारिशें या तो अब तक लागू नहीं की गई हैं, या फिर केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित रह गई हैं। इस बीच, देश के विभिन्न हिस्सों में नस्लीय हिंसा और रोजमर्रा का भेदभाव लगातार जारी है।

यह मुद्दा एक बार फिर तब सुर्खियों में आया, जब त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की उत्तराखंड के देहरादून में हत्या कर दी गई। आरोप है कि नौ दिसंबर को नस्लीय गालियों का विरोध करने पर ऐंजल पर चाकू से हमला किया गया, और 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर उत्तर-पूर्व के छात्र संगठनों और राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करके इस मुद्दे को उठाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देर की। नतीजतन प्रमुख आरोपी के नेपाल भागने की बात सामने आई है। प्रतिपक्षी नेताओं ने इस घटना को भयानक घृणा अपराध बताया और सार्वजनिक विमर्श में फैले नफरत के माहौल की आलोचना की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसने साल 2014 में अरुणाचली छात्र की हत्या के बाद आई बेजबरुआ समिति के सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था।

वास्तव में 26 दिसंबर को देहरादून के एक अस्पताल में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र चकमा की मृत्यु, मुख्य भूमि भारत में रहने वाले पूर्वोत्तर के नागरिकों द्वारा दशकों से चले आ रहे सम्मान और सुरक्षा के संघर्ष में एक नया मोड़ बन गई है। उत्तराखंड की राजधानी के सेलाक्वी क्षेत्र में घटी यह घटना इस बात की भयावह याद दिलाती है कि भारतीय राज्य की भौगोलिक सीमाएं हमेशा मुख्य भूमि के नागरिकों की भावनात्मक और सामाजिक सीमाओं से मेल नहीं खातीं। इस मामले ने एक तीखी राष्ट्रीय बहस को फिर से हवा दे दी है, जिसकी तुलना साल 2014 में हुई नीदो की हत्या से की जा रही है।

एंजेल पर हमला नौ दिसंबर की शाम को हुआ। ऐंजल और उनके छोटे भाई माइकल चकमा घरेलू सामान खरीदने के लिए सेलाक्वी क्षेत्र के एक स्थानीय बाजार गए थे। खरीदारी करते समय, सड़क किनारे एक ढाबे और शराब की दुकान के पास नशे में धुत छह स्थानीय लोगों के एक समूह ने उन्हें निशाना बनाया। झड़प मौखिक उत्पीड़न से शुरू हुई। समूह ने उन पर चीनी, नेपाली, चिंकी, और मोमो सहित नस्लीय गालियों की बौछार कर दी। एंजेल ने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर दृढ़ता से जवाब दिया, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा प्रमाणपत्र दिखाना चाहिए? उनकी इस सहज प्रतिक्रिया के बाद स्थिति शांत होने के बजाय, शारीरिक हिंसा में तब्दील हो गई।

माइकल चकमा पर पहले कड़े से सिर पर वार किया गया। जब एंजेल ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी ने कथित तौर पर चाकू से उसके सिर और पीठ पर कई वार किए। एक अन्य हमलावर ने छड़ से और अधिक चोटें पहुंचाई, जबकि समूह के अन्य लोग भी हाथापाई में शामिल हो गए। बाद में चिकित्सा रपट में इन चोटों की भयावहता का विस्तृत वर्णन किया गया। इसमें सिर के पिछले हिस्से में गहरे घाव, रीढ़ की हड्डी में दरारें और गंभीर तंत्रिका आघात के कारण शरीर के दाहिने हिस्से में पूर्ण रूप से सुन्नपन का उल्लेख किया गया है। अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में 17 दिन तक चले संघर्ष के बाद, ऐंजल ने 26 दिसंबर, 2025 को दम तोड़ दिया। जांच प्रक्रिया में वही धीमी गति देखने को मिली, जिसकी पूर्वोत्तर के कार्यकर्ता अक्सर आलोचना करते हैं। माइकल चकमा ने दस दिसंबर को प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ इंडिया (सीडीएफआइ) का आरोप है कि पुलिस ने औपचारिक एफआइआर दर्ज करने में तीन दिन का समय लिया। प्रारंभिक आरोप भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उन धाराओं के तहत लगाए गए थे जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं, लेकिन 14 दिसंबर को चिकित्सकों द्वारा एंजेल की चोटों की गंभीरता का आकलन करने के बाद ही हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े गए।

सीडीएफआइ के अनुसार, इस देरी ने मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी को सीमा पार करके नेपाल भागने का अवसर प्रदान किया। चाय की दुकान के मालिक अविनाश नेगी, बेकरी मालिक सूरज ख्वास और शौर्य राजपूत और आयुष बरोनी सहित पांच अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया या किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। अवस्थी की तलाश जारी है, और उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मणिपुर के रहने वाले ख्वास की हमलावरों के समूह में मौजूदगी एक विशेष रूप से चौंकाने वाला विवरण है जो मिश्रित शहरी परिवेश में सामाजिक गतिशीलता की जटिलता को दर्शाता है। एंजेल चकमा की मौत के बाद जनता के आक्रोश ने अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र नीदो तानिया की याद दिलाई है, जिनकी 2014 में दिल्ली में हुई हत्या ने नस्लवाद पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। खबरों में अक्सर इन दोनों मामलों को जोड़ा जाता है, जिससे कभी-कभी ऐंजल के मूल राज्य को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है।

> **यूपीए सरकार द्वारा 2014 में गठित सांसद बेजबरुआ समिति ने तो एक अलग नस्ल रोधी कानून बनाने की प्राथमिक संस्तुति की थी या फिर भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर नस्लीय भेदभाव को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया था।**

नीदो अरुणाचल प्रदेश से थे, जबकि एंजेल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के निवासी थे। यह भ्रम अन्यीकरण की प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां पूर्वोत्तर की विविध पहचानों को मुख्य भूमि के समाज द्वारा एक ही श्रेणी में समेट दिया जाता है। नीदो तानिया की मौत भी दक्षिण दिल्ली के एक बाजार में लगभग वैसी ही परिस्थितियों में हुई थी, जब दुकानदारों ने उनकी अलग शैली के बालों और कपड़ों का मजाक उड़ाया था, जिन्हें वे गैर-भारतीय मानते थे। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप एमपी बेजबरुआ समिति का गठन हुआ। इसने पूर्वोत्तर के बारे में अनभिज्ञता की कमी को दूर करने के लिए विशिष्ट नस्लभेद-रोधी कानूनों, पुलिस को संवेदनशील बनाने और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव की सिफारिश की थी। नस्लीय हिंसा और संस्थागत उदासीनता का सिलसिला नीदो तानिया मामले से भी पुराना है, और साल 2012 पूर्वोत्तर समुदाय के लिए विशेष रूप से काला वर्ष रहा। बंगलुरु में रिचर्ड लोइतम और गुड़गांव में दाना संगमा की मौत के घाव आज भी ताजा हैं। अप्रैल 2012 में मणिपुर के 19 वर्षीय वास्तुशास्त्र के छात्र रिचर्ड लोइतम अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए थे। उन पर एक टीवी चैनल को लेकर हुए विवाद में वरिष्ठों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। लगभग उसी समय, मेघालय की एमबीए छात्रा दाना सिल्वा संगमा ने एमिटी विश्वविद्यालय के अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली। उन पर आरोप था कि एक परीक्षा निरीक्षक ने नकल के आरोप में अपशब्दों का प्रयोग किया और उनका करिअर खत्म करने की धमकी दी। उनके परिवार का आरोप था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए अपमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण दाना ने आत्महत्या की। ये मामले, ऐंजल चकमा के मामले के साथ, भेदभाव के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। इनमें शारीरिक हमले से लेकर संस्थागत अपमान तक शामिल हैं।

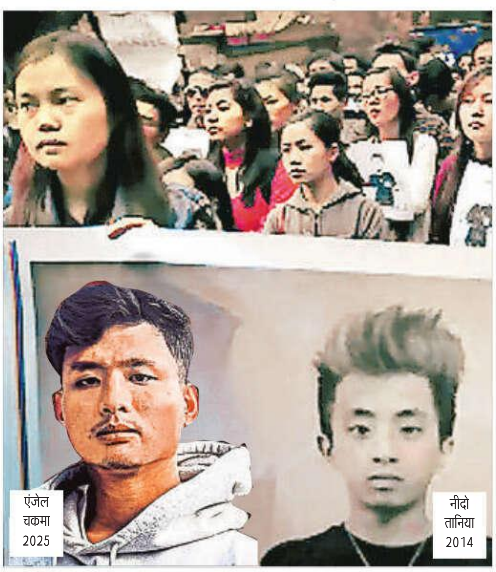

एंजेल चकमा 2025

नीदो तानिया 2014

इससे यह धारणा सामान्य हो जाती है कि वे मुख्य भूमि में मेहमान हैं न कि राष्ट्र के हितधारक। ऐंजल चकमा की मृत्यु के बाद एक प्रमुख मांग नस्ली हिंसा विरोधी कानून को लागू करना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का तर्क है कि साल 2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में परिवर्तन विधायी कमी को पूरा करने में विफल रहा। बीएनएस की धारा 103 (2) नस्ल जैसे पहचान चिह्नों के आधार पर एक समूह द्वारा हत्या को संबोधित करती है। आलोचकों का कहना है कि यह नस्लीय अपमान और रोजमर्रा के उत्पीड़न को अपराध घोषित करने में विफल रहता है जो शारीरिक हिंसा से पहले होता है।

एंजेल चकमा की मृत्यु ने पूर्वोत्तर के सभी राजनीतिक हलकों को एकजुट कर दिया है। टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा जैसे नेताओं ने इस क्षेत्र के देशभक्तिपूर्ण योगदानों को उजागर करते हुए न्याय की मांग की है। बार-बार उठने वाला सवाल, क्या हम पर्याप्त रूप से भारतीय नहीं हैं?, उस समुदाय की निराशा को दर्शाता है, जिससे सीमाओं पर अति-देशभक्ति की उम्मीद की जाती है, जबकि राजधानी में उनके साथ परदेसी जैसा व्यवहार किया जाता है। आगे का रास्ता केवल प्रतिक्रियात्मक गिरफ्तारियों से ही नहीं निकलेगा; इसके लिए बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना आवश्यक है।

देखा जाए तो बेजबरुआ समिति की सिफारिशें सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए थीं। दिल्ली के बाहर भी नस्लीय अपराध हो रहे हैं, लेकिन वहां किसी तरह का संस्थागत सहयोग नहीं मिल रहा है। दिल्ली में विशेष पुलिस इकाई और 1093 हेल्पलाइन है, लेकिन अन्य बड़े शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। अन्य पुलिस बलों को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आवास और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा अंतर बना हुआ है, लेकिन सबसे अहम सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया। नस्ल रोधी कानून की पूर्वोत्तर ने काफी पहले मांग की थी। लेकिन वह मुमकिन नहीं है तो मौजूदा कानूनों में इसे जोड़ा जाना चाहिए।

बेजबरुआ समिति की सिफारिशें अनदेखी रह गईं

एंजेल चकमा की मौत पर उपजे आक्रोश ने भारत में नस्ली भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा में मौजूद लंबे समय से चले आ रहे अंतराल को फिर उजागर कर दिया है। यूपीए सरकार द्वारा 2014 में गठित सांसद बेजबरुआ समिति ने तो एक अलग नस्ल रोधी कानून बनाने की प्राथमिक संस्तुति की थी या फिर भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर नस्लीय भेदभाव को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया था।

समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जाए। 60 दिनों के भीतर विशेष पुलिस इकाइयों द्वारा जांच हो। 90 दिनों के भीतर मुकदमे का निपटारा हो। विशेषकर उत्तर-पूर्व की महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित अदालतों या नामित अदालतों में सुनवाई की जाए।

कानूनी सुधारों के अलावा, समिति ने विशेष पुलिस इकाइयों, नामित/त्वरित अदालतों, समर्पित सहायता केंद्रों, सुरक्षित और पर्याप्त छात्रावास सुविधा, पाठ्यक्रम और शिक्षकों के संवेदनशीलकरण, तथा देशव्यापी जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सिफारिश की थी। जब भाजपा सत्ता में आई, तब अक्तूबर 2014 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने आश्वासन दिया था कि सरकार बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग एक दशक बाद भी, इन उपायों का अधिकांश हिस्सा या तो लागू नहीं हुआ है या फिर दिल्ली तक सीमित है।

क्या कर्नाटक का विधेयक राह दिखाएगा

कर्नाटक, घृणापूर्ण भाषण तथा घृणा-आधारित अपराधों पर रोक लगाने के लिए पृथक विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक घृणास्पद भाषण एवं घृणास्पद अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारतीय दंड विधि में विद्यमान उस विधायी रिक्ति को भरना है, जहां घृणापूर्ण भाषण की संकल्पना राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बार-बार प्रयुक्त होने के बावजूद अब भी विधिक रूप से परिभाषित नहीं है।

विधेयक 2025के प्रमुख प्रावधान

1-घृणापूर्ण भाषण की परिभाषा : विधेयक घृणापूर्ण भाषण को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध हानि पहुंचाती हो या सौहार्द बिगाड़ने का उद्देश्य रखती हो।

2-सामूहिक दायित्व : विधेयक में संगठनात्मक जवाबदेही का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, यदि घृणापूर्ण भाषण उनके संगठन से जुड़ा हो।

3-इंटरनेट विनियमन : यह विधेयक राज्य सरकार को आनलाइन घृणापूर्ण सामग्री को ब्लाक करने या हटाने का अधिकार देता है, जिससे घृणापूर्ण भाषण के डिजिटल प्रसार को रोका जा सके।

क्या है घृणापूर्ण भाषण

267वीं विधि आयोग रपट (2017) के अनुसार, घृणापूर्ण भाषण का अर्थ है नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा प्रसारित करने या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से कहे गए शब्द या कार्य। इस प्रकार इसमें भय पैदा करने, हिंसा भड़काने के उद्देश्य से अभिव्यक्त या लिखे गए शब्द, संकेत या दृश्य शामिल हैं।

इसे रोकने संबंधित प्रमुख निर्णय

1-शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2022 : सर्वोच्च न्यायालय ने घृणा की बढ़ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस को औपचारिक शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

2-तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ, 2018: सर्वोच्च न्यायालय ने घृणापूर्ण भाषण से प्रेरित भीड़ हिंसा के समाधान के लिए आइपीसी की धारा 153 और 295अ के तहत दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या और गोरक्षकों की रोकथाम हेतु एक जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है।

3-प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, 2014 : सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने और इसके निवारण हेतु निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के तरीकों की अनुशंसा करने को कहा।

इस पर अंकुश लगाने के प्रयास

1-विधि आयोग : 267वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2017) में घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने को अपराध घोषित करने के लिए आइपीसी में धारा 153सी और 505ए जोड़ने की अनुशंसा की।

2-विधिक पहल : वर्ष 2022 में, घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक, 2022 (निजी सदस्य विधेयक) को राज्यसभा में पेश किया गया था, ताकि घृणापूर्ण भाषण को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सके जो भेदभाव, घृणा या हिंसा को उकसाती, बढ़ावा देती या प्रसारित करती है, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया।

समितियां

1-विश्वनाथन समिति 2015 : इसने धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्मस्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराधों को उकसाने पर दो साल तक की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ आइपीसी में धारा 153उ(बी) और 505ए जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

2-बेजबरुआ समिति 2014 : इसने आइपीसी की धारा 153सी (मानव गरिमा के विरुद्ध कृत्यों को बढ़ावा देना) में संशोधन कर पांच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया तथा आइपीसी की धारा 509ए (किसी विशेष जाति का अपमान करना) में संशोधन कर तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया।

साल 2023 में 107 विधायकों-सांसदों पर घृणा भाषण के मामले दर्ज थे

एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की साल 2023 द्वारा घृणास्पद भाषणों पर जारी 183 पृष्ठों की विस्तृत रपट के अनुसार, तब के कुल 4768 सांसदों और विधायकों में से 107 के खिलाफ घृणास्पद भाषण से संबंधित मामले दर्ज थे। तब घृणास्पद भाषण के सबसे अधिक मामले, कुल 22, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के खिलाफ दर्ज हुए थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आइएनसी) के सांसदों के खिलाफ घृणास्पद भाषणों के दो मामले दर्ज थे। रपट के अनुसार, भारतीय संसद में कुल 763 मौजूदा सांसदों में से 33 सांसदों ने स्वयं अपने खिलाफ दर्ज घृणास्पद भाषण से संबंधित मामलों की घोषणा की।

रपट में दर्ज किए गए घृणास्पद भाषण के मामलों का राज्यवार विवरण भी दिया गया था। आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सात सांसदों के खिलाफ घृणास्पद भाषण के मामले दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान था, जहां चार सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज थे। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना से तीन-तीन सांसद और असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से दो-दो सांसद थे। साल 2023 में राज्य विधानसभाओं के 4005 विधायकों में से 74 के खिलाफ घृणास्पद भाषण के मामले दर्ज थे।

रपट में घोषित घृणास्पद भाषण के मामलों वाले विधायकों का दलवार विवरण दिया गया है। इस आंकड़े के अनुसार, भाजपा के 20 विधायकों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 13 और आम आदमी पार्टी के छह विधायकों के खिलाफ घृणास्पद भाषण के मामले दर्ज थे। इसके अलावा, समाजवादी पार्टी और युवा श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी से पांच-पांच विधायक, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और राष्ट्रीय जनता दल से चार-चार विधायक, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना से तीन-तीन विधायक के खिलाफ घृणास्पद भाषण के मामले दर्ज थे।

राज्यवार विवरण के अनुसार, सबसे अधिक मामले (कुल नौ) बिहार और उत्तर प्रदेश के विधायकों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के छह-छह मामले दर्ज थे। इसके अतिरिक्त, असम और तमिलनाडु के पांच-पांच, दिल्ली, गुजरात और बंगाल के चार-चार, झारखंड और उत्तराखंड के तीन-तीन, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा के दो-दो और मध्य प्रदेश और ओड़ीशा के एक-एक विधायक के खिलाफ मामले लंबित थे।

2025 बनाम नफरत

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

धर्मनिरपेक्षता के पतन ने नफरत को जन्म दिया है, एक ऐसा शब्द जिसकी हर धर्म निंदा करता है। दुख की बात है कि नफरती भाषण और लेखन के अधिकांश उदाहरण धर्म पर आधारित हैं। नफरत के अन्य कारण नस्ल, भाषा और जाति हैं। सबसे स्पष्ट नफरत मुसलमानों, उनके पहनावे और खान-पान की प्रथाओं तथा मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ दिखाई देती है। मुस्लिमों की इबादत में बाधा डाली जाती है या उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

वर्ष 2025 की आपकी सबसे यादगार स्मृति क्या है? वह कौन सा शब्द है, जो उस स्मृति को संजो कर रखेगा? भारत में सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला शब्द कौन-सा रहा?

अल्पकालिक शब्द

सिंदूर शब्द एक स्पष्ट दावेदार है। राष्ट्रीय जांच एजंसी के अनुसार, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों और उन्हें शरण देने वाले दो स्थानीय सहयोगियों ने अंजाम दिया था। इसके जवाब में आपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो एक स्वैच्छिक संघर्ष था। भारतीय वायु सेना, मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को व्यापक क्षति पहुंचाई और इसके परिणामस्वरूप भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा (जो युद्ध में अपरिहार्य है)। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीनों पाकिस्तानी एक मुठभेड़ में मारे गए। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए दो भारतीयों के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। संघर्ष के परिणामों को लेकर पारदर्शिता की कमी अभी भी बनी हुई है। *आपरेशन सिंदूर* केवल चार दिन तक चला, जो कोई स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए बहुत छोटा था।

एक और दावेदार है *शुल्क*। 2 अप्रैल, 2025 से यह शब्द हर बातचीत में सुनाई देने लगा। इसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी शब्द था- ट्रंप! ट्रंप और शुल्क ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस कर दिया है, और इसका सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, भारतीय निर्यात पर पारस्परिक शुल्क और (रूस से तेल खरीदने पर) जुर्माना अभी भी लागू है, जिससे इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा, वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद और रसायनों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पीयूष गोयल की ओर से किया गया 'निकट भविष्य' में अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते का वादा वर्ष 2025 के अंत तक उतना ही दूर है, जितना अप्रैल 2025 में था।

जीएसटी भी एक मजबूत दावेदार है। जीएसटी की विनाशकारी शुरुआत के आठ साल बाद केंद्र सरकार ने अच्छे सुझावों पर ध्यान दिया और कर संरचना को तर्कसंगत बनाया तथा कई वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरें कम कीं- फिर भी प्रशासनिक तौर पर उत्पीड़न जारी है। व्यापारियों के हर संगठन ने जीएसटी कानूनों के अनुपालन को एक दुःस्वप्न बताया है। खुदरा उपभोग के आकार की तुलना में कर में दी गई छूट बहुत कम होने के कारण खपत में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। उच्च खपत आबादी के केवल शीर्ष दस फीसद हिस्से तक ही सीमित रही।

शब्द, जो खो गए

एक अपरिचित मुहावरा- *अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा वर्ष*- चर्चा में आया, लेकिन जल्द ही गायब हो गया। यह साहित्यिक संदर्भ पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी अपरिचित था। इसके अलावा, आइएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय खातों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार से लेकर प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं तक, कई लोगों ने अर्थव्यवस्था की कमजोरियों पर बात की। अंततः रोजगार की मांग ने आधिकारिक रूप से प्रायोजित उत्सव के शोर को दबा दिया। यहां एक सबक हैः वर्तमान विकास दर पर, अमेरिका, चीन और भारत का 2025 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर अमेरिकी डालर में) में 'उत्पादन' का योगदान इस प्रकार रहा : (**देखें तालिका**)

एक ओर चीन जहां अमेरिका (सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) के साथ अंतर कम कर रहा है, वहीं भारत और चीन तथा भारत और अमेरिका के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई कमजोरियां हैं, जिन्हें सरकार स्वीकार करने से इनकार करती है या शायद समझ भी नहीं पाती। *द हिंदू* ने अपने संपादकीय में लिखाः 'अमेरिका की ओर से लगाया गया पचास फीसद शुल्क अभी भी लागू है, निजी निवेश सुस्त बना हुआ है, विदेशी पूंजी देश से बाहर जा रही है, कमजोर रुपया आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आयात को और महंगा बना रहा है, वास्तविक वेतन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है और उपभोक्ता मांग सुस्त बनी हुई है।' ऐसे में सुनहरे अवसर का दावा खोखला साबित हो रहा है।

कभी आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द *धर्मनिरपेक्ष* अब लगभग गायब हो चुका है। यह इस साल का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला शब्द बन गया है। बहुत कम लोग खुद को गर्व से धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। संपादकीय लेखक इस शब्द से परहेज करते हैं। मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य और धर्म का पृथक्करण था, लेकिन बाद में इसका अर्थ यह हो गया कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के मूल्य तर्क और मानवतावाद पर आधारित होते हैं, न कि धार्मिक सिद्धांतों पर।

देश	*वृद्धि दर*	*2025 में अतिरिक्त उत्पादन*
चीन	4.8 %	931 अरब अमेरिकी डालर
अमेरिका	1.8 %	551 अरब अमेरिकी डालर
भारत	6.6 %	276 अरब अमेरिकी डालर

शर्मनाक 'विजेता'

धर्मनिरपेक्षता के पतन ने नफरत को जन्म दिया है, एक ऐसा शब्द जिसकी हर धर्म निंदा करता है। दुख की बात है कि नफरती भाषण और लेखन के अधिकांश उदाहरण धर्म पर आधारित हैं। नफरत के अन्य कारण नस्ल, भाषा और जाति हैं। सबसे स्पष्ट नफरत मुसलमानों, उनके पहनावे और खान-पान की प्रथाओं तथा मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ दिखाई देती है। मुसलिमों की इबादत में बाधा डाली जाती है या उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। खोखला तर्क दिया जाता है कि मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और यहां के कई हिस्सों पर छह शताब्दियों तक शासन किया, और अब हिंदुओं के लिए मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने का समय आ गया है। नफरत का दूसरा निशाना ईसाई समुदाय है। गिरजाघरों में तोड़फोड़ की जाती है, ईसाई पादरियों और प्रचारकों की हत्या की जाती है, और कैरोल गाते ईसाई बच्चों पर हमला किया जाता है। ये सब हिंदू 'अधिकारों' को स्थापित करने के नाम पर किया जाता है। भारत के संविधान के लिए हिंदू वर्चस्व का विचार जितना घृणित हो सकता है, उतना और कुछ नहीं।

भारत का विचार नागरिकता की नींव पर बना है, न कि धर्म, नस्ल, जाति या भाषा पर। भारत की अधिकांश जनता डा अब्दुल कलाम और मदर टेरेसा का सम्मान करती है, लेकिन एक छोटा सा वर्ग मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाता है।

सबसे चिंताजनक पहलू इन अवैध कार्यों को साफ-सुथरा दिखाने या सही ठहराने का प्रयास है। इसके मुख्य दोषी राज्य, महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन नेता और राज्य के संरक्षण से सशक्त हुए कुछ संगठन हैं। उनके शब्द, कार्य या मौन नफरत फैलाने वालों को अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह प्रवृत्ति भारत को टुकड़ों में बांट देगी और जो होना तय है, वही होगाः एक ऐसा भारत, जो संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में बंटा होगा।

इन सभी कारणों से अत्यंत शर्म और खेद के साथ मैं उस शब्द का चयन करता हूं, जिसने 2025 में भारत को परिभाषित कियाः *नफरत*।

लोकतंत्र में विपक्ष

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

देश की समस्या यह है कि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता है, तब तक लोकतंत्र वास्तव में खतरे में रहता है। बिहार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी में वही पुरानी ऊर्जा दिखने लगी है जो लोकसभा चुनावों के बाद काफी महीनों तक नहीं दिखी थी, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बने थे बिना पूर्ण बहुमत हासिल किए। अब फिर से अपनी उपलब्धियां गिनवाने लगे हैं जैसे कि भारत को विकसित करवाने का पूरा श्रेय उनको निजी तौर पर मिलना चाहिए।

राजनीतिक नजरिए से अगर गए साल को देखा जाए, तो क्या दिखता है? मैंने अपने आप से जब यह सवाल पूछा, तो राहुल गांधी का चेहरा सामने आया इसलिए कि 2025 में उन्होंने साबित करके दिखाया कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनसे संभाली नहीं जा रही है। इस पद को संभालने का अवसर उनको मिला मुश्किल से। दो लोकसभा चुनावों में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिलीं कि नेता प्रतिपक्ष बनने का अधिकार नहीं मिल सका उन्हें। तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम इतनी सीटें दिलवाईं कि इस पद को हासिल कर सके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने पूरी तरह साबित किया कि नरेंद्र मोदी को हराना उनके बस की बात नहीं है।

हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद और इन चुनावों में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। नतीजा यह कि गए साल के अंतिम दिनों में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही रही कि जब तक नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी रहेंगे, तब तक मोदी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चर्चा यह भी होने लगी कि कांग्रेस अगर अपना अस्तित्व गंवाना नहीं चाहती है, तो राहुल की जगह प्रियंका को देनी चाहिए, लेकिन यह असंभव है, क्योंकि सोनिया गांधी ऐसा होने नहीं देंगी।

सवाल यह है कि राहुल गांधी इतने कमजोर नेता प्रतिपक्ष क्यों हैं? इसका जवाब है कि इतने चुनावों को हारने के बाद भी उन्होंने कभी ईमानदारी से हारने के कारणों को जानने की कोशिश नहीं की है। इसके बदले उन्होंने दोष डाला है चुनाव आयोग पर। पहले तो ईवीएम में 'गड़बड़' होने का आरोप लगाया, यह भूल कर कि जब कांग्रेस जीतती है, तो आरोप लगाना भूल जाते हैं। फिर शिकायत थी उनको एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से। 'वोट चोरी' का नारा उठाया। कहने लगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की सहायता से जीत चुराई। बिहार की बारी जब आई 2025 के आखिरी महीनों में, तो मतदान से पहले ही हल्ला मचाने लगे कि वोट चोरी होने वाली है। यात्रा निकाली इस मुद्दे को लेकर और हर आमसभा में लोगों से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा बुलंद करवाते रहे। ऐसा करने के बाद निकल गए एक बार फिर किसी विदेश यात्रा पर।

मैंने उनकी 2025 में विदेशी यात्राओं का जब हिसाब लगाया, तो मालूम यह हुआ। वर्ष के शुरू होते ही निकल गए थे वियतनाम, फिर दुबई और कतर गए, उसके बाद मलेशिया, फिर दक्षिण अमेरिका गए जहां ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली में दिखे। साल के अंतिम दिनों में जर्मनी की यात्रा की। जहां गए वहां अक्सर उनकी मुलाकातें हुईं प्रवासी भारतीयों से जिनको उन्होंने बताया कि भारत में लोकतंत्र तकरीबन समाप्त कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। हर भाषण में कहा कि भारत में सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया है मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। सवाल यह है कि जब देश का इतना बुरा हाल है, तो नेता प्रतिपक्ष को विदेश में घूमना चाहिए या देश में रह कर समाधान ढूंढ़ने चाहिए?

देश की समस्या यह है कि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता है, तब तक लोकतंत्र वास्तव में खतरे में रहता है। बिहार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी में वही पुरानी ऊर्जा दिखने लगी है जो लोकसभा चुनावों के बाद काफी महीनों तक नहीं दिखी थी, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बने थे बिना पूर्ण बहुमत हासिल किए। अब फिर से अपनी उपलब्धियां गिनवाने लगे हैं जैसे कि भारत को विकसित करवाने का पूरा श्रेय उनको निजी तौर पर मिलना चाहिए। ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरता है जब अखबारों में उनकी तस्वीरें न दिखती हों और टीवी पर उनका कोई भाषण सुनने को न मिलता हो।

ऐसा नहीं है कि भारत वास्तव में विकसित होने का सपना साकार करने वाला है। सड़कें, हवाईअड्डे, और बंदरगाह बेशक तीव्र गति से बनते हैं मोदी के राज में, लेकिन बेरोजगारी का काला साया नौजवानों के जीवन पर अभी भी मंडरा रहा है। पर्यावरण की समस्याएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अरावली पहाड़ियों को बर्बाद करने की साजिश अगर फिलहाल रुक गई है, तो सिर्फ इसलिए कि 'गोदी मीडिया' वालों ने भी इतना हल्ला मचाया कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलना पड़ा है।

देहातों में गरीबी की समस्या इतनी गंभीर अभी भी है कि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बिहार में अगर महिलाओं को दस हजार रुपए देने की योजना न बनी होती ऐन चुनावों से पहले, तो शायद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जीत नहीं होती। महिलाओं में चुनावों से पहले पैसे बांटने की योजनाएं बनी हैं मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद और इस में कोई शक नहीं है कि इस 'चुनावी घूस' की वजह से चुनावों की हवा बदलती है, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठा नहीं सकती है इसलिए कि राहुल गांधी ने बार-बार वादा किया है कि उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं के बैंक खातों में कई हजार रुपए आने वाले हैं 'खटाखट-खटाखट'।

सरकार राहुलजी तब बनेगी, जब आप चुनाव जीत कर दिखाएंगे। चुनाव कैसे जीतेंगे जब आपका ध्यान विदेशों में घूमने पर ज्यादा रहता है। इन यात्राओं को लेकर 2025 के आखिरी दिनों में मजाक हो रहा था सोशल मीडिया पर कि इस साल नेता प्रतिपक्ष भारत आए हैं पांच बार। सुनने में आया है कि इन दिनों राहुल गांधी एक बार फिर वियतनाम जाने की तैयारी में लगे हुए हैं!

नशे का जाल

समाज

ज्योति सिडाना

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई देश अगर कमजोर है, तो वह दूसरे देश को हराने के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए या उस समाज में बिखराव लाने के लिए नशीले पदार्थों का बाजार विकसित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रपट में बताया गया है कि प्रति वर्ष 26 लाख मौतें शराब के सेवन के कारण होती हैं, जो कुल मौत का 4.7 फीसद है।

आमतौर पर नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह आदत कब लत में तब्दील हो जाए, पता नहीं चलता। आदत को एक सकारात्मक अवधारणा के तौर पर देखा जाता है, जबकि लत या व्यसन एक नकारात्मक अवधारणा है। यह एक मनोविकार है, क्योंकि जिस नशे के सेवन की लत लग जाए, उसके बिना जीवन की निरंतरता असंभव दिखाई देती है। आदत बदलना संभवतः आसान हो सकता है, पर लत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है। चिकित्सक भी मानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन अनेक बीमारियों की जड़ है।

हालांकि, देखा जाए तो नशीले पदार्थों का सेवन कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। ग्रामीण परिवेश में हुक्का, बीड़ी और तंबाकू इत्यादि का सेवन लोग इस तर्क पर करते हैं, ताकि अधिक श्रम कर सकें और नींद की उपेक्षा कर सकें। यही नहीं, मनोरंजन के लिए भी इनका उपयोग होता था। इसका एक पक्ष यह भी था वे लोग खुद तो इनका सेवन करते थे, पर युवा पीढ़ी को इनसे दूर रहने की नसीहत और हिदायत भी देते थे, क्योंकि वे स्वयं भी मानते थे कि इन पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह, एक समय 'वाइन' (शराब) पीना प्रतिष्ठा, पश्चिमी जीवन शैली और आधुनिकीकरण के अनुकरण का प्रतीक बन गया तथा धीरे-धीरे कुछ लोगों की जिंदगी में इसने लत का रूप ले लिया। वहीं सामंतवाद में नशीले पदार्थों का सेवन राजशाही का प्रतीक था और अब पूंजीवाद के दौर में इसने एक बाजार का रूप ले लिया।

नशीले पदार्थों के सेवन को तीन दृष्टिकोणों के आधार पर समझने का प्रयास किया जा सकता है। पहला, नशे का सेवन एक चलन बन गया है, कुछ जगह इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, बच्चे या किशोर खुद को परिपक्व दिखाने के लिए इनका सेवन शुरू कर देते हैं। दूसरा, मित्र समूहों के दबाव में नशे का सेवन करना। कुछ लोग इस तरह के दबाव में आकर या घर के किसी सदस्य को नशा करते देखकर इन आदतों को अपना लेते हैं। तीसरा, राजनीतिक-अर्थवाद के रूप में नशे का सेवन करना। इस दृष्टि से देखें तो नशीले पदार्थों के बाजार से राजस्व की प्राप्ति होती है, जो किसी भी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ इसके सेवन से श्रम शक्ति कमजोर होती है, मानव पूंजी नष्ट होती है और उत्पादकता का दायरा कम होता है। यहां यह सवाल विचारणीय है कि नुकसान किसमें ज्यादा है?

इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि नशे का वैश्विक बाजार युवा शक्ति को निर्बल करने का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई देश अगर कमजोर है, तो वह दूसरे देश को हराने के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए या उस समाज में बिखराव लाने के लिए नशीले पदार्थों का बाजार विकसित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रपट में बताया गया है कि प्रति वर्ष 26 लाख मौतें शराब के सेवन के कारण होती हैं, जो कुल मौतों का 4.7 फीसद है। 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में धूम्रपान की लत भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि 26 फीसद है, जबकि शहरों में 68 फीसद है। हाल ही में सामने आए टोरंटो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 18 साल की उम्र में धूम्रपान करने वाले पुरुषों की संख्या में 36 फीसद की वृद्धि हुई है। रपट में कहा गया है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तिगत स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। हर साल इससे लाखों ऐसी मौतें होती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है। इससे दुर्घटनाओं और हिंसा का खतरा भी बढ़ जाता है।

इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि नशे के नुकसानों से परिचित होने के बाद भी ये आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैंः परिवार एवं अनौपचारिक समूहों के नियंत्रण का अभाव, नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता, मित्र समूहों की भूमिका, एकाकीपन को समाप्त करने का माध्यम, तनाव, अस्थिरता, असुरक्षा, अलगाव, भय, असफलता, कुंठा, आपराधिक प्रवृत्ति और झूठी शान का दिखावा। इसके अलावा नशीले पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट के अनुसार, 76 फीसद फिल्मों में तंबाकू एवं 72 फीसद फिल्मों में शराब का सेवन धड़ल्ले से दिखाया जाता है। वर्ष 2005 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, मगर वर्ष 2009 में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस प्रतिबंध को हटा दिया गया और अब केवल लिखित चेतावनी दिखाई जाती है। इसी तरह, वर्ष 2008 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया, वर्ष 2004 में स्कूलों से लगभग 300 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं गुटखे की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद भारत नशाखोरी में विश्व में दूसरे स्थान पर है।

नशीले पदार्थों के सेवन का प्रभाव केवल शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है, बल्कि शिक्षा, परिवार, रोजगार, व्यक्तित्व विकास, कानून व्यवस्था, अनुशासन और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। समाज पर इनके प्रभावों पर गौर करें तो इसमें संबंधित व्यक्ति का अपने आर्थिक दायित्वों को पूरा न कर पाना, उधार लेना, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होना, सामाजिक मूल्यों एवं आत्म नियंत्रण में कमी आना, पारिवारिक संघर्षों में वृद्धि और सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना आदि शामिल हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि राज्य का एक विभाग (आबकारी विभाग) तो इनसे होने वाली राजस्व प्राप्ति के लिए काम करता है और दूसरा विभाग (मद्यनिषेध विभाग) नशा मुक्ति अभियानों, विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है? सोचना यह है कि राजस्व से होने वाला लाभ ज्यादा है या विज्ञापनों एवं अभियानों पर होने वाला खर्च? किसी भी देश का यह मूल दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को शिष्ट, सुरक्षित, स्वस्थ और विकासोन्मुखी जीवन पद्धति प्रदान करे। इसलिए राजस्व हानि की परवाह किए बिना नशा करने के विभिन्न साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है।

नया अखाड़ा

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक शाम एक चैनल ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों का दल 'एसआइआर' को लेकर चुनाव आयोग से मिला, लेकिन बाहर आकर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने 'बातचीत' के बारे में कम और चुनाव आयोग द्वारा 'अंगुली दिखाने' के बारे में ज्यादा बताया।

भाजपा कहिन कि कांग्रेस में जनतंत्र नहीं। कांग्रेस कहिन कि भाजपा में जनतंत्र नहीं। अपने जनतंत्र का यही विचित्र तंत्र है कि है भी, नहीं भी!

नया वर्ष आ रहा था, लेकिन संवाददाता खांस रहे थे। कोई अक्षरधाम पर खांस रहा था, कोई धौला कुआं पर हांफ रहा था। एक चैनल ने स्क्रीन पर आठ खिड़कियां खोल दी थीं और सभी में सारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र धुंधला नजर आ रहा था। फिर एक शाम 'नेशन फर्स्ट' चैनल का एंकर परंपरागत भक्तिभाव को त्यागकर 'अरावली' को बचाने निकल पड़ा। कई दिन तक वह सरकार को निशाने पर लेता रहा... जब मुद्दा जम गया, तब छोड़ा। फिर आई इंदौर में सरकारी महकमे से प्रदत्त प्रदूषित पानी पीकर बच्चों और लोगों की मौत की खबरें और देखते-देखते अधिकतर चैनल मध्य प्रदेश सरकार और मंत्री को कठघरे में खड़ा करते रहे। अपने राष्ट्रवादी एंकर ने तो मंत्री को तुरंत हटाने की मांग तक कर डाली। एक ने तो मंत्री को 'अपराधी' तक बताया।

कई चैनल फिल्म 'धुरंधर' की 'बल्ले बल्ले' करते रहे कि फिल्म ने कुछ ही दिनों में एक हजार करोड़ से अधिक की कमाई कर सारे कीर्तिमान तोड़ दिए... वह 'शोले' के बाद सबसे बड़ी फिल्म है, उसमें 'राजनीतिक यथार्थ' और 'कला' का अद्भुत संगम है..! तो भी 'धुरंधर' की हर बहस कला बरक्स 'प्रोपेगेंडा' के बीच फंसती रही। एक कथन कि यह 'मुसलिम विरोधी' प्रोपेगेंडा है, तो दूसरा कथन कि यह मुसलिमों के खिलाफ एक 'सांस्कृतिक परियोजना' है। लेकिन एक ने कहा कि जिसे आम जनता हाथोहाथ ले रही हो, जिसे मुसलिम भी पसंद कर रहे हों, उसे कोई 'सांस्कृतिक परियोजना' कहे, तो ऐसे में क्या कहा जाए?

इस बीच एक से एक 'विभाजनकारी' कहानी बांग्लादेश देता रहा। आए दिन किसी हिंदू की भीड़ के हाथों हत्या की खबरें हिलाती रहती हैं। चैनलों की बहसों में कई नेता इन हत्याओं पर इस तर्क के साथ जवाब देते रहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, वही भारत में मुसलमानों पर हो रहा है। एक उकसावेबाज बोला कि भारत सरकार वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई 'आपरेशन सिंदूर' क्यों नहीं करती!

फिर एक दिन लखनऊ के ताजा उद्घाटित 'प्रेरणा स्थल' से गमलों की चोरी की खबर ने राष्ट्रमंडल खेलों के दिनों की याद दिला दी। तब गमला चोरों का दिल्ली में प्राकट्य हुआ था।

ऐसे ही एक दिन दिग्विजय जी पर शायद भूत सवार हो गया और उनके मुखारविंद से कुछ वचन फूट निकले कि संघ की कार्यपद्धति अच्छी... मैं संघ की विचारधारा का विरोधी हूं! लेकिन संघ की 'कार्य पद्धति' उसके विचार से ही तो निकली है, तब काहे का विरोध सर जी! इसी बीच एक इस्लामी विद्वान शमाइल नदवी कई चैनलों पर अवतरित हुए। इसका श्रेय उस बहस को जाता है, जिसमें 'ईश्वर' के अस्तित्व को लेकर 'नदवी बरक्स-जावेद अख्तर' बहस कराई। उधर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर हर शुक्रवार को अपना मुंह खोलते हैं और जवाब में कल तक के मंदिर विरोधी 'मंदिर मंदिर' जपने लगते है कि सिलीगुड़ी में 'महाकाल मंदिर' बनाएंगे और कि 'दुर्गा आंगन' सरकारी कोष से बनाएंगे। इसे देख हुमायूं ने पूछा कि मंदिर के लिए सरकारी धन क्यों?

फिर एक शाम एक चैनल ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों का दल 'एसआइआर' को लेकर चुनाव आयोग से मिला, लेकिन बाहर आकर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने संवाददाता सम्मेलन में 'बातचीत' के बारे में कम और चुनाव आयोग द्वारा 'अंगुली दिखाने' के बारे में ज्यादा बताया। बहसों में चर्चक कहे कि बंगाल का आगामी चुनाव 'घुसपैठियों' के मुद्दे पर लड़ा जाना है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि 'घुसपैठियों' के लिए केंद्र जिम्मेदार है, तो गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल सरकार तारबंदी के लिए जमीन नहीं देती, इसलिए जहां तारबंदी नहीं है, वहीं से घुसपैठिए घुसते हैं। इतने पर भी ममता दीदी ने 'दुर्योधन' और 'दुशासन' को ललकार दिया! लेकिन 'एसआइआर' ने नई मतदाता सूची के शुरुआती आंकड़ों के जरिए यह संकेत देकर, कि सभी राज्यों में वोट कटने हैं, उत्तर प्रदेश में तो दो करोड़ से अधिक कटने हैं, तो किसी राज्य में साठ-सत्तर लाख वोटर कटने हैं, सभी दलों के पेट में मरोड़ पैदा कर रखी है।

और चलते-चलते भी शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम 'केकेआर' के लिए खरीदकर एक विवाद को अनजाने ही जन्म दे दिया। एक हिंदूवादी नेता ने शाहरुख को 'गद्दार' तक कह दिया। एक एंकर ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने बांग्लादेश गए, तो क्या वे भी 'गद्दार' हो गए! इसी बीच कुछ बाबा कूद पड़े। फिर कुछ मौलाना भी कूद पड़े... नया अखाड़ा खुला..!

जनसत्ता सरोकार

साहित्य

तीन

जनसत्ता | 4 जनवरी, 2026

लेन-देन

कहानी

राजेंद्र कुमार सिंह

जब भी घर में निमंत्रण पत्र आता है, तो आने के साथ पहले घर में जो प्रयोजन हुआ था और बंदे ने नेवता में क्या दिया था, उस सूची को भरसक देखने का प्रयास करता है बाबू हरिनाम सिंह का बेटा सुमेर। किंतु आज का निमंत्रण पत्र कुछ अलग है। निमंत्रण पत्र शैलेंद्र का है, जो गांव के नाते उसका छोटा भाई है और मित्र भी। शैलेंद्र और सुमेर साथ-साथ गांव के स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने में दोनों ही बढ़िया थे।

शैलेंद्र के बाप-दादा के पास जमीन के नाम पर चार कमरों का एक मकान और कट्ठे भर की खाली जमीन थी। जिस पर मड़ई डालकर शैलेंद्र के पिता गाय पालते थे और दूध निकालकर बेचते थे। वह अपने घर की इकलौती संतान था। पिता की मौत के बाद पढ़ाई पर आंच नहीं आए, सो उसकी मां और दोगुनी रफ्तार से मेहनत करने लगी। मेहनत मजदूरी तो उस समय भी करती थी, जब उसके पति दशरथ जीवित थे। वह दूध निकालते और गांव के देहाती बाजार विक्रमगंज जाकर बेच आते थे। उसकी मां से यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब तक गाय दूध देती रही, तब तक भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। शैलेंद्र ने मां के काम को आसान करने के लिए ओने-पौने दामों में गाय को खूंटे से हटा दिया।

शैलेंद्र ने गांव के स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास कर विक्रमगंज कालेज में नामांकन करा लिया था। जबकि सुमेर ने उच्च शिक्षा हेतु जैन कालेज आरा में नामांकन लिया, जहां हास्टल की व्यवस्था थी। लेकिन, वह निजी मकान लेकर रहता था, जिसमें सहूलियत के मुताबिक एक कमरे में तीन लोगों के रहने का समुचित प्रबंध था। दूसरे गांव के दो लोग महेश रंजन और विनोद भी उसके साथ रहते थे। महीने का जो खर्च होता था, तीनों आपस में बांट लेते थे।

शैलेंद्र विक्रमगंज कालेज के लिए रोजाना घर से आना-जाना करता था। एक तो उतनी आय भी नहीं थी कि बाहर हास्टल में रहकर पढ़े, और बीमार मां को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वह मन ही मन कहता, कुछ करने की ललक हो तो कहीं भी रह कर पढ़ा जा सकता है। वह छोटी-मोटी नौकरी तलाश करने की फिराक में लग गया। अपनी इस स्थिति के बारे में वह अपने मित्रों से कभी चर्चा नहीं करता था।

शैलेंद्र की मेहनत वाकई रंग लाई। सचिवालय में लिपिक के लिए राजस्व विभाग में उसकी नियुक्ति हो गई। शैलेंद्र मां को लेकर राजधानी पटना आ गया था। आर्थिक स्थिति सुधरते ही शैलेंद्र ने राजधानी के कालेज में दाखिला ले लिया। वह कालेज तो कभी गया नहीं, घर पर रहकर ही अध्ययन करने के साथ एक कोचिंग संस्थान से जुड़ गया था। कोचिंग में प्रवेश का समय सात बजे का था। दफ्तर छह बजे तक रहता था, लेकिन घर आते तक साढ़े छह बज जाते थे। इसलिए समय का समायोजन इस कदर बैठा लिया था कि संस्थान जाने के लिए कभी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वह कोशिश करता था कि इस संबंध में संस्थान वालों को शिकायत का मौका नहीं मिले।

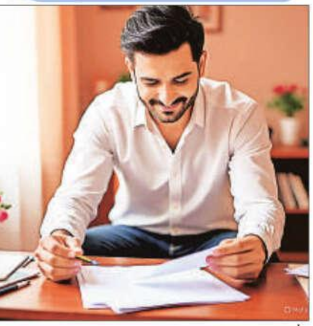

सुमेर संशय में डूबा हुआ था। अब वह रिश्तेदारी में जुड़ने जा रहा है, इसलिए तन-मन-धन से उसे अपने परिवार के साथ शैलेंद्र के प्रयोजन में शरीक होना था।

शैलेंद्र की मां का स्वास्थ्य पहले से काफी निखर गया था। वह अक्सर गांव जाने के लिए बेचैन हो जाती थीं। हालांकि शहर भी गांव से ही बनता है। उसके पड़ोस में अपने जिले के लोग ही बसे हुए थे। शैलेंद्र की तरह वे लोग भी सचिवालय के कर्मचारी थे। शैलेंद्र राजस्व विभाग में था तो उसके पड़ोस के रामदीन और महेंद्र सिंचाई विभाग में कार्यरत थे।

ड्यूटी के बाद तीनों मित्र कोचिंग करने जाते थे। इन तीनों परिवारों के बीच काफी घनिष्ठता बढ़ गई थी। शैलेंद्र अभी अविवाहित था, जबकि उन दोनों की शादी हुए तीन-चार साल हो गए थे। अब बच्चे भी थे। दोनों की पत्नियां शैलेंद्र की मां की अपनी सास की तरह सेवा करती थी। शैलेंद्र के गांव में उसकी शादी को लेकर उत्सुकता चरम पर थी। मां कहती, आप लोग शैलेंद्र से बात कीजिए। शादी तो यहीं से होगी, अपने लोगों के बीच। अब शैलेंद्र सचिवालय में अधिकारी के लिए चुन लिया गया था। शैलेंद्र ने एक पढ़ी-लिखी साधारण परिवार की लड़की से रिश्ता जोड़ लिया था।

हालांकि, रीना संजय के पिता बाबू हरिनाम सिंह के दूर के रिश्ते में ताल्लुक रखती थी। शैलेंद्र को रीना का स्वभाव बहुत पसंद आया था। शैलेंद्र की मां हरिनाम के यहां काम करने जाती थी, तब उसकी मां रीना को लेकर आई थी। जिसे गोद में खेलाया था, आज वह उसकी बहू बनने जा रही थी। शैलेंद्र की मां रीना की मां को बहन कहकर बुलाती थी। वह हरिनाम के चचेरे भाई की बहन की लड़की थी। उस समय पूरा परिवार संयुक्त रूप से रहता था। सुमेर के चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने भाई के हिस्से को हरिनाम के नाम कर गई थी। वह कहती, 'रिश्ते के लिए पैसे का मोल नहीं बस आते जाते कार्य प्रयोजन में पूछते रहिए बड़े पापा।' तब हरिनाम ने उसकी लड़की के लिए शैलेंद्र जैसे होनहार लड़के को पहले से अपनी नजरों में सहेज लिया था।

शैलेंद्र ने अपने तमाम मित्रों को सूचित तो कर दिया था। सुमेर को मित्र के साथ बड़ा भाई मानता था। सुमेर अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जिसमें उसके रिश्तेदारों से लेकर गांव ज्वार के लोगों ने जो दिया था पुनः वापस लौटाने के क्रम को देखते हुए नेवता या उपहार को लिखकर रख लिया था। किसके घर के किस प्रयोजन में क्या लेन-देन हुआ। साड़ी-धोती के साथ नकद कितना था, ताकि अगले के यहां कोई प्रयोजन हो तो समय के साथ बढ़ाकर उसको लौटाया जा सके। इसलिए वह डायरी सुमेर अपने पास रखता था। उसके निर्देशानुसार उसके बाबू समारोह में जाते तो इसे लेकर जाना पड़ता था।

शैलेंद्र की शादी का निमंत्रण-पत्र आया तो उसे अपनी सोच में बदलाव करना पड़ा। क्योंकि उसके पिता के गुजरने के बाद से घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी को नेवता दे सके। उसके अपने घर की गृहस्थी की गाड़ी आजू-बाजू के घर के छिटफुट कार्यों के करने से किसी तरह से खींच-तान कर आगे बढ़ रही थी। इसलिए कोई भी उसके घर नेवता या निमंत्रण भेजता तो यह जरूर कहता, 'बस प्यार मोहब्बत बना रहे। नेवता देने की जरूरत नहीं पूरे परिवार का आना जरूरी है। किसी तरह का उपहार या पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा।' शैलेंद्र इस बात को भली-भांति समझता था। इसलिए उसके घर के कार्यों के निष्पादन हेतु सहूलियत के हिसाब से चार घंटा पहले पहुंच जाता था। उपहार के एवज में वह खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता था।

सुमेर संशय में डूबा हुआ था। अब वह रिश्तेदारी में जुड़ने जा रहा है, इसलिए तन-मन-धन से उसे अपने परिवार के साथ शैलेंद्र के प्रयोजन में शरीक होना था। साथ में उपहार की व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी में भी शरीक होना था। और, यह उपहार अनमोल उपहार होगा, सबसे अलग।

समय सूचक

पूंजीपति बना श्रमिकों का मसीहा

जनसत्ता सरोकार

यरूशलम में एक ऐसे इंसान की कब्र है जो नाजी पार्टी का सदस्य था। वह नाजी पार्टी, जिसने यहूदियों का जनसंहार किया। यहूदियों पर नाजियों का जुल्म मानव इतिहास की खौफनाक घटनाओं में से एक है। द्वितीय विश्वयुद्ध की आपदा को पूंजीपतियों ने एक अवसर की तरह देखा, जिसमें आस्कर शिंडलर भी थे। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया। वहां के शहर क्राको में शिंडलर ने यहूदियों के पुराने कारखाने की मरम्मत करके फौजियों की जरूरत के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। शिंडलर ने कारखाने में सिर्फ यहूदी श्रमिकों को ही रखा, क्योंकि उनका वेतन सीधे नाजी खजाने में जाता था, और उन्हें काफी कम वेतन दिया जाता था। शिंडलर सस्ते श्रमिक के चक्कर में कुछ यहूदियों के फर्जी कागजात भी तैयार करवाते हैं। शिंडलर इस कारोबार में काफी मुनाफा कमाते हैं। यहूदी समुदाय शिंडलर के कारखाने को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि वे अपने श्रमिकों को नाजियों के अत्याचार से बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहूदियों पर नाजियों का अत्याचार देख शिंडलर का हृदय परिवर्तन होता है। जो शिंडलर सस्ते मजदूर और मुनाफे के लिए यहूदियों को बचाते हैं, वही बाद में अपना पूरा मुनाफा सिर्फ यहूदियों को बचाने में खर्च कर देते हैं। यहूदियों को बचाने के लिए वे नाजी अधिकारियों को भारी-भरकम रिश्वत देते हैं। शिंडलर्स ने अपने राजनीतिक संपर्क और पैसे की बदौलत 11,00 से अधिक यहूदियों को उनकी कत्लगाह आशविट्ज जाने के बजाए अपने उस कारखाने में भेजा, जहां उत्पादन के नाम पर यहूदियों का जीवन था। थामस केनेली ने इस उद्योगपित के जीवन पर आधारित 'शिंडलर्स आर्क' नाम का उपन्यास लिखा। इस उपन्यास पर स्टीवन स्पिलबर्ग ने 'शिंडलर्स लिस्ट' नाम की फिल्म बनाई, जिसे सात आस्कर पुरस्कार मिले।

आस्कर शिंडलर

गौतम की हिम्मत

बाल कथा

विमला रस्तोगी

'अरे माथे पर यह गूमड़ कैसे पड़ गया?' गौतम के स्कूल से लौटते ही मां ने पूछा। 'इसे मदान मैडम के लड़के रंजन ने धक्का दिया था', गौतम की जगह उसकी बहन आकांक्षा ने जवाब दिया।

'आज एक पीरियड खाली था। मैंने बैग में से गणित की कापी निकाली। एकदम रंजन ने खींच ली। कापी फट गई। मैंने उसे हटाया। वह डेस्क पर गिर गया। उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर दीवार से जा टकराया। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर चुप रहा', गौतम ने एक ही सांस में मम्मी को सारी बात बता दी। मां ने गौतम के माथे पर दवाई लगाई।

'रंजन अगर मैडम का लड़का न होता तो उसकी हड्डी-पसली एक कर देता', गौतम को अभी तक गुस्सा आ रहा था।

'गलत बात का विरोध करना चाहिए। तुम प्रिंसिपल से शिकायत क्यों नहीं करते?' मां ने सलाह दी।

'प्रिंसिपल का लड़का पारस भी मेरी कक्षा में है। मानीटर है। कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सारे लड़के उससे डरते हैं। सब कोई उससे परेशान हैं।'

'लेकिन क्यों? बेमतलब डरने से हीन भावना आती है। अन्याय को सहना भी अन्याय है। साहसी बनो। आगे से पारस और रंजन की गलत बातें बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी कक्षा के लड़कों को समझाना। उन्हें भी इस बात के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तुम लोग एकजुट होकर बोलो। एकता में बड़ी ताकत है', मम्मी के समझाने से गौतम का गुस्सा खत्म हो गया। सबने मिलकर खाना खाया।

अगले दिन से ही गौतम ने अपने साथियों को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। धीरे-धीरे ज्यादातर लड़के गौतम के साथ हो गए। कुछ लड़के अब भी रंजन और पारस की हां में हां मिलाते रहते थे।

पारस कक्षा में कापियां उछाल-उछाल कर बांटता था। एक दिन उसने जैसे ही कापी उछाली, गौतम ने टोका, 'पारस, कापियां ठीक से दिया करो।' 'हां, इस तरह कापियां फट जाती हैं,' दूसरा लड़का बोला।

गौतम के चाचाजी ने उसे एक कलम उपहार में दी थी। कलम बहुत सुंदर और कीमती थी। गौतम अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कलम लेकर स्कूल गया। गौतम अपने दोस्त को कलम दिखा रहा था कि रंजन ने झटक लिया, और कलम की स्याही गौतम के ऊपर छिड़क दी। गौतम के नए स्वेटर पर स्याही के छींटे गिर गए। गौतम ने गुस्से से रंजन की तरफ देखा। रंजन ने कलम डेस्क की तरफ फेंकी। डेस्क से टकराकर कलम की निब टूट गई। गौतम ने पलक झपकते ही रंजन का कालर पकड़ लिया। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। गौतम हर तरह से रंजन पर भारी पड़ रहा था। पारस वहां नहीं था। अन्य लड़कों ने आकर बीच-बचाव किया।

'मैं अभी प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर तेरी शिकायत करता हूं। गौतम के बच्चे, अभी तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी,' गुस्से में फुफकारता रंजन प्रिंसिपल के कमरे की तरफ चला गया। तब तक इंटरवल भी खत्म हो चुका था। सब बच्चे कक्षा में आ गए। रंजन नहीं आया। तभी चपरासी गौतम को बुलाने आ गया। प्रिंसिपल ने बुलाया था।

'तुमने रंजन को क्यों मारा?' प्रिंसिपल ने पूछा। गौतम ने बिना डरे हुए निःस्संकोच सारी बातें प्रिंसिपल को बता दी। अपने माथे में गूमड़ पड़ने वाली बात भी बता दी, 'मैडम, मैंने रंजन की बहुत सी गलत बातें बर्दाश्त कीं, पर अब नहीं करूंगा। मेरी मां कहती है, अन्याय को बर्दाश्त करना भी अन्याय है', गौतम ने साहस के साथ कहा।

'बताओ रंजन, गौतम सच कह रहा है?' अब रंजन चुप। वह गौतम की हिम्मत पर हैरान था।

'मैडम, रंजन से कक्षा के सब लड़के डरते हैं क्योंकि यह मदान मैडम का बेटा है। वह पूरी कक्षा को परेशान करता है। उसे लगता है कि मैडम का बेटा होने की वजह से वह जो चाहे कर सकता है,' गौतम ने कहा।

गौतम के चाचाजी ने उसे एक कलम उपहार में दी थी। कलम बहुत सुंदर और कीमती थी। गौतम अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कलम लेकर स्कूल गया। गौतम अपने दोस्त को कलम दिखा रहा था कि रंजन ने झटक लिया, और कलम की स्याही गौतम के ऊपर छिड़क दी। गौतम के नए स्वेटर पर स्याही के छींटे गिर गए।

'अगर ऐसा था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया?'

'मैं अवसर की तलाश में था। क्षमा करें मैडम, एक बात और कहनी है', गौतम ने अनुरोध किया।

'हां-हां कहो।'

'पारस से भी कक्षा के सब विद्यार्थी डरते हैं। वह कापियां तक उछालकर बांटता है, जिससे कापियां फट जाती हैं। कृपया आप इस बात का भी संज्ञान लीजिए।'

'अच्छा, वह फिर कभी ऐसा करे तो बिना संकोच मुझसे आकर कहना। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूं। रंजन, तुम गौतम से माफी मांगो तथा इसकी कलम में निब डलवाकर दो,' प्रिसिंपल ने कहा।

मजबूर होकर रंजन को गौतम से माफी मांगनी पड़ी। 'रंजन, तुम पूरे पीरियड क्लास के बाहर खड़े रहो, ताकि अन्य सभी अध्यापकों के बच्चों को भी सबक मिले और पारस भी गलतफहमी में न रहे।'

रंजन सजा में कक्षा के बाहर खड़ा रहा। कक्षा में ही क्या, पूरे स्कूल में गौतम के साहस की चर्चा होती रही। उसके दोस्तों ने गौतम को बधाई दी। गौतम ने घर आकर मां के पैर छुए। मां ने उसे साहसी बनने तथा अन्याय के खिलाफ लड़ने का आशीर्वाद दिया।

भीड़ की अदालत में गलती

मार्गदर्शन

जनसत्ता सरोकार

कुछ चीजें गलत होती हैं, और कुछ चीजों पर शोर होता है। जिन चीजों पर शोर होता है, जरूरी नहीं कि वे गलती के अनुपात में हो। इंटरनेट के इस दौर में सबसे बड़ा आघात निजता पर हुआ है। कई मसले ऐसे होते हैं, जो निजी तौर पर व्यवहार का हिस्सा होते हैं। अगर उससे दिक्कत होती भी है, तो उसके दायरे में आने वाले लोगों से बातचीत कर उसे सुलझाया जा सकता है। अगर उन्हीं मसलों को सार्वजनिक मंच पर डाल दिया जाता है, तो वे शोर के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में किसी के लिए फैसला लेना मुश्किल होता है कि वह क्या करे। वह शोर की परवाह करे या अपने निजी रिश्तों की परवाह करे, जो भावनात्मक तौर पर उन पर निर्भर हैं।

पिछले साल एस्ट्रोनामर कंपनी के मानव संसाधन विभाग की पूर्व प्रमुख क्रिस्टीन कैबट ने 16 जुलाई 2025 में हुए कोल्डप्ले विवाद को लेकर अपनी बात सामने रखी है। कोल्डप्ले के समारोह के दौरान कैमरे ने कैबट को उनकी कंपनी के प्रमुख अधिकारी एंडी बायरन के साथ नजदीक होते दिखाया था। समारोह के दौरान ही यह वीडियो एक उपयोगकर्ता ने सोशल मीडिया पर डाल दिया जो वायरल हो गया। वीडियो ने नैतिकता को लेकर बहस छेड़ दी। कैबट और उनके अधिकारी की तस्वीर दुनिया भर के लोगों के फोन में थी। अब दुनिया भर के लोग क्रिस्टीन के लिए न्यायाधीश बने हुए थे। वे क्रिस्टीन को दुनिया की गंदी महिला का खिताब देने वाले संदेश भेज रहे थे।

एक स्त्री के तौर पर क्रिस्टीन के लिए उस वक्त का माहौल बोझिल बन गया था। यह उनकी कंपनी, दोस्तों, परिवार, शहर या देश तक का मामला नहीं रह गया था। दिनभर आते अनगिनत फोन और घर के बाहर जुटे 'पैपराजी'। सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे क्रिस्टीन के दो बच्चे और तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे उनके पति। उस वक्त क्रिस्टीन ने अपने हिस्से में चुप्पी को चुना और कंपनी की साख बचाने के लिए बैरन और क्रिस्टीन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। उस वक्त क्रिस्टीन इस अपराध बोध में थीं कि मैंने अपनी जिंदगी से जुड़े अच्छे लोगों को दुखी कर दिया।

बीते साल के अंत में क्रिस्टीन ने उस बुरे दौर के अनुभव को सामने रखा है। उस दिन, समारोह में उनके दूसरे पति भी उपस्थित थे, जिनसे अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। क्रिस्टीन आज भी उस पल की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके अनुसार, वह एक बत्ती बुझने और जलने जैसा पल था।

अपनी जिंदगी के इस खौफनाक साल का अंत होते क्रिस्टीन का साझा किया अनुभव हम सबके लिए सबक है। हर आता नया साल तकनीक के मामले में और नया होगा, साथ ही हमारी निजता के लिए खतरा और बढ़ेगा। कोल्डप्ले के समारोह में तो सैकड़ों कैमरे थे, पर आज सड़क पर भी कृत्रिम मेधा वाले चश्मे का खौफ है। हर कोई, हर कहीं किसी कैमरे में कैद हो रहा है। हर किसी पर खतरा मंडरा रहा है कि वह भीड़ के इंसाफ की जद में न आ जाए। शोर और भीड़ के इस समय को समझना अब ज्यादा जरूरी है।

शर्ले टेंपल : महामंदी के दौर की मुस्कान

अमर किरदार

जनसत्ता सरोकार

सुनहरे बालों में लगभग 56 घुंघराले गुच्छे, चमकती आंखें, मुस्कुराए तो गालों में प्यारे गड्ढे। प्यारी गुड़िया सी दिखने वाली लड़की, जिसे हर कोई अपनी गोद में उठा कर दुलार करना चाहे। अपने जूते की धुन पर सबको नचा दे। 1930 के बाद जब अमेरिका आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तो इस बाल कलाकार के किरदार ने लोगों को अवसाद से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। इस बाल कलाकार का नाम था, शर्ले टेंपल। उस मुश्किल दौर में शर्ले की फिल्मों को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि अमेरिकियों ने 15 शेंट में अपनी सभी परेशानियों को भुला दिया।

शर्ले जेन टेंपल का जन्म 23 अप्रैल 1928 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां गर्टूड टेंपल और पिता जार्ज टेंपल थे। गर्टूड टेंपल को अहसास हो गया था कि उनकी बच्ची में एक करिश्माई किरदार है। उन्होंने शर्ले को गायन से लेकर नृत्य में प्रशिक्षित किया। शर्ले के बालों के घुंघराले गुच्छे उनकी मां ने ही बनाए थे। महज तीन साल की उम्र में शर्ले टेंपल एक नृत्य स्कूल जाने लगी थी, जहां से वे सिनेमाकारों की नजर में आईं और 'बेबी बर्लेक्स' से उनके फिल्मों की शुरुआत भी हो गई। शर्ले के ज्यादातर सहनायक उससे बड़े और लंबे होते थे। अपने लंबे सहनायकों से बात करते वक्त वह कमर पर हाथ रख, सिर ऊंचा कर बोलती।

शर्ले टेंपल के किरदार एक ऐसी बच्ची के होते थे, जो जिंदगी की मुश्किलों में पड़ कर हंसती और हंसाती है। कमजोर तबके की बिना पिता या मां की बच्ची या फिर अनाथ। इस बच्ची के संघर्ष को देख कर लोग अपने दुख भूल जाते थे।

आदेशात्मक सुर में बात करती। यह शैली उसकी कई फिल्मों में रही। उसके कपड़े, बाल, उच्चारण ने बाजार को बाल नायिका दे दी। उस समय शर्ले जैसी गुड़िया खूब बिकने लगी।

शर्ले टेंपल के किरदार एक ऐसी बच्ची के होते थे, जो जिंदगी की मुश्किलों में पड़ कर हंसती और हंसाती है। कमजोर तबके की बिना पिता या मां की बच्ची या फिर अनाथ। इस बच्ची के संघर्ष को देख कर लोग अपने दुख भूल जाते थे। उन्हें लगता था कि जब यह नन्ही बच्ची अपनी मुश्किलों से निकल सकती है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। एक छोटी बच्ची के लंबे संवाद, लंबी लयबद्ध कविता को सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हाल पहुंच जाते थे। दर्शक जब 'लिटिल कर्नल' देख कर निकलते तो शर्ले के सीढ़ी पर किए नृत्य की नकल करते झूमते। 'ब्राइट आइज' में गाया गाना 'आन द गुड शिप लालीपाप' शर्ले की शैली की पहचान बन गई थी। 'द लिटिल प्रिंसेस' शर्ले की पहली रंगीन फिल्म थी। 'द लिटिलेस्ट रिबेल' में उन्हें अपनी पिता की जान बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपित से मिलते दिखाया गया है। 'ए किस फार कोर्लिस' शर्ले की आखिरी फिल्म थी। उन्हें जूवेनाइल आस्कर भी मिला।

शर्ले के बड़े होने के साथ अमेरिकी समाज में बदलाव आया और उनके किरदारों की पहले जैसी ख्याति नहीं रही। 1950 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। वे घाना और चेकोस्लोवाकिया में अमेरिकी राजदूत रहीं। दस फरवरी 2014 को 85 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया।

ज्ञान की गरिमा

विचार बोध

रोहित कुमार

एक आम सूक्ति है कि जब कोई पेड़ फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। इसका अर्थ भी सामान्य और सहज है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से लैस हो जाता है तो वह विनम्र हो जाता है। बल्कि इससे ज्यादा शायद यह होता है कि एक ज्ञान से लैस व्यक्ति खुद को ज्ञान की राह का यात्री भर मानता है और कुछ जानने के क्रम में जब कुछ हासिल कर लेता है, तब वह जितना अपने पास पहुंच सके ज्ञान का सम्मान करता है, उससे ज्यादा वह अपने पास नहीं पहुंच सके ज्ञान और उससे लैस व्यक्ति की कद्र करना शुरू कर देता है। इसकी वजह यह हो सकती है कि जब व्यक्ति ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है और इस नाते वह ज्ञान के साथ-साथ ज्ञान के सभी केंद्रों का सम्मान करने लगता है।

इससे आगे की बात भी की जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को सबसे ज्ञानी या अंतिम विचार देने लायक समझने लगता है तो इसका मतलब ही है कि उसके पास इसकी घोर कमी है और वह सिर्फ ज्ञान की शक्ति के ऊपरी रूप से ही परिचित हो पाया है। ऐसे व्यक्ति की मुश्किल यह होती है कि वह किसी चीज के बारे में जानने-समझने के बजाय उस पर अपनी समझ को अंतिम मान लेता है। इससे खुद उसका नुकसान तो होता ही है, उसके परोसे ज्ञान के संपर्क और प्रभाव में आने वाले लोगों को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। सवाल है कि ज्ञान की खोज में निकला या ज्ञान का भूखा कोई व्यक्ति आखिर किस मानस का शिकार रहता है या फिर हो जाता है कि वह ज्ञान को खोजने में कम और अन्य को कमतर घोषित करने की कोशिश में ज्यादा लगा दिखता है।

नकार का रोग

इस तरह की स्थिति में होता यह है कि जो ज्ञान व्यक्तित्व के विस्तार का वाहक बन सकता है, उसे प्राप्त करने की सिर्फ कोशिश के बूते एक व्यक्ति अपनी और ज्ञान की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की राह पर निकल पड़ता है। वह कोशिश तो करता है कि किसी अन्य की मेहनत या प्रयास को खारिज किया जाए, उसके सहारे उसे अवसरों से वंचित किया जाए, लेकिन यह ध्यान रखना भूल जाता है कि इससे वह हासिल क्या कर पाता है। संभव है कि इस प्रवृत्ति की वजह से किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान हो जाए, मगर इस कीमत पर अगर कोई कुछ पाना चाहता है, तो उसका मूल्य वास्तव में शून्य बराबर होता है, भले ही वह आम परिभाषा में 'कुछ पा लेने' के तौर पर देखा-समझा जाता हो।

ज्ञान का महत्त्व तभी तक स्वीकार किया जाता है, जब वह इंसान के भीतर मानवीय मूल्यों का वाहक बने, उसमें विस्तार करे। अगर ज्ञानी होने के दंभ में कोई व्यक्ति नाहक ही किसी के प्रयास को नकारता है, उसे कमतर घोषित करता है, तो ऐसा करके वह न केवल अपने 'अधजल गगरी छलकत जाए' का परिचय देता है, बल्कि ज्ञान की गरिमा का भी नाश करता है। हालांकि यहीं इस सत्य का भी साक्षात्कार किया जा सकता है कि जिसके पास वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान का राही होने की भूख है, वह ज्ञान को लेकर कभी किसी भी तरह के अहंकार का शिकार नहीं होता। बल्कि ज्ञान का पथिक होने के नाते वह विनम्र हो जाता है और अपने प्राथमिक प्रयास के क्रम में अपने आसपास की जटिलताओं को सुलझाता है, विचारों के ऊपर पड़े जाले को साफ करता है। अगर किसी व्यक्ति से चूक होती है तो वह उसमें सुधार के लिए पूरी विनम्र पहल करता है।

सुधार के समांतर

सच यह है कि ज्ञान की खोज की राह में निकला व्यक्ति अपने विचारों से लेकर व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखता ही है, साथ ही वह अपने आसपास की विडंबनाओं में भी सुधार करता है। यह सुधार किसी प्रचार के उद्देश्य से नहीं होता, बल्कि किसी बिगड़ी बात या चीज को दुरुस्त करने की वास्तविक और मानवीय भूख से उपजा प्रयास होता है। इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं होती, बल्कि इसके उलट अपने वैचारिक परिदृश्य के साथ-साथ अपने आसपास के वातावरण में भी जीवन-तत्त्व का विस्तार करता है। दरअसल, विनम्रता की अपनी शक्ति होती है। ज्ञान की राह का एक मुसाफिर किसी भी कीमत पर इसमें कमी-बेशी के आधार पर अन्य व्यक्ति का आकलन नहीं करता। वह ज्ञान को समृद्ध करने के लिए अपने सहित अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास करता है।

> **ज्ञान** का महत्व तभी तक स्वीकार किया जाता है, जब वह इंसान के भीतर मानवीय मूल्यों का वाहक बने, उसमें विस्तार करे। अगर ज्ञानी होने के दंभ में कोई व्यक्ति नाहक ही किसी के प्रयास को नकारता है, उसे कमतर घोषित करता है, तो ऐसा करके वह न केवल अपने 'अधजल गगरी छलकत जाए' का परिचय देता है, बल्कि ज्ञान की गरिमा का भी नाश करता है।

प्रहसन का चेहरा

इस क्रम में होता यह है कि उसके आसपास लोगों के भीतर उसे लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके ठीक उलट भी होता है। ज्ञान हासिल करने की राह में निकला व्यक्ति आखिरकार अपना खोखलापन दुनिया के सामने रखता है और फिर जो ज्ञान उसके तथा आसपास के लोगों के लिए सम्मानजनक जरिया हो सकता था, वह किसी के अधकचरेपन की वजह से प्रहसन के तौर पर देखा जाने लगता है।

यह वास्तव में हीनभावना और कुंठा का सूचक होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ज्ञान की गरिमा और उसकी अहमियत को समझ नहीं पाता और अपने पास मौजूद दंभ को ही ज्ञान का पर्याय मानने लगता है। हीनता और असुरक्षाबोध में जीने वाला व्यक्ति न दूसरों के ज्ञान की कद्र कर पाता है, न अपनी गरिमा को कायम रख पाता है।

काली सौंफ की चुस्ती तन-मन करे ताजा

घरों में सामान्य सौंफ का इस्तेमाल तो आमतौर पर होता है, लेकिन काली सौंफ भी कुछ कम नहीं। हालांकि दूसरी सौंफ की अपेक्षा यह कुछ तीखी होती है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में खास तौर से किया जाता है। वहीं कई बीमारियों में यह देसी नुस्खे के रूप में काम करती है। गौरतलब है कि काली सौंफ में कैल्शियम की मात्रा काफी होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसमें ऐसे यौगिक हैं, जिनसे सांस की समस्या का उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा इससे मूत्राशय संक्रमण को रोका जा सकता है। काली सौंफ का इस्तेमाल कई तरीके से होता है। इसे कच्चा या घी में भून कर भी खाया सकता है। इसका अर्क भी उपयोग में लाया जाता है। काली सौंफ चबाने से पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है। इसके बीज कई रोगों के उपचार में कारगर हैं। इसे सोवा बीज भी कहा जाता है।

पेट की जलन

आजकल खानपान में लापरवाही से लोगों में बदहजमी होना आम बात हो गई है। वहीं खाली पेट रहने से एसिडिटी भी हो जाती है। इसके लिए कोई दवा खाने के बजाय अगर आप काली सौंफ पर भरोसा करें, तो इससे सुरक्षित कोई उपचार नहीं है। दरअसल, यह पाचन तंत्र के लिए अच्छा माना गया है। इससे पेट की जलन भी दूर होती है। यह सौंफ 'सलाइवा' यानी लार बढ़ा देती है, जिससे सीने में जलन धीरे-धीरे कम हो जाती है। एसिडिटी से आंतों में होने वाली जलन को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। यह विरेचक का भी काम करती है। जिससे कब्ज की समस्या नहीं रहती और पेट हल्का महसूस होता है।

कई मर्ज, एक दवा

शतपुष्प यानी काली सौंफ कई मर्ज की एक दवा है। पेट संबंधी कई रोगों में इसका अचूक नुस्खा है। खाना बनाते समय चुटकी भर इस सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें। इसकी चाय भी बनाई जा सकती है। यह कई रोगों को ठीक करने के लिए कारगर नुस्खा है। इसे बनाना भी आसान है। बस इतना भर करना है। दो कप उबलते पानी में एक छोटी चम्मच काली सौंफ डालें। इसे दस मिनट अच्छी तरह उबालें। इस पानी को छान कर दो बार पी सकते हैं। इससे पेट में जलन, बदहजमी और पाचन संबंधी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं।

अम्लपित्त पर काबू

महानगरों और शहरों के लोगों में आमतौर पर पेट में अम्लपित्त बनने यानी एसिडिटी की शिकायत रहती है। ऐसे में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ नुस्खे आजमाए जा सकते हैं। इस सौंफ को काली किशमिश के साथ रात भर भिगो कर रख दें। सुबह इसे छान कर पी लें। फिर किशमिश और सौंफ चबा लें। सौंफ का यह पानी वजन घटाने में भी मदद करता है। काली सौंफ अपच की समस्या दूर करती है। इससे पेट की गर्मी भी शांत हो जाती है। एक और नुस्खा है। एक चम्मच काली सौंफ भून लें। फिर इसे पानी में उबालें। चाहें तो इसमें जरी सी मिसरी मिला लें। फिर इसे कप में छान लें। आपकी चाय तैयार है। यह चाय शरीर में नमी बनाए रखती है। पाचन के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है।

नुस्खे

जीवन पर जोखिम फेफड़े का कैंसर

सेहत

बड़े शहरों के विकास के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। बेतहाशा आबादी बढ़ने के साथ इन शहरों में जिस तरह वाहनों की संख्या बढ़ी है, उससे सेहत के लिए जोखिम भी बढ़ा है। आज महानगरों से लेकर छोटे शहरों में वाहन रेंगते नजर आते हैं। इससे होने वाला प्रदूषण सेहत के लिए घातक हो गया है। वहीं कारखानों से निकलते धुएं और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल ने इस खतरे को कई स्तरों पर बढ़ा दिया है। नतीजा यह कि लोगों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। निमोनिया और तपेदिक के अलावा अब फेफड़े में कैंसर होना खतरे की घंटी है। दरअसल, यह कैंसर तब होता है जब फेफड़े में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। इसकी कई वजह हैं।

बढ़ता रोग

फेफड़े में कैंसर के मामले दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों और महानगरों में बढ़ रहे हैं। अब न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं में भी यह रोग दिखने लगा है। शहरों में महिलाओं में फेफड़े में कैंसर के मामले बढ़े हैं। चिकित्सकों का कहना है कि शल्यक्रिया के दौरान शहरी लोगों के फेफड़े का रंग काला दिखाई देता है। वहीं गांवों और पहाड़ी इलाकों के लोगों के फेफड़े गुलाबी दिखाई देते हैं। प्रदूषण का असर गले और ग्रास नलिका पर भी पड़ा है।

लक्षणों की पहचान

फेफड़े के कैंसर का शुरुआती दौर में पता नहीं चलता। जब पुख्ता लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय तक रोग गंभीर अवस्था में पहुंच चुका होता है। गले में घरघराहट होने लगे, आवाज बैठ जाए और सांस में लेने में कठिनाई हो, तो इसे संकेत समझा जा सकता है। इसके अलावा, सीने में दर्द होना, खांसी ठीक न होना और खून की उल्टी होना गंभीर लक्षण हैं। जब फेफड़े का कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने लगे, तो कुछ और लक्षण भी दिखते हैं। ऐसे में मरीज की हड्डियों में भी दर्द होता है। वजन कम होने लगता है। भूख कम लगती है। चेहरे और गर्दन में सूजन दिखाई देती है। कभी-कभी सिर में दर्द होता है। इन लक्षणों को पहचान कर चिकित्सक मरीज का तत्काल उपचार शुरू करते हैं।

धूम्रपान के जोखिम

आमतौर पर प्रदूषण फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। वहीं यह फेफड़े की कोशिकाओं को भी क्षति पहुंचाता है और कैंसर की वजह भी बनता है। दूसरी ओर, सिगरेट के धुएं में कैंसर पैदा करने वाले तत्त्व होते हैं। सांस के भीतर धुआं अंदर लेने पर कार्सिनोजेन नाम का तत्त्व फेफड़े के उत्तकों को नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में शरीर इस नुकसान की भरपाई कर लेता है। मगर बार-बार संक्रमण से फेफड़े की स्वस्थ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। आखिरकार वहां कैंसर बनने की स्थिति बन जाती है। कुल जमा ये कि अधिक या कम धूम्रपान करने वाले भी समान रूप से जोखिम में हैं। हालांकि जितना अधिक कोई धूम्रपान करेगा, वह उतनी ही जल्दी फेफड़े के कैंसर की चपेट में आएगा। हालांकि कई उद्योगों में कार्यस्थलों पर कैंसर पैदा करने वाले कणों के संपर्क में आने पर भी यह खतरा रहता है।

निदान के रास्ते

फेफड़े का कैंसर गंभीर बीमारी है। इसका समय पर सही निदान होना चाहिए। मरीज की पहली जांच तो छाती के एक्सरे से शुरू होती है। कभी-कभी सीटी स्कैन की भी मदद ली जाती है। चिकित्सक जरूरत पड़ने पर बायोप्सी अथवा ब्रोंकोस्कोपी भी कराते हैं। फेफड़े में कैंसर का पता चलने पर मरीज के लिए यह कठिन समय होता है। अगर यह शुरुआती चरण में है, तो चिकित्सक दवा या अन्य विकल्प पर विचार करते हैं। जरूरत पड़ने पर शल्यक्रिया की जाती है। इस रोग पर नियंत्रण के लिए मरीज को चीनी, शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि वे सूप, दलिया और उबली सब्जियां लें। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ और बहुत अधिक नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

संबंधों में विश्वास पर स्वार्थ की परतें

जीवन शैली

विश्वास जीवन का आधार है, जो सकारात्मक सोच विकसित करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सफलता, सुरक्षा और सार्थक जीवन के लिए विश्वास जरूरी है, चाहे वह खुद पर हो, या दूसरों पर। इसके बिना रिश्तों की नींव भी अधूरी है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने और मजबूत बने रहने की क्षमता देता है। या यों कहा जाए कि यह हर कार्य में सफलता की कुंजी है। खुद पर भरोसा होने से न केवल हालात से उपजी चुनौतियों से मुकाबला करना आसान हो जाता है, बल्कि सही निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। हालांकि विश्वास अर्जित करना आसान नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यवहार और कार्य में ईमानदारी एवं पारदर्शिता शामिल हो, तो दूसरों के भीतर भरोसा स्वतः पैदा होने लगता है। मगर, आज के दौर में विश्वास में भी 'विष का वास' होने लगा है।

मानसिक मजबूती

विश्वास एक ऐसी शक्ति है, जो व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। आत्मविश्वास तनाव और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है और निराशा के भाव को खत्म कर देता है। विश्वास के साथ किया गया कोई भी प्रयास अक्सर सफल होता है, जबकि इसके बिना छोटे से छोटा कार्य भी असंभव लगने लगता है। यह समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने और उनका समाधान ढूंढ़ने की ताकत देता है। वास्तव में यह किसी भी काम में दृढ़ता और संकल्प लाने का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास को किसी भी रिश्ते की धुरी माना जाता है। यह संबंधों में सहयोग और सामंजस्य को मजबूती देता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है।

व्यवहार की कसौटी

विश्वास में बहुत गहरा अर्थ और महत्त्व समाहित है। यह हमारे व्यवहार और कार्यशैली से उपजा एक ऐसा भाव होता है, जो दूसरों के अंतर्मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। समस्या तब होती है, जब इस आकर्षण पर स्वार्थ की परतें चढ़ने लगती हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे में विश्वास के निर्माण के दौरान सभी पहलुओं पर गौर करना और उन्हें कसौटी पर परखना बेहद आवश्यक है। विश्वास के धागे तभी बुनने चाहिए, जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि इसमें स्वार्थ का कोई रेशा शामिल नहीं है।

> *विश्वास को किसी भी रिश्ते की धुरी माना जाता है। यह संबंधों में सहयोग और सामंजस्य को मजबूती देता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है।*

शुरू से अंत तक

जीवन शुरुआत से अंत तक विश्वास पर ही टिका होता है। बच्चे के जन्म के बाद उसे विश्वास होता है कि भूख लगने या कोई भी समस्या होने से रोने पर मां उसे संभाल लेगी। जब अंगुली पकड़ कर चलना सीखते हैं, तो विश्वास होता है कि माता-पिता उसे गिरने नही देंगे। बड़े होने पर दांपत्य जीवन में यह विश्वास होता है कि जीवनसाथी का साथ है, तो मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद बच्चों पर विश्वास होता है कि बुढ़ापे में वे हमारा सहारा बनेंगें। मगर सवाल है कि आज के दौर में भी क्या यह विश्वास कसौटी पर खरा उतर पा रहा है? अगर जवाब हां है, तो कई रिश्तों के घरौंदे बनने के कुछ समय बाद ही क्यों धराशायी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्गों को घर-परिवार छोड़कर आश्रय स्थलों में शरण क्यों लेनी पड़ रही है? यह ऐसा विषय है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

खुशबू आए तो मन ललचाए

रसोई

आलू चना

यह व्यंजन उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है और अमूमन हर घर में बनता है। इसे बनाने के तरीके भी अलग-अलग हैं। कुछ लोग चना और आलू दोनों को उबालकर बनाते हैं, तो कुछ सिर्फ चना को ही उबालते हैं और आलू को सब्जी की तरह पकाते हैं। इससे स्वाद में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन दोनों का जायका बेहतरीन होता है।

सामग्री

सफेद चनाः 150-200 ग्राम, आलूः 300 ग्राम, टमाटरः दो, अदरकः एक इंच, लहसुनः 5-6 कलियां, साबूत धनियाः एक चम्मच, जीराः एक चम्मच, मिर्च पाउडरः आधा चम्मच, हल्दीः आधा चम्मच, चना मसालाः आधा चम्म्च, कसूरी मेथीः आधा चम्मच, नमकः स्वादानुसार।

विधि

सफेद चना को पानी से धोकर कुकर में उबाल लें। इसके बाद सूखे मसाले, टमाटर, अदरक और लहसुन मिक्सी में पीस ले। इस बीच, आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें साबूत धनिया और जीरा हल्का सा भून लें। फिर इसमें मिर्च पाउडर और हींग डालें, साथ ही कटे हुए आलू भी डाल दें और धीमी आंच पर दो-तीन मिनट तक भूनें। अब इसमें पीसा हुआ मसाला तथा टमाटर-अदरक-लहसुन का पेस्ट और कसूरी मेथी मिला दें। थोड़ा सा पानी और नमक डालकर इसे करीब पांच मिनट तक पकाएं। फिर उबले हुए चने इसमें डाल दें और जरूरत के मुताबिक पानी डालें। अगर उबले हुए चने का पानी बचा हो, तो ज्यादा अच्छा होता है। अब कड़ाही पर ढक्कन रखकर इसे दस-बारह मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। थोड़ा ठंडा होने पर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अब आलू चना बनकर तैयार है। इसे थाली में दो चम्मच मलाई डालकर रोटी या चावल के साथ परोसें।

गोभी टिक्का मसाला

गोभी की सब्जी कई तरह से बनती है, इसे दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है। मगर, गोभी टिक्का मसाला का अपना ही स्वाद है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका जायका लाजवाब होता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे खूब पसंद किया जाता है। होटल-रेस्तरां में तो यह व्यंजन अक्सर बनता है, लेकिन इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है।

सामग्री

फूलगोभीः 500 ग्राम, प्याजः दो, टमाटरः दो, मिर्च पाउडरः एक चम्मच, धनिया पाउडरः एक चम्मच, हल्दीः आधा चम्मच, बेसनः 50 ग्राम, दहीः एक कप, अजवाइनः आधा चम्मच, नमकः स्वादानुसार।

विधि

फूलगोभी को काटकर कुछ देर के लिए गरम पानी में रखें और थोड़ा सा नमक भी डाल दें। फिर एक कड़ाही में थोड़ा सा बेसन भूनकर उसे एक कटोरे में निकाल लें और इसमें अजवाइन मिला दें। इस बीच अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लें और साबूत गरम मसले मिक्सी में पीस लें। फिर गोभी को गरम पानी से निकालकर बेसन वाले कटोरे में डाल दें और इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, दही और पीसे हुए मसाले मिला दें। अब इसमें हल्का सा नींबू का रस तथा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें जीरा और कटा हुआ प्याज भून लें। जब प्याज का रंग हल्का सुनहरा हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर डालें और थोड़ा सा पानी डालकर करीब दो मिनट तक पकाएं। फिर इसमें मलाई और काजू खसखस का पेस्ट मिला दें। इस बीच गोभी के मिश्रण को तवे पर भूनकर इसे टमाटर की तरी में डाल दें और नमक भी मिला दें। अब इसे ढक्कन रखकर पांच-सात मिनट तक पकाएं। इसे गरमागरम चपाती या नान के साथ परोसा जा सकता है।

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, रविवार, 4 जनवरी 2026

जो व्यक्ति एक घंटा भी समय बर्बाद करने का साहस करता है, उसने जीवन का मूल्य नहीं समझा है। -चार्ल्स डार्विन

इंदौर में दूषित पानी से मौतें, देश के महानगरों के लिए चेतावनी

नए वर्ष की शुरुआत के साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रदूषित जल ने जो मौत का पैगाम बांटा है, उसमें अब तक 19 लोग काल का ग्रास बन गए हैं। लगभग 300 व्यक्ति अस्पतालों में उपचाराधीन है। इसे केवल डायरिया का प्रकोप कहकर नहीं नकारा जा सकता, जैसा मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है। यह दूषित पेयजल से पैदा हुई त्रासदी है जो स्वच्छता की अवहेलना और सीवरेज सिस्टम के प्रति लापरवाही बरतने के कारण हुई है। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि उसने मामले की गंभीरता को पहचानते हुए लोक सेहत आपातकाल के कदम उठाए हैं और अब पूरी स्थिति नियंत्रण में है।

लेकिन यह कैसा नियंत्रण है जो दूषित जल पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों को गहरा सदमा दे गया है। 294 लोगों का अब भी अस्पताल में उपचाराधीन होना और 32 लोगों का आईसीयू में होना बताता है कि त्रासदी बड़ी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को कुप्रशासन का केन्द्र बताया है। इंदौर के अलावा बाकी देश की ओर भी ध्यान कीजिए।

क्या स्वच्छता को एक नई आदत और सीवरेज की सफाई को प्राथमिकता के तौर पर अपनाया गया है? जवाब है, नहीं। किसी भी राज्य को देख लीजिए, स्वच्छता अभियान पर राजनीति होने लगती है। सीवरेज की उचित सफाई न होना कितना कुप्रभाव दिखाता है, यह पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में इस वर्ष असाधारण बारिशों के दौरान देखा गया है। महानगरों में थोड़ी सी बारिश कैसे जलथल कर देती है और पानी बार-बार घरों में प्रवेश करके लोगों की आम जिंदगी और उनके साजो-सामान की हानि कर देता है।

मूल कारण यही है कि जिनका कर्त्तव्य शहरों को सहज रखना है, सीवरेज को चलते रहने देना है और कूड़े के डम्पों का निस्तारण करना है, वे अपना काम नहीं कर रहे। इसीलिए, जब पानी प्रदूषित पदार्थों से मिश्रित होता है तो यह जहर बनकर लोगों को घरों तक पहुंचता है। मध्य प्रदेश में कार्रवाई के नाम पर दो अफसरों को हटा दिया गया है। जब इंदौर जैसा स्वच्छ शहर भी प्रदूषण से बच नहीं सका तो देश के अन्य शहरों का क्या होगा जो कूड़े की वजह से साल-दर-साल अपनी रैंकिंग खोते जा रहे हैं। प्रदूषण की यह समस्या देश के अधिकांश महानगरों की है। रिपोर्ट मिली है कि लोग तो मांउट एवरेस्ट पर भी कूड़ा छोड़ने से बाज नहीं आते। सरकारी जुर्मानों के बावजूद मांउट एवरेस्ट के ऊपर कूड़े का एक और पहाड़ बनता जा रहा है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो लोगों में जहर बांट रही है और बीमारी भी। अब वक्त आ गया है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझे। यह सोच देश के अन्य राज्यों और महानगरों के लिए भी है। कूड़े से लेकर प्रदूषण के विस्तार तक इन शहरों में हवा घुटनभरी हो गई है और पानी जहर की खुराक बांट रहा है।

हर राज्य को संत बलबीर सिंह सीचेवाल जैसे लोग चाहिए, जिन्होंने काली बेईं को सफेद बेईं बना दिया और अब बुड्ढे नाले के कायाकल्प के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी जनसेवा का स्वागत है लेकिन यह मत भूलें कि दायित्व तो सरकार का बनता है। सभी राज्य सरकारों को इंदौर की इस त्रासदी से सीख लेनी चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से बचने की एक ऐसी कारगर योजना बनानी चाहिए कि जिसका असर लोगों की सेहत पर सकारात्मक पड़े। उन्हें अयाचित मौत न मिले बल्कि वे जब तक जिएं, एक सेहतमंद जिंदगी जिएं। इंदौर की दूषित पेयजल त्रासदी का संज्ञान न्यायपालिका ने भी लिया। वकील संघ के अध्यक्ष रितेश ईनाणी की ओर से जनहित याचिका डाली गई। न्यायालय ने 19 मौतों और 294 संक्रमण रोगियों के बारे में जानकारी ली है और सरकार को अपना दायित्व निभाने के लिए कहा है। मौत के बाद परिजनों को मिला मुआवजा जिंदा रहने का बदल नहीं होता। **-शीतल विज**

भारत में गिरती जन्म दर का संकट

सरकार की ओर से घोषणा है कि इस वर्ष देश में जनगणना शुरू कर दी जाएगी। अगले वर्ष जनगणना समाप्त होने के बाद आंकड़े जारी होंगे। फिर सरकार अपने जनकल्याण कार्यों की रूपरेखा तैयार करेगी। लेकिन एक अन्य संकट जो पहले चीन के समक्ष खड़ा था अब वही भारत के सामने खड़ा हो गया है। संकट यह है कि परिवार नियोजन की चाह में देश में बच्चों की जन्म दर कम हो गई है। आंकड़ा था कि भारत आबादी के लिहाज से चीन को भी पछाड़ गया है।

लेकिन आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए जितनी प्रजनन दर चाहिए, उससे हम महरूम हो गए हैं। चीन में तो जन्म दर इतनी गिरी है कि उन्हें अपनी परिवार नियोजन की सक्रिय नीति और 'हम एक हमारा एक' का नारा छोड़ना पड़ रहा है। चाहे औपचारिक रूप से चीन ने एक परिवार एक बच्चा की नीति को त्याग दिया था लेकिन फिर भी अधिकांश लोग परिवार बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। चीन चाहे आर्थिक रूप से जितना भी सामर्थ्यवान देश हो लेकिन उसकी जनसंख्या समय से पहले बूढ़ी हो रही है। 2024 में चीन में 95.4 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह एक दशक पहले की तुलना में आधी है।

तीन साल से चीन में आबादी लगातार कम हो रही है। इस वर्ष पहली जनवरी से चीन ने गर्भनिरोध उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला कर दिया है। गर्भनिरोधक दवाइयां महंगी होंगी क्योंकि इन पर 13 फीसदी टैक्स लग गया है। उधर नए बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखरेख पर टैक्स छूट मिल गई है। यही हाल भारत का भी होता जा रहा है। शिक्षा के दबाव, नौकरी की अनिश्चितता, महंगे इलाज और आर्थिक असुरक्षा के कारण भारतीय परिवार एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने से गुरेज कर रहे हैं और देश में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ गया है।

नई पीढ़ी अब शादी की बजाय बिना विवाह साथ रहने को अधिमान दे रही है क्योंकि कानून इसे अमानवीय या गैर-कानूनी नहीं मानता। अब बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और अपने अंधेरे भविष्य की चिंता युवाओं को शादी से विमुक्त कर रही है। परिवार नियोजन पहले चीन और भारत में एक महत्वपूर्ण अभियान माना जाता था। आज यही परिवार नियोजन भारत की युवा पीढ़ी का सफाया करने लगा है। इसलिए जरूरी है कि परिवार नियोजन की नई नीति सामने आए। इसमें लोगों को एक नहीं, तीन बच्चे पैदा करने का आश्वासन मिले। **-शीतल विज**

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

नये साल को 'नये आप' की जरूरत नहीं!

(खुद को नये सिरे से गढ़ना क्यों हमेशा स्वागतयोग्य नहीं है)

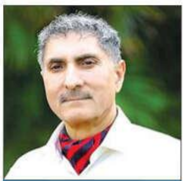

परनीत सचदेव

अंतर्यात्रा

हर नया साल एक जानी-पहचानी नैतिक सीख लेकर आता है। और अच्छे बनो, और पतले बनो, और शांत बनो, अधिक उत्पादक बनो, अधिक कामयाब बनो। मानो कैलेंडर यह जोर देता है कि उसके पन्ने पलटने वाला पूरा का पूरा बदल जाए। यह विश्वास सख्त होकर एक रस्म बन चुका है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है:

जिस इंसान ने पिछले साल को सहा,
वह आने वाले साल के लिए अपर्याप्त है।

आमूलचूल बदलाव वाले आत्म-पुनर्संयोजन की कीमत

यह धारणा विश्लेषण के लायक है, इसलिए नहीं कि विकास अवांछनीय है, बल्कि इसलिए कि आधुनिक संस्कृति जिस तरह से बदलाव को पेश करती है, वह मनोवैज्ञानिक रूप से महंगा और आध्यात्मिक रूप से असंगत है। *जब खुद को नए सिरे से गढ़ने को किसी के मूल्य की पूर्व शर्त माना जाता है, तो यह अक्सर वही ठहराव पैदा करता है जिसे यह दूर करना चाहता है।*

व्यवहार विज्ञान लंबे समय से आमूलचूल बदलाव वाले आत्म-पुनर्संयोजन की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाता रहा है। *आदत निर्माण पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अचानक, उच्च-तीव्रता वाले व्यवहारगत परिवर्तन में त्याग की दर बहुत अधिक होती है, विशेषकर तब जब यह संज्ञानात्मक और भावनात्मक दबाव की परिस्थितियों में किया जाता है।* अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा संकलित शोध यह दर्शाता है कि संकल्प-आधारित परिवर्तन असफल होता है, प्रेरणा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह पहचान की निरंतरता और तंत्रिका थकान को नजरअंदाज करता है (एपीए मॉनिटर ऑन साइकोलॉजी, 2020)।

मस्तिष्क उस परिवर्तन का विरोध करता है जो व्यक्ति के अस्वीकार जैसा महसूस होता है, न कि उसके विस्तार जैसा।

आधुनिक मनोविज्ञान यह समझने के लिए एक सटीक ढांचा प्रस्तुत करता है कि 'न्यू यू' (नया आप) की कथा क्यों विफल हो जाती है। ई. टोरी हिगिंस द्वारा विकसित स्व-भिन्नता सिद्धांत यह दर्शाता है कि जब 'वास्तविक आत्म' और 'आदर्श आत्म' के बीच का अंतर बहुत अधिक हो जाता है, तो व्यक्ति प्रेरणा के बजाय बढ़ी हुई चिंता, शर्म और अलगाव का अनुभव करता है।

एक आदर्शीकृत भविष्य की पहचान के पीछे भागना विकासात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खतरे की प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है (साइकोलॉजिकल रिव्यू, 1987)।

तंत्रिका विज्ञान इस अंतर्दृष्टि को और गहरा करता है। फंक्शनल एमआरआई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लगातार आत्म-आलोचना मस्तिष्क की डिफॉल्ट खतरा परिपथ प्रणाली को सक्रिय करती है, विशेष रूप से अमिग्डाला को, जबकि आत्म-दया और स्वीकृति उन तंत्रिका नैटवर्कों को सक्रिय करती हैं जो सीखने और व्यवहारगत लचीलेपन से जुड़े होते हैं। *स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक ऐतिहासिक अध्ययन ने यह दिखाया है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत परिवर्तन को स्वीकृति के दृष्टिकोण से अपनाते हैं, वे आत्म-निर्णय से प्रेरित लोगों की तुलना में दीर्घकालिक व्यवहारगत दृढ़ता अधिक दिखाते हैं (स्टैनफोर्ड सैंटर फॉर कम्पैशन एंड अल्ट्रइज्म रिसर्च, 2016)।*

नववर्ष के बहुत-से संकल्पों में जो अनुशासन के रूप में दिखाई देता है, वह तंत्रिका स्तर पर दीर्घकालिक आत्म-खतरे का एक रूप है।

प्राचीन ज्ञान और आत्म की निरंतरता

आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा इन तंत्रों को स्पष्ट करने से बहुत पहले, शास्त्रीय ज्ञान परंपराओं ने समान निष्कर्षों तक पहुंच बना ली थी। ***भगवद्गीता व्यक्तिगत पुनर्निर्माण का समर्थन नहीं करती है; यह अभ्यास पर बल देती है—स्थिर, दोहराया जाने वाला अभ्यास जो आत्म-ज्ञान में निहित है, आत्म-अस्वीकार में नहीं।***

अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि कर्म स्पष्टता से उत्पन्न होना चाहिए, न कि अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति तिरस्कार से (भगवद्गीता)।

बौद्ध मनोविज्ञान भी इसी मार्ग का अनुसरण करता है। बुद्ध ने अचानक आत्म-परिवर्तन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया और इसके बजाय यह सिखाया कि मुक्ति विचार, संवेदना और प्रवृत्ति के समयबद्ध सजग अवलोकन से उत्पन्न होती है।

परिवर्तन कोई और बनने से नहीं होता, बल्कि यह अधिक स्पष्ट रूप से देखने से होता है कि व्यक्ति पहले से ही क्या है (गौतम बुद्ध)।

यह दृष्टि अपूर्णता स्वीकार करती है, बिना उसे हीनता के बराबर ठहराए। ये परंपराएं एक ही अंतर्दृष्टि पर आकर मिलती हैं: विकास के लिए आत्म-प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं है। इसके लिए आत्म-समझ आवश्यक है।

उत्पादकता, थकान और अंतहीन उन्नयन का मिथक

खुद को नए सिरे से गढ़ने की आधुनिक मांग हर चीज के 'इष्टतमीकरण' यानी चीजों को अधिकतम

उपयोगी, कुशल बनाने के प्रति बृहत्तर सांस्कृतिक आसक्ति से अलग नहीं है। व्यक्ति को एक ऐसी परियोजना की तरह देखा जाता है जो निरंतर नवीनीकरण के अधीन है, जिससे उत्पादकता, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक प्रदर्शन में लगातार उच्चतर परिणामों की अपेक्षा की जाती है। फिर भी संज्ञानात्मक विज्ञान यह सुझाव देता है कि यह मॉडल मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है।

निर्णय संबंधी थकान पर किए गए शोध से पता चलता है कि आत्म-नियंत्रण क्षमता सीमित होती है। रॉय बॉमिस्टर के अहं-क्षय (ईगो डिप्लीशन) पर व्यापक शोध ने यह प्रदर्शित किया कि पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी के बिना आत्म-नियंत्रण में निरंतर प्रयास खराब निर्णय, कम दृढ़ता और भावनात्मक अस्थिरता की ओर ले जाता है (जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, 1998)। यद्यपि बाद के अध्ययनों ने सिद्धांत के कुछ पहलुओं को परिष्कृत किया, मुख्य निष्कर्ष अब भी दृढ़ है: मनुष्य बिना पुनःपूर्ति के स्वयं पर अनिश्चितकाल तक सुधार नहीं थोप सकते।

इसका नववर्ष संकल्पों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनवरी में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, जो पहले से ही अनसुलझे तनाव, आर्थिक अनिश्चितता या पिछले वर्ष के भावनात्मक अवशेष से बोझिल है, तंत्रिका स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन के लिए सक्षम नहीं होता है।

रीइन्वेंट के बजाय इनहैबिटेशन

जब नए साल को इनहैबिटेशन के निमंत्रण के रूप में देखा जाता है, तो एक अधिक टिकाऊ विकल्प सामने आता है। इनहैबिटेशन यानी खुद में निवास करने का मतलब है अपने मौजूदा जीवन, भूमिकाओं और सीमाओं के भीतर मौजूद रहना और साथ ही धीरे-धीरे उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाना। यह बाहरी बदलाव के बजाय एक आंतरिक पुनर्सरचना है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह दृष्टिकोण ***न्यूरोप्लास्टिसिटी*** के बारे में जो कुछ भी पता है, उसके साथ बहुत करीब से मेल खाता है।

ध्यान और व्यवहार में छोटे, लगातार बदलाव नाटकीय हस्तक्षेपों की तुलना में तंत्रिका मार्गों को अधिक मजबूती से नया आकार देते हैं।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अध्ययनों से पता चलता है कि आदत बनने के लिए आमतौर पर हफ्तों या महीनों तक लगातार दोहराव की आवश्यकता होती है, न कि अचानक उत्साह की (यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, 2009)। पहचान की निरंतरता पर आधारित क्रमिक परिवर्तन, न्यूरोलॉजिक रूप से किफायती होता है।

आध्यात्मिक रूप से, इनहैबिटेशन लगातार आत्म-सुधार की नैतिक हिंसा का विरोध करता है और उसकी जगह ध्यानपूर्ण जीवन को लाता है।

यह व्यवहार में कैसा दिखता है

जब इसे वास्तविक जीवन के अनुभव में बदला जाता है, तो यह दर्शन ऐसे बदलाव लाता है जो सूक्ष्म और स्थायी होते हैं। लोग यह गौर करने लगते हैं कि कितनी ही आदतें कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे कभी सुरक्षात्मक कार्य करती थीं। कंटेम्प्लेटिव न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि गैर-प्रतिक्रियाशील जागरूकता की छोटी-छोटी दैनिक अवधियां भी बेसलाइन कोर्टिसोल के स्तर को कम करती हैं और समय के साथ भावनात्मक विनियमन में सुधार करती हैं (हार्वर्ड मैडिकल स्कूल, 2018)। वे शांत, सौम्य पुनर्संयोजन हैं।

लक्ष्य प्राप्ति पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से इरादों की घोषणा करने से समय से पहले मनोवैज्ञानिक इनाम मिलने के कारण फॉलो-थ्रू कम हो सकता है (साइकोलॉजिकल साइंस, 2009)। *इसके विपरीत, मौन प्रतिबद्धताएं प्रेरक ऊर्जा को बनाए रखती हैं।*

आत्म-त्याग के बिना एक नया साल

आधुनिक आत्म-सुधार संस्कृति में सबसे आम विचारों में से एक यह धारणा है कि गलतियां विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत विफलताएं हैं। गुरबानी एक बिल्कुल अलग रुख अपनाती है। यह मानती है कि मानवीय त्रुटि स्वयं दैवीय विधान (हुक्म) के भीतर प्रकट होती है।

जो किछु करै सो आपे करै,
आपे करता आपे करै।
(जो कुछ भी होता है, वह स्वयं ही करता है; सृष्टिकर्ता स्वयं ही करने वाला है।)

यह छंद पूर्ण आत्म-रचना के भ्रम को भंग करता है। मानवीय क्रिया को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसे संदर्भ दिया जाता है। व्यक्ति न तो अपराधबोध से कुचला जाता है, न ही जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है, बल्कि उसे एक ऐसे ढांचे में रखा जाता है जहां सीखना आत्म-निंदा की जगह ले लेता है।

कृपा के एक रूप के रूप में आत्म-क्षमा

गुरबानी बार-बार इस बात पर जोर देती है कि मुक्ति लगातार आत्म-दंड से नहीं, बल्कि *कृपा (नदर)* से मिलती है जो अंतर्दृष्टि जगाती है।

गुनहा बख्शणहार सबाइआ,
आपे बख्से आप छडाइआ।
(वही सभी पापों को क्षमा करने वाला है; वह स्वयं क्षमा करता है और हमें मुक्त करता है।)

यहां, क्षमा को नैतिक नरमी के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए एक दिव्य तंत्र के रूप में दर्शाया गया है। गलती को ईमानदारी से पहचानने के बाद खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है। यह कृपा में भागीदारी है।

सिख दर्शन अतिवाद से बहुत सावधान रहता है। जड़ता (आलस) जागरूकता को कम कर देती है, लेकिन खुद के प्रति क्रूरता सीखने को तोड़ देती है।

विकास इसलिए संभव है क्योंकि इंसान अच्छाई या बुराई में जमे हुए नहीं हैं। यह अंतर्दृष्टि आधुनिक व्यवहार विज्ञान से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है, जो दिखाता है कि पहचान-आधारित निंदा ('मैं एक असफल व्यक्ति हूं') व्यवहार-आधारित सुधार ('यह काम असफल रहा') की तुलना में बदलाव को कहीं ज्यादा रोकती है।

यह सिख समझ **स्टोइक दर्शन** में एक अप्रत्याशित प्रतिध्वनि पाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है कि हर दिन की शुरुआत इंसानी असफलता की उम्मीद के साथ करनी चाहिए–अपनी और दूसरों की दोनों–और इससे परेशान न होने का संकल्प लेना चाहिए।

दोनों परंपराओं में, नैतिक कार्य एक ही है: न तो भोग और न ही कठोरता, बल्कि स्थिरता। व्यक्ति असफल होता है, सोचता है, माफ करता है, समायोजन करता है और आगे बढ़ता है।

कुल मिलाकर, गुरबाणी, स्टोइकवाद और आधुनिक मनोविज्ञान का मिलन इस एक अंतर्दृष्टि पर होता है: जड़ता और आत्मसंतुष्टि विकास को रोकते हैं। अत्यधिक आत्म-आलोचना इसे नष्ट कर देती है। इन चरम सीमाओं के बीच एक अनुशासित कोमलता है–आत्म-घृणा के बिना सीखने की इच्छा, आत्म-अस्वीकृति के बिना बदलने की इच्छा।

अब जब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो शायद सबसे अनुशासित काम खुद को फिर से बनाना नहीं, बल्कि लगातार सुधार करते हुए मौजूद रहना है। नए साल को एक 'नए आप' की जरूरत नहीं है। बल्कि आपके एक लगातार बेहतर संस्करण की जरूरत है। जो दयालु हो!

सामाजिक और नैतिक यथार्थवाद पर आधारित कन्फ्यूशियस ज्ञान ने इस नैतिकता को इस प्रकार व्यक्त किया है:

'बिना नुक्स के कंकड़ से नुक्सदार हीरा बेहतर है।'

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।)

परनीत सचदेव (आई.आर.एस.) रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एवं प्रख्यात लेखक हैं।
parneetsachdev@gmail.com

जीवन अधूरा रह जाने का दर्द

सुरेश सेठ

दुनिया बदल गई है! आजकल दावों, घोषणाओं और सफलता के मिथ्या आंकड़ों का उत्सव मनाया जाता है, और अपूर्ण रह जाने पर सवाल उठाने को अनुशासनहीनता। सड़कों से लेकर शहरों तक के नाम बदलने का आज हमने इतिहास बना दिया, और इसे देश से विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक गरिमा की पुनर्स्थापना बता दिया, लेकिन साथ ही इस सच को स्वीकार भी लिया, कि यहां 'कथनी और करनी' में अंतर होता है। कर्त्तव्य पथ पर कर्त्तव्यच्युत लोग चलते हुए नज़र आते हैं, और लोक पथ पर लोगों को लोक जीवन की बेहतरी के ठेके आजकल धनी प्रासादों को दिए जाने लगे हैं।

'सब चलता है' की धारणा को आदत नहीं बनाएंगे, तो भला अपने महान हो जाने की शार्टकट को अपनी संस्कृति कैसे बनाये रखेंगे? देश में तरक्की बहुत हो गई है। सबसे पहले तो हमने अपनी महाशक्ति मनाने का उत्सव विश्व के बाहुबलियों के गले लग कर मना लिया है। देश प्रसन्न है क्योंकि बाहुबलियों ने हमें गले से लगाने के काबिल समझ लिया, और उन्होंने हमें अपना प्रिय मित्र होने का दर्जा दे दिया। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, और लक्ष्य पूरा हो जाने का भ्रम आसमान बन गया है। ऐसा नहीं कि देश में समस्याएं नहीं हैं, लेकिन उन समस्याओं की पहचान जीवन जीने के स्तर पर नहीं, बल्कि मीडिया के शीर्षकों में होती है।

नश्तर की मुस्कान

शीर्षक बताते हैं कि आबादी के लिहाज़ से हमारा देश चीन को पछाड़ कर नम्बर एक हो गया, लेकिन इस पर गर्व कैसे करें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के आधे लोग युवा होने के बावजूद अपने आपको असमय बूढ़ा महसूस करते हैं। उन्हें विसंगतियों में जीने की आदत हो गई है, और वे कार्य योग्य हो जाने के बावजूद नौकरियां पाने की खिड़कियों के बाहर नहीं, उपकार बांटने की दुकानों के बाहर खड़े नज़र आते हैं। यहां कर्म की नहीं, दान की भावना की संस्कृति युग सत्य बन गई है, और सस्ता अनाज बांटने की खिड़कियों के जीवन के चिरजीवी हो जाना तरक्की का पैमाना बन चुका है।

शार्टकट संस्कृति के साथ-साथ सम्पर्क संस्कृति का भी बोलबाला हो गया है। हर व्यक्ति अपने आपको प्रशासन, समाज या राजनीति में किसी न किसी सफलता से मंडित व्यक्ति के समीप होने का उनका भाई-भतीजा होने की घोषणा करने की फिराक में लगा है। यहां तरक्की का अर्थ यह है कि आदमी अपने मूल्यों में परिवर्तन कर किसी न किसी सफल आदमी का खूंटा हो जाने का जश्न मना ले। यह अलग बात है कि खूंटे तो वहीं दीवारों पर गढ़े रह गए, और उन खूंटों का सहारा लेकर चतुर सुजान उपलब्धि की छत पर पहुंच विजय का बकरा बुला रहे हैं। आज जनता का सबसे बड़ा प्रतिशत बदलाव की घोषणाओं के बीच 'अपने जहां थे वहां रहो' जिसे यथास्थितिवाद कहते हैं, पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। बल्कि प्रश्न न उठाने को अपनी सांस्कृतिक पहचान, या उसके वारिस धीरज और सहनशीलता को अपनी प्रवृत्ति बना गर्वित रहे हैं।

आज अतीत में लौटना हमारी सांस्कृतिक पहचान बन गई है। इस अतीत में कर्म है, समर्पण है। समर्पण हमने अपने समाज, राजनीति, प्रशासन और साहित्य के नये खुदाओं के प्रति अपना लिया, और कर्म को भ्रम में तबदील कर दिया। हम काम नहीं कर रहे, बल्कि उसके पूरे हो जाने का भ्रम पाल रहे हैं। इसलिए काम की परिभाषाएं बदल गई हैं। यहां नया काम बन गया है, सफल आदमियों का चंवर झुलाना, और उनके बड़प्पन का जयघोष हो जाना। इसीलिए तो यहां घोषणाओं के हो जाने के बाद उनके साकार हो जाने का नामोनिशान कहीं मिलता है तो धनियों के हर युग में बहुमंज़िला होते जाने के प्रासादों में मिलता है। देश की युवा पीढ़ी उपकृत हो जाने की कतारों में खड़ी असमय बुढ़ा रही है, और हर चुनाव घोषणा में अपने लिए काम की परियोजनाएं तलाश करने के स्थान पर मुफ्तखोरी की नई रेवड़ियां बांटने का इंतज़ार करती है। मेहनत मजदूरी करके पेट पालना बीते युग का फैशन हो गया क्योंकि पेट पालना है तो तरक्की का मतलब महलों के साये में मुफ्त राशन या मुफ्त सुविधाओं के बंटने की प्रतियोगिता में नई घोषणाओं की दौड़ बन गया है।

बेशक हम आर्थिक विकास के शीर्ष पर इस दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन यह विकास दर बड़े आदमियों के सामने बेमोल नज़र आता है, और मुरम्मत की गई सड़कें फिर से टूट-टूट कर उनका जश्न मनाती हैं। अध-बने पुल अपने अधूरेपन में सफलता का प्रसाद बांटते हैं और देश की एक्सप्रैस सड़कें बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के आंकड़ों का प्रसाद। हर प्रसाद बंटने पर हम कृत-कृत्य हो जाते हैं, और उससे पैदा अधूरेपन को एक चिरंतन सत्य मानकर उसे आध्यात्मिकता से मुक्ति के वैकल्पिक राह पर डाल देते हैं। इसी बहाने एक दिन दुनिया का गुरुदेव हो जाने का सपना पालते हैं। आमीन।

(शिरोमणि साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सेठ का प्रखर राजनीतिक व्यंग्य)

बढ़ती नस्लीय हिंसा, देश के विकास में बाधा

जब चौतरफा विरोध हो रहा होने लगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दबाव डाला, साथ ही उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे मेघालय के कोनार्ड संगमा व दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने उत्तराखंड के डीजीपी, देहरादून के डीएम व एसपी को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्रिपुरा के 24-वर्षीय छात्र अंजेल चकमा की नस्लीय हिंसा में की गई निर्मम हत्या को 'उनकी सरकार बहुत गंभीरता से लेगी और इस किस्म के अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा'।

पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से दो नाबालिग हैं। गौरतलब है कि देहरादून में एमबीए कर रहे अंजेल 9 दिसम्बर 2025 को अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे कि छह व्यक्तियों ने उन पर अभद्र व नस्लीय टिप्पणी की। अंजेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि 'हम चीनी नहीं... भारतीय हैं', लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और दोनों भाइयों पर चाकुओं व अन्य धारधार हथियारों से हमला बोल दिया। इस वारदात के 14 दिन बाद अंजेल की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई अभी गंभीर अवस्था में है, उसका उपचार चल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में, इस साल केवल दिसम्बर में नस्लीय भेदभाव के कारण हुई यह लिंचिंग की तीसरी घटना है।

इसके अतिरिक्त क्रिसमस व उसकी पूर्व संध्या पर अलग-अलग शहरों से चर्चों में तोड़फोड़ व ईसाई समुदाय पर हिंसक हमले हुए, जिससे भारत की दुनियाभर में कड़ी आलोचना हुई। ये सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। जाहिर है, इन सब निंदनीय हरकतों और राज्य सरकारों द्वारा इन पर सख्ती से नियंत्रण न कर पाना, न सिर्फ देश की छवि खराब कर रही हैं बल्कि भारत की प्रगति व विकास में बहुत बड़ी बाधा हैं। इनकी वजह से बड़े बड़े प्रोजैक्ट्स अधर में लटक जाते हैं, निवेश रुक जाता है। विश्व गुरु जीडीपी बढ़ाने से नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने से बना जाता है ताकि हर कोई व्यापार, शिक्षा आदि के लिए सुरक्षित महसूस करे।

संक्षेप में बात केवल यह है कि नस्लीय भेदभाव व हिंसा एक ऐसी समस्या है, जिसे अगर अनदेखा किया जाएगा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्ष 2025 का अंत बहुत ही शर्मनाक व डरावने मोड़ पर हो रहा है-अन्य दिन, अन्य राज्य, अन्य भयावह लिंचिंग दिसम्बर की तीसरी। ऐसा प्रतीत हो रहा है हम 'वह अलग है' का सामान्यीकरण कर रहे है, जोकि अत्यधिक चिंताजनक व भयावह है। क्या युवा व कामकाजी लोग अपने ही देश में बिना डर व सुरक्षा के साथ इधर से उधर नहीं घूम सकते? देहरादून में एक एमबीए के छात्र की नस्लीय हिंसा में मौत के बाद दो प्रवासी श्रमिकों की लिंचिंग हुई। 19-20 वर्षीय बंगाली की ओडिशा में और 31-वर्षीय छत्तीसगढ़ी की केरल में। इन दोनों को ही 'बंग्लादेशी' कहकर पुकारा गया, जो एक ऐसा आरोप है, जिससे देश में हर जगह प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अफ्रीका व उत्तर-पूर्व भारत के छात्र व श्रमिक दशकों से दिल्ली व उत्तरी राज्यों में नस्लवाद का सामना करते आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की एक नेता ने एक अफ्रीकी को धमकाया कि उसने हिंदी क्यों नहीं सीखी, जिसका वीडियो वायरल है। लेकिन अफसोस, किसी सरकार ने नस्लवाद या नफरती अपराध का संज्ञान नहीं लिया। पुलिस आमतौर से नफरत भरे खतरनाक बयानों और ऐसी भयावह हिंसा को 'छिटपुट घटनाएं' कहकर टाल देती है, जोकि वह नहीं हैं। इस नस्लवाद और 'वह अलग है' का एक पैटर्न है, लेकिन उसे संबोधित नहीं किया जाता है, जिससे इस क्रूर अभिव्यक्ति में निरंतरता आती जा रही है।

विदेशों में भारतीय छात्र स्वयं नस्लवाद का शिकार हो रहे हैं, विशेषकर ट्रम्प के अमेरिका में। अभी हाल में कनाडा में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। रईस व उच्चवर्ग के भारतीयों को धक्का लगता है, जब पश्चिमी देशों में उन्हें 'कलर' की श्रेणी में रखा जाता है, यानी उस तथाकथित 'नीच श्रेणी' में जिसमें वह स्वयं दूसरे समुदायों को समझते हैं।

दूसरे देशों में पीड़ित होने के बावजूद हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव को अनदेखा करते हैं। नीति पॉलिसी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक भारत के केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में 1 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र होंगे। यह उस समय तक संभव नहीं हो सकता जब तक विदेशी छात्रों की सुरक्षा-नस्ल व त्वचा के रंग के आधार पर-100 प्रतिशत सुनिश्चित नहीं की जाती है। भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों को लम्बे समय से यह शिकायत रही है कि शेष भारत में उन्हें 'अलग' समझा जाता है व उनके साथ भेदभाव होता है। इस शिकायत को संबोधित करने की बजाय उसे जाने-अनजाने में विकराल रूप धारण करने दिया गया है, जिसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। नस्लीय भेदभाव व हिंसा से न सिर्फ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो रही है, विदेशों में भारतीयों पर खतरा बढ़ता जा रहा है बल्कि हमारी अपनी सरकारों की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का आरोप है कि इस साल ईसाइयों के विरुद्ध भारत में 600 से अधिक वारदातें हुई हैं, जिस पर अमेरिका, इंग्लैंड आदि के अखबारों में अग्र लेख लिखे गए हैं। दरअसल, स्वयंभू धर्म के ठेकेदारों को छूट देना खतरे से खाली नहीं है। अब राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील पश्चिम बंगाल, असम व केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो 'घुसपैठिया' का घिसा-पिटा आरोप असहिष्णुता में वृद्धि कर रहा है। 'वह अलग है' एक किस्म का व्यवस्थित जहर है। इसको फैलने से हर हाल में, हर कीमत पर रोकना होगा वर्ना सरकारों का बस यही काम रह जाएगा कि लोगों को लोगों से सुरक्षित रखती रहें।

एकात्म शासन पद्धति

शुद्ध प्रखरतर राष्ट्रभक्ति की लहर उठे सबकी नस नस में।
बलिदानी प्राणों की आंधी उठे आज जन-जन मानस में।।

॥ नित्यप्रेरणा ॥

गुरु जी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का श्रीगणेश हिन्दू जन के संगठित तथा एकीभूत जीवन-रचना के एकमात्र उद्देश्य से हुआ है। निस्संदेह यह एक कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें पहले इसके मार्ग में आनेवाले अवरोधों व समस्याओं की विवेचना करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो हमारी आंखों को खटकती हैं, वह यह है कि हममें से बहुत से हिन्दू भाई, जिनमें शिक्षित और सदाशयी हिन्दू भाई भी शामिल है, स्वयं को 'हिन्दू' कहने में संकोच करते हैं।

कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा कि वे समाजवाद और संप्रदायनिरपेक्षता के सूत्रपात के लिए विश्वधर्म की बात करते थे। परंतु वास्तविकता यह है कि विवेकानंद साहित्य में ऐसे असंख्य अनुच्छेद आते हैं जिनमें वह हमें हिन्दू को रूप में गर्व से सिर ऊंचा करने का उद्बोधन देते हैं। उन्होंने हमारा आह्वान किया है कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर उद्घोष करो 'मैं हिन्दू हूं।' महर्षि अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म के लिए हिन्दू-राष्ट्र का सार है। अतः स्वयं को 'हिन्दू' कहने में लज्जा का अनुभव इन महान द्रष्टाओं व विचारकों की शिक्षा के सर्वथा प्रतिकूल है। द्वितीय विषय है हिन्दू-समाज का विभिन्न भागों व खंडों में विघटन।

जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषागत आधार पर अनगिनत विभाजन हमारे सम्मुख पूर्ण विभाजन हमारे सम्मुख पूर्ण विभाजन का निराशाजनक चित्र उपस्थित करते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व भाषा को एकता का सबल सूत्र माना जाता था, परंतु अब यह मान्यता निर्मूल हो चली है। समान भाषा-भाषी लोग भी अलग होकर पृथक राज्य का गठन करना चाहते हैं। मराठी लोगों में यह प्रवृत्ति पहले ही विद्यमान थी। अब आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना हेतु आंदलन भी इस प्रकार का है।

परदेस में मूल्य-निर्धारण

विनिमय/ विवेकरंजन श्रीवास्तव

पर्यटन इन दिनों विश्व स्तर पर बहुत सहज है। इस स्थिति में दूसरे देश में चीजों की कीमत समझने का सबसे सही तरीका सिर्फ़ अपनी मुद्रा में कन्वर्ट करना नहीं बल्कि वहां की आमदनी और जीवन स्तर के संदर्भ में सोचना है। जिस तरह भारत में 80, 100 रुपये की एक अच्छी चाट आम शहरी के लिए सामान्य मानी जाती है, उसी तरह अमेरिका में लगभग 10 डॉलर की एक प्लेट चाट वहां के मध्यमवर्गीय व्यक्ति के लिए उतनी ही सामान्य बात है। जब भारतीय पर्यटक किसी विदेशी रेस्तरां के मेन्यू पर 10 या 15 डॉलर देखते हैं और तुरंत दिमाग में उसे 900 या 1200 रुपये में बदल देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कीमत बहुत अधिक लगती है लेकिन यह तुलना अधूरी है क्योंकि यह केवल मुद्रा के गणित को देखती है।

उस समाज की आय और खर्च की वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना सही मूल्यांकन संभव नहीं होगा। किसी भी देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग दो चीजों से मिलकर बनती है, रोजमर्रा के खर्च और वहां की आमदनी। भारत में एक औसत व्यक्ति का मासिक व्यक्तिगत खर्च डॉलर में बदलने पर भले कुछ सौ डॉलर दिखे पर इसी के साथ यह भी सच है कि औसत आय अपेक्षाकृत कम है, इसलिए 500 या 1000 रुपये का अतिरिक्त खर्च सोचे समझे बिना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरी ओर अमेरिका, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में वही व्यक्तिगत खर्च डॉलर या पाउंड में देखने पर भारत की तुलना में कई गुना अधिक नजर आता है।

लेकिन उनकी टैक्स के बाद की औसत सैलरी भी अक्सर भारत के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। इसीलिए जो चीज भारत के नजरिए से फिजूलखर्ची लग सकती है, वही उन देशों के निवासी के लिए सिर्फ़ एक साधारण रोजमर्रा का व्यय होती है। भारत से सीधी तुलना करें तो यूएई, यूके, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकप्रिय देशों में जीवन यापन का औसत खर्च लगभग 3 से 6 गुना तक अधिक दिखाई देता है। किराया, ट्रांसपोर्ट, बाहर खाना, सेवाएं, सबकी कीमतें भारत से ज्यादा दिखती हैं।

विशेष तौर पर लंदन, दुबई, न्यूयार्क, सिडनी या टोरंटो जैसे बड़े शहर इस दृष्टि से और भी महंगे पड़ते हैं किंतु वही चित्र तब संतुलित दिखने लगता है जब यह देखा जाए कि इन देशों में औसत नैट सैलरी से किसी व्यक्ति का डेढ़ से दो महीने तक का व्यक्तिगत खर्च निकल सकता है, यानी वहां का निवासी यदि अपने शहर की स्टैंडर्ड नौकरी पर है तो उसे 10 डॉलर की कॉफी या 15 डॉलर के लंच से उतना झटका नहीं लगता जितना वह रकम सीधे भारत की अर्थव्यवस्था में डालकर सोचने पर लगती है। इस अंतर को अनदेखा करके केवल कन्वर्जऩ करने से हर कीमत अस्वाभाविक रूप से महंगी लगने लगती है। यूएई का उदाहरण लें तो दुबई जैसे शहर में किराया, बिजली, पानी और रोजमर्रा के सामान की कीमतें भारत के औसत से कई गुना ऊपर हैं लेकिन वहां बहुत से पेशों में टैक्स फ्री या कम टैक्स वाली उच्च आय मिलती है जो इन खर्चों को संतुलित कर देती है।

सबसे दिलचस्प और उपयोगी मानसिक अभ्यास यह है कि जब भी किसी बोर्ड पर 10, 15 डॉलर या 8, 12 पाउंड की कीमत देखकर झटका लगे तो अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाए, यदि मेरी तनख़्वाह भी इस देश की औसत सैलरी जितनी होती तो क्या यह दाम उतना ही चुभता। बहुत बार इसका उत्तर नहीं होगा और वही क्षण होता है जब समझ में आता है कि दिक्कत वास्तविक कीमत से ज्यादा हमारे तुलना करने की मानसिकता में है। करेंसी कन्वर्जऩ का यह जाल जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही भ्रामक भी है। तब 10 डॉलर की चाट केवल 950 रुपये की फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि एक नए समाज के जीवन स्तर की छोटी सी झलक बन जाती है, और यात्रा का अनुभव सचमुच ज्ञानवर्धक और रोचक हो उठता है।

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नैटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

स्लो लाइफ, आलस्य नहीं चेतना का नाम है

कभी धीमी रफ्तार आलस्य का पर्याय रही हो, लेकिन आज जब फास्ट लाइफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन बर्नआउट और डिप्रेशन का सबसे बड़ा स्रोत बता रहा है, तब पूरी दुनिया में स्लो लाइफ या धीमे जीवन की ओर बढ़ने को आलस्य की निशानी बल्कि नई चेतना का पर्याय माना जा रहा है। हालांकि किसी गलतफहमी में न रहें इसलिए जानते चलें कि-

- स्लो लाइफ का मतलब काम को अधूरा छोड़ या जीवनशैली से समझौता नहीं है और न ही स्लो लाइफ का मतलब घर में पड़े रहना है, इसका मतलब है कम लेकिन अर्थपूर्ण काम करना।
- बीच-बीच में पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स होना।
- स्थानीय जीवन का आनंद लेना और पारिवारिक जीवनशैली का लुत्फ उठाना।
- परंपरागत व्यंजनों का आनंद लेना और प्रकृति से भरपूर जुड़ाव रखना।
- रिश्तों की गुणवत्ता बढ़ाना, न कि उनकी संख्या बढ़ाना।

शहरों से गांवों की ओर

पूरी 20वीं सदी में और 21वीं सदी के पहले लगभग दो दशकों तक पलायन का मतलब गांव से शहर की ओर जाना ही होता रहा है। लेकिन कोविड के बाद यूरोप में 16 प्रतिशत और अमेरिका में 6 प्रतिशत लोग शहर छोड़कर गांवों में बस गये। भारत में भी उच्च आयवर्ग में अपनी जड़ों की ओर लौटने का चरण शुरू होने लगा है। हालांकि ये प्रतिशत अभी बहुत कम है, लेकिन इसके बढ़ने के आसार हैं।

आखिर क्यों थकी दुनिया

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से लगातार दुनिया तेज रफ्तार जीवनशैली को कामयाबी और स्टेट्स सिंबल की तरह पेश करती रही है, तो सवाल है फिर आखिर 21वीं सदी में आकर दुनिया का तेज रफ्तारी से मोहभंग क्यों हो गया? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जिनमें सबसे बड़ी वजह कोविड है। लोग अब परिवार के साथ रहना चाहते हैं। कृषि और पशु धन का महत्व समझने लगे हैं। साथ ही यह भी समझने लगे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ किया तो जीवन खुशहाल नहीं रह सकता।

रफ्तार के शोर से दूर

ठहराव की पनाह में

नए साल में रफ्तार से थके मन जरा-सा थमने के बारे में विचार करेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि पूरी दुनिया अब स्लो लाइफ की तरफ बढ़ रही है...

एक जमाना था, जब तेज रफ्तार होना रोमांच का सबब था, कामयाबी की निशानी थी। इसलिए इंसान तेज-तेज और तेज की तरफ पिछली एक सदी से दौड़ता रहा है और इस भागमभाग में वाकई उसने अपनी जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज कर ली है। फास्ट इंटरनेट, बुलेट ट्रेन, आवाज की गति से दौड़ते हवाईजहाज, एक मिनट में सौ खबरें और तीन महीने में कॅरियर की बुलंदी छूना, ये सब इतनी तेज रफ्तार के उदाहरण हैं कि अब इंसान इस तेज रफ्तारी को रोमांच की बजाय आफत का सबब मानने लगा है। यही कारण है कि 2026 की दुनिया तेज रफ्तारी से रोमांचित नहीं है बल्कि स्लो लाइफ की तरकीबें खोज रही है और कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में लोग तेज रफ्तार से उकताकर अब स्लो लाइफ और स्लो रफ्तार का दामन थाम रहे हैं। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक आज स्लो लाइफ स्टेटस सिंबल बन चुकी है, क्योंकि लोग मशीन बनने से थक चुके हैं, अब वह अपनी आत्मा से संवाद करना चाहते हैं।

क्यों लौट रहे हैं धीमे की ओर

पूरी दुनिया में लोग स्लो लाइफ की तरफ लौट रहे हैं, तो इसकी वजह है कि पिछले कई दशकों के भागमभाग के कारण परिवार का मतलब खत्म हो चुका है। फोन आपको किसी क्षण बेफिक्र नहीं होने देता, फुर्सत में नहीं आने देता। नये-नये पकवानों की इस कदर बमबार्डिंग हो रही है कि लोग अपने स्वाद का स्थायी सुख ही भूल गये हैं।

नींद अब दुनिया की सबसे बड़ी नियामत बन चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुद को भूल चुका है। इसलिए आज अमेरिका हो या अफ्रीका, लोग परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। कुछ घंटे या हफ्ते में एक दिन कम से कम बिना फोन के रहना चाहते हैं। कभी आराम से धीरे-धीरे पकाकर अपनी मनपसंद डिश खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम हफ्ते का एक दिन तो ऐसा हो, जब सोकर जगने का टाइमर सेट न हो और हां, इस सबके बीच लोग अब अपने साथ भी कुछ घंटे, कुछ दिन बिताना चाहते हैं, इसलिए तेजी से लोग तेज रफ्तारी को छोड़कर धीमी और सुकूनभरी जिंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं।

कोहरा, धुंध या बारिश की स्थिति

आपको कोई कानूनी छूट नहीं देती

लीगल जोन

प्रभाकांत

ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर परिस्थितियां खराब हों, ऐसे समय पर ट्रैफिक रूल इतनी कड़ाई से लागू नहीं किये जाने चाहिए। लेकिन इस बात को गंभीरता से जान लीजिए कि चाहे सर्दियां हों, कोहरा हो, बारिश हो या भारी ट्रैफिक हो, किसी भी स्थिति में आपको ट्रैफिक रूल तोड़ने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलती। भले लोग कानून के भीतर कुछ अतिरिक्त छूट और नियमों की उपेक्षा की उम्मीद लगाते हों, लेकिन कानून में इस तरह कोई छूट नहीं देता।

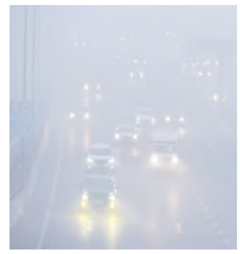

नियम तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी

मोटर व्हीकल एक्ट किसी भी चालक को कोहरे के कारण, धुंध के कारण या ज्यादा सर्दियां होने के कारण, गलती की सजा कम नहीं करता या गलती करने की छूट नहीं देता। भारत में सड़क, यात्रा और नागरिक सुरक्षा से जुड़े कानून, मौसम निरपेक्ष हैं, यह याद रखना जरूरी है।

सावधानी ही कानून की आत्मा

हमारे यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है रीजनेबल केयर यानी उचित सावधानी। कहने का मतलब कानून आपसे कोहरे में ज्यादा सावधानी की उम्मीद करता है, इसलिए खराब मौसम में भी तेज गति या लापरवाही को गंभीर अपराध माना जाता है। अगर 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति साफ मौसम में ठीक है, वही गति घने कोहरे की स्थिति में लापरवाही मानी जा सकती है। कानून कहता है यह आपको तय करना है कि स्थितियां खराब न हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कोहरा किसी तरह की दुर्घटना का कारण नहीं होता। दुर्घटना चालक की असावधानी का नतीजा होती है। अगर आपने कोहरे में हेडलाइट नहीं जला रखी, फॉग लैंप नहीं जलाया, स्पीड कंट्रोल नहीं की, तो ये परिस्थितियों की देन नहीं, ये आपकी लापरवाही है।

स्कूल या दफ्तर में भी छूट नहीं

खराब मौसम के कारण कोई दफ्तर अपने कर्मचारियों को देर से आने या जल्दी जाने की छूट नहीं देता, न ही कोई स्कूल ऐसे खराब मौसम में स्कूल के टाइम टेबल से आगे पीछे होने या उसे पूरी तरह से न मानने की छूट नहीं देता। हो सकता है व्यावहारिक स्तर पर किसी दिन विशेष पर अध्यापक या प्रशासनिक अधिकारी बच्चों के खराब मौसम में देर से स्कूल पहुंचने पर कोई सजा न दे या उन्हें इसके लिए दोषी न ठहराएं। लेकिन आप ऐसे व्यवहार की मांग नहीं कर सकते। अदालत में हरगिज छूट नहीं पा सकते।

क्या पुलिस कोई नरमी बरत सकती है?

कभी-कभी व्यावहारिक स्थितियां देखते हुए पुलिस ऐसे मामलों में नरमी बरत देती है। लेकिन यह नरमी या छूट पाना किसी का अधिकार नहीं, बस पुलिसकर्मी की सहानुभूति हो सकती है। वह भी व्यक्तिगत तौरपर न कि सार्वजनिक तौरपर कोई पुलिसकर्मी इस तरह की छूट किसी को दे सकता है। यही कारण है कि कोहरे या धुंध के समय स्कूल बसों की टाइमिंग में तो ढील दे दी जाती है। भारी कोहरे की स्थिति में कई शहरों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक तो लगायी जा सकती है और यहां तक कि प्रशासन के द्वारा खराब मौसम में यात्रा को टालने की एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। ये सबके सब प्रशासनिक फैसले होते हैं, लेकिन कोई नागरिक इस तरह के फैसलों की अपने अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे कानून मौसम निरपेक्ष हैं। इसलिए कोई भी मौसम हो, सजग और सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी चालक की होती है।

इंश्योरेंस में भी छूट नहीं

बीमा कंपनियां कोहरा और धुंध जैसी स्थितियों को मानती ही नहीं। अगर आपने कोहरे की स्थिति में अपनी गलती से एक्सीडेंट किया है, तो उसे आपकी लापरवाही ही माना जायेगा। इसके लिए आपको मौसम की बिना पर कोई छूट नहीं मिलेगी। लब्बोलुआब यह कि खूब धुंध या कोहरे में भी आप ओवर स्पीडिंग की गलती करते हैं, शराब पीकर कार चलाते हैं, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई बीमा क्लेम नहीं मिल सकता।

ब्रेल लिपि: अंधेरे में अक्षरों की रोशनी

4 जनवरी का दिन उस विलक्षण प्रतिभा को याद करने का है, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि देखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी संवेदना होती है। 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और दृष्टिहीन लोगों के लिए ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए। लुई ब्रेल बचपन में एक दुर्घटना के कारण अपनी दृष्टि खो बैठे थे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उपलब्ध पद्धतियां न तो सरल हैं और न ही उपयोगी। इसी चुनौती ने उन्हें ऐसी लिपि विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जा सके।

छह उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि ने अक्षरों, अंकों और चिह्नों को एक नई पहचान दी। ब्रेल लिपि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वैज्ञानिक सरलता है। बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों से शब्द बनते हैं, जिन्हें स्पर्श के माध्यम से आसानी से पढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि यह लिपि केवल भाषा तक सीमित नहीं रही, बल्कि गणित, संगीत और विज्ञान जैसे विषयों में भी अपनाई गई।

आज ब्रेल लिपि दुनिया की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी ब्रेल भी शामिल है। यह लिपि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा का माध्यम ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आधार भी है। डिजिटल युग में ऑडियो तकनीकें भले ही आगे बढ़ी हों, लेकिन ब्रेल लिपि आज भी भाषा की समझ, शुद्धता और गहराई के लिए अपरिहार्य है।

भारतीय कला कीर्ति और कमाई के नये दरवाजे खुलेंगे

2026 भारतीय कला के लिए प्रदर्शन से आगे बढ़कर संवाद, नवाचार और आर्थिक संभावनाओं का वर्ष बन रहा है। समकालीन कला, लोक परंपराएं और हस्तशिल्प इस साल वैश्विक मंचों पर नई पहचान हासिल करेंगे...

साल 2026 भारतीय कला के लिए एक तरह से उत्सवों का वर्ष है। देश और विदेश में फैले मंचों पर समकालीन कला, लोक परंपराओं की जीवंतता और सदियों पुरानी हस्तशिल्प विरासत एक साथ संवाद करती दिखाई देगी।

नई दिल्ली में आयोजित होने वाला इंडिया आर्ट फेयर, जिसे दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली कला मेलों में गिना जाता है, इस साल भी भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों और कलेक्टर्स से जोड़ने का अहम मंच बनेगा। वहीं केरल में 31 मार्च 2026 तक चलने वाली कोच्चि-मुजिरिस बिएनाले, एशिया की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी के रूप में, भारतीय कला को दुनिया के दो दर्जन से अधिक देशों तक पहुंचाने का काम करेगी।

मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में 24 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाली 134वीं ऑल इंडिया एनुअल आर्ट एग्जिबिशन भी इस साल के कला परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रदर्शनी न सिर्फ कलाकारों को पहचान और पुरस्कार देती है, बल्कि यहां प्रदर्शित कृतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करती हैं। वहीं सूरजकुंड

हस्तशिल्प मेला भी खास रहेगा। यह मेला लोककला और शिल्पकारों के लिए दक्षिण एशिया की मजबूत पहचान बन चुका है। मिट्टी, धातु, कपड़ा और लकड़ी से जुड़ी पीढ़ीगत कलाएं यहां न सिर्फ सम्मान पाएंगी, बल्कि नए बाजार और रोजगार के अवसर भी खोलेंगी। डिजिटल क्यूरेशन, एआर-वीआर अनुभव और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन्स के जरिए कई कला महोत्सव युवा दर्शकों को जोड़ने की तैयारी में हैं। आर्ट वर्कशॉप कला को समझने का अवसर भी देंगी। अहम बदलाव यह है कि 2026 में भारतीय कला आर्थिक दुनिया में भी मजबूती से कदम रखती दिखेगी। मिड-लेवल आर्ट मार्केट के विस्तार, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप निवेशकों की बढ़ती रुचि के साथ कला अब क्रिएटिव इकोनॉमी का अहम हिस्सा बन रही है।

सियासत और कॉर्पोरेट दुनिया में

खूब चर्चा में हैं ब्लैक मीटिंग्स

इन दिनों सत्ता से लेकर कार्पोरेट गलियारों में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा फुसफुसाहट के साथ सुना जा रहा है, तो वह है- ब्लैक मीटिंग्स। न कोई आधिकारिक एजेंडा, न कोई प्रेस रिलीज, न तस्वीरें, यहां तक कि औपचारिक फोन कॉल्स भी नहीं। गुपचुप तरीके से गुरिल्ला अंदाज में होने वाली इन मीटिंग्स का पता आमतौर पर तब चलता है, जब कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया जा चुका होता है, जिससे राजनीति से लेकर कॉर्पोरेट गलियारे तक समूचा

परिदृश्य बदल जाता है, इसीलिए ऐसी मीटिंग्स को अकसर ब्लैक मीटिंग्स कहकर संबोधित किया जाता है। इस शब्द में बहुत कुछ छिपा है। खतरनाक साजिश, गुपचुप मंसूबे और उलटफेर के हैरान करने वाले फैसले, इसलिए ये मीटिंग्स अपने संदर्भ में बहुत सनसनीखेज और डरावना होती हैं।

आखिर क्या है ब्लैक मीटिंग?

ब्लैक मीटिंग्स ऐसी बैठकें होती हैं-

- जिनकी कोई घोषित तारीख नहीं होती।
- जिनका कोई घोषित एजेंडा नहीं होता।
- जिनमें घोषित हिस्सेदार नहीं होते।
- जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता।

ऐसी मीटिंग्स किसी उलटफेर के नतीजे के लिए होती हैं। चाहे दुनिया कॉर्पोरेट की हो

गुपचुप की जाने वाली बैठकें कर्मचारियों के बीच कंपनी की साख खराब कर सकती हैं, वहीं राजनीति में ऐसा होता है, तो कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन का भी भरोसा टूटता है...

या सियासत की। सीधी भाषा में कहें तो ऐसी मीटिंग्स में निर्णय पहले लिए जाते हैं और बाद में उन्हें औपचारिक ढांचों में फिट कर दिया जाता है यानी निर्णय पहले और निर्णय की औपचारिकता बाद में। चुनाव के बाद अक्सर ऐसी ब्लैक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, विशेषकर जब गठबंधन की सरकार बननी हो।

कॉर्पोरेट दुनिया में भी इस तरह की बैठकों का सिलसिला चल पड़ा है। पिछले दिनों रिलायंस और उसके पहले अडानी ग्रुप में जिस तरह अखबारों के बिजनेस पेज पर एक के बाद एक लगातार हो रही ब्लैक मीटिंग्स की खबरें छपीं, वह सिलसिला इस बात का गवाह है कि अब वहां भी- छंटनी, रि-स्ट्रक्चरिंग, निवेशकों के दबाव को काउंटर करने के लिए, रातोंरात तकनीक में गुपचुप बदलाव के लिए, वैश्विक हेल-मेल और गठबंधन बनाने के लिए ब्लैक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, पर ये न सियासत के लिए अच्छी है, न कारोबार के लिए, इनसे लोगों का भरोसा टूटता है, साख भी खराब होती है।

सप्ताहिक राशिफल

राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म की राशि और वर्तमान नाम राशि अलग हों तो वर्तमान नाम राशि से दैनिक कार्यकलाप प्रभावित होते हैं।

आचार्या कीर्ति शर्मा, 9950570978

मेष: चंद्रमा की स्थिति सुधरने से सप्ताह मौज-शौक में बीतेगा। बुध-गुरु की स्थिति के कारण हल्का तनाव रह सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताहांत में आय में वृद्धि के योग हैं।

मिथुन: प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह संबंध तय हो सकते हैं। किसी पुराने साथी से मुलाकात संभव है। सर्दी-जुकाम से सावधान रहें। बुधवार से धन आगमन के साथ खर्च भी बढ़ेगा। सप्ताहांत में मन में विचलन रहेगा।

सिंह: मित्रों से मुलाकात होगी और जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। अनायास खर्चे हो सकते हैं। दूर-दराज की यात्रा के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं से सावधानी बरतें।

तुला: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार में अतिथियों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। कार्यस्थल पर वर्चस्व स्थापित करने में सफलता मिलेगी। धन का आगमन सुचारु बना रहेगा।

धनु: सप्ताह की शुरुआत में मां से मुलाकात के योग हैं। मित्रों से भी भेंट होगी। संतान या मित्रों के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। शनिवार को सर्दी-जुकाम से बचें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ: सप्ताह की शुरुआत में पुराने मित्र से मुलाकात होगी। धन की आवक बनी रहेगी। वाणी में मधुरता रहेगी। भाग्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। साढ़ेसाती के प्रभाव के कारण दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। क्रोध से बचें।

वृषभ: दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता का अनुभव करेंगे। धर्म-कर्म में धन व्यय होगा। सप्ताह मध्य से सप्ताहांत तक आय के योग बन रहे हैं। छात्रों को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।

कर्क: सप्ताह की शुरुआत उत्साह के साथ होगी। कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें। पूरे सप्ताह धन का आगमन बना रहेगा, साथ ही सैर-सपाटे पर खर्च भी होगा। रिश्तेदारों के आगमन से घर में चहल-पहल बनी रहेगी। आप भी बाहर जाने की योजना बना सकते हैं।

कन्या: पति-पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे। आय में वृद्धि होगी। सप्ताह मध्य में घर में नया वाहन आ सकता है। सप्ताहांत तक नया व्यापार भी प्रारंभ हो सकता है। पूरा सप्ताह मौज-शौक में बीतेगा। सर्दी-जुकाम से बचें।

वृश्चिक: धर्म-कर्म में धन व्यय होगा। मित्र या संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। माता से धन की प्राप्ति संभव है।

मकर: पति-पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे। मित्रों से मुलाकात होगी। छात्रों का मन अध्ययन में लगेगा। सप्ताहांत में मन में चंचलता रहेगी। जीवनसाथी के जीवन में उन्नति के योग हैं। परिवार में सुख का माहौल रहेगा।

मीन: सप्ताह की शुरुआत में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। संतान या मित्रों से मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में थोड़ा कार्य-दबाव रह सकता है। धन का आगमन बना रहेगा। झूठ बोलने से परहेज करें।

टोरी खोरी

टोरी: आज मेरी भैंस ने अंडा दिया है।

खोरी: भैंस कब से अंडा देने लगी?

टोरी: मेरी भैंस देती है। तुम चाहो तो तुम्हारी भैंस भी देने लगेगी।

खोरी: वो कैसे?

टोरी: बस तुमको अपनी मुर्गी का नाम भैंस रखना पड़ेगा।

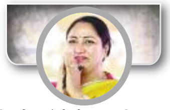

एक ओर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राष्ट्र निष्ठ, मूल्यों से ओतप्रोत राजनीतिक संस्कार, दूसरी ओर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ज्ञान, शुचिता और अखंड राष्ट्र बोध। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर दिल्ली विधानसभा जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र हित के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।

-रेखा गुप्ता

असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से शिष्टाचार भेंट कर लोकभवन के ब्रह्मपुत्र विंग अतिथि गृह का निरीक्षण किया। इसका अनावरण मा. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था।

-केशव प्रसाद मौर्य

संपादकीय

स्वच्छता बनाम दूषित पानी

अजीब विडंबना है कि जो शहर पिछले आठ साल से देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर होने का तमगा भारत सरकार से हासिल करते हुए खुद पर इतरा रहा था,उसी शहर में पिछले डेढ़ साल से लोग सीवर मिला पानी पी रहे थे और प्रशासन आत्ममुग्ध हो सो रहा था। ऊपर से बेशर्मी यह कि जब यह सवाल मध्यप्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने उसे फोकट का सवाल कहकर पत्रकार को ही डपट दिया। जिसके चलते उन्हें भारी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 हजार से ज्यादा लोग बीमार है और 200 लोग शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। बावजूद राज्य सरकार और सरकारी मशीनरी बेपरवाह है। भला हो हाईकोर्ट का जिसने मामले की सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से मांग ली।जब तब जाकर आनन-फानन में कार्रवाई शुरू हुई और कुछ अधिकारियों को निलंबित या स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में दाखिल की गई,उसमें सरकार ने दूषित पानी पीने से महज 4 लोगों की मौत को ही स्वीकार किया। साथ कहा है कि वे सभी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे। यानी उनकी नजर में बुजुर्गों की जिंदगी कोई खास मायने नहीं रखती है। खैर इस घटना ने सरकार और भ्रष्ट सरकारी तंत्र की पोल खोल दी है। जिसकी फाइलों में इंदौर चमक रहा है। लेकिन लोग मल-मूत्र से दूषित गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। चमचमाते पुरस्कारों के नीचे सीवर मिले पानी की आपूर्ति हो रही है। जनता हलकान है,नेता भी परेशान हैं। लेकिन नगर निगम अपनी मस्ती में नववर्ष का जश्न मना रहा है।खुद शहर के महापौर अपनी विवशता बयां करते हुए रूंधे गले और नम आंखों से कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। जिला कलेक्टर फोन नहीं उठाते हैं,संदेश का भी जवाब नहीं देते हैं, तो वे ऐसे सिस्टम के साथ कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि उनकी बात वे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें तो शायद कुछ कार्रवाई हो जाए। इसी तरह जल कार्यसमिति के प्रभारी से लेकर पार्षद तक सभी व्यवस्था व अफसरशाही को लेकर सवाल खड़े करते हैं।इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम यह हालात बताता है कि शहर का स्वच्छता सिस्टम सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है। किसी की कोई जवाबदेही तय नही है। अधिकारी केवल फाईलों में ही शहर को चमकाने और अपना नम्बर बढ़ाने में व्यस्त हैं। स्वास्थ्य विभाग भी सबकुछ चकाचक बता रहा है।जबकि शहर के लोग दूषित पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि जो शहर अभी तक देश-दुनिया में अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता था,वह इस समय दूषित जलापूर्ति और उससे होने वाली मौतों को लेकर सुर्खियों में है। यह घटना इंदौर के मुंह पर लगी ऐसी कालिख है,जिसे आसानी से धुला नहीं जा सकता। संभव है सबसे स्वच्छ शहर का तमगा उसे फिर से हासिल हो जाए। लेकिन जिन परिवारों ने नगर निगम के दूषित जल के पीने से अपने परिजनों को खोया है उनकी पीड़ा क्या इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। वे क्या अब भी गर्व कर पाएंगे कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या स्वच्छता के दायरे में पानी नहीं आता है? अगर आता है तो इसके तय मानकों की अनदेखी क्यों की गई। ऐसे तमाम सवाल हैं,जिनसे सरकार को रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्यप्रदेश सरकार अभी भी इसे कोई बड़ी घटना नहीं मानती है। यह सरकारों का असंवेदनशील रवैया है। हंगामा मचने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जरूर की है। लेकिन इतने से समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। इसे लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर सरकार वाकई ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है तो उसे जवाबदेही तय करनी चाहिए। सरकारी तंत्र की गैरजिम्मेदारी के चलते लोगों की जान जाती है और सरकार उस जान की कीमत दो लाख रुपए तय करके मामले को खत्म करना चाहती है तो यह लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा मजाक है। ऐसे मामले लापरवाही से हत्या जैसे हैं और इनमें इसी आपराधिक धारा में जवाबदेही तय करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तभी इस तरह के मामले रुक सकते हैं। अन्यथा अभी इंदौर की पोल खुली है। आने वाले दिनों कई अन्य शहरों में भी इसी तरह मामले आएंगे और अधिकारी अपनी नींद में सोते रहेंगे।

आपका मत

जहरीला और दूषित पानी

आज इंदौर एक दुखद और विडंबनापूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है जहां जहरीले और दूषित पानी की वजह से कम से कम 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। यह शहर नर्मदा नदी के पानी पर निर्भर है जो अब बैक्टीरिया और ई.कोलाई से संक्रमित पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डायरिया, उल्टी और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'जहर की सप्लाई' करार देते हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अपनी सरकार को घेरा है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार को इंदौर प्रशासन के साथ मिलकर युधिष्ठिर पर कार्य करना होगा ताकि भविष्य में कोई जान और न जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी साफ पानी की सप्लाई के आदेश दिए हैं। इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्वच्छता सिर्फ कूड़ा उठाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पानी, हवा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे और निर्दोष जिंदगियां यूं ही हारते जा रहे हैं।

-वीरेंद्र कुमार जाटव दिल्ली

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।

loksatyaedit01@gmail.com

दृष्टिहीनों की शिक्षा में ब्रेल लिपि की भूमिका

योगेश कुमार गोयल

दृष्टि विकलांग लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की स्पर्शनीय प्रणाली है, जिसकी खोज 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपवरे में जन्मे लुई ब्रेल ने महज 15 वर्ष की आयु में की थी। संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में विश्वभर में जागरूकता फैलाने, दृष्टि-बाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिवस को 'विश्व ब्रेल दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेन्शन' में ब्रेल लिपि को संचार के एक साधन के रूप में उद्धृत किया गया है।

'विश्व ब्रेल दिवस' पर विशेष

ब्रेल लिपि नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों और दृष्टि विकलांग लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की स्पर्शनीय प्रणाली है, जिसकी खोज 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपवरे में जन्मे लुई ब्रेल ने महज 15 वर्ष की आयु में की थी। संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में विश्वभर में जागरूकता फैलाने, दृष्टि-बाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिवस को 'विश्व ब्रेल दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेन्शन' में ब्रेल लिपि को संचार के एक साधन के रूप में उद्धृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 'यूनेस्को' ने वर्ष 1949 में ब्रेल लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समस्याओं पर ध्यान देने वाला एक सर्वेक्षण आगे बढ़ाने की पहल की थी।

लुई ब्रेल ने केवल तीन साल की उम्र में ही एक दुर्घटना के कारण अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखें संक्रमित होने के कारण उनकी आंखों की दृष्टि पूरी तरह चली गई थी लेकिन दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि छात्रवृत्ति पर 'रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ' चले गए। 1821 में फ्रांसीसी सेना के एक कैप्टन चार्ल्स बार्बियर लुई ब्रेल के स्कूल के दौरे पर आए थे, जिन्होंने सेना के लिए एक विशेष क्रिप्टोग्राफी लिपि का विकास किया था, जिसकी मदद से सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते हैं। चार्ल्स ने स्कूल में बच्चों के साथ 'नाइट राइटिंग' नामक यही तकनीक साझा की, जिसका उपयोग सैनिक दुश्मनों से बचने के लिए किया करते थे। इसके तहत वे उभरे हुए बिन्दुओं में गुप्त संदेशों का आदान-प्रदान करते थे किन्तु उनका यह कोड बहुत जटिल था।

ब्रेल ने इसी आइडिया के आधार पर अपनी लिपि पर कार्य शुरू किया और 'रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ' में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने 1824 में अपनी लिपि को तैयार कर लिया, जो काफी सरल थी। इसी लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया और सरल लिपि की खोज के बाद दुनियाभर में नेत्रहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन लोगों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो गई। अपने इसी आविष्कार के कारण लुई ब्रेल दुनियाभर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए मसीहा बन गए।

ब्रेल लिपि कोई भाषा नहीं है बल्कि एक तरह का कोड है। यह ऐसी लिपि है, जिसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है और इसमें उभरे हुए बिन्दुओं की श्रृंखला पर उंगलियां रखकर या उन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि को टाइपराइटर जैसी दिखने वाली एक मशीन 'ब्रेलराइटर' के जरिये लिखा जा सकता है या पेंसिल जैसी नुकीली चीज 'स्टायलस' और ब्रेल स्लेट 'पट्ट' का इस्तेमाल करके कागज पर बिन्दु उकेरकर लिखा जा सकता है। ब्रेल में उभरे हुए बिन्दुओं को 'सेल' के नाम से जाना जाता है। 1 से 6 बिन्दुओं की यह एक व्यवस्था या प्रणाली होती है, जिसमें बिन्दु अक्षर, संख्या और संगीत व गणितीय चिन्हों के संकेतकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रेल लिपि के अंतर्गत उभरे हुए बिन्दुओं से एक कोड बनाया जाता है, जिसमें 6 बिन्दुओं की तीन पंक्तियां होती हैं और इन्हीं में इस पूरे सिस्टम का कोड छिपा होता है।

चार्ल्स बार्बियर की शुरुआती कूट लिपि 12 बिन्दुओं पर आधारित थी, जिन्हें 66 की पंक्तियों में रखा जाता था। तब इसमें विराम, संख्या और गणितीय चिन्ह मौजूद नहीं थे। लुई ब्रेल ने इसमें सुधार करते हुए 12 की जगह 6 बिन्दुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिह्न का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने विराम चिन्ह, संख्या और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिह्न उपलब्ध कराए। ब्रेल ने हालांकि 1824 में पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने कार्य को प्रस्तुत किया था लेकिन ब्रेल लिपि प्रणाली को 1829 में पहली बार प्रकाशित कराया। उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय ब्रेल लिपि प्रणाली का विस्तार करने में बिताया। हालांकि जीते जी उनके काम को उचित सम्मान नहीं मिला और उनके निधन के 16 वर्ष बाद 1868 में ब्रेल लिपि को प्रामाणिक रूप से मान्यता मिली, जो आज दुनियाभर में मान्य है।

समय के साथ तकनीकी युग में ब्रेल लिपि में कुछ बदलाव होते रहे हैं और अब ब्रेल लिपि कम्प्यूटर तक भी पहुंच गई है। ब्रेल लिपि वाले ऐसे कम्प्यूटर में गोल व उभरे हुए बिन्दु होते हैं और कम्प्यूटरों में यह तकनीक उपलब्ध होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब दृष्टिहीन व्यक्ति भी तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं। ब्रेल लिपि में अब बहुत सारी पुस्तकें निकलती हैं, यहां तक कि स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ भी छपते हैं। भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2009 को लुई ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूरे होने पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का निधन हो गया लेकिन उनकी खोजी ब्रेल लिपि ने आज विश्वभर में दृष्टिहीनों तथा आंशिक रूप से नेत्रहीनों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है।

जब जिम्मेदारियां अलार्म से पहले जाग जाती हैं

कृति आरके जैन

सुबह की पहली रोशनी के साथ जब शहर जागता है, तब एक कामकाजी मां पहले ही कई लड़ाइयाँ जीत चुकी होती है। अलार्म की आवाज़ से पहले उसकी जिम्मेदारियां जाग जाती हैं—बच्चे का टिफिन, घर की व्यवस्था, और मन में चलती दफ्तर की सूची। वह आईने में खुद को देखती है, मुस्कान ओढ़ती है और बाहर निकल पड़ती है, जैसे सब कुछ सहज हो। पर इस सहजता के पीछे छिपा है एक कठिन संघर्ष, जहां मातृत्व और करियर के बीच संतुलन साधना रोज़ की परीक्षा बन चुका है। यह संघर्ष दिखाई नहीं देता, पर हर सांस में महसूस होता है। समय उसके लिए केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि लगातार पीछा करने वाला दबाव है। सुबह से रात तक भूमिकाएं बदलती रहती हैं, पर विश्राम की जगह नहीं बनती।

एक स्त्री, कई भूमिकाएँ और अंतहीन अपेक्षाएँ

आधुनिक समाज कामकाजी मां से दोहरी पूर्णता की अपेक्षा करता है। घर में वह आदर्श मां हो, और कार्यस्थल पर समर्पित पेशेवर। इन अपेक्षाओं के बीच उसकी थकान को अक्सर स्वाभाविक मान लिया जाता है। समय उसके लिए केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि लगातार पीछा करने वाला दबाव है। सुबह से रात तक भूमिकाएं बदलती रहती हैं, पर विश्राम की जगह नहीं बनती। समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जो एक व्यक्ति से हर मोर्चे पर उत्कृष्टता चाहती है। जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा, संतुलन एक चुनौती ही बना रहेगा।

समय प्रबंधन कामकाजी माताओं के जीवन का सबसे जटिल अध्याय है। एक ओर मीटिंग्स और डेडलाइंस हैं, दूसरी ओर बच्चे की ज़रूरतें और परिवार की अपेक्षाएं। इस भागदौड़ में निजी समय सबसे पहले बलि चढ़ता है। नींद कम होती जाती है, और थकान जमा होती जाती है। समाधान केवल अधिक मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से चुनी गई प्राथमिकताएं हैं। डिजिटल टूल्स, साझा कैलेंडर और स्पष्ट सीमाएं दिनचर्या को सरल बना सकती हैं। जब मां अपने समय को महत्व देती है, तभी वह दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाती है।

भावनात्मक अपराधबोधः कामकाजी माताओं की सबसे गहरी पीड़ा है। दफ्तर में बिताया हर अतिरिक्त घंटा उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं वे अपने बच्चे से कुछ छीन तो नहीं रहीं। समाज मातृत्व को पूर्ण त्याग से जोड़ देता है, जिससे यह अपराधबोध और गहरा हो जाता है। पर सच्चाई यह है कि एक मानसिक रूप से संतुलित मां ही बच्चे को सुरक्षित माहौल दे सकती है। आत्मस्वीकृति, माइंडफुलनेस और अपने प्रयासों को स्वीकार करना इस बोझ को हल्का करता है। जब मां खुद को दोषी मानना छोड़ती है, तभी वह वास्तव में मजबूत बनती है।

करियर की राह पर मातृत्व : अक्सर एक अदृश्य दीवार बन जाता है। मातृत्व अवकाश के बाद लौटने पर अवसरों में कमी, क्षमता पर संदेह और धीमी प्रगति कई महिलाओं का अनुभव है। यह धारणा कि मां कम प्रतिबद्ध होती है, वास्तविकता से परे है। मातृत्व महिलाओं को बेहतर योजनाकार, अधिक संवेदनशील और मजबूत निर्णयकर्ता बनाता है। इस अनुभव को कमजोरी नहीं, योग्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। मेंटरशिप, नेटवर्किंग और निरंतर कौशल विकास से महिलाएं इस दीवार को तोड़ सकती हैं और अपने लिए नई राह बना सकती हैं।

सामाजिक दबाव कामकाजी माताओं के आत्मविश्वास को लगातार चुनौती देता है। रिश्तेदारों की टिप्पणियां, परंपरागत सोच और अनचाही सलाह उन्हें हर फैसले पर कटघरे में खड़ा करती हैं। यह दबाव उन्हें यह महसूस कराता है कि वे कभी पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन यही संघर्ष आत्मबल का स्रोत भी बन सकता है। जब महिलाएं अपनी कहानियां साझा करती हैं और एक-दूसरे का साथ देती हैं, तो यह दबाव कमजोर पड़ने लगता है। सामूहिक आवाज़ धीरे-धीरे सामाजिक सोच को बदलने की ताकत बन जाती है।

लचीली कार्य नीतियां कामकाजी माताओं के लिए संतुलन की मजबूत नींव हैं। घर से काम, फ्लेक्सी टाइम और चरणबद्ध वापसी जैसी व्यवस्थाएं उन्हें निरंतरता देती हैं। तकनीक ने इस संतुलन को और सहज बना दिया है।

कविता

धूप बांटे रवि

बन ठन के निकले रवि घर से,
सब में बांटने को धूप,
फूलों से तन खिलखिला उठे-
नद,तरु,ताल,खग या कूप।

राह रोके हैं श्यामल मेघ,
चिरकर घन निकले हैं रवि,
वन,उपवन,मधुबन महक उठे-
पाकर रब की अनुपम छवि।

सन सन सन जब चले हैं पवन,
झूमता मतवाला जिया,
छम छम छम बरसे हैं पानी-
बावरा होवे हैं पिया।

कलुषित जीवन को हरकर के,
मन में जगमग दीप जलें,
सुप्त नैनों के पलकों तले-
निस दिन नित नव सपन पले।

-नलिन खोईवाल

Blogger

धर्म का स्वरूप: सेवा या स्वार्थ?

डॉ प्रियंका सौरभ

भारत को सदियों से धर्म, आस्था और आध्यात्म की भूमि माना जाता रहा है। यहाँ धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन के हर पक्ष को दिशा देने वाला तत्व रहा है। आस्था ने व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संबल दिया, उसे नैतिकता और मानवता से जोड़े रखा।

बदलते समय के साथ यह देखा जा रहा है कि आस्था का स्वरूप धीरे-धीरे विकृत होता जा रहा है। धर्म, जो आत्मिक शांति का माध्यम था, कई स्थानों पर भय, अंधविश्वास और व्यापार का साधन बनता जा रहा है।

आज का यथार्थ यह है कि धार्मिक परंपराओं का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। जिन कर्मकांडों का उद्देश्य मनुष्य को आत्मिक संतुलन देना था, वे अब आर्थिक लेन-देन और दिखावे से जुड़ गए हैं।

तीर्थस्थल, जो कभी तप, त्याग और साधना के केंद्र हुआ करते थे, आज कई बार बाजार का रूप धारण कर चुके हैं। श्रद्धालु की भावना से अधिक उसकी आर्थिक स्थिति को महत्व दिया जाने लगा है।

आस्था का मूल आधार विश्वास है—ईश्वर में, जीवन में और स्वयं में। यह विश्वास किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से उपजता है। जब आस्था भय पर आधारित हो जाती है, तब वह पाखंड में बदल जाती है।

दुर्भाग्यवश, आज अनेक धार्मिक गतिविधियाँ इसी भय को केंद्र में रखकर संचालित की जा रही हैं। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यदि उन्होंने किसी विशेष परंपरा का पालन

नहीं किया या तय राशि का दान नहीं दिया, तो अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार धर्म, जो आश्वासन देने वाला था, भय पैदा करने वाला बनता जा रहा है।

परंपराएँ किसी भी समाज की पहचान होती हैं। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से विकसित होती हैं। लेकिन परंपराएँ तब तक ही उपयोगी हैं, जब तक वे समय, विवेक और मानवता के अनुरूप हों। परंपराओं को पत्थर की लकीर मान लेना समाज के विकास में बाधा बनता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपराओं की समीक्षा करें—यह समझें कि उनका उद्देश्य क्या है और वे वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक हैं।

धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष सेवा रहा है। सेवा का अर्थ है—निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। किंतु जब सेवा के बदले मूल्य तय कर दिया जाए, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। दान तभी दान कहलाता है जब वह स्वेच्छा से दिया जाए। जब दान दबाव, भय या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण दिया जाता है, तब वह अपनी पवित्रता खो देता है। दुर्भाग्य से, आज दान भी कई जगह अनिवार्य शुल्क की तरह वसूला जाने लगा है।

इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव साधारण और भावनात्मक लोगों पर पड़ता है। दुख, शोक या संकट की घड़ी में व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। ऐसे समय में यदि उसकी आस्था का शोषण किया जाए, तो यह न केवल अनैतिक है, बल्कि अमानवीय भी है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को टूटने से बचाना है, न कि उसे और अधिक बोझिल बनाना।

पाखंड का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह धीरे-धीरे धर्म के प्रति अविश्वास को जन्म देता है। जब लोग बार-बार ठगे जाते हैं, उनकी भावनाओं का दोहन होता है, तो वे या तो धर्म से दूर हो जाते हैं या फिर हर परंपरा को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। यह स्थिति समाज के लिए घातक है, क्योंकि धर्म का स्वस्थ स्वरूप सामाजिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज के शिक्षित और जागरूक समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति हर बात को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखे। आस्था और विवेक एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्ची आस्था वही है जो विवेक के साथ चल सके। यदि कोई परंपरा मानवता, नैतिकता और करुणा के विरुद्ध जाती है, तो उसे बदलना ही धर्मसम्मत कदम माना जाना चाहिए।

धार्मिक संस्थानों और धर्म से जुड़े लोगों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी केवल कर्मकांड करवाना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। यदि धार्मिक नेतृत्व स्वयं लालच और स्वार्थ से प्रेरित होगा, तो आमजन से नैतिकता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। धर्म को व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाना समय की माँग है।

इसके साथ ही समाज की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तब तक पाखंड समाप्त नहीं होगा। प्रश्न करना अधर्म नहीं है। हर परंपरा का उद्देश्य समझना और उस पर विचार करना बौद्धिक परिपक्वता का संकेत है। आँख मूँदकर हर बात मान लेना न तो आस्था है और न ही धर्म।

राजनीति प. बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में मई से पहले चुनाव, एनडीए-विपक्ष के संगठन, नेतृत्व और रणनीति की जोर आजमाइश

2026 का संग्राम; क्षेत्रीय दलों की अग्नि परीक्षा

संजय कुमार
चुनाव विश्लेषक और निदेशक, सीएसडीएस

भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्र में चुनावों का चक्र अलग होता है। वर्ष 2026 भी इससे अलग नहीं होगा। इस साल अप्रैल-मई में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं- पूर्वी भारत में असम और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन राज्यों में होने वाले चुनावों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल मुख्य भूमिका में होंगे। ये चुनाव एक बार फिर राजनीतिक दलों के जनाधार, संगठनात्मक ताकत, चुनावी रणनीति और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेंगे, क्योंकि भारतीय चुनावों में यही सफलता के सबसे अहम कारक होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शासन और कल्याणकारी राजनीति भी मायने रखती है, लेकिन किसी भी पार्टी की चुनावी जीत की असली नींव संगठन और नेतृत्व ही होते हैं।

इस समय यह कहना बेहद मुश्किल है कि किसी भी राज्य में कौन-सी पार्टी को बढ़त हासिल है। मगर रणनीतिक कारणों से दांव बहुत ऊंचे हैं- खासतौर पर दो बड़े राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस, वाम मोर्चा और क्षेत्रीय दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), डीएमके और एआईएडीएमके के लिए। कई अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी ताकत आजमाएंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर दल अपने राज्यों में प्रभावशाली या बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में लड़ने की संभावना रखते हैं।

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भविष्य; इंडिया गठबंधन का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि 2026 में चुनाव लड़ने वाले राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल कैसा प्रदर्शन करते हैं। असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, जहां वह पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है। एक और हार कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। केरल में भी कांग्रेस के सामने बड़ी परीक्षा है। सत्ता परिवर्तन की परंपरा के बावजूद कांग्रेस 2021 में जीत नहीं पाई थी। इस बार पार्टी पर दबाव और ज्यादा है। 'इंडिया' के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बेहद अहम हैं। यदि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और डीएमके सत्ता में बनी रहती हैं, तो गठबंधन मजबूत रहेगा। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी 2026 के चुनावों का असर पड़ेगा।

भाजपाध्यक्ष का टेस्ट; भाजपा में नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की भी परीक्षा होगी। अगर भाजपा असम, बंगाल या केरल में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उनका कद बढ़ेगा। असम में जीत से सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के लिए राष्ट्रीय भूमिका का रास्ता भी खुल सकता है। कुल मिलाकर, चुनावी दृष्टि से 2026 एक बेहद दिलचस्प साल होने जा रहा है।

वो सबकुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है

सियासी समीकरण; बंगाल में ममता व असम में हिमंता का किला मजबूत, तमिलनाडु में 'थर्ड पार्टी' का ट्विस्ट

प. बंगाल: 'सत्ता विरोधी' भावना से भाजपा को बड़ी आस

टीएमसी सरकार बचाने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा पूरी ताकत से ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का प्रयास करेगी। टीएमसी पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है, इसलिए कुछ हद तक सत्ता-विरोधी भावना और असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, शिक्षकों की भर्ती से जुड़े विवाद और हाल ही में मशहूर फुटबॉलर मेसी के दौरे के दौरान हुई अव्यवस्था जैसी घटनाओं ने टीएमसी और खासकर ममता की छवि को कुछ नुकसान पहुंचाया है। सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे अब अतीत बन चुके हैं या भाजपा इन्हें चुनावी मुद्दा बना पाएगी।

प्रभावी फैक्टर; 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें व 38.1% वोट हासिल कर मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को स्थापित किया। कांग्रेस और वाम मोर्चा सिंगल डिजिट वोट शेयर पर सिमट गए। भाजपा की यह बड़ी उपलब्धि रही कि उसने कांग्रेस और वाम दलों को काफी पीछे छोड़ दिया।

तमिलनाडु: एक्टर विजय की पार्टी हो सकती है गेम चेंजर

तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही सीधा मुकाबला रहा है। लेकिन अब अभिनेता विजय द्वारा शुरू की गई नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। विजय ने साफ किया है कि उनकी पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अपनी पहली बड़ी पार्टी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा को वैचारिक दुश्मन और डीएमके को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कहा। हालांकि उनकी रैली में भारी भीड़ जुटी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह भीड़ वोट में बदले। बिहार में जन सुराज का उदाहरण सामने है, जहां बड़ी रैलियों के बावजूद पार्टी को सिर्फ 3.3 प्रतिशत वोट मिले।

प्रभावी फैक्टर; डीएमके और कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन में चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को लेकर अन्नामलाई अहम कड़ी बने हुए हैं। बड़े मुद्दों की बात की जाए तो यहां हिंदी-तमिल भाषा विवाद, एसआईआर और एंटी इन्कंबेंसी निर्णायक हो सकते हैं।

असम: दोनों दलों के वोट शेयर में अंतर काफी कम है

भाजपा यहां अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी। 2021 में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 75 सीटें जीती थीं (जिसमें 60 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं) और पार्टी ने 43.9% वोट हासिल किए थे। वहीं, इंडिया गठबंधन (जिसे असम में महाजोत कहा गया) ने 50 सीटें जीती थीं और 42.3% वोट पाए थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि सीटों के लिहाज से दोनों गठबंधनों में बड़ा अंतर था, लेकिन वोट शेयर का फर्क सिर्फ 1.6% था। समर्थन आधार में थोड़ा सा भी बदलाव एनडीए के सत्ता समीकरणों को बिगाड़ सकता है, हालांकि राज्य में मौजूदा जनभावना को देखते हुए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।

प्रभावी फैक्टर; असम में चुनावी सफलता की कुंजी सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि यह भी होगी कि कांग्रेस और भाजपा छोटे क्षेत्रीय दलों (खासतौर पर जनजातीय, जातीय और समुदाय आधारित दलों) के साथ गठबंधन कितनी सफलतापूर्वक कर पाती हैं। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की भी परीक्षा होगी।

केरल: पिछला चुनाव छोड़ दें तो सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है

केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला रहा है और हर चुनाव में सत्ता बदलती रही है। 2021 का चुनाव अपवाद रहा, जब एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा। भाजपा केरल में लगातार विस्तार की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने त्रिशूर सीट जीतकर राज्य में खाता खोला। हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 सीटों में भाजपा ने 50 सीटें जीतीं और सिर्फ एक सीट से बहुमत से चूक गई। हालांकि एक निर्दलीय के समर्थन के बाद भाजपा को बहुमत मिल गया था। अब इसे राज्यव्यापी समर्थन का संकेत समझें या सिर्फ स्थानीय प्रभाव।

प्रभावी फैक्टर; 2019 व 2024 के लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और हालिया स्थानीय चुनाव दिखाते हैं कि केरल में भाजपा का आधार बढ़ रहा है। 2026 में भाजपा एक अहम खिलाड़ी होगी। भाजपा को यहां आरएसएस की मजबूत हो रही जमीनी पकड़ का भी फायदा मिल सकता है।

पुडुचेरी: हर सीट पर मतदाताओं की संख्या कम है, हार-जीत का अंतर ज्यादा नहीं होता... इसलिए सत्ता समीकरण जटिल

30 सदस्यीय विधानसभा वाले छोटे राज्य पुडुचेरी में चुनाव हमेशा से जटिल रहे हैं। यहां हर विधानसभा सीट में मतदाताओं की संख्या कम होती है और हार-जीत बहुत छोटे अंतर से तय होती है। अक्सर किसी भी दल या गठबंधन को बड़ा बहुमत नहीं मिल पाता। एनडीए (भाजपा और एनआर कांग्रेस का गठबंधन) पुडुचेरी में अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगा। असम की तरह ही यहां भी पूर्व-चुनावी गठबंधन अहम होंगे। हालांकि, पुडुचेरी में बाद में बनने वाले गठबंधन और निर्दलीय विधायकों की भूमिका भी चुनाव के बाद सरकार गठन में महत्वपूर्ण रही है। **प्रभावी फैक्टर**; एनडीए को 2021 में 16 सीटें मिलीं, जिसमें 6 भाजपा की थीं। डीएमके ने 6, कांग्रेस ने 2, निर्दलीय ने 6 और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थीं। गठबंधन जारी रहेगा, अन्नाद्रमुक की संभावित एंट्री। पीएमके भी शामिल हो सकती है। लेकिन कांग्रेस-द्रमुक मजबूत चुनौती दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन महिलाओं/युवाओं पर फोकस से एलजेके उभर सकता है।

• दुनिया की राजनीति

अमेरिका; मिड-टर्म चुनाव ट्रम्प का भविष्य तय करेंगे

अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड-टर्म चुनाव होने हैं। ये हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक दो साल बाद होते हैं। यदि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी हाउस या दोनों सदनों में बहुमत खोती है, तो उनका दूसरा कार्यकाल राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा। बड़े कानून पास कराना मुश्किल होगा। यदि वे जीतते हैं तो टैरिफ वॉर बढ़ सकता है। भारत, चीन, ईयू, मैक्सिको जैसे देशों पर दबाव बढ़ेगा। सप्लाई चेन में अनिश्चितता लौटेगी।

बांग्लादेश; तारिक की वापसी से बीएनपी मजबूत है

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं, जो 11वीं संसद के 300 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये चुनाव शेख हसीना के 2024 में हटाए जाने के बाद पहले पूर्ण चुनाव हैं। शेख हसीना की पार्टी 'आवामी लीग' को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
▪ छात्र नेताओं द्वारा बनाई गई नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच गठबंधन की खबरें आई हैं, जिससे देश की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है।
हम पर असर- तारिक रहमान की वापसी से बीएनपी को फायदा। बीएनपी जीती तो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी प्रभावित होगी। ट्रेड रुकावट संभव। हालांकि, रहमान से संबंध सुधरे तो हालात बदलेंगे।

नेपाल; कांग्रेस जीती तो भारत के लिए सकारात्मक

नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने हैं। इसमें प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों के लिए मतदान होगा। यह चुनाव पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन के बाद पहला पूर्ण आम चुनाव है। भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के आरोपों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।
हम पर असर- नेपाली कांग्रेस की जीत भारत के लिए सकारात्मक होगी। व्यापार, और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। यूएमएल या माओवादी जैसे दल मजबूत होते हैं, तो यहां चीन का असर बढ़ सकता है।

रूस; सितंबर में चुनाव संभावित, पुतिन ही दावेदार

रूस में सितंबर 2026 में स्टेट ड्यूमा (निचली संसद) का चुनाव होना तय है। यानी 450 सदस्यीय ड्यूमा की सभी सीटों के लिए मतदान होगा। यूनाइटेड रूस पार्टी जो पुतिन-समर्थक नेतृत्व की है, अगले चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत पाने की स्थिति में है। कई सर्वे में पार्टी को लगभग 55% वोट मिलने का अनुमान बताया गया है।
हम पर असर- भारत को रणनीतिक अनिश्चितता का खतरा कम रहता है। हालांकि, पुतिन के कारण रूस-पश्चिम तनाव बना रहता है, जिससे भारत को बार-बार डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करनी पड़ती है।

ड्रोन

40 किमी ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन आएंगे

एल्विन एंथोनी
सीईओ व को-फाउंडर
नेक्स्टलीप एरोनोटिक्स

ड्रोन के लिए भी 2026 टर्नअराउंड साल साबित होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव एग्रीकल्चर में दिखेगा। करीब 14,500 ड्रोन खेती के काम के लिए तैनात होंगे। मिट्टी की जांच, दवा डालने से लेकर पौधे की सेहत पर नजर रखेंगे। खेती का इकोसिस्टम बदल जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति को एक एकड़ खेत में दवा छिड़कने में आधा दिन लगता है, लेकिन ड्रोन से यह काम 8 मिनट में हो जाएगा। साथ ही, फसलों में बीमारी लगने से पहले ही पता चल जाएगा और उनका निवारण किया जा सकेगा।

रेस्क्यू टीम से पहले पहुंचेंगे ड्रोन, मदद करेंगे
ड्रोन इस साल सिक्योरिटी, सर्विलांस, सड़क दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप जैसे मामलों में बेहद उपयोगी होंगे। किसी हादसे की जगह पर मेडिकल टीम और पुलिस से पहले पहुंच कर पीड़ित की मदद कर सकेंगे। दक्षिण और उत्तर पूर्व राज्यों में पुलिस विभाग, वन विभाग से लेकर डिजास्टर टीम ड्रोन की खरीदारी कर रहे हैं और इसे इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी शहर में कोई हादसा होता है तो पुलिस और मेडिकल टीम को पहुंचने में 40 से 45 मिनट तक लग जाते हैं। लेकिन सूचना मिलते ही ड्रोन एक्टिव होंगे और महज 5-10 मिनट में पहुंच सकेंगे। घटनास्थल की लाइव इमेज और वीडियो भेजेंगे। रेस्क्यू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। नागरिक सुरक्षा में भी अहम रोल निभाएंगे।
मान लीजिए किसी महिला ने अपने फोन पर सेफ्टी एप डाउनलोड कर रखा है। वो किसी छेड़छाड़ या अनहोनी की स्थिति में सेफ्टी बटन दबाती है तो सूचना मिलते ही कुछ ही मिनट में ड्रोन लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इससे अपराधी की पहचान की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये एआई ड्रिवेन ड्रोन अलार्म बजाकर महिला को बचाने की भी कोशिश करेंगे।

हाइराइज बिल्डिंग, सोलर पैनल की क्लीनिंग करेंगे
अब हाइराइज बिल्डिंग की साफ-सफाई से लेकर पेंटिंग भी ड्रोन से होगी। यहां तक की सोलर पैनल की सफाई भी ड्रोन करेंगे। इससे सौलर पैनल पार्क की क्षमता बढ़ेगी। पावर लाइन की मरम्मत भी कर रहे हैं।

ड्रोन युद्धनीति का अहम हिस्सा... बिना सिग्नल के 40-50 किमी ऊपर उड़ सकेंगे, जैमर पकड़ नहीं सकेंगे
आज ड्रोन युद्धनीति का अहम हिस्सा है। एआई और 5 जी से इंटीग्रेट ड्रोन निगरानी तंत्र को अचूक बना रहे हैं। इस साल ऐसे ड्रोन आ सकते हैं, जो 40-50 किमी ऊपर उड़ान भर सकते हैं और 2 घंटे तक ट्रैवल कर सकें। ये ड्रोन जैमर को धोखा देने में माहिर होंगे। यहां तक कि जीपीएस सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल के बिना चल सकेंगे। फिलहाल इस तरह के ड्रोन के ट्रायल हो रहे हैं। हमारी कंपनी ने भी एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो फाइबर ऑप्टिक्स से चलते हैं।

लाजिस्टिक और सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनेंगे
ड्रोन सप्लाई चेन में अहम हिस्सा बनेंगे। दूरदराज के इलाकों में मेडिकल सप्लाई और सामान डिलीवर करने के काम में तेजी आएगी। साथ ही, पैकेज को डार्कस्टोर (गोदाम) तक पहुंचाने में मददगार होंगे। हालांकि घर-घर डिलीवरी का इकोसिस्टम बनने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं।

विदेश नीति शक्ति केंद्रों में फंसी दुनिया, भारत ने संतुलन साधा

कूटनीति... भारत किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, इसलिए हम सबसे मजबूत स्थिति में

वीना सीकरी,
वरिष्ठ राजनयिक, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रह चुकीं

वर्ल्ड ऑर्डर 2026 में और भी जटिल रहने वाला है। बहुध्रुवीय शक्ति केंद्रों में फंसी दुनिया में भारत ने संतुलन को बखूबी साधा है। यूक्रेन हो या फिर गाजा युद्ध भारत की बात सभी पक्ष सुनते हैं। हमारी विदेश नीति का मंत्र है किसी भी ग्रुप के साथ रहने के बजाय सभी देशों के साथ, जिससे हमारे हितों का संरक्षण हो। इसी का नतीजा है कि भारत इस साल दुनिया में सबसे मजबूत पोजीशन में रहने वाला है। बहुध्रुवीय दुनिया में हर देश के साथ अलग-अलग तालमेल। इसका आधार हमारी मजबूत इकोनॉमी है। इस साल कई बड़े देशों के साथ भारत के फ्री टेड एग्रीमेंट पाइपलाइन में हैं। पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारी चिंता के क्षेत्र हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को दुनिया भर से सपोर्ट मिला है। भारत की मिलिट्री पावर से हमने दुनिया को मजबूती दिखाई है। बांग्लादेश अभी बड़े बदलाव से गुजर रहा है, लेकिन वहां चुनाव के बाद लीडरशिप को समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश के हित भारत से जुड़े हैं। दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है।

3 सुपरपावर... जिन्हें हमारी पावर बैलेंस करेगी

अमेरिका; ट्रेड डील होनी तय, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए करार

अमेरिका के साथ इस साल ट्रेड डील होनी लगभग तय है। इसका बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा थोपे 50% टैरिफ के बावजूद भारतीय इकोनॉमी 7% की अधिक दर से बढ़ रही है। निर्यात भी बढ़ रहा है। इस साल की पहली तिमाही में ट्रेड डील हो सकती है। डिफेंस के सेक्टर में 10 साल के फ्रेमवर्क पर करार हो चुका है। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी मिलेंगे।
▪ सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में तकनीक ट्रांसफर होगा। स्पेस प्रोग्राम बड़ा गेमचेंजर साबित होगा। नासा और इसरो मिलकर स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे।

चीन; हमारी इकोनॉमी के बूते सुरक्षा मुद्दे सुलझे, ग्लोबल साउथ में नई ऊर्जा

चीन के साथ हमारे सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे सुलझे हैं। विवादों के सुलझने से ग्लोबल साउथ में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भारत और चीन विकासशील देशों की मुखर आवाज बनेंगे। चीन हमारी इकोनॉमी को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हमारा बड़ा मार्केट और मिडिल क्लास चीन के सामने एक बड़ी मजबूत प्रतिरोधी दीवार के समान काम करता है।
▪ भारत-चीन ब्रिक्स की सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। डॉलर के प्रभुत्व को चैलेंज कर सकते हैं। ट्रम्प टैरिफ को यदि लंबे समय तक हथियार बनाते हैं तो इस साल भारत और चीन अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी कर सकते हैं।

रूस; एनर्जी ट्रेड जारी रहेगा, भारत की वैश्विक ताकत से रूस को फायदा

अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच एनर्जी ट्रेड जारी रहेगा। इसके वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। रूस के साथ हमारा ऑयल बास्केट इस साल और बढ़ सकता है। भारत और रूस की दोस्ती का आधार बरसों से डिफेंस डील रहे हैं, लेकिन अब हमने इसे और इसका विस्तार किया है। भारत की वैश्विक ताकत में रूस भी अपना फायदा देख रहा है। भारत की दुनिया में स्वीकार्यता मेनस्ट्रीम से अलग रूस के लिए लाभकारी साबित होती है। रूस ये तथ्य जानता है।

स्पेस स्टार्टअप

'ऑन-डिमांड' लॉन्च होने लगेंगे छोटे सैटेलाइट्स

पवन कुमार चंदना
सीईओ व को-फाउंडर
स्काईरूट एयरोस्पेस

साल 2026 भारत के लिए स्पेस स्टार्टअप क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है, जहां भारतीय निजी स्पेस स्टार्टअप्स न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बल्कि दुनिया के लिए अंतरिक्ष का द्वार भी खोलेंगे। स्पेस सेक्टर केवल रॉकेट भेजने तक सीमित नहीं रहा। इसमें तीन प्रमुख व्यावसायिक अवसर दिखाई दे रहे हैं :
लॉन्च: अंतरिक्ष तक पेलोड ले जाने की क्षमता।
स्पेस इंफ्रा: सैटेलाइट और निजी स्पेस स्टेशनों का निर्माण।
स्पेस इंटेलिजेंस: अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा का विश्लेषण, जो खेती से लेकर आपदा प्रबंधन तक में काम आएगा।

2026 का बड़ा धमाका: विक्रम-1 की लॉन्चिंग
'स्काईरूट एयरोस्पेस' ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट 'विक्रम-1' श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की तैयारी में है। उद्देश्य छोटे सैटेलाइट्स के लिए 'ऑन-डिमांड' लॉन्च सेवा देना है। भारत की स्थिति ऐसी है कि यहां से 'लो अर्थ ऑर्बिट' में सैटेलाइट भेजना आसान है। 2033 तक भारत की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना। भारत एक भरोसेमंद और सस्ता लॉन्च पैड बन जाएगा।

इसरो और निजी क्षेत्र का तालमेल: निजी क्षेत्र के आने से इसरो को बड़ी राहत मिलेगी। कमर्शियल लॉन्चिंग और छोटे सैटेलाइट्स का जिम्मा स्टार्टअप्स संभालेंगे, जिससे इसरो अपना पूरा ध्यान गहरे अंतरिक्ष मिशनों, गगनयान जैसे मानव मिशनों और स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने पर लगा पाएगा।

स्पोर्ट्स क्रिकेट वर्ल्ड कप समेत कई खेलों में भागीदारी, दो टूर्नामेंट की मेजबानी भी

सिर्फ क्रिकेट नहीं, 9 बड़े वर्ल्ड इवेंट्स में रहेंगे मेडल के दावेदार

शारदा उगरा
स्पोर्ट्स एक्सपर्ट

साल 2026 भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। 2026 में ऐसे कई बड़े आयोजन हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी और टीमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से सीधा मुकाबला करेंगी। एशियन गेम्स, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप और दो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल की पहचान होंगे। उम्मीद यही है कि भारतीय खेल रिकॉर्ड, पदक, जीत और वर्ल्ड टाइटल के रूप में नए मुकाम छुए। क्रिकेट के लिहाज से यह साल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ शुरू हो रहा है। पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीमें एक साथ वर्ल्ड चैम्पियन हैं, भले ही फॉर्मेट अलग हों। पुरुष टीम को भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खिताब बचाने की चुनौती मिलेगी, जबकि महिला टीम इंग्लैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में दुर्लभ डबल जीत का प्रयास करेगी। टेस्ट क्रिकेट में पुरुष टीम से खोई हुई चमक वापस पाने की उम्मीद रहेगी। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की राह कठिन है, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर बेहतर प्रदर्शन इस दिशा में अहम कदम हो सकता है। यह साल नए चैम्पियनों के उभार और पुराने सितारों की वापसी का भी संकेत देता है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा से लेकर बैडमिंटन की उभरती पीढ़ी तक, भारतीय खेल एक नए दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। साथ ही डोपिंग, संघों के पेशेवर प्रबंधन और फुटबॉल में मची उथल-पुथल से निपटने पर पर ध्यान देना जरूरी है।

इस साल ये 9 बड़े इवेंट्स... आंकड़ों में जानिए हमारी दावेदारी कितनी मजबूत

▪ जिम्बाब्वे-नामीबिया में जनवरी में यूथ वर्ल्ड कप, भारत 5 बार विजेता। सर्वाधिक 78% जीत, पिछले 5 फाइनल खेले। वैभव सूर्यवंशी बड़ा चेहरा।

▪ फरवरी में भारत टी20 वर्ल्ड कप में उतरेगा। गत चैम्पियन है। घर पर रिकॉर्ड 68% जीत के साथ खिताबी दावेदार।

▪ जून में महिला टी20 वर्ल्ड कप। भारत वनडे चैम्पियन है। 2025 में टी20 में दूसरा बेस्ट 143.92 स्ट्राइक रेट रहा।

▪ पुरुष हॉकी टीम अगस्त में वर्ल्ड कप में उतरेगी। 1975 के बाद सूखा तोड़ने की उम्मीद। टॉप-10 रैंकिंग में है, पिछले साल एशिया कप चैम्पियन बनी थी।

▪ अगस्त में 17 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप की मेजबानी। वर्ल्ड नंबर-3 जोड़ी सात्विक-चिराग से बड़ी उम्मीदें।

▪ शतरंज ओलिंपियाड में डबल गोल्ड डिफेंड करेंगे। 'कैंडिडेट्स' जीतने पर वर्ल्ड फाइनल प्रागी बनाम गुकेश संभव।

▪ अक्टूबर में कुश्ती वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहरीन में। भारत 23 मेडल जीता है, जिसमें 2018 के बाद 12 आए हैं। गैर ओलिंपिक वर्ष, इसलिए कम प्रतिस्पर्धा।

▪ एशियन गेम्स सितंबर में जापान में। पिछली बार 107 मेडल जीतकर बेस्ट प्रदर्शन। एथलेटिक्स, शूटिंग में उम्मीद।

▪ चीन में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग इवेंट। ओलिंपिक क्वालिफायर। यूथ रिकॉर्ड तोड़ चुकीं कोयल, चानू से उम्मीदें।

रोमांच: आईपीएल में 300+ की उम्मीद : आईपीएल में पहली बार 300+ स्कोर की संभावना है। पिछले सीजन रिकॉर्ड 52 बार 200+ पार हुए। औसत स्ट्राइक रेट 152.39 रिकॉर्ड स्तर पर है। टीम इंडिया भी टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा कर सकती है।

सम्पादकीय

जानलेवा जल, इंदौर में दूषित पेयजल से 14 लोगों की मौत

देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा रखने वाले इंदौर में दूषित पेयजल से 14 लोगों की मौत हो जाना बहुत ही आघातकारी और शर्मनाक घटना है। यह स्वच्छता के मानकों पर सवाल खड़े करने के साथ ही नगर निगम के नाकारापन को बयान करने वाली एक ऐसी घटना है, जो देश की छवि भी मलिन कर रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की आपूर्ति इसलिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि सीवर की गंदगी पीने की पाइपलाइन में चली गई और फिर वह घरों तक पहुंच गई। यदि दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर तत्काल ध्यान दिया गया होता तो इस भयावह त्रासदी को रोका जा सकता था, लेकिन जैसा कि अपने देश में होता है, गंदी जलापूर्ति की शिकायतों पर तब तक ध्यान नहीं दिया गया, जब तक लोग मरने नहीं लगे। 14 लोगों की मौत और एक हजार से अधिक लोगों के बीमार होने और इनमें से सौ से ज्यादा लोगों के अस्पताल में भर्ती होने से यह सहज ही समझा जा सकता है कि कितने अधिक जहरीले जल की आपूर्ति हो रही थी। यह आपूर्ति इंदौर के उस इलाके में हो रही थी, जो नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र है और पेयजल की आपूर्ति करने वाला विभाग उनके ही मंत्रालय के तहत आता है। जब मंत्री महोदय से इस हत्यारी लापरवाही पर सवाल किए गए तो उन्होंने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए ऐसे सवालों को फोकट का बता दिया। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि चौतरफा आलोचना से घिरने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने खेद जता दिया, क्योंकि उनकी वह संवेदनहीनता तो प्रकट हो ही गई, जो ऐसी घटनाओं का कारण बनती है। यह भी संतोषजनक नहीं कि इंदौर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि एक तो निलंबन कोई सजा नहीं और दूसरे, इसमें संदेह है कि ऐसे उपाय किए जा सकेंगे, जिससे फिर कभी दूषित जलापूर्ति न हो सके। यह समझा जाए तो अच्छा कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति केवल इंदौर नगर निगम को ही सुनिश्चित नहीं करनी, क्योंकि देश में आम तौर पर पेयजल की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं। इसका प्रमाण यह है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ आदि का सहारा लेना पड़ता है या फिर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक ओर जहां पेयजल की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी होती है, वहीं दूसरी ओर और टूटी-फूटी पाइपलाइनों की सुधि मुश्किल से ही ली जाती है। इसका परिणाम यह है महानगरों तक में गुणवत्ताहीन पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके चलते प्रति वर्ष टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के लाखों मामले सामने आते हैं। यह तथ्य नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का है कि भारत में सुरक्षित पेयजल के अभाव में हर साल लगभग दो लाख लोग जान गंवाते हैं।

कक्षा की दीवारों से बाहर शिक्षा: अनिवार्य उपस्थिति की वैचारिक पड़ताल

डॉ सत्यवान सौरभ

न्यायालय ने दोहराया कि छात्रों को परीक्षा देने या अकादमिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर न देना, यदि उन्होंने 'कठोर उपस्थिति मानदंड' के अनुसार अपने प्रदर्शन का कम से कम एक अंश दिखाया है, तो यह शिक्षा के होने के कारण का अपमान है। ये बयान इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं कि, आज तक, उच्च शिक्षा में छात्र केवल बच्चे नहीं हैं; वे अधिक परिपक्व लोग हैं, जिन्हें अनुभव के साथ आने वाले आत्म-अनुशासन और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। शिक्षा का मूल्य वास्तव में सीखने की क्षमता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ पाठों में बैठने के अनुसार,

उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों को डिग्री देना या उन्हें एक निश्चित साँचे में ढालना नहीं है। इसका सार यह भी है कि एक छात्र को उसकी बेड़ियों से मुक्त कर एक चिंतनशील नागरिक बनाना जो स्वतंत्र सोच के योग्य हो। फिर भी भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जहाँ हर छात्र को कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है, और यह डिग्री शिक्षा की सीमा है, और इससे अधिक 'निगरानी और अनुशासन' नहीं है। यदि किसी की उपस्थिति का भौतिक स्थान सीखने के लिए एक पूर्वापेक्षा बन जाता है, तो ज्ञान यांत्रिक हो जाता है, जिससे जिज्ञासा, संवाद और आलोचनात्मक सोच जैसे अन्य तत्व बाहर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सभी छात्र सीखने की खुशी या बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं, बल्कि नियमों और दंड से प्रेरित होते हैं।

ऐसे वातावरण में, इस मुद्दे के नैतिक और कानूनी आयाम को दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया बयानों द्वारा रेखांकित किया गया है। न्यायालय ने दोहराया कि छात्रों को परीक्षा देने या अकादमिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर न देना, यदि उन्होंने 'कठोर उपस्थिति मानदंड' के अनुसार अपने प्रदर्शन का कम से कम एक अंश दिखाया है, तो यह शिक्षा के होने के कारण का अपमान है। ये बयान इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं कि, आज तक, उच्च शिक्षा में छात्र केवल बच्चे नहीं हैं; वे अधिक परिपक्व लोग हैं, जिन्हें अनुभव के साथ आने वाले आत्म-अनुशासन और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। शिक्षा का मूल्य वास्तव में सीखने की क्षमता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ पाठों में बैठने के अनुसार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। यह भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों में पारंपरिक

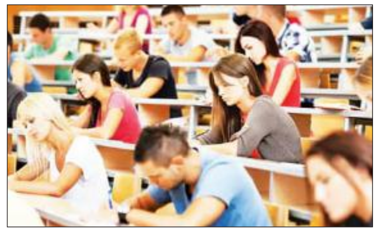

प्रथा को चुनौती देता है जो उपस्थिति को शैक्षिक योग्यता का मुख्य प्रतिबिंब मानता है। इन परिसरों के भीतर पाउलो फ्रेरे की %आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र% और विशेष रूप से उनका %बैंकिंग मॉडल% प्रचलित शैक्षिक मॉडल की एक शक्तिशाली आलोचना प्रस्तुत करता है। शिक्षण के उस चरित्र के द्वारा जिसमें शिक्षक ज्ञान के जमाकर्ता होते हैं और छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, एक शैक्षिक प्रक्रिया फ्रेरे के अनुसार असंतुलित रहती है। इस बैंकिंग मॉडल में, शिक्षक बैंक का दिल होता है, और छात्र मूल रूप से, आज्ञाकारी उपभोक्ता होता है। अनिवार्य उपस्थिति की धारणा केवल इस मॉडल को मजबूत करती है, क्योंकि अब यह छात्र की उपस्थिति है न कि सीखने की गुणवत्ता। इस तरह, शिक्षा संवाद और सहयोग का कार्य बनना बंद कर देती है और नियंत्रण और निगरानी का तंत्र बन जाती है। ऐसे सिस्टम के नैतिक परिणाम गंभीर होते हैं। जैसे ही स्कूल छात्रों को नियमों का पालन करने वालों की श्रृंखला के रूप में देखना शुरू करते हैं, वे उनकी स्वायत्तता और गरिमा छीन लेते हैं। शिक्षा, जो स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय को उत्पन्न करने का साधन है, अनुशासन उपकरण बन जाती है। और वहाँ, उन्हें यह प्रतिक्रिया मिलती है कि उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, यदि नहीं तो समझने, या प्रश्न पूछने के लिए एकमात्र है। समय के साथ, यह मानसिकता स्थापित हो जाती है; कि सीखना बाहरी उत्तेजनाओं के सामने किया जाता है, आंतरिक प्रेरणा के पक्ष में नहीं। नैतिक रूप से, यह आज्ञाकारिता के लिए शिक्षा है, स्वतंत्रता के लिए नहीं। अनिवार्य उपस्थिति के इस कठोर दृष्टिकोण से छात्र स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उच्च शिक्षा कई मायनों में आज तक की तुलना में अधिक जटिल और बहुआयामी है। नए प्रकार के सीखने और अवसर मौजूद हैं जिनमें ऑनलाइन संसाधन, वेब-आधारित सामग्री, अनुसंधान जांच, परियोजनाएं और फील्डवर्क शामिल हैं। इसके साथ कहा गया है, उपस्थिति केवल कक्षा में बैठने जितनी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि ये सफल, वैकल्पिक सीखने के तरीके नजरअंदाज किए जाते हैं। यह शिक्षा को मानक और विशिष्ट बनाता है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और गतिशील है। अनिवार्य उपस्थिति नीति सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा देती है। ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक कारणों से अंशकालिक काम कर रहे हैं, माता-पिता जो अपने सभी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, कुछ जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कई जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिली है। ऐसी कठोर उपस्थिति नियम इन विविध परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हैं और सभी छात्रों के लिए एक ही उपस्थिति मानक लागू करते हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय की चिंता महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में कि यह अन्याय और देखभाल के हमले के तहत शिक्षा का मामला है, यह जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निहित करता है कि शिक्षा को न्याय और मानव संवेदनशीलता के संदर्भ से जांचा जाना चाहिए। जब यह छात्रों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होता है, जहां वे अपने जीवन में हैं, हम समान अवसर नहीं हैं, समान अवसर की बहुत अवधारणा पतली हो जाती है।

फ्रेरे की आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र में, शिक्षा का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में किया जाता है। उनके अनुसार, शिक्षा की भूमिका केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है बल्कि चेतना को प्रोत्साहित करना भी है, छात्रों को एक नींव प्रदान करना जो उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने और प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाता है।

बैंकिंग मॉडल के अपवाद के साथ, बैंकिंग मॉडल छात्रों को यथास्थिति बनने के लिए सिखाता है। जब शिक्षा को अनिवार्य उपस्थिति के माध्यम से नियंत्रण और अनुशासन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह आलोचनात्मक चेतना के गठन में बाधा बन जाती है। यथास्थिति को चुनौती देने और विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने के बजाय, छात्र सीखते हैं कि सुरक्षा नियमों के अनुसार अनुरूपता में निहित है।

स्वच्छता के 'सिरमौर' के सामने शुद्ध जल की एक चुनौती......

विवेक वैष्णव

स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहने का अर्थ केवल सड़कों का साफ होना या कचरा उठना नहीं है। एक 'स्मार्ट सिटी' और 'स्वच्छ शहर' की सार्थकता तभी है जब उसके नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, विशेषकर शुद्ध पेयजल, बिना किसी संशय के प्राप्त हो। इंदौर शहर के कुछ हिस्सों से दूषित पानी की आपूर्ति और उससे फैलने वाली बीमारियों की खबरें यह दर्शाती हैं कि नगर निगम का 'ड्रेनेज सिस्टम' और 'वॉटर सप्लाई लाइन' कई जगह जर्जर हो चुकी हैं। इंदौर को 'वॉटर प्लस' का प्रमाणन मिला है, जिसका अर्थ है कि शहर का सीवरेज प्रबंधन उत्कृष्ट है और कोई भी गंदी पानी नदियों में नहीं मिल रहा। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत दिखती है।

इंदौर ने बीते वर्षों में स्वच्छता के मानकों को जिस तरह बदला है वह पूरे देश के लिए एक नजीर है। कचरा प्रबंधन और जन-भागीदारी में नंबर वन रहने वाले इस महानगर के लिए हालिया 'प्रदूषित जल' का प्रकरण न केवल चिंताजनक है बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि धरातल पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्वच्छता में सात बार देश में इंदौर ने प्रथम आकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, 'प्रदूषित पानी' की खबरें उस छवि पर एक प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इंदौर के प्रदूषित पानी के प्रकरण को यदि और अधिक गहराई से देखा जाए तो यह केवल पाइप लाइन के लीकेज का मामला नहीं है बल्कि यह नगरीय नियोजन और पर्यावरणीय संकट का एक जटिल मिश्रण है।

स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहने का अर्थ केवल सड़कों का साफ होना या कचरा उठना नहीं है। एक 'स्मार्ट सिटी' और 'स्वच्छ शहर' की सार्थकता तभी है जब उसके नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, विशेषकर शुद्ध पेयजल, बिना किसी संशय के प्राप्त हो। इंदौर शहर के कुछ हिस्सों से दूषित पानी की आपूर्ति और उससे फैलने वाली बीमारियों की खबरें यह दर्शाती हैं कि नगर निगम का 'ड्रेनेज सिस्टम' और 'वॉटर सप्लाई लाइन' कई जगह जर्जर हो चुकी हैं। इंदौर को 'वॉटर प्लस' का प्रमाणन मिला है, जिसका अर्थ है कि शहर का सीवरेज प्रबंधन उत्कृष्ट है और कोई भी गंदा पानी नदियों में नहीं मिल रहा। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत दिखती है। शहर में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता या दक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम की जल कार्यसमिति और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की कमी है। पानी के नमूनों की नियमित जांच केवल कागजों तक सीमित रह जाती है।

शहर का विस्तार जिस तेजी से हुआ है उसके अनुपात में बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। इंदौर के मध्य और पुराने क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली दशकों पुरानी है। कई स्थानों पर पानी की पाइप लाइन नालियों के भीतर से गुजर रही हैं। कई पुराने क्षेत्रों में पेयजल की पाइप लाइन और सीवरेज की लाइन समानांतर या बहुत करीब हैं। लीकेज की स्थिति में गंदा पानी पीने के पानी में मिल जाता है। जब पाइप लाइन में प्रेशर कम होता है तो

'सेक्शन' के कारण नालियों का गंदा पानी लीकेज के जरिए पीने के पानी में मिल जाता है। शहर में बड़ी संख्या में अवैध जल कनेक्शन भी हैं जिन्हें लेने के लिए पाइप लाइन में जो छेद किए जाते हैं वे भी भविष्य में प्रदूषण का मुख्य स्रोत बनते हैं।

आधुनिकीकरण के चक्कर में इंदौर की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियों का स्वरूप बदल चुका है। औद्योगिक क्षेत्रों का अनुपचारित केमिकल युक्त पानी भी नदियों में गिरता रहता है। नदियों के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण आसपास के क्षेत्रों का भूजल भी जहरीला हो चुका है। जिन बस्तियों में लोग बोरिंग के पानी पर निर्भर हैं वहां चर्म रोग और पेट की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषित पानी का सबसे सीधा प्रहार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। दूषित पानी के कारण होने वाली बीमारियाँ न केवल शारीरिक कष्ट देती हैं बल्कि निम्न आय वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ भी डालती हैं।

प्रशासन अक्सर तात्कालिक सुधार (पैचवर्क) कर जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है लेकिन जरूरत दीर्घकालिक समाधान की है। अमृत योजना और अन्य जल परियोजनाओं के बावजूद अगर नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर हैं तो व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। इंदौर के प्रदूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान केवल मरम्मत से संभव नहीं है। इसके लिए एक 'बहु-आयामी दृष्टिकोण' की आवश्यकता है। पुराने शहर में जहाँ दोनों लाइनें एक-दूसरे के करीब हैं, उन्हें कम से कम 3 से 5 फीट की दूरी पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। नई लाइनों के लिए 'डक्ट सिस्टम' का उपयोग किया जाए ताकि भविष्य में लीकेज होने पर बिना सड़क खोदे उसे ठीक किया जा सके।

अवैध तरीके से पाइप लाइन में छेद करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यही छेद संक्रमण का मुख्य द्वार बनते हैं। दूषित जलापूर्ति होने पर संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि काम में लापरवाही न बरती जाए। उद्योगों को यह अनिवार्य करना होगा कि वे अपना एक बूंद भी अनुपचारित पानी नदियों में न बहाएं। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में साझा उपचार संयंत्र की क्षमता बढ़ानी होगी।

नदियों के किनारों पर 'इंटर सेप्टर पाइप लाइन' का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि नालों का गंदा पानी नदी में जाने के बजाय सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचे। जल वितरण नेटवर्क में सेंसर्स लगाए जाने चाहिए जो पानी के दबाव और गुणवत्ता में किसी भी गिरावट की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दें।

हर वार्ड का नियमित अंतराल पर 'वॉटर ऑडिट' होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में पानी की बर्बादी हो रही है या कहाँ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। केवल मुख्य जल संयंत्रों पर ही नहीं बल्कि हर वार्ड स्तर पर 'मिनी लैब' होनी चाहिए। नागरिकों के लिए भी 'ऑन-डिमांड' पानी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इंदौर के '311 ऐप' की तरह एक समर्पित 'जल सुरक्षा पोर्टल' होना चाहिए जहां नागरिक पानी के रंग, गंध या लीकेज की फोटो अपलोड कर सकें और जिस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो। मोहल्ला स्तर पर नागरिकों की समितियां बनाई जाए जो जल वितरण के समय और गुणवत्ता की निगरानी करें।

रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरुरत है

अशोक भाटिया

कुत्तो के कटाने और रेबीज़ होने की घटनाओं के समाचार तो रोज आते रहते है परन्तु उत्तर प्रदेश में जनपद बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के पिपरौल गांव से एक अज़ब घटना सामने आई है । वहां एक भैंस की मौत के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। हालात ऐसे हो गए कि एक घर में तेरहवीं की दावत में रायता खाने वाले करीब 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी पहुंचकर एहतियातन रैबीज का टीका लगवाया। ग्रामीणों के मुताबिक, 23 दिसंबर 2025 को गांव में तेरहवीं संस्कार था, जिसमें पूरे गांव की दावत रखी गई थी। दावत में रायता भी परोसा गया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने खाया। बाद में जानकारी सामने आई कि जिस भैंस के दूध से रायता तैयार किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। 26 दिसंबर को उस भैंस की मौत भी हो गई। इसके बाद गांव में संक्रमण की आशंका को लेकर अफरा तफरी मच गई। डर के माहौल में शनिवार को पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं और युवा भी बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वैक्सीनेशन कराया।

कुछ समय पूर्व सरकारी खबरों के अनुसार अनुसार भारत में, रेबीज से होने वाली मौतों को 2030 तक कम करके शून्य करने का लक्ष्य है। लक्ष अच्छा था क्योकि यह उस समाचार के बाद था जिसके कारण हर साल लगभग 5,700 मौतें रेबीज के कारण हो रही थी । हालांकि, रेबीज से होने वाली मौतों में 75त्न की कमी भी दर्शाई गई थी । रेबीज के बारे में जाने तो यह एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित जानवरों की लार से फैलती है, खासकर कुत्तों के काटने से। एक बार जब रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं, तो यह लगभग हमेशा घातक होती है। एक आंकड़े से पता चलता है कि रेबीज से दुनिया भर में हर साल करीब 60 हजार मौतें होती है, जिसमें से 95 प्रतिशत से अधिक मौतें अफ्रीका और एशिया में होती हैं। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। खासकर कुत्तों के काटने से यह बीमारी होती है। रेबीज दुनिया भर में संक्रामक रोगों से होने वाली मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। भारत में हर साल रेबीज से होने वाली मौतों में से ज्यादातर मामले कुत्ते के काटने के कारण होते हैं। उत्तर प्रदेश ये घटना अलग-थलग और दुर्लभ हैं । हालांकि, अब वे पूरे भारत में परेशान करने वाले हो गए हैं। वे एक मूक संकट पर कठोर प्रकाश डालते हैं जो वर्षों से तेज हो रहा है। आवारा कुत्तों की आबादी में विस्फोट के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी परिणाम हुए हैं। फिर भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण आवारा कुत्तों की समस्या को समाप्त करने में विफल रहे हैं जो जल्दी से जनता के लिए खतरा बन रहा है।स्ट्रीट डॉग लंबे समय से भारतीय शहरों और गांवों में मनुष्यों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। हालांकि, आज उनकी संख्या अभूतपूर्व और खतरनाक है।

औपनिवेशिक युग के दौरान और आजादी के बाद भी कई दशकों तक, कुत्तों की आबादी नियंत्रण की मानक विधि में शामिल था, या शाब्दिक संसदीय भाषा में, 'कुत्तों को नष्ट करना'। ऑपइंडिया द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, हर साल स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनकी संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास में हजारों कुत्तों को मार दिया जाता है।

हालांकि, इस तरह के कठोर उपायों के बावजूद, जनसंख्या बढ़ती रही। इसने भारतीय संदर्भ में किल-आधारित रणनीतियों की विफलता की ओर इशारा किया। हालांकि, संख्या कुछ हद तक नियंत्रण में रही, और अगर विधि को नसबंदी अभियानों के साथ मिलाया गया होता, तो यह सड़क के कुत्तों की आबादी को काफी हद तक नियंत्रित करता।

काश, यह वैसा नहीं होता जैसा इसे होना चाहिए था। 2012 की पशुधन गणना में कहा गया था कि भारत में लगभग 1। 71 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 2019 में, रिपोर्ट की गई संख्या 1। 53 करोड़ थी। जबकि आंकड़े आवारा लोगों की संख्या में कमी दिखाते हैं, विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए। उन्होंने अंडर-रिपोर्टिंग और असंगत सर्वेक्षण विधियों का हवाला दिया।

जहाँ अक्षर उँगलियों से बोलते हैं: ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल

सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 4 जनवरी को 'विश्व ब्रेल दिवस' (वर्ल्ड ब्रेल डे) के रूप में मनाया जाता है, क्यों कि आज ही के दिन ब्रेल लिपि(नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए एक लिपि) के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा और उनके लिए समान अवसरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रेल कोई भाषा नहीं, बल्कि यह एक लिपि है, जिसे दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अपनाया जा सकता है। केवल छह उभरे बिंदुओं के संयोजन से अक्षर, अंक, गणितीय चिह्न, संगीत संकेत और यहां तक कि कंप्यूटर कोड भी पढ़े-लिखे जा सकते हैं। जानकारी मिलती है और लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का विकास मात्र 15 वर्ष की उम्र में किया था। आज ब्रेल केवल काग़ज़ तक सीमित नहीं है। डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल नोट-टेकर और स्मार्ट डिवाइसों ने इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया है, जिससे आज शिक्षा और रोज़गार के नए अवसर खुले हैं। भारत में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए मानकीकृत ब्रेल उपलब्ध है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति के अधिकार को सुदृढ़ करना, समाज में समावेशन (इन्क्लूजन) की भावना को बढ़ावा देना और सुलभ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ब्रेल साक्षरता आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन की आधारशिला है और वास्तव में यही संदेश विश्व ब्रेल दिवस के केंद्र में रहता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि (2026 की थीम के संदर्भ में) उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कोई अनिवार्य/स्थायी आधिकारिक थीम घोषित नहीं करता है तथा 2026 में भी यह दिवस व्यापक रूप से सुलभता, समावेशी शिक्षा और दृष्टिबाधितों के अधिकारों जैसे संदेशों के साथ मनाया जाएगा। कुल मिलाकर, विश्व ब्रेल दिवस हमें याद दिलाता है कि सुलभता कोई सुविधा नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकार है, और ब्रेल लिपि इस अधिकार को साकार करने का सशक्त माध्यम है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि फ्रांस में जन्मे लुईस ब्रेल नेत्रहीनों (अंधों) के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने-लिखने के योग्य बनाया।

सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि जिसे ब्रेल के नाम से जाना जाता है, छोटी उम्र में ही विकसित की। पाठकों को यहां जानकारी देना चाहूंगा कि लुई ब्रेल का पारिवारिक जीवन अत्यंत साधारण, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था।उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को कूपव्रे, फ्रांस में हुआ था तथा उनके पिता साइमन-रेने ब्रेल पेशे से चमड़े का काम (हार्नेस बनाने) करते थे, जबकि माता मोनीक ब्रेल एक गृहिणी थीं। जानकारी मिलती है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन माता-पिता ने बच्चों को संस्कार, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया।लुई ब्रेल अपने परिवार के चार बच्चों में सबसे छोटे थे।

कहते हैं कि मात्र तीन वर्ष की उम्र में पिता की कार्यशाला में खेलते समय एक औज़ार से उनकी आंख में चोट लगी, जो संक्रमण के कारण धीरे-धीरे पूर्ण दृष्टिहीनता में बदल गई। इस दुर्घटना के बाद परिवार ने उन्हें बोझ नहीं समझा, बल्कि हर संभव सहयोग दिया। माता-पिता ने उनके आत्मविश्वास को बनाए रखा और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया।

जन एक्सप्रेस

सम्पादकीय

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हमले की घटनाएं, सेक्युलर दलों की चुप्पी

मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से हिन्दुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला वास्तव में हिन्दुओं रक्त का प्यासा हो गया है जो उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की जनसभा में कहता है कि 'हादी तुम जहां कहीं भी हो हम तुम्हारे हर सपने को अवश्य पूरा करेंगे।' यह भाषण यूनुस की खतरनाक मंशा का संकेत कर रहा है। बांग्लादेश इस बात का प्रमाण है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वहां पर अन्य अल्पसंख्यक समाज का रहना दूभर हो जाता है।

अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक प्रदर्शनों के चलते अपना देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर आक्रमण, हत्या और आगजनी की भीषण घटनाएं हुई क्योंकि हिन्दुओं को उनकी पार्टी का समर्थक माना जाता है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस के आते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई और भारत तथा हिन्दू विरोधी आग भड़काने में जुट गई। दिसंबर 2025 में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद यह आग और भड़क गई। अब ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाकर हिन्दुओं की हत्याएं की जा रही हैं। हिन्दू घरों में बाहर से ताला लगाकर आग लगाई जा रही है। इन सभी क्रूर आपराधिक घटनाओं को यूनुस सरकार का मौन समर्थन है जिससे हिन्दू जान बचाकर भाग तक नहीं पा रहा है। विभाजन के समय बांग्लादेश में हिन्दू जनसँख्या 23 प्रतिशत थी। 1974 की जनगणना में यह घटकर मात्र 13.5 प्रतिशत रह गई थी और अब मात्र 7.96 प्रतिशत है। हिन्दुओं पर हो रहे धार्मिक अत्याचारों का यही हाल रहा तो बांग्लादेश में हिन्दू पूरी तरह से लुप्तप्राय हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में अल्पसंख्यकों पर 47 हमले दर्ज किए गए जो 2023 में बढ़कर 302 हो गए और फिर 2024 में तेजी से बढ़कर 3200 हो गए। दिसंबर माह में ही पहले दीपू चन्द्र दास और फिर अमृत मंडल को भीड़ ने ईशनिंदा के नाम पर बर्बरता से मार डाला। चटगांव मे हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई। घटनास्थल से एक धमकी भरा नोट मिला जिसमें हिन्दुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था और गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई। हादी की मौत का बदला लेने के लिए भीड़ हिन्दुओं के खून की प्यासी होकर हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रही है। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और अब तक 850 से अधिक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। केवल ताजा हिंसा में ही अभी तक 200 से अधिक हिन्दुओं की हत्याएं और 170 से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में साल 2022 से 2024 के बीच हिन्दू अल्पसख्यकों पर हमलों के मामले आठ गुना बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में जिस प्रकार से वृद्धि देखी जा रही है वह केवल तात्कालिक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है अपितु देश की सामाजिक तथा जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए दशकों से किए जा रहे कट्टर इस्लामी राजनीतिक प्रयासों का परिणाम भी है। बांग्लादेश मे हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। शेख हसीना की सरकार के समय भी हमले होते थे, विशेषकर जब हिन्दुओं के पवित्र नवरात्र प्रारंभ होते थे तब ईशनिंदा की झूठी अफवाहें फैलाकर दुर्गा पंडालों पर हमले किए जाते थे और उनमें तोड़फोड़ की जाती थी। अब अंतर यह आ गया है कि इन घटनाओं का नियंत्रण पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई व कट्टरपंथी अराजक तत्वों के हाथ में आ गया है। बांग्लादेश मे ईशनिंदा कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आठ ऐसे अवसर रहे हैं जब हिंदुओं पर ईशनिंदा के नाम पर भयानक हमले किए गए। सुनामगंज में एक फेसबुक पोस्ट के बाद पूरा हिंदू गांव तबाह कर दिया गया। रंगपुर के गंगा चरा में एक हिंदू युवक पर आरोप लगाने के बाद दंगाइयों ने 22 हिंदू घरों को ध्वस्त कर दिया।

एक्सप्रेस आलेख

आत्मनिर्भर भारत के लिए अवसर भी है पर हम अपनी सीमाओं को भी नजरअंदाज़ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए युवा भारत को अक्सर एक पूंजी के रूप में घोषित किया जाता है पर इसके लिए कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होगा। कौशल विकास की कमी और युवाओं में बेरोज़गारी के चलते समाज में असंतोष पैदा हो रहा है। यद्यपि नई शिक्षा नीति के दस्तावेज में अनेक प्रावधान हैं पर उसकी विसंगतियों को दूर कर उनके कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। उपेक्षा और साधनों के अभाव में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट चिंताजनक है। शिक्षा की पहुँच, उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता को लेकर संशय बना हुआ है।

राष्ट्रीय नवोन्मेष और विकसित भारत की संकल्पना

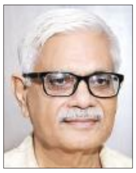

गिरीश्वर मिश्र

विकास रोजगार-रहित या अल्प-रोजगार वाला हो रहा है, आय और संपत्ति की असमानता भी बढ़ी है और अनौपचारिक क्षेत्र की असुरक्षा बनी हुई है। साथ ही जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय विषमताएँ भी हैं। उनको दूर कर बहिष्कृत जनों का समावेश जरूरी होगा अन्यथा राजनैतिक दलों द्वारा सामाजिक ध्रुवीकरण कर चुनावी लाभ लेने का चक्र चलता रहेगा। हमें बहुलता और राष्ट्रीय एकता को जोड़ना आवश्यक है।

पिछले एक दशक में भारत की छवि निश्चित रूप से एक सशक्त देश के रूप में निखरी है। नए वर्ष में इस बदलते भारत के भविष्य के बारे में सोचते हुए हमें देश की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना दोनों को ध्यान में रखना होगा। लोक की स्मृति में अभी भी नैतिक और न्यायपूर्ण शासन के लिए राम-राज्य की अमिट छवि कायम है। न केवल साल 1950 में लागू भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों वाले अध्याय के आरंभ में राम का चित्र अंकित किया गया था बल्कि साल 2025 में अक्टूबर तक 22 करोड़ लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। साल के अंत तक यह संख्या 50 करोड़ हो सकती है। इसलिए जहाँ वैश्वीकरण के अनुकूल आकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा वहीं नैतिकता, सत्य तथा अहिंसा जैसे मानदंडों की भी चिंता करनी है। राम-राज्य धर्म का राज्य की संकल्पना है जिसमें समता, समानता और सौहार्द के साथ सबका हर तरह से कल्याण मुख्य लक्ष्य है। देश की प्रगति की कथा को देखें तो उसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मिलते हैं। आज हमें संयत होकर यह विचार करना होगा कि विकसित भारत कैसा होगा ? यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी हैं कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बहुलताएँ हैं जिसे लेकर कुछ विचारक देश की मौलिक एकता को प्रश्नांकित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतीय दृष्टि में बहुलता अंतर्निहित मौलिक एकता का ही प्रकटन होती है- एकम् सद् विप्राः बहुधा वदंति। उसी एकता को खोजना पहचानने का उद्देश्य होना चाहिए। यही सात्विक ज्ञान है जैसा गीता में कहा गया है- अविभक्तम् विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति यानी बंटे हुओं में वह तत्व जो अनबंटा रहते हुए सब में मौजद रहता है उसे देखना चाहिए। पूरे प्राणी जगत में निकटता को आधार बना कर विविधताओं का सह अस्तित्व और पारस्परिक संवाद इस भारत की मौलिक सोच रही है। ऐसे में दूसरा या अन्य अनन्य (गहरा दोस्त!) हो जाता है। तब दूसरा या 'पर' हमारे अपने स्व या आत्म का हिस्सा या 'अपर' हो जाता है। हम दूसरे का आदर करते हैं और अपरिचित को अतिथि देवता के रूप में पूजते हैं । यह अकारण नहीं है कि परिवार या कुटुंब का रूपक हमारी सोच में केंद्रीय है। सबको शामिल करते हुए वसुधैव कुटुंबकम् के लक्ष्य को अपनाते हुए ही विविधता में समरसता स्थापित हो सकेगी। देश की एकता, देश को अपनाने के भाव और देशप्रेम के लिए भी यह दृष्टि जरूरी है। बीता वर्ष भारत के लिए चुनौतियों भरा था। अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात, रुपये की कीमत, निवेश तथा भुगतान संतुलन आदि को लेकर मुश्किलें खड़ी कर दीं। राष्ट्रपति ट्रम्प की तथाकथित अमेरिकी हितों को आक्रामक ढंग से आगे धकेलने की नीति ने निश्चित ही व्यापारिक दृष्टि से अहित किया। अमेरिका द्वारा पारस्परिक सीमा शुल्क अर्थात् 25

भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और अनुमान है कि साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। आशा की जाती है कि आर्थिक उन्नति से आम जनों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।

प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया। इन सबको देखते हुए स्थिति संभालने के लिए भारत ने कई कदम उठाए गए। जीएसटी की दरें कम की गई और श्रम कानून में बदलाव लाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है कि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितिता की विकट परिस्थितियों में भी भारत की जीडीपी की दर विश्व में अव्वल दर्जे की बनी रही। खुदरा मंहगाई दर भी आठ साल में सबसे कम रही। अच्छी पैदावार, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कच्चे तेल की कम कीमत ने इस परिस्थिति में मदद की। शेयर बाजार में घरेलू निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बने। आयकर रिटर्न के दाखलों और कर-संग्रह में भी सुधार हुआ। कई देशों के साथ व्यापार समझौते भी किए जा रहे हैं। बिजली, शहरी विकास, खनन, और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में नई पहलें की गईं। भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और अनुमान है कि साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। आशा की जाती है कि आर्थिक उन्नति से आम जनों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। सामाजिक संरचना की दृष्टि से मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है जिससे खपत और शहरीकरण में वृद्धि और ग़रीबी में कमी के आसार बन रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचा विस्तृत और सुदृढ़ हो रहा है। खासतौर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई), अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रो और बुलेट ट्रेन आदि को लेकर प्रगति दर्ज हो रही है। मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप्स में भारी वृद्धि से रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र में प्रगति की संभावना दिख रही है और स्वदेशी विकास की नीति अपनाई जा रही है। अनुमान है कि 5-जी और रोबोटिक्स के उपयोग का दायरा विस्तृत होता जायेगा। व्यापारिक लेनदेन अधिकाधिक 'कैशलेस' होते जाएँगे। अब ऑनलाइन ख़रीददारी और ओटीटी प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भविष्य में एआई का प्रभुत्व और भी बढ़ेगा। उसी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण सरोकार बन रहा है। इन सबके साथ यह भी याद रखना जरूरी है कि देश का भविष्य सिर्फ आर्थिक उन्नति के सूचकों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास को केवल वृद्धि दर के अर्थ में ही नहीं, बल्कि रोजगार के अधिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता और आम जनों के जीवन-स्तर में उन्नति के संदर्भ में भी देखना होगा। जनसंख्या का विशाल आकार और सबके लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था को ज्ञान-केंद्रित और सामाजिक रूप से ज्यादा उत्तरदायी भी बनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अवसर भी है पर हम अपनी सीमाओं को भी नजरअंदाज़ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए युवा भारत को अक्सर एक पूंजी के रूप में घोषित किया जाता है पर इसके लिए कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होगा। कौशल विकास की कमी और युवाओं में बेरोज़गारी के चलते समाज में असंतोष पैदा हो रहा है। यद्यपि नई शिक्षा नीति के दस्तावेज में अनेक प्रावधान हैं पर उसकी विसंगतियों को दूर कर उनके कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। उपेक्षा और साधनों के अभाव में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट चिंताजनक है। शिक्षा की पहुँच, उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता को लेकर संशय बना हुआ है। इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। अभी भी महिला श्रम-भागीदारी निम्न दर पर है।

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरुरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन से टाइम में चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के चौघड़िया के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, यही हमारी ओर से शुभ मंगल कामना है।

तिथिः	पूर्णिमा 15:32 तक
नक्षत्रः	आर्द्रा 17:32 तक
पक्षः	शुक्ल
वारः	शनिवार
योगः	ऐन्द्र, 29:15 तक
सूर्योदयः	07:14
सूर्यास्तः	17:36
चंद्रमाः	मिथुन राशि में
राहुकालः	09:50-11:07
विक्रमी संवत्:	2082
शक सम्वतः	1947
मासः	पौष
शुभ मुहूर्तः	12:04-12:46

जन एक्सप्रेस

हो जीवन खुशहाल !

हो नववर्ष मंगलमय ।
मिले रोज उपहार ।।
सुख और समृद्धि ।
रहे आपके द्वार ।।
मनोकामना पूर्ण हो ।
हो जीवन खुशहाल ।।
प्रगति हर पल आपकी ।
करती रहे कमाल ।।
यश? और कीर्ति ।
खूब मचाए शोर ।।
बजे इसका डंका ।
और फैले चहुंओर ।।
समय और उर्जा का ।
है करना उपयोग ।।
आपके प्रशंसको का ।
मिले सदा सहयोग ।।

- कृष्णेन्द्र राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

नए साल पर चेहरे की चमक बढ़ने के लिए ऐसे बनाए होममेड ब्लीच

आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और ठीक से स्किन की देखभाल न करने के कारण बहुत से लोगों को स्किन पर डेड सेल्स के जमा होने, स्किन के टैन होने और स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में स्किन को नेचुरल रूप से ग्लोइंग बनाने और हेल्दी बनाए रखने के लिए घर पर हल्दी और बेसन जैसे औषधीय गुणों से युक्त चीजों से ब्लीच बनाया जा सकता है।

हल्दी और बेसन के ब्लीच के फायदे: आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. किरण गुप्ता के अनुसार, इस ब्लीच में नेचुरल चीजें होती हैं, जो स्किन को नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में सहायक हो सकती हैं, लेकिन इनसे किसी भी तरह की एलर्जी हो तो इसके इस्तेमाल से बचें।

स्किन को एक्सफोलिएट करे: इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करने और स्किन को नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद मिलती है। इससे डल स्किन की समस्या से राहत देने और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

इंफेक्शन से बचाव करे: इस ब्लीच में मौजूद हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियस के गुण होते हैं। ऐसे में इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से स्किन का इंफेक्शन से बचाव करने, सूजन को कम करने और स्किन को नेचुरली हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

स्किन को मॉइस्चराइज करे: इस ब्लीच में मौजूद शहद में भरपूर मात्रा में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से स्किन को अंदर से नमी देने, स्किन को हाइड्रेट करने और त्वचा में निखार लाने में मदद मिलती है।

स्किन को ग्लोइंग बनाए: इस ब्लीच में अच्छी मात्रा में विटामिन-सी होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से स्किन को नेचुरल रूप से ग्लोइंग बनाने, त्वचा की टैनिंग को कम करने, त्वचा में निखार लाने और त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने में मदद मिलती है।

सावधानियां: इस ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी चीज से परेशानी होने, एलर्जी होने या स्किन के सेंसिटिव होने पर इसका इस्तेमाल करने से बचें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करना फायदेमंद हो सकता है।

निष्कर्ष: हल्दी, बेसन, शहद, नींबू के रस, गुलाब जल और दही से बने इस नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल करने से स्किन को नेचुरल रूप से एक्सफोलिएट करने, स्किन का इंफेक्शन से बचाव करने, टैनिंग कम करे, स्किन को मॉइस्चराइज करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रहे, स्किन के सेंसिटिव होने या इससे किसी भी तरह की एलर्जी होने पर इसका इस्तेमाल करने से बचें। स्किन से जुड़ी अधिक समस्या महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

एक्सप्रेस विशेष

हिंदुओं और भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों में कैसे भरा जा रहा है जहर

पंकज जयसवाल

हर बार जब भारतीयों या हिंदुओं को नस्ली सफ़ाई या नरसंहार का शिकार बनाया जाता है, तो उनकी आसानी से उपलब्ध नफ़रत की कहानी उत्प्रेरक का काम करती है। हर बार जब ये हिंदू विरोधी नरसंहार और जातीय सफ़ाई होती है।

यह जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि दूसरों को भारत के खिलाफ़ निष्क्रिय या आक्रामक तरीके से लामबंद होने के लिए उकसाया जा सके, उन्हें भारत पर आक्रमण और भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ़ नस्ली सफ़ाई के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य भारतीयों को बड़े पैमाने पर और गंभीर रूप से नीचा दिखाना है, ठीक वैसे ही जैसे नाज़ी जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों में यहूदियों के साथ किया गया था।

श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किए जाने और विवेक रामास्वामी के 26 दिसंबर, 2024 को एक्स पर पोस्ट करने के बाद, जब वे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लीडर के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल में थे, तो प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी नफरत में काफी बढ़ोतरी देखी गई। जनवरी 2025 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने ङ्ग पर भारत विरोधी नस्लवाद पर एक रिपोर्ट जारी की। तब से, इस बात का कोई खास संकेत नहीं मिला है कि एक्स सहित सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पूर्वाग्रह कम हुआ है। इस रिपोर्ट में एक्स पर भारत विरोधी नस्लवाद के मौजूदा स्तर का विश्लेषण किया गया है। यह भारत विरोधी भावना में बढ़ोतरी का विश्लेषण करती है, भारत विरोधी नस्लवादी बातचीत में मुख्य विषयों और कहानियों को बताती है और उन पोस्ट और मुद्दों पर प्रकाश डालती है जिनका उल्लेखनीय प्रभाव और पहुंच रही है। एक्स पर 680 ज़्यादा एंगेजमेंट वाली भारत विरोधी नस्लवादी पोस्ट को 1 जुलाई से 7 सितंबर, 2025 के बीच 281.2 मिलियन व्यूज़ मिले। भारतीयों को हमलावर और नौकरी चोर बताने वाली कहानियों के साथ-साथ भारतीयों को देश से निकालने की मांगों वाली 474 पोस्ट (69.7%) और 111.8 मिलियन व्यूज़ मिले, जिससे इमिग्रेशन और निष्कासन से जुड़ी बातें एंगेजमेंट का मुख्य कारण बन गई। असंतोष और नौकरी चोरी की बातें मुख्य समूह में प्रमुख थीं, जोज़ेनोफ़ोबिया को आर्थिक असुरक्षा के साथ मिला रही थीं और भारतीयों पर वीज़ाप्रतिबंध, इनकार, निर्वासन और नागरिकता रद्द करने की मांगों को बढ़ा रही थीं। 121 पोस्ट (17.8%) में भारत विरोधी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें 74.3 मिलियन व्यूज़ मिले। 12 अगस्त को फ्लोरिडा में एक सिख ड्राइवर से जुड़े ट्रक दुर्घटना संबंधी 74 पोस्ट (10.9%) को 94.9 मिलियन व्यूज़ मिले, जिससे पता चलता है कि कैसे एक ही घटना का इस्तेमाल पूरे समुदाय को पेशे के आधार पर बलि का बकरा बनाकर बदनाम करने के लिए किया जाता है। अगस्त 2025 में गतिविधि चरम पर थी, जिसमें 381 पोस्ट और 189.9 मिलियन व्यूज़ थे। अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद और घटना-आधारित गुस्सा कहानियों में बढ़ोतरी के साथ मेल खाता था, जो दर्शाता है कि नीतिगत तनाव और ब्रेकिंग न्यूज़ नस्लवादी सामग्री को बढ़ाने वाले अनुमानित कारक के रूप में काम करते हैं। लगभग 65% पोस्ट यूएस पर केंद्रित थे, जिससे यह कन्फर्म होता है कि स्टडी के दौरान यूएस ही भारत विरोधी डिजिटल नस्लवाद का केंद्र था। असल में, वे भारत से नफ़रत नहीं करते बल्कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता और विकासशील देशों के प्रति पूर्वाग्रह है। यह उनके प्रभुत्व और भारत के अपनी पुरानी शान में लौटने के लिए खतरा पैदा करता है। पश्चिमी मीडिया और सत्ता संरचनाओं में कई लोगों के लिए भारत सिर्फ़ हिंसा, पूर्वाग्रह, गरीबी और सामाजिक अशांति का प्रतीक हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सोच वाले भारतीय बुद्धिजीवी भी ऐसे ही हैं। हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी नफ़रत कई अलग-अलग रूप ले सकती है, जानबूझकर और अनजाने में भी। उदाहरण के लिए, छठी कक्षा के छात्र को मूर्ति पूजक कहा जा सकता है और उसे अपनी क्लास से अलग-थलग महसूस कराया जा सकता है; एक दक्षिण एशियाई प्रोफेसर एक कॉलेज छात्र को हिंदू विरासत का छात्र होने के लिए निशाना बना सकता है और उसे शर्मिंदा कर सकता है; एक चुने हुए अधिकारी पर अमेरिका-भारत संबंधों पर उसकी स्थिति के कारण दोहरी वफ़ादारी का आरोप लगाया जा सकता है और उसके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा सकता है या एक हिंदू अमेरिकी को उसी कारण से नाज़ी समर्थक कहा जा सकता है। यह कोई आलोचना नहीं है। सैन्य स्टील्थ हथियारों की तरह, यह एक बेहद घातक, नरसंहार करने वाला मनोवैज्ञानिक हथियार है जो सबकुछ नष्ट कर देता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा ए0वी0बी0 रेप्रोग्राफिक्स, ए-59, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताल कटोरा, लखनऊ से मुद्रित तथा अय्यूब कॉम्पलेक्स, 82/68, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ पिन-226004, उ0प्र0 से प्रकाशित। संपादकः अरुण कुमार त्रिपाठी, (प्रबन्ध संपादक- मनोज तिवारी, सह-संपादकः इमरान खान, राज्य ब्यूरो प्रमुख- सन्तोष कुमार दीक्षित) आर.एन.आई. पंजीयन संख्या : UPHIN/2009/30003, फोन नं.: 0522-4330955 मोबाइल नं. 8933805555, **(नोटः सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।)**

वोट बैंक का लालच बना है पर्यावरण विनाश का कारण

योगेंद्र योगी

वोट बैंक का लालच सत्तारुढ़ दलों को इस कदर हाथ बांधे रखने के लिए मजबूर रखता है कि बेशक प्राकृतिक आपदाओं के विनाश से लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इसकी सरकारों को चिंता-परवाह नहीं है। लगता है उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है हर हाल में वोट बैंक को बनाए रखना। ऐसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति तब सामने आई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूकदर्शक की तरह बैठे रहे और अदालत ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवदेनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है। पिछले आठ वर्षों में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3,554 लोगों की जान गई, 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। मानसून का मौसम लगातार घातक साबित होता है, जिससे राज्य की पहले से ही नाजुक भूभाग पर हर साल एक नया घाव हो जाता है। बादल फटने से धारली में आई भीषण बाढ़ में 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। उत्तराखंड एक खतरनाक चक्र में फंस गया है। व्यापक और सक्रिय आपदा प्रबंधन के अभाव में, 'देवभूमि' (देवताओं की भूमि) प्रकृति के प्रकोप से लगातार क्षतिग्रस्त होती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों से हो रही देवदार के पेड़ों की कटाई ही उत्तरकाशी में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। देवदार के पेड़ों की जड़ें घनी होती हैं जो मिट्टी को बांधकर रखती हैं, कटाव को रोकती हैं और भारी बारिश या भूस्खलन के दौरान मलबे और पानी के बहाव को रोककर संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि यदि धराली में ऐतिहासिक देवदार के वन क्षेत्र बरकरार रहते, तो इस आपदा का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता, या शायद नगण्य ही हो जाता। एक समय उत्तराखंड के ऊंचे और हिमालयी क्षेत्र - विशेष रूप से समुद्र तल से 2,000 मीटर से ऊपर के इलाके - देवदार के घने जंगलों से आच्छादित थे। प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार के पेड़ पाए जाते थे। वन, जो प्राकृतिक ढलानों को स्थिर रखते हैं, उनकी कमी से जल निकासी बाधित होती है और पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है, जिससे आपदाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पेड़-पौधे मिट्टी को जकड़कर रखते हैं। जब पेड़ कटते हैं, तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भारी बारिश के दौरान आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और मलबा प्रवाह होता है, जैसा कि 2013 के केदारनाथ आपदा में देखा गया था।5 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई विनाशकारी आपदा ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमालयी राज्य की दीर्घकालिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था। इस त्रासदी में 66 लोग लापता हुए। पिछले एक दशक में राज्य में लगभग 18,464 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गई, जिनसे भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास कई बड़ी आपदाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1991 के उत्तरकाशी भूकंप में 768 लोगों की जान गई, उसके बाद 1998 के मालपा भूस्खलन (225 मौतें) और 1999 के चमोली भूकंप (100 मौतें) का नंबर आता है। साल 2013 की केदारनाथ बाढ़ सबसे विनाशकारी रही, जिसमें 5,700 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 2021 की रेनी आपदा में मरने वालों की संख्या में 206 रही। पिछले एक दशक में दर्ज की गई 18,464 घटनाओं में से चौंका देने वाली 12,758 घटनाएं भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण हुईं।भारत में 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण है, जो कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश और असम सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहाँ लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी मात्रा में वन भूमि अतिक्रमित है। जिससे वन, वन्यजीव और पर्यावरण को गंभीर खतरा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि पर सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और असम सबसे आगे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य भी महत्वपूर्ण अतिक्रमण वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13,056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत था। इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर और दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने वन अतिक्रमण से संबंधित आंकड़े और विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सरकारें पर्यावरण और वनों के विनाश को रोकने के लिए कितनी चिंतित हैं। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं है। कारण साफ है इससे वोट नहीं मिलते, उल्टे वन भूमि पर अतिक्रमियों को हटाने से वोट बैंक का नुकसान होता है। यही वजह है कि सभी दल ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसके बावजूद कि पर्यावरण बिगड़ने से होने वाली तबाही की कीमत देश को हर साल भारी जान-माल से चुकानी पड़ती है।

संपादकीय

रैगिंग शिक्षा व्यवस्था पर अभिशाप

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाने के सपनों के साथ किसी कालेज में दाखिला ले और वहां परिचय के नाम पर होने वाली प्रताड़ना की वजह से उसकी जान चली जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की रैगिंग के चलन पर पाबंदी है, लेकिन आज भी इसके बहाने अलग-अलग रूप में विद्यार्थियों को जानलेवा शक्ल में प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा के साथ रैगिंग का जैसा मामला सामने आया है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि किसी भी रूप में इस चलन का जारी रहना शिक्षा से लेकर समाज तक के कितने हित में है। साथ ही, तमाम सख्ती के बावजूद आज भी इस पर रोक क्यों नहीं लग सकी है? गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित एक कालेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर के विरुद्ध पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले के मुताबिक, बीते 18 सितंबर को पिटाई और प्रताड़ना की वजह से पीड़ित छात्रा की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।इस घटना में शर्मनाक यह भी है कि कालेज के जिस प्राध्यापक को उत्पीड़न की घटना को रोकना चाहिए था, वह खुद भी छात्रा को प्रताड़ित करने में शामिल हो गया। इस घटना में संस्थान भी कठघरे में है, क्योंकि वहां का प्रबंधन रैगिंग के नाम पर होने वाली ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा।हिमाचल प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी विद्यार्थी को रैगिंग की वजह से जानलेवा हद तक यातना दी गई। करीब डेढ़ दशक पहले राज्य में कांगड़ा के एक कालेज में मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र अमन काचरू के साथ वहीं के चार वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग के दौरान मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी।ऐसी कई घटनाओं के जैसे त्रासद नतीजे सामने आए, उससे एक व्यापक बहस खड़ी हुई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नवागंतुक विद्यार्थियों की रैगिंग को क्यों नहीं तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इसी क्रम में कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाए गए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी। यह समझना मुश्किल है कि कालेज में कुछ वरिष्ठ कहे जाने वाले विद्यार्थियों के भीतर नए विद्यार्थी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करने के मानसिक ढांचे के स्रोत क्या हैं! क्या इसके पीछे किसी नवागंतुक विद्यार्थी के मनोबल को तोड़ देने की मंशा काम करती है?आपसी परिचय या सहजता के नाम पर किसी विद्यार्थी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि वह उसके लिए जानलेवा साबित हो, क्या एक सामंती कुंठा का परिचायक नहीं है? अगर परिचय के नाम पर यातना देने के चलन को आपस में सहज होने के लिए सिर्फ मनोविनोद के रूप में देखा-जाना जाता है, तो क्या यह एक आपराधिक तरीका नहीं है, जिसमें कालेज में आए एक नए विद्यार्थी के मन पर गहरी चोट पहुंचती है, वह खुद को अपमानित महसूस करता है, उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है?

पश्चिम बंगाल: बीजेपी का जुनून ही शायद उसके पतन का कारण

शिखा मुखर्जी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2025 के आखिरी ढाई दिनों में कोलकाता के एक होटल में ठहरे रहे। यहां उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की कमान उनके ही हाथ में है। उन्होंने अपने चहेते विषय- घुसपैठियों को लेकर जमकर प्रचार किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनका संदेश तीखा और स्पष्ट था। बीजेपी को बंगाल की शहरी सीटों पर जीत हासिल करनी ही होगी और हिन्दुओं को यह बताना होगा कि मुस्लिम घुसपैठिये उनके और राज्य के लिए सभ्यतागत और अस्तित्वगत खतरा हैं। उन्होंने मतदाताओं को उतना ही सरल संदेश देने का प्रयास किया: बीजेपी सत्ता सौंपें और राज्य में होने वाले बदलाव को देखें। बांग्लादेश से आए हिंदू घुसपैठियों को उनका संदेश था: बीजेपी को अपना वोट दें और हम आपकी नागरिकता सुनिश्चित करेंगे। समझदार पर्यवेक्षकों के लिए दो बातें साफ हो गईं। पहली, शाह विभाजन से पहले पश्चिम बंगाल में मौजूद हिंदू बहुमत की तुलना में हिन्दू घुसपैठियों के सापेक्ष आकार और महत्व को समझने में विफल रहे। दूसरी, बीजेपी मटुआ समुदाय में फूट और संदेह से हिल गई है जो हाल तक पार्टी का एक सुरक्षित वोट बैंक था। दरअसल, 'घुसपैठिया' हिंदू मतदाता शाह की सोच से कहीं अधिक समझदार हैं। बीजेपी से उनका सवाल है कि इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हें बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे शरणार्थियों के रूप में मान्यता दी जाएगी, न कि घुसपैठियों के रूप में? ममता बनर्जी लगातार यही कहती रही हैं कि किसी भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने जिन जिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, वहां उसने शिविर आयोजित किए हैं। इसके बावजूद, लौटने वाले प्रवासी, शरणार्थी और मटुआ समुदाय के लोग, जिन्हें ईआरओ ने नोटिस भेजे हैं या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सुनवाई के लिए बुलाया है, बीजेपी के पार्टी कार्यालयों के बजाय स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में जाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। यह बात लोगों की नजरों से नहीं बची है।अवैध रूप से आए शरणार्थियों या वैध नागरिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो शाह के राजनीतिक व्यवस्था के शुद्धिकरण संबंधी बयान डरावने हैं। इनसे पश्चिम बंगाल के सांप्रदायिक और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की योजना का संकेत मिलता है। शाह के आश्वासन खोखले बयानबाजी ही लगते हैं, जिनका उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के 48 प्रतिशत और बीजेपी के 38.7 प्रतिशत के बीच के अंतर को कम करने के लिए मतदाताओं को लुभाना है।वोट और सुरक्षा के बीच संतुलन ही बीजेपी की लोकप्रियता का आधार है। बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया से जूझ रहे व्यक्तिगत मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रही है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है- एक तरफ तो उसने परेशान मतदाताओं को गहन समर्थन दिया है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के साथ तीखी बहस और टकराव का सहारा लिया है। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के बाद ज्ञानेश कुमार पर अभद्र, आक्रामक होने और उन पर उंगली उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अक्सर आपा खो बैठते थे और उन्होंने चुनाव आयोग को बैठक का वीडियो फुटेज जारी करने की चुनौती दी। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के अधिकारियों और सत्ताधारी दल पर अपना अविश्वास खुलकर जाहिर किया है।इस बीच, घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव, सभ्यतागत और सांस्कृतिक खतरे की मिली-जुली कहानी तेजी से एक खतरनाक विचारधारा का रूप ले रही है। कोलकाता में बांग्लादेश के राजनयिक कार्यालयों के बाहर हुई हिंसक रैलियों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक छोटे समूह को बांगियो हिन्दू जागरण मंच जैसे आरएसएस से जुड़े संगठनों का समर्थन प्राप्त था। शाह के निकट माने जाने वाले सुवेंदु अधिकारी ने तो यहां तक मांग कर दी कि भारत गाजा पर इसराइल जैसा हमला करे और बांग्लादेश पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा ताबड़तोड़ आक्रमण करे।इस तरह बीजेपी का नैरेटिव आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर आधारित है। 'हिन्दुओं पर खतरा' की धारणा को दोहराते हुए, वह राजनीतिक रूप से अस्थिर बांग्लादेश को एक शत्रु देश के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध हिंसा का सहारा लेकर स्वयं राज्य के विरुद्ध हिंसा को उचित ठहराया जाता है।बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व के एसआईआर प्रक्रिया पर स्वामित्व और राजनीतिक रुख के कारण पंगु हो गई है; साथ ही घुसपैठियों को लेकर उसकी सनक भी इसका एकतरफा जुनून है। <स2026स्द्बद्धछ्वक्ष्यष्द्धद्द जैसे मिश्रित हैशटैग वाले उसके केंद्रीय रूप से नियोजित अभियान उपहास का पात्र बनते हैं, क्योंकि बंगाली लोग यह बताते हैं कि सही बांग्ला वाक्यांश <स2026-द्द-क्वद्धक्क-ड्डह्यष्द्धद्द होता। भारत के अन्य हिस्सों में बंगाली मुसलमानों को 'बांग्लादेशी' कहकर निशाना बनाए जाने पर अमित शाह की चुप्पी भी स्थिति को और बिगाड़ रही है।

फिर आया मौसम झूम के चुनावों का

राकेश अचल

सावधान इस साल देश कोई विकास कार्य शायद ही कर पाए क्योंकि अघोषित रूप से वर्ष 2026 चुनावों का साल है. इस साल अप्रैल से चुनाव का साल शुरू हो जाएगा. सरकार आम बजट पेश करने के फौरन बाद चुनाव में उलझ जाएगी. आपको बता दूं कि साल 2026 में चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं. असम विधानसभा में 126 सीटें, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा की 30 सीटें है. इसके साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों की 75 राज्यसभा सीटें अप्रैल से लेकर जून और नवंबर 2025 खाली हो रही है, जिसमें यूपी की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने है. इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा चुनाव होने है.साल 2026 में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी है. मौजूदा विधायक के निधन से सीटें खाली हुई हैं. गोवा की पोंडा क्षेत्र, कर्नाटक का बागलकोट क्षेत्र और यूपी की घोसी सीट, महाराष्ट्र की राहुरी, मणिपुर की ताडुबी सीट और नागालैंड की कोरिडांग सीट पर चुनाव होने हैं. इसके अलावा कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लेकर यूपी तक शामिल है.महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव 2026 में होना है. चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव करने का लक्ष्य रखा है. हिंदी पट्टी के सबसे अहम सूबे यूपी में पंचायत चुनाव 2026 में होने है, जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है. ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों व अध्यक्षों के चुनाव होंगे.सबसे बडा और कडा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होगा. बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई, 2026 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते यहां पर निर्वाचन आयोग अप्रैल-मई 2026 में चुनाव करा सकता है. बंगाल में कुल 294 विधासनभा सीटें है. 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी तो बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी.बंगाल के बाद तमिलनाडु में चुनावी बिसात बिछेगी. तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है. तमिलनाडु में भी डीएमके के नेता स्टालिन की परीक्षा होनी है. यहाँ एआईएडीएमके अपनी वापसी के लिए बेताब है लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद मुकाबला किस करवट बैठेगा, कोई नहीं जानता.2021 के चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने राज्य की कुल 234 में से 133 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 18 सीटे जीती थीं . सूबे की सत्ता पर 10 सालों तक काबिज रही एआईएडीएमके महज 66 सीटें जीत पाई थी लेकिन यहा भाजपा को भी चार सीटें मिली थीं.इस बार के सियासी हालत बदल गए हैं. इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक में ही नहीं बल्कि तीसरा फ्रंट भी मैदान में है. तमिल एक्टर थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कज़गम बनाकर डीएमके बनाम एआईएडीएमके की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है. ऐसे में देखना है कि स्टालिन कैसे अपनी सत्ता बरकरार रखते हैं?वामपंथियों के इकलौते गढ केरल में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में केरल में अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने की संभावना है. केरल में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले वाम मोर्चा के सामने भी यूडीएफ चुनौती है. केरल में पिनराई विजयन अगर तीसरी बार सफल होते हैं तो रेकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन हार जाते हैं तो लेफ्ट का देश से सफाया हो जाएगा. ऐसे में वामपंथियों के लिए अपना आखिरी किला बचाए रखने की चुनौती है.केरल का चुनाव वमियों की अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के बीच है. 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी. इस बार कांग्रेस की कोशिश सत्ता में वापसी की है. प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं तो राहुल गांधी के खासुलखास माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल भी केरल से आते हैं. इस लिहाज से कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेताब है तो भाजपा की अपना सियासी जनाधार बढ़ाए रखने में जुटी है.भाजपा ने हाल ही में स्थनीय निकाय चुनाव में अपनाखाता खोला है.भाजपा शासित असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल भी 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है. असम में अप्रैल-मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. भाजपा 2016 से असम की सत्ता में है और लगातार दो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार सत्ता में आने क जुगत में है तो कांग्रेस की कोशिश अपने सियासी वनवास को खत्म करने की है.साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी थी. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा है. असम में एक तीसरा फ्रंट मुस्लिम सियासत के बदरुद्दीन अजमल का है.केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 15 जून, 2026 को खत्म हो रहा है. यहां पर मई-जून 2026 तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे. 2021 के पिछले चुनाव में ऑल-इंडिया एनआर कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन ने कुल 30 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी. एएनआरसी ने 10 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी इसके उलट कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी, यहां वर्तमान में एएनआरसी के संस्थापक एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं. इस बार भी मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच है. जाहिर है कि दक्षिण-पूर्व जीतने के लिए भाजपा, आर एस एस, पूरा कस बल लगाएंगे. प्रधानमंत्री भी चैन की सांफ नहीं ले पाएंगे. भाजपा के नये कार्यकारी अध्यक्ष को भी इन चुनावों में अपना कौशल दिखाना होगा. देशश का आम बजट भी इस बार जनोन्मुखी होने के बजाय चुनावोन्मुखी होगा.

धर्मशाला, रविवार, 4 जनवरी, 2026

दिव्य हिमाचल | divyahimachal.com

अपने अपने लोग

टिप्पणियां

राजनीतिक विडंबनाओं का यथार्थ

डा. हेमराज कौशिक
मो.-9418010646

पृथीपाल सिंह ने विभिन्न विधाओं में प्रयोजनमूलक सरस सृजन किया है। 'अपने अपने लोग' उनकी लघु कलेवर की कहानी है। यह कहानी अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था के अवमूल्यन के साथ उसकी आंतरिक संरचना के अधोपतन को भी रेखांकित करती है। सत्ता और प्रशासन की भ्रष्ट जुगलबंदी कहानीकार ने स्थूल ब्योरों से नहीं, सूक्ष्म पर्यवेक्षण से निरूपित की है। एक भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने धनबल पर बिना किसी राजनीतिक समझ और जन सेवा भाव के टिकट प्राप्त कर लोगों को गुमराह कर निर्वाचित होकर भ्रष्ट ठेकेदारों को लाभ पहुंचा कर गुप्त रूप से उनसे धनराशि ऐंठता है। उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती। एक्सीडेंट में घायल होने पर लोगों के मध्य जनसेवक होने का दिखावा करने के लिए उन ठेकेदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। लोकप्रियता अर्जित करने के लिए उन्हीं ठेकेदारों से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करवाता है। बिना किसी जनाधार और सेवा भाव के किस तरह से राजनीतिक पार्टियों में टिकटों का आवंटन धनबल पर होता है, उसको भी कहानी सामने लाती है। यह व्यंग्य मिश्रित शिल्प में ढली कहानी है। इसमें विधायक के चरित्र को भ्रष्टाचार में संलिप्त एक ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में उभारा है जिसका जनता के दुख दर्द की अपेक्षा अपने को धन संपन्न बनाना उद्देश्य होता है। भ्रष्ट नेताओं से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों तक के चरित्र को यह कहानी यथार्थ के धरातल पर निरूपित करती है। संदर्भित कहानी बिना किसी शिल्पगत चमत्कार के सहज-सरल भाषा शैली में तीव्र कटाक्ष और महीन बुनावट के साथ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का विकृत चेहरा अनावृत करती है।

राजनीतिक खेल दर्शाने वाली कहानी

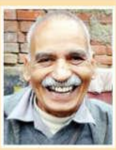

डा. गंगाराम राजी
मो.-9418001224

'**अपने** अपने लोग' पृथीपाल सिंह की आधुनिक राजनीतिक परिवेश पर लिखी कहानी है। वर्तमान समय में जो राजनीति में हो रहा है, उसका कच्चा चिट्ठा लेखक ने चरित्रों के आपसी संवादों के द्वारा खोल कर रख दिया है। कहानी का नायक एमएलए, एक सेवानिवृत्त अधिकारी अपने कार्यकाल में राजनीतिज्ञों की सेवा, बजट के दशांश की राशि के थैले दान करते करते फलस्वरूप विधायक के लिए पार्टी का टिकट प्राप्त कर विधायक बन जाता है। अपने अधिकारिक काल के समय के लेन-देन से भलीभांति परिचित होने के फलस्वरूप अपने ही आदमियों को सरकारी ठेका दिला कर अपना दशांश रेस्ट हाऊस में महंगी शराब के साथ प्राप्त करता है। महंगी गाड़ियों में सफर करते हुए भी जनता में अपना रोष, थकावट, काम का बोझ सांझा करने की औपचारिकता नहीं भूलता, ताकि जनता में उसकी मान मर्यादा बनी रहे। लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि कोई भी पार्टी राज करे, जनता का हक, पैसा सब मिल कर लूटते हैं। जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं, हल्की-फुल्की मदद करने का नाटक करते हुए, अपना नाम कमाते आए हैं। और दूसरी ओर राजनीतिज्ञों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला एक वर्ग ऐसा है, जो अपने काम में हमेशा सफल होता है, भले ही सरकार किसी भी दल की हो। असली माखन राजनीतिज्ञों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। लेखक यह राजनीतिक खेल दर्शाने में बखूबी सफल हुआ है।

राजनीतिज्ञों के किरदार का पोस्टमार्टम करती कहानी

डा. धर्मपाल साहिल
मो.-9876156964

यह कहानी एक अधिकारी से विधायक बने राजनीतिज्ञ द्वारा लोक सेवा के नाम पर अपने लोगों को ठेके/टेंडर दिलवाने और उसके बदले सरकारी खजाने की लूट मचाने का कच्चा चिट्ठा खोलती है। अधिकारी जो पहले ही विधायकों/मंत्रियों से उचित तालमेल रखने, उन्हें खुश रखने तथा पर्दे के पीछे की गतिविधियों से भलीभांति परिचित है और वह इस अनुभव का पूरा लाभ उठाता है। आम लोगों और खास लोगों से अलग मुलाकात करना, लग्जरी गाड़ी में सफर करके अपने इलाके की समस्याओं की आवाज उठाने को भी कष्टप्रद समझना और कथित अपने लोगों से मोटी माया हासिल करके मदिरा पार्टियों का आनंद उठाना, यह सब उसके किरदार की असलियत को प्रकट करता है। ठेकेदारों से शुक्राना वसूल करने गया विधायक किस प्रकार दुर्घटना में घायल लोगों की मिजाजपुर्सी के लिए अस्पताल में पहुंच कर एक पंथ दो काज करते हुए अवसर का पूरा फायदा उठाता है, इसका चित्रण लेखक ने बखूबी किया है। लघु और इकहरे कलेवर वाली यह कहानी बड़ी सहजता, सरलता और रोचकता से उस कटु सत्य का पर्दाफाश कर जाती है जिससे अक्सर आमजन अनभिज्ञ रहते हैं।

सृजन प्रक्रिया

यह कहानी तीन वर्ष पूर्व लिखी गई थी। एक प्रदेश के विधायक पर टेंडर आबंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ी अखबारी खबर ने इसकी प्रेरणा दी। उसी छोटे से समाचार-वृत्तांत से उपजी यह हास्य कथा सत्ता, स्वार्थ और आम जन की विडंबनाओं को हल्के व्यंग्य में उजागर करती है...

कहानी की तलाश में हिमाचल

यहां कहानी पलकें खोलकर मुस्कराना चाहती है। इसकी पाजेब में बजते घुंघरू, कई मौन-कई सन्नाटे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई घरौंदे, कई समाज और कई शिकवे-शिकायतों का हुजूम। कभी किसी दूब पर दूर से आती छटा, शब्दों को भावों में पिरोती हवा। एक स्पर्श कहीं दीप में बुझती बाती को सहला रहा, तो कहीं क्रंदन किसी महफिल के रोमांच में अनसुना रह गया। हिमाचल का कहानीकार, समाज के रंगमंच पर वर्षों से श्रम साधना करता हुआ, अभिव्यक्ति के नजराने पेश कर रहा। 'हिमाचली हिंदी कहानी - विकास यात्रा' की 106 किस्तों के बाद कहानी अपने श्रृंगार में सीधे पाठकों तक। हर कहानी की पृष्ठभूमि, उसकी संरचना, कथानक, विषय, पात्र, उद्देश्य, भाषा और शैली के साथ एक पूरा रचना संसार शिरकत कर रहा है। एक अपनापन या अपनों से रूठा मन, पहाड़ की गवाहियों में खड़े उदास मंजर या किसी झरने के पास प्यासी नदी का स्पंदन। जीवन की तलाश में कहानी का सफर कहां पहुंचा, इसी बिंदु पर विवेचन की परंपरा के हिमाचली हस्ताक्षर खोज कर ला रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र राजन। पेश है आज 31वीं किस्त :

कहानी

पृथीपाल सिंह
मो.-9418063303

'**अरे** कभी इस बैठक के लिए तो कभी उस बैठक के लिए यह जो बार-बार राजधानी जाना पड़ता है और फिर पार्टी के आदेश के मुताबिक वापिस अपने निर्वाचन क्षेत्र में आना पड़ता है, आजकल इसी ने ही जिंदगी का सुख-चैन बर्बाद करके रखा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब खुद तो हेलिकॉप्टर में सफर करते रहते हैं, पर हमारे जैसे एमएलए लोग सड़कों पर धक्के खा-खा कर परेशान होते रहते हैं। इससे तो नौकरी ही अच्छी थी, कम से कम उसमें यह सब झंझट तो नहीं थे। एक बार जिधर बैठ गए तो बैठ गए। रोज-रोज की भागदौड़ तो नहीं थी।'

'क्या बात करते हो जनाब! कहां नौकरी और कहां विधायकी। आप भी कमाल करते हैं, आपकी एक अवाज पर छत्तीस नौकरी वाले खड़े हो जाएं दरवाजे के बाहर।' 'वह तो है पर मैं सफर का आदी नहीं हूं। हालत खराब हो जाती है आते-जाते।' 'पर जनाब आपकी नई गाड़ी तो काफी आरामदायक है।' 'अरोड़ा जी क्या बात करते हैं आप भी...गाड़ी आरामदायक होने से सफर थोड़े ही कम हो जाता है।' 'वो बात तो है जनाब...यहां से राजधानी कोई चार सौ किलोमीटर दूर तो होगी ही।' 'हां...और मेरा निर्वाचन क्षेत्र तो यहां से भी बीस किलोमीटर आगे से शुरू होता है...और घर तो होगा कोई पचास किलोमीटर दूर।' 'पर चलो जनाब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं...आप के हलके को इसका फायदा तो मिलेगा ही...वहां की समस्याएं ऊपर तक पहुंचेंगी तो कोई हल भी निकलेगा। आपके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा।'

'अरे काहे का विकास महाजन साहब... सब कुछ अस्त-व्यस्त हो रखा है। न तो आप जैसे लोगों के साथ ढंग से मिलना हो पाता है और न ही इलाके की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है, इसकी पकड़ बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। अगर सिर पर न रहें तो अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और पता नहीं किस-किस के साथ सेटिंग होती रहती है उनकी। हमें बाईपास करके किस को ठेका दे रहे हैं, किस को सप्लाई मिल रही है सब उनके स्तर पर हमें बिना पूछे ही हो जाता है। हमारे लोग जो दिन-रात हमारा साथ देते हैं, वे तो खाली ही रह जाते हैं और मिठाई कोई और ही खा जाता है।' विधायक साहब वैसे तो पहली बार चुनाव जीते थे, पर अपने वरिष्ठ साथियों से बातचीत करके, उनकी सलाह लेकर वे राजनीति की आंतरिक बारीकियां और कलाकारियां बहुत जल्दी सीख रहे थे। राजनीति से पहले वे सरकारी अधिकारी थे जहां वे संविधान में दी हुई लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए नेताओं के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। अपने सेवाकाल में उनके साथ सद्भावनापूर्वक मिलजुलकर उन्होंने अपने पद के सदुपयोग से अपनी व उनकी धनरेखा को बलवान करने का कार्य काफी मन लगा कर किया था।

रिटायरमेंट के बाद उनकी योग्यता और उपयोगिता को देखते हुए सरकार उन्हें सेवाविस्तार देना चाहती थी, पर वे काफी सोच-विचार के बाद अपने गांव आ गए और सिर पर खड़े विधानसभा चुनावों में अपने राजनीतिक रिश्तों का फायदा उठाकर अपने लिए किसी तरह पार्टी के टिकट का जुगाड़ कर लिया। हालांकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को कम ही जानते पहचानते थे, पर पार्टी के नाम से और जमा किए हुए पैसे के बल पर तमाम अटकलों को झुठलाते हुए जैसे-तैसे चुनाव जीत गए। क्योंकि सरकारी सेवक के रूप में भी दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर लोगों से मिलने के उनके अपने उसूल हुआ करते थे, इसलिए विधायक बनकर भी उन्होंने अपने उन उसूलों को बरकरार रखा था।

अपनी और लोगों की सुविधा के लिए वे अपने क्षेत्र के आम लोगों से अपने घर पर दरबार-ए-आम में मिलते थे पर खास-खास लोगों से वह आते-जाते जिला मुख्यालय में स्थित विश्रामगृह के खास कमरे में ही मिलते थे, जिनमें से इक्का.दुक्का विभागों के अधिकारियों को छोड़कर ज्यादातर ठेकेदार और सप्लायर ही होते थे। आज अरोड़ा साहब और महाजन साहब को मिलने का समय मिला हुआ था। दोनों को पिछले सप्ताह ही करोड़ों के सड़क और पुल के निर्माण कार्य आवंटित हुए थे जिसका शुक्राना वे अपने-अपने कामों के आकार के अनुपात वाले पैक्टों में डालकर अदा करने आए थे।

'आज मेरा सुबह वहां से निकलने का कार्यक्रम किसी मीटिंग की वजह से पहले कैंसिल होने वाला था, पर बाद में मैंने सोचा कि आप लोगों को समय दिया है तो मीटिंग जल्दी निपटा कर चलो निकल ही चलते हैं। इसलिए पहुंचने में थोड़ी देर भी हो गई। यदि आप को मिलने का समय देकर भी न आता तो अच्छा नहीं लगना था। उसूल की बात है कि अगर किसी को समय दिया है तो मिलो जरूर।' 'जी जनाब !!! यह बात तो आपकी मानने वाली है कि जो वादा आप करते हैं उस से पलटते नहीं', अरोड़ा ने यह बोलते हुए सोचा कि आना कैसे नहीं था, पैकेट जो मिलने वाले थे। 'और किस्मत से टाईमिंग तो देखो, आप आए और एक्सीडेंट में घायल लोगों को लेकर एंबुलेंस भी उसी समय आ गई। आप ने अच्छा किया जो हॉस्पिटल का दौरा करके घायलों का हालचाल जान लिया। कल सभी अखबारों में आपकी फोटो के साथ खबर छपेगी कि आप अपने क्षेत्र के लोगों का कितना ध्यान रखते हो। यह आपका हॉस्पिटल में जाकर उनकी मदद करने का काम पब्लिक में एक पॉजिटिव मैसेज देगा।' महाजन साहब ने कुछ देर पहले हुई एक सड़क दुर्घटना को विधायक साहब की किस्मत से जोड़ते हुए इसे एक तरह से उनकी छवि चमकाने के लिए मिले हुए अवसर के रूप में दिखाते हुए कहा। थोड़ी देर पहले ढाकपुर गांव को जा रही एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड टैक्सी, शहर से बाहर निकलते ही एक तीखे मोड़ पर पलट गई थी जिसमें आठ-दस लोग घायल हो गए थे। गुजरती हुई एंबुलेंस देखकर पूछने पर विधायक साहब को पता चला कि वे लोग उसके अपने चुनाव क्षेत्र में पड़ने वाले गांव से हैं। वे सीधे महाजन और अरोड़ा को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गए और उनसे उनके इलाज और दवाई-कंबल का प्रबंध करवा कर कुछ पैसे भी दिलवा दिए।

'चलो अच्छा रहा कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। डॉक्टर बोल रहा था कि कल तक सब को डिस्चार्ज कर देंगे', उसने टेबल पर काजू-बादाम और सलाद के साथ-साथ शीशे के गिलास सजाते हुए चौकीदार को देखते हुए कहा, 'आज कोई खास प्रोग्राम लग रहा है आप लोगों का।' 'नहीं जनाब कुछ खास नहीं, आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला है तो सोचा कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसे भी लगे हाथ सेलिब्रेट कर लें।' एक बैग जितने आकार वाले लिफाफे का मुंह खोल कर उसमें पड़े हुए दो पैकेट दिखाते हुए अरोड़ा ने उसे विधायक साहब को सौंप दिया। इसी बीच महाजन ने पैरों में पड़े हुए एक शॉपिंग बैग में से कोई महंगी स्कॉच की बोतल निकाली और मेज पर रखे हुए उसे गिलासों की बगल में रख दिया।

'अगर आप इसी प्रकार इसी लगन से हमारे साथ जुड़े रहे तो सौभाग्य और आशीर्वाद सब मिलते रहेंगे, हाहाहा...', उसने सम्भालकर लिफाफे को पास ही पड़े बैग की जिप खोलकर अंदर धकेलते हुए एक ठहाका लगाते हुए कहा। 'उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र न करो जनाब, कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, आप आशीर्वाद देते रहो और हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हाहाहा..।' कमरा बनावटी ठहाकों से भर गया। 'सोडा लेंगे या पानी?' महाजन ने स्कॉच गिलासों में डालने के बाद बोतल का ढक्कन बंद करते हुए पूछा। 'पानी ही डालो। सोडा महंगी शराब का मजा खराब कर देता है।' विधायक ने यह बात दायें से बायें अपनी गर्दन घुमाते हुए मदिरा शास्त्र के किसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले किसी दार्शनिक की तरह कही। अचानक बेड के साथ वाले स्टूल पर चार्जिंग पर लगे हुए विधायक साहब के फोन की घंटी बज उठी। कमरे में ठहाकों की जगह अब रिंगटोन की आवाज ने ले ली थी।

'अरे इस वक्त किसका फोन आ गया। घर पर तो बात हो ही चुकी है मेरी, कहीं मुख्यमंत्री साहब ने कोई मीटिंग न रख दी हो और कल सुबह दोबारा राजधानी न भागना पड़ जाए।' बुदबुदाते हुए वह सोफे से उठकर फोन की ओर बढ़ने ही लगे थे कि इतने में अरोड़ा ने अपने पिछली तरफ जाकर फोन को चार्जर से अलग किया और लाकर उन्हें पकड़ा दिया। 'विधायक साहब का है, जानकीप्रसाद जी का।' 'अच्छा', उधर से चुपचाप एक मिनट तक बात सुनने के बाद विधायक के मुंह से यही पहला शब्द निकला। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट उभर आए थे। 'जनाब चुनाव के बाद क्या पक्ष और क्या विपक्ष। आखिर काम तो हमारा एक ही है, समाज सेवा, और इसके लिए आपका हलका या मेरा हलका या किसी और का भी हलका हो तो क्या फर्क पड़ता है। आखिर हमारा जिला और प्रदेश तो एक ही है न!!! प्रदेश क्या देश तो हमारा भारत ही है, हमारे पुरखों ने तो इससे भी बड़ी 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली बात कही है, अरे जनाब इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? आप भी हद करते हैं, आज मैं इधर था तो मैंने देख लिया, कल को आप होंगे मौके पर तो आप भी देखोगे ही, इग्नोर थोड़े करोगे, आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है, राजनीति अपनी जगह पर इंसानियत तो पहले है न, अरे ना ना जनाब, यह कैसी बात कर दी आपने, आप हमारे सीनियर हैं, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, आपके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमें इतनी तो समझ है कि पहाड़ पर सिर नहीं पटका जाता, अपना ही सिर फूटता है और पहाड़ का कुछ भी नहीं जाता। ठीक है जनाब, जय माता की।' काफी लंबी बात के बाद फोन कटा तो माथे पर उभर आईं पसीने की बूंदों को पोंछते हुए विधायक साहब ने फोन वापिस अरोड़ा के हवाले कर दिया।

'क्या हुआ जनाब? लग रहा था कि जानकीप्रसाद जी उखड़े हुए हैं', अरोड़ा ने उठकर फोन को दोबारा चार्जिंग पर लगाते हुए पूछा। 'यह ढाकपुर नाम का कोई गांव इस जानकीप्रसाद के चुनाव-क्षेत्र में भी पड़ता है क्या? बहुत नाराज हो रहा था, बोल रहा था कि उसके हलके के लोगों को कंबल पैसे बांट कर सत्ता पक्ष वाले उसके खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं? बड़ी मुश्किल से बात को सम्भाला मैंने, नहीं तो उसने हंगामा खड़ा कर देना था।' एक गहरी सांस लेने से पहले स्कॉच का गिलास एक घूंट में ही उसके हलक से नीचे उतर चुका था।

पुस्तक समीक्षा

पहाड़ी कविताओं का सुंदर काव्य संग्रह

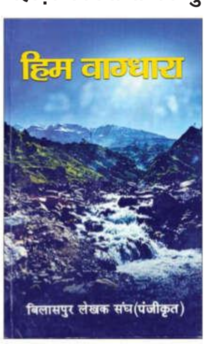

बिलासपुर लेखक संघ ने सांझा पहाड़ी काव्य संग्रह प्रकाशित किया है। हिम वाग्धारा नाम से निकला काव्य संग्रह पाठकों को पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। इसका संकलन रवींद्र कुमार शर्मा ने किया है। क्राउन पब्लिशिंग बिलासपुर से प्रकाशित इस काव्य संग्रह की कीमत 384 रुपए है। इस संग्रह में 35 साहित्यकारों की 145 रचनाएं हैं। डा. अनेक कुमार सांख्यान 'किसाना री जून ना पाई' में कहते हैं, 'गोरे-बग्गे बैलां री थी जोड़ियां/निक्के निक्के खेतरू ही पाहड़ियां/ना कमांदे खेता हुण अजके छोरू/पाई रे खिल्ले किस बाहणे डोहरू।' दुखिया नामक कविता में अनीता रानी कहती हैं, 'तिसदे अम्मा-बाबा भी रहदें थे बड़े ही दुखी/इक दिन सै दुखी होई ने जांदा अपणे के गुरू बल/गुरू बल जाइने बोलदा अनी मेरेगे नौकरी/ता रहंदा में बड़ा ही दुखी।' निक्का जेया फौजी कर्नल जसवंत सिंह चंदेल की कविता है। इसमें फौजी की पुकार सुनिए, 'खामखवाह मत मिंजो होरी बोलो/अऊं निक्का जेया इक फौजी आ/मिंजो खुसी मिलणी जे फौजी बोलो/खामखवाह मत मिंजो हीरो बोलो।' केशव शर्मा की कविता है 'असा हिमाचलियां जो बड़ा खरा लगदा'। इसका भाव देखिए, 'पहाड़ी गाणेयां पर सारेयां मिली कने नचणा/ब्याहां च पहाड़ी धामां रा स्वाद चखणा/अपणे भाईचारे कन्ने मिली के चलणा/असां हिमाचलियां जो बड़ा खरगा लगदा।' कविता सिसोदिया की कविता है बंदेया तू कजो हुआं दुखी। इसका भाव देखिए, 'मानस योनि तिजो मिलूरी/तिसारी तू कीमत जाण/गुजारा तेरा बंदेया चलूरा/पर बड्डा मुंह काजो बाकूरा/टबरा कने मौज मना/भगवाना रा नांव जपदा जा/तेरे लालचा रा ता अंत नी हुणा/तेरा आपणा अंत आई जाणा/फेरी ते बौहत पछताणा।' संग्रह की अन्य कविताओं में भी विविध भावों की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा साझा प्रयास प्रशंसा योग्य है।

-फीचर डेस्क

जयंती विशेष

मोहन राकेश : हिंदी नाटक को दी नई दिशा

मोहन राकेश (जन्म : 8 जनवरी 1925, मृत्यु : 3 जनवरी 1972) नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे। हिंदी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ, जब स्वाधीनता के बाद पचास के दशक में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार देश में जीवन के हर क्षेत्र को स्पन्दित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ नाटक का आस्वाद, तेवर और स्तर ही बदल दिया, बल्कि हिंदी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य काल में मोहन राकेश ने अपने लेखन से दूर होते हिंदी साहित्य को रंगमंच के करीब ला दिया और स्वयं को भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के समकक्ष खड़ा कर दिया।

मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत् में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। उन्होंने 'आषाढ़ का एक दिन' के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा। कहानीकार-उपन्यासकार प्रकाश मनु भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश को सर्वोपरि मानते हैं। प्रकाश मनु ने कहा 'नयी कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदली है। उस दौर में तीन नायक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव रहे। खुद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी राकेश को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर (पंजाब) में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साहित्य और संगीत के प्रेमी भी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। मोहन राकेश ने पहले लाहौर के ओरियंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की।

किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुझान लघु कहानियों की ओर हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। बाद में अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे।

अपनी साहित्यिक अभिरुचि के कारण मोहन राकेश का अध्यापन कार्य में मन नहीं लगा और एक वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का सम्पादन किया। इस कार्य को भी अपने लेखन में बाधा समझकर इससे किनारे कर लिया और जीवन के अंत तक स्वतंत्र लेखन ही इनके जीविकोपार्जन का साधन रहा।

मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुनकर उनका सार्थक सम्बन्ध खोज निकालना उनकी कहानियों की विषय-वस्तु थी। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटक दोबारा रंगमंच से जुड़े।

हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई लीक से हटकर नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। बीच में और भी कई नाम आते हैं, जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्त्वपूर्ण पड़ाव तय किए, किन्तु मोहन राकेश का लेखन एक अलग ही स्थान पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिलों को छूती हैं।

एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और बाकलमा खुदा हैं। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके कुछ मशहूर नाटक हैं। लहरों के राजहंस उनका सबसे विख्यात नाटक रहा।

मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। उन्होंने साहित्य में कई पुरस्कार प्राप्त किए। अब वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन साहित्य में हमेशा अमर रहेंगे।

किताबें मिली

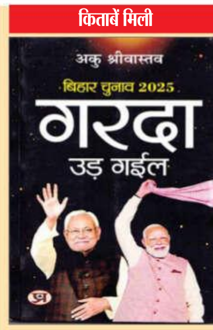

1. पुस्तक विशेष : बिहार चुनाव 2025 : गरदा उड़ गईल, लेखक : अकु श्रीवास्तव

2. कहानी संग्रह : चेन्ना माया, लेखक : शेर सिंह

समझें काल-संवेग को

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक, आईआईएम इंदौर

मैं अक्सर लोगों को कहता हुआ सुनता हूं: 'समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला'।

मुझे लगता है कि उनका प्रश्न वास्तव में इस अनुभूति से पूर्ण होता है कि वर्ष समाप्त हो जाता है, कोई रिश्ता बदल जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और पीछे मुड़कर देखने पर केवल यही अनुभव शेष रहता है कि घड़ी तो चलती रही, पर हम समय को जी नहीं पाए। यही प्रश्न धीरे-धीरे एक आध्यात्मिक विचार की ओर ले जाता है कि क्या समय केवल घड़ी और कैलेंडर की गति है, या उसके पीछे कोई ऐसी आंतरिक अनुभूति भी है, जिसे हर व्यक्ति अलग-अलग रूप में अनुभव करता है? इसी अनुभूति को काल-संवेग कहा जा सकता है, अर्थात समय को भीतर से महसूस करने की क्षमता, जहां समय केवल बीतता नहीं, बल्कि चेतना में आकार लेता है।

जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ मिनट घंटों जैसे भारी लगते हैं और कभी-कभी पूरे दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं। परीक्षा कक्ष में बैठा विद्यार्थी समय के हर सेकंड को महसूस करता है, जबकि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया गया समय कब समाप्त हो गया, यह पता ही नहीं चलता। यह अंतर बाहरी समय में नहीं, बल्कि भीतर की मनःस्थिति और चेतना में होता है। काल-संवेग वस्तुतः वही बिंदु है जहां मन, स्मृति और अनुभव मिलकर समय की अनुभूति का निर्माण करते हैं। जब मन अस्थिर, भयग्रस्त या अपेक्षाओं से भरा होता है, तब समय बोझ बन जाता है, और जब मन उपस्थित, सजग और तन्मय होता है, तब वही समय 'प्रवाह' बन जाता है।

आधुनिक जीवन में यह समस्या और भी बढ़ गई है। निरंतर बदलती सूचनाएं, त्वरित निर्णय, लक्ष्य-आधारित जीवन और भविष्य की चिंता ने समय को एक दौड़ में बदल दिया है। हम समय को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसे बचाने की योजनाएं बनाते हैं, पर उसे महसूस करना भूल जाते हैं। मनोविज्ञान भी मानता है कि समय की अनुभूति सीधे-सीधे हमारी ध्यान क्षमता और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति लगातार भविष्य या अतीत में जीता है, तब वर्तमान क्षण का काल-संवेग क्षीण हो जाता है। परिणामस्वरूप जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला बनकर रह जाता है, जिनके बीच कोई गहराई नहीं बचती।

भारतीय ज्ञान परंपरा में समय को केवल बाहरी शक्ति नहीं माना गया। उपनिषदों और दर्शन में काल को चेतना से जुड़ा हुआ तत्व समझा गया है। जब मनुष्य की चेतना स्थिर होती है, तब समय का अनुभव भी संतुलित हो जाता है। वास्तव में समय वही है, जो अनुभव के माध्यम से जाना जाए। इसका आशय यह है कि व्यक्ति का भीतर का अनुभव समय के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसी कारण ध्यान, साधना और आत्म-निरीक्षण को समय-बोध के परिष्कार का साधन माना गया।

प्रवाह

काल-संवेग का अभाव हमें लगातार अधीर बनाता है। हम चाहते हैं कि परिणाम तुरंत आएं, संबंध शीघ्र स्पष्ट हों और जीवन की उलझनें जल्द सुलझ जाएं। जब ऐसा नहीं होता, तो भीतर असंतोष जन्म लेता है। यह असंतोष वास्तव में समय के साथ संघर्ष का परिणाम है। जो व्यक्ति समय को शत्रु समझता है, वह हर क्षण स्वयं से भी लड़ता रहता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझने लगता है, वह धैर्य और संतुलन का विकास करता है। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि हर प्रक्रिया का अपना काल होता है और हर परिवर्तन अपना समय मांगता है। तनाव, अवसाद और मानसिक थकान का एक बड़ा कारण समय से जुड़ी असंतुलित अपेक्षाएं हैं। लोग लंबे समय तक कार्य करते हैं, पर उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि उनका समय सार्थक रूप से उपयोग हो रहा है। यही कारण है कि कई लोग बाहरी रूप से व्यस्त होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। काल-संवेग का विकास व्यक्ति को यह सिखाता है कि व्यस्तता और सार्थकता एक नहीं हैं। जब हम समय के साथ उपस्थित होते हैं, तब कम कार्य भी अधिक पूर्णता का अनुभव करा सकते हैं।

भारतीय ग्रंथों में कई प्रसंग मिलते हैं जहां समय की आंतरिक समझ निर्णायक भूमिका निभाती है। महाभारत में विदुर का चरित्र इसका सुंदर उदाहरण है। वे जानते थे कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब चेतावनी देनी है और कब प्रतीक्षा करनी है। उनका विवेक केवल ज्ञान का परिणाम नहीं था, बल्कि काल-संवेग की परिपक्वता का फल था। इसके विपरीत, दुर्योधन का पतन केवल नैतिक दोष का नहीं, बल्कि समय को न समझ पाने का भी परिणाम था। उसने हर क्षण अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया, पर समय के स्वभाव को नहीं समझा।

संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब हम समय से आगे भागना चाहते हैं या उसे रोकना चाहते हैं। जीवन की कई समस्याएं इसी संघर्ष से जन्म लेती हैं। समाधान तब मिलता है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि समय कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब समय का दबाव कम हो जाता है। निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और अनुभव अधिक गहरे। यही काल-संवेग की परिपक्व अवस्था है, जहां समय हमें चलाता नहीं, बल्कि हम समय के साथ चलते हैं।

नए वर्ष में हम सभी किसी न किसी प्रकार का संकल्प ले रहे हैं, किन्तु यदि इन संकल्पों में काल-संवेग की समझ न हो, तो वे केवल सूची बनकर रह जाएंगे। नया वर्ष वास्तव में नया तभी बनता है, जब हम समय को केवल बदलते अंकों के रूप में नहीं, बल्कि बदलती चेतना के रूप में देखें। यदि हम आने वाले दिनों में थोड़ा ठहरकर यह महसूस करना सीखें कि प्रत्येक क्षण हमें क्या सिखा रहा है, तो समय हमारे लिए बोझ नहीं, मार्गदर्शक बन सकता है।

तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर

हृदय नारायण दीक्षित
चिंतक-विश्लेषक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उप्र

भारतीय संस्कृति उत्सवधर्मा है। यहां बारहों महीने उत्सव चलते हैं। 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक ऋतु के अपने उत्सव हैं। वर्षा और बसंत प्रकृति प्रायोजित उत्सव हैं। शिशिर और हेमंत का क्या कहना। होली सनातन उल्लास है। व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र की भी ऊर्जा होती है। जैसे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही समाज और राष्ट्र को स्वस्थ रखने के प्रयास जरूरी हैं और यह प्रयास संस्कृतिधर्मा लोगों द्वारा किया जाता रहता है। उत्स का अर्थ होता है मूल। उत्सव का अर्थ है देश के मूल से जुड़ी सामाजिक सक्रियता।

संस्कृति मनुष्य की रचना है। संस्कृति का निर्माण सतत प्रवाही प्रक्रिया है। भारत के मन की संस्कारमय संस्कृति प्राचीन ज्ञान परंपरा में निहित है। भारत की संस्कृति का जन्म और विकास ज्ञान व दर्शन की परंपरा से हुआ है। भारतीय दर्शन में बुध और जैन को मिलाकर आठ दार्शनिक धाराएं हैं। भारत के राष्ट्रजीवन के सभी धाराओं ने प्रभावित किया है। कपिल का सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी माना जाता है। बुद्ध व जैन दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अद्वैत वेदांत का प्रभाव काफी बड़ा है। अद्वैत की धारा शंकराचार्य के पहले से थी, लेकिन शंकराचार्य ने उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र के तत्वों के आधार पर ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा है। वे घर बैठ तर्क का आनंद उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे।

शंकराचार्य ने देश की एकता को देखते हुए चार धामों की घोषणा की। उन्होंने उत्तर में ऊंचे पहाड़ों पर बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और पश्चिम में द्वारका की। पूरब में जगन्नाथ पुरी की और दक्षिण में रामेश्वरम की। चारों स्थान पहले बहुत प्रतिष्ठित नहीं थे, लेकिन शंकर की घोषणा के बाद वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गए।

भारत का मन उत्सवी है। भारतीयों की रुचि पर्यटन के बजाय तीर्थाटन में रही है। पर्यटन और तीर्थाटन में मूलभूत अंतर है। पर्यटन में अच्छा खाना, अच्छे होटल और अच्छी सुख सुविधाएं जरूरी होती हैं, लेकिन तीर्थाटन में इन कारकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती। तीर्थाटन में प्रायः किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जहां नदियां आपस में मिलती हैं। जहां प्रकृति खिलती है, जहां किसी न किसी देवता के दर्शन की अभिलाषा रहती है। प्रयागराज इसका जीवंत उदाहरण है। ऋषिकेश की गगनचुम्बी पहाड़ियों के दरश परश से मन संगीतमय हो जाता है। ऋग्वेद में नदियों से पर उतरने के लिए उथले स्थल को तीर्थ बताया गया है। जहां से हम आसानी से नदी पार कर सकते हैं। उपासना परंपरा में किसी देवता के नाम से चले आ रहे पुण्य स्थान तीर्थ कहलाते हैं। कुंभ (प्रयागराज) में सारी दुनिया के लोग आते हैं। करोड़ों लोगों का यह एकत्रीकरण गंगा, जमुना व सरस्वती का संगम बनता है।

प्रयागराज दुनिया का आकर्षण है। ऐसे ही हरिद्वार, रामेश्वरम, तिरुपति, कांचीपुरम आदि अनेक स्थलों पर तीर्थ यात्री भूखे प्यासे चले जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी ऐतिहासिक तीर्थ हैं। काशी में शिव दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। वैसे भारतीय दर्शन में तीर्थाटन की तुलना में दर्शन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को सत्य मानते हुए कर्मकांड को भी उचित बताया है। उन्होंने काशी के प्रवास में अपना दर्शन सबको बताया था। ब्रह्म को एकमात्र सत्य और संसार को मिथ्या बताने वाले आचार्य शंकर के दर्शन ने परवर्ती संतों का ध्यान भी आकर्षित किया था। शंकराचार्य जगत को मिथ्या बताते थे।

भारत स्वयं में एक तीर्थ है। सारी दुनिया को परिवार बताने वाला यह राष्ट्र शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। आवागमन के साधन बढ़े हैं। शंकराचार्य के समय न साइकिल थी न रेल। आश्चर्य है कि आचार्य ने कैसे भारत भ्रमण किया होगा? अब आवागमन के

द्रुतगामी साधन बढ़े हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी अल्प समय में तय की जा सकती है। आधुनिक सभ्यता के दबाव में देश के लोगों का एक वर्ग तनाव में रहता है। वह तीर्थाटन का मजा नहीं लेता। पर्यटन को महत्व देता है। पर्यटन से मानसिक शांति नहीं मिलती। तीर्थाटन से लौटे परिवार आनंद से भरे पूरे दिखाई पड़ते हैं। भारत राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मविश्वास से भरा पूरा है। पर्यटन उद्योग बन गया है। पर्यटन की दृष्टि से महात्मा गांधी के जन्म और कर्म स्थान साबरमती जाना अपने आप में जीवंत अनुभव है। सरदार पटेल की प्रतिमा केवड़िया, गुजरात में दर्शनीय है। डॉक्टर आम्बेडकर के दिल्ली सहित कई स्थानों पर बने स्मारक दर्शनीय हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणास्थल भी दर्शनीय है।

यज्ञ में काफी धन लगता था। इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ का विकल्प तीर्थ यात्रा बताया गया है। महाभारत वन पर्व के 42वें अध्याय में यज्ञ के विकल्प की चर्चा की गई है। पुलस्त्य भीष्म से कहते हैं कि, "ऋषियों के अनुसार यज्ञ करने से इस लोक और परलोक में फल मिलता है। परंतु गरीब मनुष्य यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते। उनके पास साधन नहीं होते। इसलिए जो साधनहीन हैं, वे तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा को यज्ञ के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, "मनुष्य तीर्थ यात्रा से जो फल पाता है वह बड़े से बड़े यज्ञों से नहीं मिलता।"

महाभारत के रचनाकाल में ज्यादातर तीर्थ कुरुक्षेत्र के आसपास थे। पुष्कर तीर्थ का महत्व बताते हुए कहते हैं, "पुष्कर में दस सहस्त्र कोटि तीथर्झं का निवास रहता है।" यहां पुष्कर तीर्थ का महत्व बताने कि लिए दस खरब तीर्थों की उपस्थिति बताई गई है। बताते हैं कि पुष्कर में ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। यहां स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का दस गुना फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है।

महाकाल (उज्जैन) में शिव के दर्शन से हजार गोदान का फल मिलता है। ऐसी बहस बहुत सी नदियां हैं, जिनमें स्नान करने से यज्ञ के फल मिलते हैं। नर्मदा सहित अनेक नदियों में स्नान से यज्ञों के फल मिलते हैं। महाभारत के रचनाकाल में सरस्वती पर्याप्त जल से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये बाद में सूखीं। सिंधु और सागर के मिलन स्थल पर स्नान करने से वरुण लोक मिलता है। सरस्वती ऋग्वेद के ऋषियों की प्रिय नदीतमा हैं। पुलस्त्य कहते हैं कि वायु द्वारा उड़ा कर लाई गई कुरुक्षेत्र की धूल से मनुष्य को परम गति मिल जाती है। जो यहां नहीं रहते कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा करें। तीर्थ की प्रशंसा मजेदार है। बताते हैं भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र तीर्थ है।

देवी उपासना भारत में वैदिक काल से स्पष्ट दिखाई देती है। ऋग्वेद में जल माताएं हैं। वन देवी हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल देवी उपासना का महत्वपूर्ण केन्द्र है। मध्य प्रदेश का दतिया अ©र असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शनार्थ पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। तीर्थाटन से मिलने वाले लाभ व हानि पर आग्रही बहस चलना जरूरी नहीं है। मुख्य बात है देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भारत भक्तों का आवागमन। शंकराचार्य ने इसीलिए चारों धामों की स्थापना की थी। प्रत्येक तीर्थ के साथ अविश्वसनीय कथाएं चलती हैं। इन्हें बड़े सरल ढंग से अंधविश्वास कहा जा सकता है। लेकिन पर्यटन का विकल्प तीर्थाटन ही है।

संघ का उद्देश्य : संपूर्ण हिन्दू समाज को एकजुट कर, भारत को परमवैभव पर पहुँचाने के संकल्प से जन्मा है संघ

किसी की प्रतिक्रिया या विरोध में शुरू नहीं हुआ संघ

डॉ. लोकेन्द्र सिंह
समीक्षक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करने पर बहुत रोचक और आश्चर्यजनक बातें सामने आती हैं। संघ को लेकर जितने प्रकार के नैरेटिव समाज में चलते हैं, उनमें से ज्यादातर संघ विरोधियों ने फैलाए हैं। यानी जो संघ को जानते नहीं है, मानते नहीं हैं, उन्होंने समाज को बताने का प्रयास किया कि संघ क्या है और कैसा है। अनेक अवसरों पर संघ के हितैषी भी संघ की वास्तविक प्रतिमा समाज के सामने रखने में चूके हैं। शताब्दी वर्ष के प्रसंग को निमित्त मानकर संघ ने तय किया है कि समाज के सामने संघ को संघ के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए। संघ के बारे में वास्तविक और अधिकृत जानकारी रखी जाए, ताकि समाज पर छाए भ्रम के बादल कुछ हद तक छंट जाएं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक एवं सरकार्यवाह के प्रवास देशभर में हो रहे हैं। देश के चार प्रमुख केंद्रों- दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता और मुम्बई में तो सरसंघचालक जी की विशेष व्याख्यानमालाएं हो रही हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उनका संवाद हो रहा है। इसी क्रम में 2-3 जनवरी, 2026 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी का प्रवास हुआ। इस अवसर पर वे चार कार्यक्रमों- युवा संवाद, प्रमुख जन गोष्ठी, सामाजिक सद्भाव बैठक और शक्ति संवाद में सम्मिलित हुए। अपने इस प्रवास में उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य समाज के सामने रखे, जो निश्चित ही संघ के बारे में देखने का नया नजरिया देते हैं।

संघ विरोधियों ने एक भ्रम पैदा किया कि संघ प्रतिक्रियावादी संगठन है। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संघ किसी की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ संगठन नहीं है। संघ की किसी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। संघ का जन्म क्यों हुआ? उन्होंने बताया कि संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने देश-समाज के हित में चलने वाले सभी प्रकार के कार्यों में सहभागिता की। क्रांतिकारी संगठन में शामिल हुए। क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब योजनापूर्वक कोलकाता पढ़ने गए क्योंकि उस समय कोलकाता क्रांतिकारियों का गढ़ था। वहाँ से लौटकर उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों का अनुभव भी लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। यह सब काम करते हुए वे भारत की स्थितियों को लेकर चिंतन-मंथन करते थे।

बालगंगाधर तिलक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित उस समय के कई महापुरुषों के साथ देश की परिस्थितियों को लेकर उनकी चर्चा हुई है। उनको ध्यान आया कि बाहर से आने वाले मुट्ठीभर लोग, जो हमसे कमतर हैं, इसके बाद भी हमको, हमारे घर मे आकर ही पराजित कर देते हैं। हम स्वतंत्र होने ही वाले हैं लेकिन फिर से पराधीन नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने भारतीय समाज की नब्ज को पकड़ा। हजार वर्षों के संघर्ष के कारण भारतीय समाज मानसिक दासता का शिकार हो गया था। जब तक भारत के मूल समाज को आत्मदैन्य की स्थिति से बाहर निकालकर उसके मन में आत्मगौरव का भाव नहीं जगाएंगे, तब तक हम कमजोर ही रहेंगे। स्वाधीनता को सुनिश्चित और स्थायी करने के लिए समाज को 'स्व' का बोध कराना आवश्यक होगा। भारत के भाग्य को बदलना है तो इस समाज को ठीक करना होगा। यह सब विचार करके ही डॉ. हेडगेवार ने तय किया कि समाज में एकता और गुणवत्ता स्थापित करने के लिए संघ का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उन्होंने संघ की घोषणा करने के बाद कई प्रयोग किए। लगभग 14 वर्ष कार्य के बाद संघ की विशिष्ट कार्य पद्धति विकसित हुई। इस कार्यपद्धति में किसी का विरोध और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं अपितु स्वाभाविक रूप से हिन्दू समाज के स्वाभिमान को जगाने का अभ्यास है।

संघ के स्वयंसेवक जो प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं अपितु सबके कल्याण की बात है। संघ भारत के उस विचार को जीता है, जो विश्व को परिवार मानकर सबके हित की चिंता करता है। संघ अपने जन्म से ही एक लक्ष्य लेकर चल रहा है कि संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन कर, अपने धर्म-संस्कृति का संरक्षण कर, अपने भारत को परम वैभव पर लेकर जाना है। संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक यह प्रतिज्ञा करता है।

संघ इसलिए भी प्रतिक्रियावादी संगठन नहीं हो सकता क्योंकि यह समाज में अपनी अलग पहचान नहीं देखता है। सरसंघचालक डॉ. भागवत जी ने इस संदर्भ में कहा कि संघ ने प्रारंभ से तय किया कि हमें समाज में 'दबाव समूह' के तौर पर संगठन खड़ा नहीं करना है। अपितु सम्पूर्ण हिन्दू समाज का ही संगठन करना है। कहने का अर्थ है कि संघ, समाज में अलग से संगठन के तौर पर अपनी पहचान नहीं चाहता है। याद रखें कि जो संस्थाएं या संगठन किसी प्रतिक्रिया में शुरू होते हैं, वे अपनी पहचान भी चाहते हैं और समाज में दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं। सरसंघचालक जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि किसी देश के भाग्य का निर्धारण वहाँ के नेता, नीति, सरकार, अवतार तय नहीं कर सकते। देश को बड़ा बनाने का काम तो वहाँ का गुण सम्पन्न समाज ही करता है। नेता, नीति और सरकार तो इस कार्य में सहायक भर हो सकते हैं। यदि समाज योग्य नहीं है, तब वह अच्छे नेताओं का भी उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए समाज को गुण सम्पन्न बनाना सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। संघ, शाखा के माध्यम से ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा करने का काम कर रहा है, जो इस प्रकार का समाज बनाएंगे। संघ की 100 वर्षों की यात्रा को देखें तो यह व्यक्ति निर्माण से समाज और राष्ट्र निर्माण का स्वाभाविक आंदोलन है।

यूं ही बीत रहा है साल-दर-साल ?

गुरु मंत्र

नागेश्वर सोनकेशरी

नया साल 2026 आ चुका है और पुराना अब जैसे बीती बात । यह जीवन यूँ ही चलता रहता है साल-दर-साल । जीवन के इस रंगमंच में हमें अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है ।क्योंकि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है ।किसी को खूब पैसे कमाने हैं, किसी को खूब नाम कमाना है , किसी को जीवन में कुछ सार्थक करना है , कोई परमात्मा की भक्ति से लेकर सत्य को जानने की राह में चल पड़ता है ।जीवन एक खाली कैनवास है और हम ही वह चित्रकार हैं, जो इसे रंगों से भर सकते हैं।

हम अपने सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं और अपने डर को गले लगाकर उसे ताकत में बदलने की कोशिश कर सकते हैं ।

इस नए साल में एक कोशिश कीजिए-वह यह है कि खुद से पूछिए कि 2025 में मैंने ऐसा क्या किया जो मैं फिर 2026 में दोहराना चाहूँगा ।सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करिए, जिन्होंने आपके जीवन को अर्थ दिया हो ।कोई बड़ा काम जिससे आपको संतुष्टि मिली हो, कोई छोटी सी बात जो बड़ी बन गई हो, कोई कठिन अनुभव जिसने सीख दी हो ।दुःख और पीड़ा का रोना मत रोइए, इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन इससे भागने की जरूरत नहीं है ।पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी गुरू है ।हर दुख, असफलता, हमें कुछ सिखाती है । बल्कि जीवन में जब भी दुख आता है, तब वह एक तरह से व्यक्ति को मांजता है और आगे के जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिये तैयार करता है ।दुख की अपेक्षा कोई नहीं करता लेकिन सुख का आनंद भी इससे गुजरने के बाद आता है ।

जब जीवन नीचे गिराए, तो उठ कर और मुस्कुराकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का आनंद अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं ।प्रेम वह नहीं ,जो हमें कमजोर बनाए ।सच्चा प्रेम वह है, जो हमें और मजबूत बनाए, जो हमें हमारे असली स्वरूप को खोजने में मदद करे। हमें तो अपने रिश्तों में ईमानदार रहना है और बस उन लोगों को चुनना है जो हमें ऊपर उठाएँ न कि नीचे खींचें ।हमें अपने कर्मों को इतना बड़ा करना चाहिए कि वे समय की सीमाओं को पार करें । हमारा हर कदम ,मेहनत, सपना हमें अमर बना सकता है ।अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी कहानी दुनिया को प्रेरणा दे। अपने भीतर दया,करुणा और प्रेम मानवता के तीन महत्वपूर्ण पहलू को अवश्य शामिल करें , जो हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं ।ये बातें आज इसिलिए कि हम 2026 को अपने जीवन का यादगार वर्ष या एक सार्थक जीवन की नींव का वर्ष बना सकें ।

जीवन एक चुनौती है, एक अवसर भी है और सबसे बढ़कर, एक उपहार है । किसी भी स्थिति में इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए । अपने भीतर जीने की आग को जलाए रखकर अपने तरीके से जीने की हिम्मत करने और अपने सपनों को सच करने की कोशिश, करने की जरूरत है ।अगर हमारे भीतर एक सुखी, सफल और सार्थक जीवन जीने की भूख है, तो इस वर्ष को पिछले वर्ष की तरह बेकार न जानें दें ।उठें और पूरे साहस के साथ सार्थक जीवन जीने की ओर चल पड़ें ।

संतश्री सिद्ध भाऊजी : एक ही नाम सारे धाम

शिक्षा ही कालांतर में बालक को सामर्थ्यवान बनाती है

विजय जोशी
पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक, भेल

भारतीय दर्शन में चार के अंक का बड़ा महत्व है। फिर चाहे वह हों चार दिशाएं, गृहस्थ आश्रम, वेद या सतयुग से कलियुग तक के चार कालखंड। शंकराचार्य ने भी वर्षों पूर्व चार धाम की स्थापना की जहां की यात्रा कर आम हिन्दू अपने जीवन को धन्य कर लेता है।

ऐसे में यदि किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार हो जाए जिनके साथ सत्संग में चारों धाम का पुण्य समाया हो तो बात कितनी अद्भुत हो जाती है। तो आइए एक विहंगावलोकन संतश्री सिद्ध भाऊजी के चौमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व का।

स्वाध्याय : मानस की शुद्धि हेतु स्वाध्याय की महिमा सर्वविदित है। महात्मा गांधी भी स्वाध्याय के सबसे बड़े सूत्रधार थे : जीयो ऐसे जैसे कल मर जाना हो और सीखो ऐसे जैसे आजीवन रहना हो। स्वाध्याय के प्रति भाऊजी की अभिरुचि स्वतः परिलक्षित होती है। अध्ययन परंपरा के पुनर्जीवन हेतु आप भेंट में शिक्षाप्रद पुस्तकों का चयन खुद करते हैं ताकि यह संदेश समाज में पहुंच सके।

सेवा : सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर केवल वह जो अहंकाररहित हो। सेवा का मन में भाव होना चाहिये। सेवा धर्म सरल

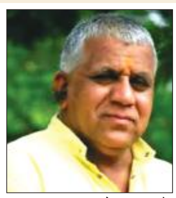

भी नहीं। भगवान राम ने खुद कहा है : सेवा धरमु कठिन मैं जाना। इस पैमाने पर संत सिद्ध भाऊजी सेवा के साक्षात अवतार हैं। सुबह से रात्रि के अंतिम पहर तक आप उन्हें स्वार्थ सेवा में व्यस्त पाएंगे। न चेहरे पर कोई थकान या तनाव और न ही मन में कोई गुरूर :

परहित सरिस धरम नहीं भाई
पर पीड़ा सम नहीं अघमाई

संस्कार : यह विरासत से प्राप्त वह थाती है जिसका बेटन पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सौंप कर अपने जीवन का सुखद समापन करती है। इसमें गृहण करने योग्य समस्त सूत्र सम्मिलित हैं। ये बालक के जीवन की इमारत में सुदृढ़ नींव का काम करते हैं। इस सत्य को संतजी ने स्वयं के आचरण में अंगीकार करते हुए ट्रस्ट सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित करते हुए उन्हें संस्कारधानी में परिवर्तित कर दिया। अध्ययनरत बच्चों तथा बालिकाओं को चरित्रवान बनाते हुए समाज सेवा के पुनीत यज्ञ का सहभागी बनाया है। उसी तरह जैसे राजा राम भोर में उठते ही :

प्रातःकाल उठि के रघुनाथा
गुरु पितु मातु नावहिं माथा
आयसु मागि करहिं पुर काजा
देखि चरित हरषइ मन राजा

शिक्षा : शिक्षा ही कालांतर में बालक को सामर्थ्यवान बनाती है। हिरदाराम ट्रस्ट में इस ध्येय कार्य संपन्न हो पाने का श्रेय आप ही को जाता है। आप जानते हैं कि बालिकाओं के जीवन के सफल संचालन की ठोस नींव तैयार करके ही समाज व देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

यूं तो पत्थर की भी तकदीर
बदल सकती है
शर्त सिर्फ ये है कि सलीके
से संवारा जाए

उपरोक्त एक छोटी सी बानगी है माननीय भाऊजी के विनम्र योगदान की। लिखने बैठें तो एक लंबी फेहरिस्त बनती चली जाएगी तकनीकी कौशल, प्राकृतिक चिकित्सा, आरोग्य केन्द्र, निशुल्क शिक्षा से लेकर नेत्र दान आदि तक। शब्द भी एक सीमा तक ही सक्षम हैं। कुछ व्यक्तित्व शब्दों की सीमा से भी परे होते हैं। सो आपको कुछ यूं बयां किया जा सकता है :

U सभी चार दिन की है चांदनी, ये तिजारतें, ये वज़ारतें
U मुझे उस फ़क़ीर की शान दे कि जिसकी जमाना मिसाल दे

लुई ब्रेल : दृष्टि बाधित लोगों के मसीहा

योगेश कुमार गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

ब्रेल लिपि नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों और दृष्टि विकलांग लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की स्पर्शनीय प्रणाली है, जिसकी खोज 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपवरे में जन्मे लुई ब्रेल ने महज 15 वर्ष की आयु में की थी। संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में विश्वभर में जागरूकता फैलाने, दृष्टि-बाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिवस को 'विश्व ब्रेल दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेन्शन' में ब्रेल लिपि को संचार के एक साधन के रूप में उद्धृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 'यूनेस्को' ने वर्ष 1949 में ब्रेल लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समस्याओं पर ध्यान देने वाला एक सर्वेक्षण आगे बढ़ाने की पहल की थी। लुई ब्रेल ने केवल तीन साल की उम्र में ही एक दुर्घटना के कारण अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखें संक्रमित होने के कारण उनकी आंखों की दृष्टि पूरी तरह चली गई थी लेकिन दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि छात्रवृत्ति पर 'रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ' चले गए। 1821 में फ्रांसीसी सेना के एक कैप्टन चार्ल्स बार्बियर लुई ब्रेल के स्कूल के दौरे पर आए थे, जिन्होंने सेना के लिए एक विशेष क्रिप्टोग्राफी लिपि का विकास किया था, जिसकी मदद से सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते हैं। चार्ल्स ने स्कूल में बच्चों के साथ 'नाइट राइटिंग' नामक यही तकनीक साझा की, जिसका उपयोग सैनिक दुश्मनों से बचने के लिए किया करते थे। इसके तहत वे उभरे हुए बिन्दुओं में गुप्त संदेशों का आदान-प्रदान करते थे किन्तु उनका यह कोड बहुत जटिल था। इसीलिए ब्रेल ने इसी आइडिया के आधार पर अपनी लिपि पर कार्य शुरू किया और 'रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ' में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने 1824 में अपनी लिपि को तैयार कर लिया, जो काफी सरल थी। इसी लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया और सरल लिपि की खोज के बाद दुनियाभर में नेत्रहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन लोगों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो गई। अपने इसी आविष्कार के कारण लुई ब्रेल दुनियाभर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए मसीहा बन गए।

विश्व ब्रेल दिवस

धार्मिक पर्यटन में इजाफा

भारत तीर्थ यात्राओं का देश माना जाता है। यहां तक कि इसकी भौगोलिक सीमाएं तय करने में भी भारतीय उपमहाद्वीप में बसे हिन्दू तीर्थ स्थलों का विशेष योगदान माना जाता है। हिन्दू धर्म के अलावा भारत सिख, जैन व बौद्ध धर्मों का भी जन्मस्थल है अतः इन धर्मों से जुड़े तीर्थ स्थलों की भी भारत के निर्माण में विशेष भूमिका है। इनके अलावा इस देश में मुस्लिम व इसाई समुदाय के लोग भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं अतः इन धर्मों के अनुयायियों के भी कुछ तीर्थ स्थलों का इस देश में निर्माण व विकास हुआ है, परन्तु जहां तक हिन्दू धर्म स्थलों का प्रश्न है तो पूरे विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इस धर्म के तीर्थस्थल भारत के हर प्रदेश व अंचल तक में भरे पड़े हैं। इन तीर्थ स्थलों पर प्रत्येक वर्ष विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर हिन्दू तीर्थ यात्रा करके पुण्य लाभ कमाते हैं। पिछले एक दशक से भारत में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जबर्दस्त इजाफा हुआ है और इन स्थलों पर हर वर्ष लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या इसका कारण यह है कि भारत के लोग ज्यादा धार्मिक हो गये हैं? इसका उत्तर हमें आसानी से इस पहेली में मिल सकता है कि पहले हिन्दू तीर्थ स्थलों के सर्वांगीण विकास की तरफ सरकारों का ध्यान नहीं था और इनमें सामुदायिक सुविधाओं की व्यापक कमी पाई जाती थी, मगर पिछले दो दशकों से इस तरफ सरकारों के साथ ही बाजार की वाणिज्यिक शक्तियों ने भी ध्यान देना शुरू किया और धार्मिक पर्यटन को व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला जरिया भी माना। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाओं की तलाश की गई, परन्तु यह सारा कार्य सरकार के सहयोग से ही संभव हो सकता था। अतः केन्द्र की सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की ठोस नीति बनानी शुरू की और इसके संस्कृति व पर्यटन मन्त्रालय ने इस तरफ कारगर पहल की, मगर इससे भी जरूरी काम यह था कि हिन्दू धार्मिक स्थलों का प्रबन्धन सुधरे। इस तरफ 90 के दशक में उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को सुगम व सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें सरकार व नागरिकों की भागीदारी तय करके यह सुनिश्चित किया गया कि इस क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा कम से कम कष्टकारक हो और मन्दिर की व्यवस्था भी पारदर्शी बनी रहे। यह कार्य स्वर्गीय जगमोहन के जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहते हुआ। उत्तर भारत में सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक असर हुआ और प्रतिवर्ष वैष्णो देवी यात्रियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने लगी, हालांकि दक्षिण के राज्यों के तीर्थ स्थलों व प्रसिद्ध मन्दिरों के प्रबन्धन में वहां की राज्य सरकारों की भागीदारी पहले से ही चली आ रही थी, मगर उत्तर भारत में स्व. जगमोहन ने यह सफल प्रयोग किया था। मोदी सरकार के केन्द्र में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया गया कि धार्मिक स्थलों को रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई और तीर्थ स्थलों पर सामुदायिक व वाणिज्यिक सेवाएं सुधारने के प्रयास किये गये। संस्कृति व पर्यटन मन्त्रालय ने सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों व मन्दिरों के विकास के लिए योजनाओं का खाका खींचना शुरू किया और सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी अपेक्षित सहयोग मांगा। केन्द्र ने हिन्दू, बौद्ध, सिख व जैन धर्मों की तीर्थों को जोड़ने वाले सर्किलों का विकास करना शुरू किया और इनके सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के बनारस में तो भगवान विश्वनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर परिसर का नवोचार किया गया और यहां विश्वनाथ कारीडोर बनाया गया जिससे इस तीर्थ स्थल पर पहुंचने वाले यात्रियों को भगवान के दर्शन व पूजा-अर्चना करने में सुविधा हो सके। इसी प्रकार की योजना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार श्रीवृन्दावन में भी लाने जा रही है और यहां के जगत प्रसिद्ध बांके बिहारी मन्दिर का आधुनिक कारीडोर बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आधुनिकी करण व विकास पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। यहां के अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्म स्थली पर बना मन्दिर विश्व विख्यात हो चुका है और यहां आने वाले धार्मिक यात्रियों की भीड़ छंटने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार ने अयोध्या में न केवल श्रीराम मन्दिर बनाया बल्कि पूरे अयोध्या नगर का भी कायाकल्प किया। यहां सड़क यातायात को सुगम बनाने के साथ ही हवाई अड्डे का निर्माण भी किया गया, हालांकि अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे के अलावा सैकड़ों मन्दिर पहले से ही थे, मगर तीर्थ यात्रियों की संख्या यहां सीमित रहती थी। राम जन्म स्थान पर मन्दिर बन जाने के बाद अब अयोध्या धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नम्बर एक बनने की तरफ अग्रसरित हो रहा है। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन के अन्य इलाकों में भी बढ़ने से उन स्थानों का चहुंमुखी विकास होता है और वहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने पर जोर देने का वादा भी किया था। आज भारत के कुल घरेलू पर्यटन उद्योग में धार्मिक पर्यटन का हिस्सा 60 प्रतिशत है और इसमें हर वर्ष 10 से लेकर 12 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। वास्तविकता यह है कि यह वृद्धि केवल हिन्दू तीर्थ स्थलों के पर्यटन में ही नहीं हो रही है, बल्कि इसाई व मुस्लिम तीर्थ यात्रियों की संख्या भी उनके धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही है। इससे यह भी आभास होता है कि भारत के औसत आदमी की आमदनी अब इतनी होने लगी है कि वह अपने बीवी-बच्चों के साथ साल में एक बार धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जा सके। बेशक कहा जा सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, मगर यह भी हकीकत है कि भारत में प्रति व्यक्ति खर्च करने की आदत में बढ़ौत्तरी हुई है जो बिना आय बढे.संभव नहीं है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में जब महाकाल कारीडोर का निर्माण हुआ तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की थी मगर कारीडोर बनने के बाद उज्जैन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और नगर में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी है। दरअसल अब भारत के लोग पर्यटन को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

कोहरा के पहरा परल,तहरा नाइं बुझाइ
सहरा के तजि द्या पिया, गउवां रहल बुलाइ
गउवां रहल बुलाइ,सुना ननदी के भइया
नीक न लागइ सेज,काम उकसावइ दइया
कह सुरेश कविराय न होई घर मा सोहरा
कइसे लागइ जिया, पिया छाइल बा कोहरा

आज का कार्टून

साभार

बारूदी ढेर पर सुलगती दुनिया की प्राथमिकताएं!

> दुनिया आज लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आधारशिला पर खड़ी है, लेकिन जब नानाविध भेदभावों को समुचित नियम कानूनों के जरिए परोसा जाएगा तो समानता व बंधुत्व का भाव गायब होना लाजिमी है। आज की लोकतांत्रिक दुनिया इसी अनैतिक विडंबना से ग्रस्त है

साल 2026 में देश-दुनिया की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, इसमें पूंजीवादी देशों, साम्यवादी देशों और समाजवादी देशों के शासकों और उनके कथित संरक्षकों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि समदर्शी व समावेशी लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता कम करना और हर हाल में विश्व में शांति की स्थापना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि ये उपेक्षित विषयवस्तु / क्षेत्र वैश्विक स्थिरता, विकास और दुनियावी सुशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये मुद्दे आम आदमी के समसामयिक व दूरगामी हितों की दृष्टि से भी काफी जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, सतत विकास और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा करके ही उपर्युक्त दुरूह यानी कठिन लक्ष्य को हासिल करके इस दुनिया को रमणीय बनाया जा सकता है। देखा जाए तो प्रकृति ने प्राणिमात्र के लिए सबकुछ निःशुल्क दिए हैं, बस आवश्यकता इस बात की है कि इसे कारोबारी नजरिए से नहीं बल्कि प्राणी मात्र के अहर्निश सेवा भाव के नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में समवेत कोशिश होनी चाहिए। दुनिया आज लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आधारशिला पर खड़ी है, लेकिन जब नानाविध भेदभावों को समुचित नियम कानूनों के जरिए परोसा जाएगा तो समानता व बंधुत्व का भाव गायब होना लाजिमी है। आज की लोकतांत्रिक दुनिया इसी अनैतिक विडंबना से ग्रस्त है, क्योंकि बहुमत के लोकतंत्र से आगे सर्वसम्मत लोकतंत्र की बात सोचने, समझने और उसे अंगीकार करने की चाहत हमलोगों में न के बराबर है, जबकि यह भावना प्रबल होनी चाहिए क्योंकि इसी में सबका हित सन्निहित है। खासकर जब दुनिया की संपदा महज 10 प्रतिशत लोगों के पास सिमटी हुई हो तो समदर्शी और समावेशी लोकतंत्र व अर्थतंत्र की बात और ज्यादा मुखर हो उठती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इजरायल जैसे देशों लोकतांत्रिक या साम्यवादी/ समाजवादी देशों को फ्रांसीसी क्रांति की मूल भावना को सरजमीं पर लागू करना चाहिए ताकि बेलगाम अमेरिकी पूंजीवाद और चीनी साम्यवादी पूंजीवाद को असली समाजवादी भावना की कसौटी पर कसा जा सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो जलवायु संकट समेत तमाम विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलेगा। समसामयिक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2026 में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना सबकी स्पष्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। चूंकि चरम मौसम यानी ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए वैश्विक समझौतों को मजबूत करना जरूरी है। इस नजरिए से विकसित और विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने के ठोस लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जहां तक संभव हो विकास और सुशासन के प्राकृतिक मॉडल को अपनाने की नीति का अनुशरण सभी देशों को करना चाहिए। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग और सभी प्रकार के प्रदूषणों में बढ़ोतरी होगी, जिसकी कीमत खास आदमी से ज्यादा आम आदमी चुकाने की अभिशप्त नजर आता है। इससे आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ती है। असमानता घटाने हेतु धनी देशों को विकासशील राष्ट्रों की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि दुनियावी रिपोर्ट्स बताती हैं कि शीर्ष 10% लोगों के पास अधिकांश धन केंद्रित है। इसलिए रोजगार सृजन और शिक्षा पर जोर देकर सभी देशों के मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना होगा। आखिर में दुनिया की सरकारों को भूमि संपदा के समुचित बंटवारे, खनिज संपदा के उपभोग में सहकारिता की भावनाओं को मजबूत करने और सबके लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर पैदा करने की बात सोची जानी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों व बुजुर्गों की सेवा भावना और युवाओं के लिए स्वस्थ कार्यशैली विकसित किए जाने पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता और स्वार्थपरक क्रूरता को कुचलने के लिए सबको एकजुट रहना चाहिए। ऐसा करके ही शांति व विकास परक आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को पाया जा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाले देश कहीं खुद युद्ध छेड़ते हैं तो कहीं दूसरों को उकसाते हैं। इससे इनके हथियार, नशा, चिकित्सा व पुनर्निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए वैश्विक तनावों के बीच संतुलित व समग्र कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह ठीक है कि अब भारत और जर्मनी जैसे देश नई शुरुआतों की बात कर रहे हैं। लिहाजा, युद्धों और अस्थिरता से बचने के लिए संवाद बढ़ाना अनिवार्य है। जो लोग जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रवाद आधारित राष्ट्रवाद की आड़ में अपने पड़ोसियों को उलझा रहे हैं, इनकी स्पष्ट शिनाख्त और इनके विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। नक्सलवाद, आतंकवाद व अंडरवर्ल्ड को कुचलना चाहिए। आज विकास को हथियार व नशे के कारोबार आदि स्वार्थपरक भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें हतोत्साहित किये जाने की जरूरत है। वहीं, सबमें प्राणिमात्र के लिए सेवाभावी दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। इससे ही मानव समुदाय का भला होगा। तकनीकी विकास को मानव मात्र के लिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए। खासकर औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति के दृष्टिगत एआई और क्वांटम तकनीक का नैतिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र विकास को गति देंगे लेकिन जोखिमों पर नियंत्रण जरूरी है। सतत नवाचार से समस्याओं का समाधान संभव है। आप मानें या न मानें, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि 2026 में शीर्ष वैश्विक नीतिगत प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए जिसके मूल में जलवायु परिवर्तन से निपटना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नैतिक नियमन और आर्थिक असमानता कम करना होनी चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका इनमें निर्णायक होगी। जलवायु संकट से चरम मौसम घटनाओं का सामना करने हेतु वैश्विक नीतियां नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित हों। चरम मौसम और संसाधन दबाव नीति-निर्माताओं को त्वरित कदमों के लिए बाध्य कर रहे हैं। विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन फंडिंग बढ़ाना आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सेमीकंडक्टर में अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने हेतु वैश्विक मानक बनाएं। तकनीकी प्रभुत्व की होड़ नवाचार बढ़ाएगी लेकिन सहयोग को चुनौती देगी। भारत जैसे देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर जोर देकर नेतृत्व कर सकते हैं। वैश्विक व्यापार खंडीकरण से बचने हेतु मुक्त व्यापार समझौते और ब्रिक्स जैसे मंच मजबूत करें। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता विकास, वित्त और जलवायु मुद्दों पर केंद्रित रहे।

■ कमलेश पांडेय

आखिर चाहते क्या हैं मोहम्मद यूनुस?

दीपू चंद्र दास और खोखनचंद्र दास के बाद एक और हिंदू सुरक्षा कर्मचारी अमृत मंडल की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई है अभी तक वहां अल्पसंख्यक हिंदू केवल तात्कालिक ख़तरा महसूस कर रहे थे लेकिन अब एक भय का माहौल उनके बीच पसरता दिखाई दे रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश किस मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है वह एक बहुत बड़ा और खतरनाक संकेत है। जिस तरह 2024 में अगस्त में युवा छात्र की आंदोलन के चलते हुए स्थितियां इतनी बिगड़ी कि वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को भारत में शरण लेनी पड़ी, वह कुछ-कुछ बाद में नेपाल में हुए जैन जी आंदोलन का ही एक पूर्वांक यानी प्रीक्वेल दिखाई पड़ता है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां की सत्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं ग्रामीण बैंक के संस्थापक तथा शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस उम्मीद के साथ अल्पकाल के लिए सौंपी गई थी कि वे वहां पर न केवल शांति स्थापित करेंगे अपितु अव्यस्था की ओर बढ़ रहे बांग्लादेश को फिर से पटरी पर लाकर वहां लोकतंत्र की परिपाटी को मजबूत करेंगे लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि बांग्लादेश के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि वहां लोकतंत्र कभी भी लंबे समय तक एवं मजबूती से नहीं टिका है। 1971 में आजाद होने के बाद शेख मुजीबुर्रहमान ने पहले वहां के राष्ट्रपति एवं बाद प्रधानमंत्री के पद संभाले, तब लगा था कि पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्ति के बाद बांग्लादेश अब लोकतंत्र की स्वस्थ शासन में फले फूलेगा लेकिन केवल 4 साल बाद ही 1975 में एक सैनिक षड्यंत्र के तहत शेख मुजीबुर्रहमान की सपरिवार हत्या कर दी गई. केवल उनकी दो बेटियां जिनमें एक शेख हसीना है, इसलिए बच गई कि वे वहां नहीं थी। उसके बाद एक अल्पकालीन सरकार खोंडकर मुश्ताक के नेतृत्व में बनी. उसका पतन भी एक सैन्यतख्ता पलट में मेजर जनरल जियाउर्रहमान के नेतृत्व में हुआ और 1981 में चटगांव दौरे के दौरान मार डाले गए । एक बार फिर अल्पकालिक सरकारों के बाद सत्ता पर लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने कब्जा किया और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरता की ओर धकेल दिया लेकिन दो शत्रु राजनीतिज्ञ खालिदा जिया और शेख हसीना आपस में मिल गए और इरशाद को भी 1990 में सत्ता गंवानी पड़ी। इरशाद के पतन के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र का एक लंबा दौर चला और वहां पर सत्ता खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच बदलती बदलती रही। 80 साल की उम्र में 28 दिसंबर 2025 को अपनी जीवन लीला पूरी करने वाली खालिदा जिया 10 साल 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं जबकि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना 1996 से 2001 तक और उसके बाद थोड़ी उथल-पुथल के साथ 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की सबसे सशक्त नेता बनकर उभरीं। उनकी इस ताकत के पीछे जहां उनके पिता का प्रभामंडल था, वहीं उनका भारत के प्रति झुकाव और भारत का उनके प्रति समर्थन भी एक प्रमुख कारक था लेकिन अगस्त 2024 में उनकी सरकार का भी

तख्तापलट हुआ और तब से अब तक बांग्लादेश लोकतंत्र और शांति की प्रतीक्षा में है। मोहम्मद यूनुस ने वादा किया हुआ है कि मार्च 2026 तक में चुनाव करके एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को सत्ता सौंप कर एक तरफ हो जाएंगे और वह समय अब करीब करीब आ गया है लेकिन इस बीच मोहम्मद यूनुस की नीति और नीयत दोनों पर ही शक भी उभर रहा है। खालिदा जिया की मृत्यु एवं तारीक रहमान की बांग्लादेश वापसी के बाद राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि यह सारा खेल यूनुस के ही इशारों पर खेला जा रहा है ताकि चुनाव को टाला जा सके एवं सत्ता पर खुद या अपने खास मोहरों को बैठाया जा सके। शेख हसीना हसीना को बांग्लादेश के न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी वतन वापसी अभी तो असंभव सी हो गई है। उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग को पहले ही बांग्लादेश के चुनाव से अलग कर दिया गया है और यूनुस का झुकाव बांग्लादेश के कट्टरवादी दल जमाते इस्लामी की ओर साफ-साफ दिखाई देता है। इस दल की बढ़ी हुई गतिविधियों के बरक्स ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति नफ़रत का सैलाब सा उभर आया है। आज़ादी के समय बांग्लादेश में 22% हिंदू थे जो 1974 की जनगणना के समय 13.5% दर्ज किए गए और आज वहां पर केवल 7.9% हिंदू ही बचे हैं और उनका भी जीवन, परिवार संपत्ति व व्यापार सब कुछ दांव पर लगा है लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार आगे बढ़कर कोई कड़ा कदम उठाने की नहीं हिम्मत कर पा रही है और न ही इतनी सामर्थ्य उसमें लगती है कि वह कुछ कर पाए। यहां सवाल केवल बांग्लादेश का नहीं अपितु पूरे दक्षिण एशिया में जिस तरह एक हिंदू विरोधी लहर उठी हुई है वह चिंता का विषय है। यदि गहराई में जाएं तो साफ-साफ यह है एक राजनीतिक वैमनस्य के शिखर पर चढ़ने जैसा है। पिछले कुछ ही वर्षों में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ-साथ मलेशिया और इंडोनेशिया में भी हिंदू विरोधी लहर दिखाई दी है । नफ़रत के इस खेल में पाकिस्तान के 15% हिंदू अब केवल दो प्रतिशत बचे हैं और कट्टरतावादी तत्व उन्हें भी वहां से भगाने, मारने पर तुले हैं> कहीं यह एक सोची समझी रणनीति का तो हिस्सा नहीं है? यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो फिर दक्षिण एशिया में जनसंख्यिकी बदलाव साफ-साफ देखा जा सकता है और ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जाएगा, मारा जाएगा, तब स्वाभाविक रूप से उनकी शरणस्थली केवल भारत ही बनेगा।

■ घनश्याम बादल

मुक्ति का मार्ग श्रीराम

भगवान श्रीराम भारतीय जनमानस में समग्र चेतना का रूप हैं। श्रीराम नाम के साथ एक मंत्र है, जो सभी को पार उतार देता है। श्रीराम एकत्व और समूह सभी का स्वरूप हैं। हमारे साथ श्रीराम हैं और श्रीराम के साथ हम हैं अर्थात हम में श्रीराम हैं और श्रीराम में हम हैं। सिय राम मय सब जग जानी। श्रीराम हर एक वस्तु में हैं. चारों ओर देखे तो हर दिशा और लोक में श्रीराम के ही दर्शन होते हैं। श्रीराम सकल संसार के तारण हार हैं। श्रीराम नाम जिसने भी गाया-सुना है, वह पार उतर गया है। श्रीराम भजन सुमिरन जितना किया जाए, उतना ही कम लगता है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य, दिव्य, अलौकिक श्रीराम मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्ष बाद हुआ है। श्रीराम मंदिर एक मंदिर होने के साथ-साथ त्रेतायुग से और वर्तमान युग तक के सभी प्रमाण, आस्था, विश्वास, भक्ति, योग, साधना, व्रत और साधु, संत, महात्माओं के संकल्प का प्रतीक है। श्रीराम हमारे रोम-रोम में बसे हैं। भारत भूमि का हर एक खंड तीर्थ है। विचार करें तो अयोध्या धाम हर युग में तीर्थ स्थल रहा है और आगे भी रहेगा। इसकी कितनी ही कथाएं हमारे वेदों, शस्त्रों आदि में लिखी हैं। हमारे पूज्य संतों ने इसके बारे में बताया भी है। तीर्थ नगरी में संतों के यज्ञ, तप का ही फल है कि वहां दिव्य अवतार होते हैं। महात्मा परम पूज्य ऋष्यश्रृंग ने अग्नि से भगवान श्रीराम के पैदा होने वाले उसे दिव्य, अद्भुत पदार्थ का पान तीनों माताओं को कराया। माता कौशल्या को प्रभु श्रीराम ने गर्भ में ही दर्शन दिए लेकिन माता ने शिशु लीला करने की बात कही और प्रभु ने इसे स्वीकार किया। प्रभु श्रीराम सहज, सरल, सौम्य आदि दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। अयोध्या में भगवान श्रीराम के जन्म के साथ भगवान की बाललीला और राज के बारे में संत-महात्मा कथाओं में बताते हैं। आज भी विश्व में किसी राज में सुशासन की बात होती है तो वह रामराज की ही बात होती है। गांधी जी भी भारतवर्ष में रामराज की बातें करते रहें। वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, साथ ही श्रीराम मंदिर की नींव रखने से लेकर धर्म ध्वज लहराते तक की यात्रा में मोदी जी हर कार्य में उपस्थित रहे हैं। संत समागम और सामान्य जन की उपस्थिति में यह सभी मांगलिक कार्य समयानुसार हुए हैं। धर्म ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराने के साथ-साथ भारतीय जनमानस के हृदय में भी लहरा रही है। जब देश का प्रधान सेवक राममय होकर कार्य करता है तो वहां रामराज ही दिखाई देता है। भगवान श्रीराम की असीम कृपा के चलते ही सुयोग्य पात्र को ही श्रीराम मंदिर के सभी मांगलिक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीराम आस्था, विश्वास, भक्ति के साथ-साथ लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जितने भी साधु, संत, महात्मा आदि जल और वायु को ही ग्रहण करके अपने दिव्य संकल्प, व्रत के साथ राम मंदिर निर्माण में लग रहें, उन सबका संकल्प भी पूरा हुआ है। कितने ही समाधि में चले गए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए। भगवान श्रीराम की दिव्य जन्मभूमि पर जिसके भी चरण पड़ते हैं वह राममय हो जाता है। मां सरयू के पावन पुनीत तट पर कितने ही साधु, संत, महात्माओं का तप इस दिव्य भूमि को और भी अधिक उज्जवल तथा प्रकाशवान बना देता है। अयोध्या धाम भगवान श्रीराम के अवतार और राज के साथ-साथ दिव्य यज्ञ, तप, व्रत आदि की भूमि है।

■ डॉ. नीरज भारद्वाज

फिजिटल इंश्योरेंस: मानवीय स्पर्श और डिजिटल गति का संगम

फ्यूजन हमेशा खूबसूरत होता है। यह अलग-अलग चीजों को लेकर कुछ असाधारण गढ़ता है। संस्कृतियाँ मिलती हैं, तो नई परंपराएं जन्म लेती हैं। विचारों के मिलने से नवाचार उभरता है। जब लोग एकजुट होते हैं, तो तरक्की होती है। फिजिटल भी एक फ्यूजन है। फिजिकल (भौतिक) और डिजिटल का मेल। बचपन में हमने यह शब्द नहीं सुना था। रिटेल और मार्केटिंग में 2007 के आसपास पहली बार आया "फिजिटल" शब्द इंटरनेट के बढ़ते प्रसार के साथ महत्वपूर्ण होता गया। कोविड-19 महामारी के बाद यह मुख्यधारा में आ गया। क्योंकि कारोबारों को टिके रहने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन को जोड़ना पड़ा। हाइब्रिड इवेंट्स, डिजिटल शॉपिंग के साथ भौतिक डिलीवरी सब कुछ इस फिजिटल दुनिया का हिस्सा बन गया है। बीमा उद्योग ने भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कदम रखा है। लंबे समय तक बीमा को एक पारंपरिक, कागजी कार्यवाही वाला, आमने-सामने बैठकर परामर्श करने वाला उद्योग माना जाता रहा। लेकिन अब कंपनियां मानवीय स्पर्श और डिजिटल सुविधा को मिलाकर ग्राहक यात्रा में बदलाव ला रहीं हैं। आज भारत में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर हैं। केवल जुलाई-25 के माह में ही 19.47 अरब यूपीआई लेन-देन हुए। इनका मूल्य 25.08 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की मई-25 की रिपोर्ट के अनुसार, 85.5% घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन है। 86.3% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। स्पष्ट है कि डिजिटल क्रांति हमारे रोजमर्रा के जीवन को नए सिरे से गढ़ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीमाकर्ता डिजिटल विकल्प देते हुए मानवीय स्पर्श को कैसे बनाए रख रहे हैं? भारत में बीमा पैठ अभी भी बहुत कम है। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का केवल 3.7% (लाइफ और गैर लाइफ को मिलाकर)। बीमा एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय होना चाहिए, न कि जबरिया बिक्री का नतीजा। डिजिटल पहुंच के बावजूद मानवीय जुड़ाव आज भी आवश्यक है। बीमाकर्ता इसे निम्नलिखित तरीकों से बनाए रखते हैं:-

1. व्यक्तिगत अनुभव (पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस)-एआई चैटबॉट, जिन्हें अक्सर गीता या राशि जैसे भारतीय नाम दिए जाते हैं। सहानुभूतिपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही सवाल भावनात्मक या जटिल होते हैं, वैसे ही ग्राहक को तुरंत किसी मानवीय सलाहकार से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह, क्लैम प्रक्रिया में डिजिटल टूल्स शुरुआत करते हैं। पर भरोसा और आश्वासन देने के लिए मानवीय क्लैम मैनेजर आगे आते हैं।

2. हाइब्रिड क्लैम प्रक्रिया-ग्राहक दस्तावेज और फोटो ऑनलाइन अपलोड करते हैं। क्लैम की स्थिति डिजिटल रूप से ट्रैक करते हैं। लेकिन सर्वेयर या क्लैम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मार्गदर्शन देता है। इससे तनावपूर्ण समय में संवेदनशीलता बनी रहती है।

3. भौतिक उपस्थिति-डिजिटल प्लेटफॉर्म और केंद्रीकृत प्रणालियों के बावजूद, बीमाकर्ता देशभर में शाखाओं, कॉल सेंटर्स और फील्ड स्टॉफ के माध्यम से अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। यह ग्राहक के पास जाकर फिजिटल तरीके से जुड़ते हैं।

4. डिजिटल माध्यमों से मानवीय मार्गदर्शन बीमाकर्ता केवल भुगतान लिंक भेजने के बजाय वीडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पॉलिसी समझाने लगे हैं। एक वित्तीय सलाहकार डिजिटल माध्यम पर भी ग्राहक को मार्गदर्शित और आश्वस्त करता है। समय-समय पर यह सुनने को मिलता है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा। लेकिन भरोसे पर आधारित उद्योग जैसे बीमा में ग्राहक अनुभव को गहराई से देखें, तो तस्वीर अलग नज़र आती है। डिजिटल टूल्स गणना, डेटा प्रोसेसिंग और गति के लिए बेहतरीन हैं। लेकिन संकट या नुकसान के क्षणों में आश्वस्त करने वाली मानवीय आवाज की जगह वे नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई या सूरत के एक कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी, तो ग्राहकों ने क्लैम डिजिटल रूप से दर्ज किए, लेकिन क्लैम मैनेजर के सहयोग ने ही तेज निपटान और कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने में असली फर्क पैदा किया। एआई आगे भी विकसित होता रहेगा और डिजिटल और मजबूत होगा। फिर भी जीत का मंत्र फिजिकल और डिजिटल में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों को संतुलित रूप से जोड़ना है। यही फिजिटल इंश्योरेंस का सार है — डिजिटल सुविधा के साथ मानवीय स्पर्श।

– अफताब अल्वी

संपादकीय

हम समझते हैं' कह देना आसान है

कई बार लोग कहते हैं कि हम आपको समझते हैं... आपकी पीड़ा, आपके दुख और तकलीफ, भावनाओं को समझते हैं। ऐसे शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कई बार हमारे बहुत करीबी, रिश्ते-नातेदार अपनी निकटता दिखाने के लिए कहते हैं कि हम आपके दुख, आपकी पीड़ा को समझते हैं। उनका यह कहना वास्तव में मात्र जुबानी जमा खर्च होता है, जिसे कोई भी किसी को सांत्वना देने के लिए आमतौर पर औपचारिकता निभाने की खातिर कह देता है। हालांकि ऐसा कहना एक तरह की कठोरता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सच यही है।

अगर हम एक इंसान के रूप में थोड़े-से संवेदनशील हैं, तो हम किसी के दुख के प्रति भावुक हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके दुख से हम थोड़े बहुत दुखी भी हो जाएं, पर पूरी तरह किसी के दुख, पीड़ा, मर्म को समझ पाना लगभग असंभव है। एक हद तक अगर संभव है भी, तो यह तब हो पाता है, जब कोई व्यक्ति खुद उसी के बराबर की पीड़ा से गुजरा होता है।

किसी को समझना और किसी की पीड़ा की गहराई में उतरना क्या आसान है? इंसान का दुख एक अंधेरे गहरे कुएं की तरह होता है। उस अंधेरे और गहराई में कितनी तहें हैं, यह कोई नहीं जानता है। बाहर से देखने पर कुछ और लगता है और अंदर उतरने पर कुछ और भी हो सकता है। और जब कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, सौ फीसद क्या है, यह हम नहीं बता सकते। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के दुख के कुएं में कूद जाएं। जाने के लिए भावनाओं की एक पूरी नदी पार करनी पड़ती है। अपनत्व की सीढ़ी बनानी पड़ती है। संवेदना से अपनी हृदय-भूमि को सिंचित करना पड़ता है। उसके बाद एक-एक सीढ़ी उतरना पड़ता है। वह भी बेहद संभल-संभल कर, तब जाकर कहीं नीचे तक हम पहुंचने की राह मिल पाती है। अगर हम जरा भी जल्दबाजी और अनमनापन दिखाते हैं, तो आधे रास्ते से वह सीढ़ियां गायब हो जा सकती हैं और वहीं से हमें वापस आना पड़ जा सकता है। जुबान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई किसी की पीड़ा को पूरी तरह से समझ ले। जिस रूप में व्यक्ति पीड़ा को भोग रहा है, उसी रूप में, उन्हीं भावनाओं के साथ कोई महसूस कर ले। क्या यह संभव है? अपने पांव पर चलने वाला पूरी तरह स्वस्थ इंसान साल भर से बिस्तर पर अशक्त रूप से पड़े हुए किसी इंसान के मन के दुख को किस तरह समझ सकता है। पूरी तरह स्वस्थ तो छोड़ दिया जाए, जो उस अवस्था से गुजर रहा है, वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति की पीड़ा को सौ फीसद नहीं समझ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों की परिस्थितियां अलग हों। हम किसी की पीड़ा का मात्र कुछ अंश ही समझ सकते हैं, पूरी तरह समझना असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ा भोग रहा है, वह पूरे समय इस दुख में जीता है। और जो व्यक्ति समझने का दावा कर रहा है कि उसकी पीड़ा को समझ रहा है, वह मात्र उस व्यक्ति के समंदर-से दुख के मात्र एक कतरे को समझने का प्रयास कर रहा है। यह कतई संभव नहीं है कि हम एक पूरी किताब को एक पन्ना पढ़कर समझ जाएं। किसी के दुख को पूरी तरह या पर्याप्त गहराई के साथ समझने के लिए उस किताब को पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसी परिस्थिति में पढ़ना पड़ेगा और उसी अवस्था, भावना में पढ़ना पड़ेगा और उतना ही समय लेना पड़ेगा। तब जाकर हो सकता है कि कहीं हम किसी व्यक्ति की पीड़ा की तहों में पहुंच पाएं। इसीलिए यह संभव नहीं है कि हम कितने भी संवेदनशील व्यक्ति हों, किसी के दुख को समझ सकते हैं। दुख-सुख दरअसल परिस्थिति, भावनाओं, अपनों के व्यवहार के अलावा भी बहुत सारी बातों के साथ मिलकर संगति करता है। एक पति-पत्नी बरसों साथ रहते हैं। एक खुशहाल परिवार के रूप में रहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे की पीड़ा को पूरी तरह समझते हों। अक्सर हम लोगों को उतना ही समझते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद अन्यथा के रूप में छोड़ देते हैं। हर इंसान को हर रिश्ते में सबसे बड़ा दुख या फिर शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके।

डिजिटल संसार में सेहत के जोखिम

बच्चों के मामले में यह स्थिति और भी संवेदनशील है। उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। 'विजुअल प्रोसेसिंग' यानी दृश्य प्रसंस्करण वह क्षमता है, जिससे बच्चा आकार, रंग, दूरी, दिशा और गति को समझता है।

डॉ विजय गर्ग

यह मानव स्वभाव है कि हर पीढ़ी अपने बच्चों को खुद से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करती है। मगर ऐसा लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सौंप दी है। बच्चे अब पहाड़, समुद्र, युद्ध, महामारी और उत्सव सब कुछ अंगुलियों के एक स्पर्श से देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया को समझ भी पा रहे हैं? या फिर सिर्फ देख रहे हैं, बिना याद रखे, बिना गहराई से

'बेड किए? इसी प्रश्न के बीच दो नई आदतें उभरकर सामने आती

और स्क्रॉलिंग संस्कृति, जो बच्चों की दृश्य स्मृति मानसिक सक्रियता को प्रभावित कर रही 7 'हैं। 'बेड-राटिंग' का अर्थ है- लंबे समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहना और मोबाइल चलाते रहना। पढ़ाई, मोबाइल, आराम सब कुछ एक ही जगह पर यह आदत अकसर थकान उदासी के नाम पर शुरू होता है रू होती है, लेकिन धीरे-धीरे जीवनशैली बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब बिस्तर केवल सोने की जगह न रहकर जागने और स्क्रीन देखने का केंद्र बन जाता है, तो दिमाग को स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। । इसका सीधा असर नींद की गुणवत्ता और स्मृति निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है। '

बच्चों के मामले में यह स्थिति और भी संवेदनशील है। उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। 'विजुअल प्रोसेसिंग' यानी दृश्य प्रसंस्करण वह क्षमता है, जिससे बच्चा आकार, रंग, दूरी, दिशा और गति को समझता है। दृश्य स्मृति वह शक्ति है, जिससे वह देखी हुई जानकारी को याद रखता है, चाहे वह शब्दों का रूप हो, किसी का चेहरा हो या रास्ते की पहचान। इन क्षमताओं का विकास केवल किताबों या स्क्रीन से नहीं होता, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभवों से होता है, जैसे खुली जगह, खेल, दौड़ना, चेहरे पढ़ना, , और वस्तुओं को छूकर समझना आदि। लगातार बिस्तर पर रहकर एक सीमित दूरी से स्क्रीन देखना दृश्य अनुभव को संकुचित कर देता है। ऐसे में बच्चा तेज, चमकीली और लगातार बदलती तस्वीरों का आदी हो जाता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान से जुड़े शोध बताते हैं कि इस तरह के एकरूप दृश्य अनुभव से मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और दृश्य विशेष 'कौशल कमजोर हो सकता है। इसका असर आगे चलकर पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता पर भी दिखता है।

इसी सीमित दृश्य संसार में प्रवेश करती है 'इम स्क्रॉलिंग' यानी नकारात्मक, डराने वाली और संकट से भरी सूचनाओं को बिना रुके देखते जाना महामारी, युद्ध, अपराध और आपदाओं की लगातार तस्वीरें बच्चों और किशोरों के मन में यह भावना बैठा देती हैं कि दुनिया असुरक्षित और भयावह है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, इस तरह की आदत चिंता, अवसाद और मानसिक थकान बढ़ाती है। चिंतित दिमाग न तो ध्यान केंद्रित कर पाता है और न ही नई जानकारी को ठीक से याद रख पाता है। इसके विपरीत हाल के वर्षों में 'ब्लूम-स्क्रॉलिंग' की अवधारणा सामने आई है, यानी सकारात्मक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री को चुनकर देखना सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह बच्चों में जिज्ञासा, आशावाद और रचनात्मक सोच को बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश डिजिटल मंच बच्चों को सोच-समझकर चुनने की बजाय लगातार स्क्रॉल करते रहने के लिए डिजाइन

किए गए हैं। एल्गोरिदम का उद्देश्य मानसिक विकास नहीं, बल्कि स्क्रीन- समय बढ़ाना होता है। 'बेड-राटिंग' और 'स्क्रॉलिंग' संस्कृति का समग्र प्रभाव बच्चों की ध्यान क्षमता पर साफ दिखाई देता है शिक्षक बताते हैं कि बच्चे लंबे समय तक किसी पाठ पर ध्यान नहीं लगा पाते।

इस पर हुए अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन- उपयोग से क्रियाशील स्मृति और अनुक्रमिक विचारशीलता कमजोर हो सकती है। नींद इस पूरी समस्या का केंद्र है। वैज्ञानिक रूप से यह स्थापित तथ्य है। कि स्मृति विशेषकर दृश्य नींद के दौरान स्मरण शक्ति में स्थायित्व हासिल करते हैं। जब बच्चे देर रात तक बिस्तर पर स्क्रीन देखते रहते हैं, तो नींद की अवधि ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी घटती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जिससे दिमाग को आराम का संकेत नहीं मिल पाता। नतीजतन अगला दिन थकान, चिड़चिड़ेपन और ध्यान भंग के साथ शुरू होता है।एक समय था, जब परिवार के बुजुर्ग बच्चों से सहज रूप से पूछ लेते थे- 'कोई पहाड़ा सुनाओ।' यह केवल गणित का अभ्यास नहीं था, बल्कि बच्चे की मानसिक सक्रियता को परखने 7 तरीका था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो पहाड़ा याद करना क्रियाशील स्मृति, अनुक्रमित प्रसंस्करण और दृश्य श्रवण समन्वय तीनों को सक्रिय करता है। बच्चे को अंकों की का दृश्य छवि बनानी होती है, क्रम याद रखना होता है और बिना रुके सही उत्तर देना होता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान बताता है कि ऐसी गतिविधियां मस्तिष्क के

हास

जिम्मेदार

खास हिस्सों को सक्रिय करती , जो ध्यान और स्मृति के लिए हैं। आज जब उत्तर एक क्लिक में स्क्रीन पर मिल जाता है. तो दिमाग की वह कसरत नहीं । है। दुनिया के कई देशों ने बदलती स्थिति को गंभीरता से लिया है। फ्रांस, डेनमार्क और नार्वे जैसे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। आस्ट्रेलिया में सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यूरोप कई स्कूलों में 'डिजिटल वेल बीइंग' यानी डिजिटल तकनीक के संतुलित उपयोग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, बच्चे तकनीक का उपयोग करना सीखें, उसके गुलाम न बनें। भारत में तस्वीर थोड़ी जटिल है। यहां डिजिटल साधनों को शिक्षा और रूप में देखा जाता है, जो सही अवसर के रूप है मगर इस उत्साह में बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी हो रही है। शहरी घरों में बच्चों का खेल मैदान मोबाइल बन न चुका है। छोटे शहरों

? वत्ति बढ़

कस्बों में भी यही सीमित और एकरूप होता जा रहा है। यह कहना जरूरी है कि समस्या तकनीक नहीं, उसका असंतुलित उपयोग है। स्क्रीन अपने आप में न तो

है। परिणामस्वरूप बच्चों का दृश्य संसार है और न समाधान, यह एक माध्यम है। सवाल यह है कि क्या बच्चों को

स्क्रीन के अलावा भी देखने, चलने, खेलने और सोचने के पर्याप्त अवसर मिल

रहे हैं? यदि नहीं, तो उनकी

मामले

दृश्य स्मृति और समझ अधूरी ही रह जाएगी। इस माता-पिता की भूमिका निर्णायक है। यह स्पष्ट होना चाहिए समान का जगह है, पूरे दिन

कि बिस्तर केवल सोने की जगह है,

गतिविधियों केंद्र नहीं।

स्क्रीन मुक्त समय और स्थान तय करना, बच्चों के साथ

बैठकर 'सामग्री चुनना तथा उनके डिजिटल अनुभव पर संवाद करना आज की जरूरत है। स्कूलों को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि इसमें परोसी जा रही रही सामग्री का बच्चों के दिमाग पर कैसा असर हो रहा है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि नकारात्मक सूचनाओं और सामग्री से मानसिक दूरी कैसे बनाई जाए और सकारात्मक जानकारी को कैसे चुना जाए। बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज जिम्मेदारी है। उम्र-आधारित दिशा-निर्देश, डिजिटल मंच की जवाबदेही और सार्वजनिक जागरूकता, तीनों पर एक साथ काम करने की जरूरत है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

ऊर्जा की जरूरतों का हरित विकल्प

डॉ विजय गर्ग

केंद्र सरकार ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार का लक्ष्य हर वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना । गौरतलब है हरित हाइड्रोजन उद्योग जिस तरह बड़े पैमाने पर स्थापित हो रहे हैं, ऐसे में उच्च क्षमता वाला बिजली उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए जो विधि उपयोग में लाई रही है, वह सुगम और सस्ती है। मगर वहीं पर पर हाइड्रोजन ऊर्जा की आपूर्ति के आंकड़े वर्तमान सीमित हैं, क्योंकि दुनिया में करीबन 96 5 फीसद हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से पैदा होती है। इसमें महज तकरीबन चार फीसद बिजली के इलेक्ट्रोलिसिस (विद्युत अपघटन) द्वारा तैयार की जाती है। भारत सरकार चाहती कि जब तक हर गांव और बाजार मुहल्ले 1 ऊर्जा जरूरतें इसके जरिए न पूरी होने लगें, तब तक इसके लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इससे जागरूकता आएगी और लोग हाइड्रोजन ईंधन की महत्ता को भी समझने लगेंगे

हाइड्रोजन आने वाले वक्त का ऊर्जा आपूर्ति का आधार बनेगा। हरित हाइड्रोजन में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपार क्षमता है। यह परिवहन और उद्योग में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो ऊर्जा का एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत होगा। कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन में कमी लाने वाला ऊर्जा विकल्प का सबसे बेहतर स्रोत हरित हाइड्रोजन बनने जा रहा है। आने वाले समय में शायद हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होगा। जिंदगी को अधिक सुगम बनाने के लिए इसका उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग की जिंदगी को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्य स्वच्छ किफायती और टिकाऊ ऊर्जा के लिए बड़े सोलर पार्क, हरित हाइड्रोजन, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, और माइक्रो ग्रिड के जरिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर खास जोर दे रहे हैं। सरकार ने 2047 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिल कर आगे की कार्ययोजना तैयार की है। इसी तरह की योजना देश के सभी राज्यों को तैयार करनी होगी, क्योंकि कार्बन-मुक्त ऊर्जा पैदा करने के लिए जैव ऊर्जा सबसे किफायती है। इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हरित हाइड्रोजन में कई संभावनाएं छिपी हैं। दरअसल, ऊर्जा क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए सरकार हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वैश्विक क्षमताओं के बीच भारत को अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के मिशन माध्यम से 2030 तक 50 लाख टन (एमएमटी) वार्षिक हरित हरित हाइड्रोजन क्षमता हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लागू करने के लिए 19.744 करोड़ का परिव्यय मंजूर कर चुकी है। इससे देशभर में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 2030 तक हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता जोड़ने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख टन रखी है। इससे यह अनुमान लगाया गया है। कि ऊर्जा की कमी जिन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, उन सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है।वर्ष 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य की घोषणा की है। इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हरित हाइड्रोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उत्पादन कई नजरिए से खास है। पर्यावरणीय मानकों पर यह सबसे खरा उतरता है, क्योंकि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सौर, पवन या जलविद्युत जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल कर पानी को आक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्वच्छ और उत्सर्जन मुक्त ईंधन प्राप्त होता है। इसमें जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपार क्षमता दुनियाभर में परिवहन, पत्तन और स्टील सहित 7 कई क्षेत्रों को कार्बन- मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन की मांग तेजी से बढ़ है। । विशेषज्ञों के अनुसार भारत में हाइड्रोजन का अकूत भंडार है. जिससे दो सौ वर्ष से समय के लिए जरूरी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल नए आविष्कारों के जरिए घरेलू उपयोग के लिए जल्द ही सुलभ हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की वार्षिक आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि भारत बिजली खरीद या बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए पहले से ही लंबित 40 गीगावाट क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भी बताया गया है कि वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 160 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़नी होगी।अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की शुरुआती परियोजनाओं के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं।

इसमें सौ करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जैविक पदार्थ का उपयोग शामिल है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जैविक पदार्थों के उपयोग सहित अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए कुल सौ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो एनजीएचएम के तहत नवउद्यम योजनाओं के लिए पहले से आबंटित सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। गौरतलब है एनएचएम का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना 'बनाना है।

इसका परिव्यय 19,744 1 करोड़ रुपए [है। साथ ही इसका लक्ष्य 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और छह लाख से अधिक हरित रोजगार उत्पन्न करना भी है। इससे सबसे बड़ा फायदा पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने में दिखाई देगा। देश के बड़े शहरों, नगरों और कस्बों में कार्बन और धूल प्रदूषण से बीमारियों सहित होने वाली तमाम परेशानियों से लोग बचेंगे। इससे अरबों रुपए बचेंगे। साथ ही साथ हड्डी, मस्तिष्क, रक्त, आंत, आंख और सांस आदि से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों में कमी आएगी और औसत उम्र में वृद्धि भी होगी।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

रेल में सोने की लूट और जांच का धोखा

इस बात का खुलासा तब हुआ, जब पटना रेलवे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने गहन तहकीकात की। हैरत की बात है कि जिस अधिकारी को रेल में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अपराधियों की जमात में खड़ा पाया गया

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो यह व्यवस्था में एक गहरी और चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। इससे आमजन में असुरक्षा, निराशा और अविश्वास की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। अगर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगें, तो सुरक्षा और न्याय की उम्मीद किससे की जाए! बिहार में एक ऐसी ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपए के सोने की लूट की जांच कर रहा राजकीय रेलवे पुलिस का अधिकारी ही मामले में संलिप्त पाया गया।

इस बात का खुलासा तब हुआ, जब पटना रेलवे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने गहन तहकीकात की। हैरत की बात है कि जिस अधिकारी को रेल में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अपराधियों की जमात में खड़ा पाया गया।

ऐसे में यह सवाल और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि व्यवस्था में पनप रहे इस तरह के भ्रष्टाचार और अपराध के दरख्तों को खाद-पानी कहां से मिल रहा है?

गौरतलब है कि कोलकाता स्थित एक स्वर्ण कारोबारी के कर्मचारी ने बिहार के गया रेल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गत वर्ष नवंबर में हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस रेल में यात्रा के दौरान गया स्टेशन पर पुलिस वर्दी में चार लोग ट्रेन में सवार हुए। पहले उन्होंने सोने को लेकर उनसे पूछताछ की और बाद में वे एक किलो सोने के बिस्कुट लेकर फरार हो गए।

इसके बाद गया रेल थाना प्रभारी ने जांच शुरू की। जाहिर है कि जब लूट में शामिल पुलिस अधिकारी ही जांच कर रहा हो, तो सच सामने आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। भारतीय रेल आए दिन अलग-अलग बहाने से किराए में बढ़ोतरी करने या अधिक पैसे वसूलने में तो कोई संकोच नहीं करती, लेकिन यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर को सुनिश्चित करने में शायद उसकी कोई रुचि नहीं है।

विडंबना यह है कि यात्रियों के सामने आपराधिक तत्त्वों के अलावा अब वैसे लोगों से भी खुद को बचाने की चुनौती है, जो उनकी सुरक्षा के लिए ही तैनात किए जाते हैं।

सुंदरता नहीं, जनस्वास्थ्य हो शहरों की प्राथमिकता

स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार अव्वल आने वाले शहर में अगर सैंकड़ों लोग दूषित पानी के कारण बीमार पड़ जाएं और उन्हें जीवन-मौत से जूझना पड़े, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 'स्वच्छता' का अर्थ केवल सड़कों की सफाई और पेंटिंग तक ही सीमित है?

दूषित पानी पीने से मौत की घटना देश में कहीं भी हो- शर्मनाक है। इंदौर जैसे शहर में ऐसी घटना का होना और भी चिंता की बात है क्योंकि यह शहर कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा लिए फिरता है। स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार अव्वल आने वाले शहर में अगर सैंकड़ों लोग दूषित पानी के कारण बीमार पड़ जाएं और उन्हें जीवन-मौत से जूझना पड़े, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 'स्वच्छता' का अर्थ केवल सड़कों की सफाई और पेंटिंग तक ही सीमित है? क्या नागरिकों को शुद्ध पेयजल जैसा मौलिक अधिकार देना नगर निगम और प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है? यह त्रासदी हमें इसलिए भी झकझोरती है क्योंकि अन्य शहरों के मुकाबले यहां कहीं अधिक चाक-चौबंद व्यवस्था की अपेक्षा रही है। यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत विफलता का भयावह चेहरा है। जिम्मेदारों पर आपराधिक लापरवाही की कार्रवाई होनी चाहिए।

इंदौर के भागीरथपुरा की घटना ने यह साबित कर दिया है कि स्वच्छता का जो महल खड़ा किया गया है, उसकी नींव में बुनियादी ढांचे की भारी कमजोरी है। पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें की जा रही थीं लेकिन, प्रशासन की कुंभकर्णी नींद तब तक नहीं खुली, जब तक घरों से अर्थियां नहीं निकलीं। जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए गुहार लगा रही हो और जिम्मेदार अधिकारी उदासीन रहें तो इसे 'आपराधिक लापरवाही' के अलावा और क्या नाम दिया जाए? इस त्रासदी में सबसे अधिक आहत करने वाला पहलू मंत्री एवं स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय का रवैया रहा है।

लोकतंत्र में जनता अपने नुमाइंदों को इसलिए चुनती है कि वे संकट के समय उनके साथ खड़े होंगे, न कि इसलिए कि वे उनकी मौतों को 'फोकट की बात' करार देंगे।एक तरफ इंदौर को 'स्मार्ट सिटी' और 'स्वच्छ शहर' के रूप में ग्लोबल ब्रांड बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गरीब बस्तियों के लोग दम तोड़ रहे हैं। ऊपर से राजनीतिक नेतृत्व का यह अहंकार न केवल निंदनीय है, बल्कि यह उस भरोसे का कत्ल भी है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी इस मामले में एक उम्मीद की किरण है। अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रशासन की विफलता को रेखांकित किया है। फौरी तौर पर कुछ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई इस समस्या का समाधान नहीं है।

पानी की पाइपलाइनों का ड्रेनेज लाइनों के साथ मिलना या उनमें लीकेज होना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी नियमित निगरानी की कमी एक बड़ा अपराध है। यह घटना केवल इंदौर के लिए नहीं, बल्कि देश के उन तमाम शहरों के लिए एक चेतावनी है जो बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज कर बाहरी सौंदर्यीकरण पर पैसा बहा रहे हैं। जन-स्वास्थ्य किसी भी शहर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूषित पानी पीने से मौत की घटना देश में कहीं भी हो- शर्मनाक है। इंदौर जैसे शहर में ऐसी घटना का होना और भी चिंता की बात है।

संपादकीय

निर्माण क्षेत्र में विकास की ठोस नींव

भारत की आर्थिक यात्रा का सबसे मजबूत स्तंभ पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र का विस्तार रहा है। सड़कें, पुल, शहरी ढांचा, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र इन सभी में अभूतपूर्व गति देखने को मिली है। यह गति ही देश में आज रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और समग्र आर्थिक स्थिरता का आधार बनी है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी 'इंवेस्ट इंफारमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी' (आईसीआरए) की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय निर्माण क्षेत्र की आय में 8 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है। वस्तुतः यह अनुमान भविष्य के प्रति विश्वास जगाता है कि मोदी सरकार की नीतिगत दिशा और क्रियान्वयन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज आईसीआरए का भारतीय निर्माण क्षेत्र के लिए स्थिर नजरिया बनाए रखना इस बात का संकेत है कि यह क्षेत्र आने वाले समय में संतुलित और टिकाऊ विकास की राह पर बना रहेगा। आर्थिक अनिश्चितताओं और वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद यदि कोई क्षेत्र स्थिर बना हुआ है, तब निश्चित ही उसके पीछे मजबूत नीतियां, दीर्घकालिक दृष्टि और प्रभावी प्रशासन की भूमिका जिम्मेदार है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानते हुए जिस निरंतरता के साथ निवेश और परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है, उसका असर आज इन अनुमानों में साफ दिखता है।

आय वृद्धि के अनुमान और सरकार की भूमिका

वित्त वर्ष 2026 में जहां निर्माण क्षेत्र की आय वृद्धि 6 से 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में इसके 8 से 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह सुधार मामूली नहीं है। यह दशार्ता है कि सरकारी परियोजनाओं, शहरी विकास योजनाओं और ऊर्जा व सिंचाई जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ता निवेश कंपनियों को नए अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति, शहरी बुनियादी ढांचे पर जोर और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार जैसी पहलों ने निर्माण उद्योग को दीर्घकालिक काम का भरोसा दिया है। आईसीआरए के अनुसार, सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों का प्रदर्शन कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि शहरी बुनियादी ढांचा, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की वृद्धि बेहतर रहने की संभावना है। यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि मोदी सरकार की विकास रणनीति एक क्षेत्र पर केंद्रित न होकर बहुआयामी है। शहरीकरण, जल प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर देकर सरकार ने निर्माण उद्योग के लिए विविध अवसर तैयार किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो निर्माण कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। इसके विपरीत जो कंपनियां केवल सड़क निर्माण या जल जीवन मिशन पर निर्भर हैं।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

आज की समृद्धि, कल की कीमत: वैश्विक कर्ज का सच

प्रो. आरके जैन

"नकारात्मक परिदृश्य में वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ा संकट भी संभव है। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर का रिफाइनेंसिंग संकट विकसित बाजारों को हिला सकता है। यदि निवेशकों का भरोसा डगमगाया, तो शेयर और बॉन्ड बाजारों में भारी गिरावट देखी जा सकती है, जो 2008 की वित्तीय मंदी से भी अधिक गहरी हो सकती है। विकासशील देशों में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है, जबकि अमीर देशों में आय और संपत्ति की असमानता और तेज हो सकती है"

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां विकास की गति से अधिक तेजी से कर्ज का पहिया घूम रहा है। दुनिया का कुल सार्वजनिक कर्ज 100 ट्रिलियन डॉलर की ऐतिहासिक सीमा पार कर चुका है, जो अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 94.7 प्रतिशत के बराबर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह आंकड़ा 2025 में लगभग 111 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और यदि मौजूदा प्रवृत्तियां जारी रहीं, तो 2029 तक यह जीडीपी के 100 प्रतिशत को पार कर सकता है (प्रतिकूल स्थिति में 115-123% तक)। यह स्थिति केवल आर्थिक आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक निर्णय क्षमता के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। कर्ज अब केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि भविष्य की नीतियों पर बोझ बनता जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह संकट और भी गहराता दिख रहा है। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के 110 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुका है। अकेले अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जहां सालाना ब्याज भुगतान लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है यह राशि कई देशों के कुल रक्षा बजट से भी अधिक है। ओईसीडी की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि सरकारों का बढ़ता ब्याज व्यय अब शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे उत्पादक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों को निगल रहा है। जब सरकारें कर्ज चुकाने में अधिक धन खर्च करती हैं, तो विकास निवेश स्वाभाविक रूप से सिमट जाता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। इस वैश्विक कर्ज संकट की जड़ें हाल के वर्षों की असाधारण घटनाओं में छिपी हैं। कोविड-19 महामारी ने सरकारों को अभूतपूर्व स्तर पर उधार लेने के लिए मजबूर किया। स्वास्थ्य प्रणालियों को संभालने, लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को जीवित रखने और सामाजिक सहायता योजनाओं को चलाने के लिए ट्रिलियनों डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज जारी किए गए। इसके तुरंत बाद रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा और खाद्य संकट को जन्म दिया, जिससे सब्सिडी और रक्षा खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इन दोनों घटनाओं ने राजकोषीय संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि ओईसीडी देशों में ब्याज खर्च जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो अब रक्षा व्यय से भी अधिक है।

विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति और भी नाजुक है। इन देशों पर कुल कर्ज लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और वे हर साल करीब 921 अरब डॉलर केवल ब्याज भुगतान में खर्च कर रहे हैं। ऊंची वैश्विक ब्याज दरें और कमजोर आर्थिक वृद्धि इस संकट को और गहरा कर रही हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड मिलाकर वैश्विक बॉन्ड बाजार 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो चुका है, जिससे रिफाइनेंसिंग जोखिम खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी का बहिर्वाह, मुद्रा अवमूल्यन और भुगतान संतुलन संकट की आशंका लगातार बढ़ रही है। आने वाला वर्ष 2026 इस संकट का निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता है। अनुमान है कि बढ़ता कर्ज वैश्विक आर्थिक विकास दर को लगभग 3.2 प्रतिशत पर सीमित कर देगा। उभरते बाजारों में करीब 8 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड रिडेम्प्शन की चुनौती सामने होगी, जिससे कई देशों की मुद्राएं दबाव में आ सकती हैं। अमेरिका में सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के 102 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है, जहां ब्याज भुगतान संघीय बजट का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा निगल सकता है। यूरोप में पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर कटौती का खतरा मंडरा रहा है, जबकि एशिया में चीन का बढ़ता उधार उसकी विकास गति को सुस्त कर सकता है। आईएमएफ चेतावनी देता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वैश्विक कर्ज जीडीपी के 115 प्रतिशत तक जा सकता है, जो एक नई वैश्विक मंदी को जन्म दे सकता है।

नकारात्मक परिदृश्य में वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ा संकट भी संभव है। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर का रिफाइनेंसिंग संकट विकसित बाजारों को हिला सकता है। यदि निवेशकों का भरोसा डगमगाया, तो शेयर और बॉन्ड बाजारों में भारी गिरावट देखी जा सकती है, जो 2008 की वित्तीय मंदी से भी अधिक गहरी हो सकती है। विकासशील देशों में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है, जबकि अमीर देशों में आय और संपत्ति की असमानता और तेज हो सकती है। भू-राजनीतिक तनाव पूंजी प्रवाह को बाधित करेंगे, जिससे उधार और महंगा हो जाएगा और संकट का दायरा और फैल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब कर्ज पर से नियंत्रण फिसलता है, तो उसके झटके केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और राजनीति की नींव तक को हिला देते हैं। ग्रीस और इटली जैसे देशों के कर्ज संकट ने यह कड़वा सच उजागर किया है कि वित्तीय असंतुलन कैसे वर्षों तक विकास की गति को जकड़े रखता है और नीतिगत विकल्पों को सीमित कर देता है। लेकिन आज का वैश्विक संकट इन उदाहरणों से कहीं अधिक व्यापक और जटिल है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व स्तर पर आपस में जुड़ चुकी हैं। ऐसे में यदि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाती हैं, तो उसकी कीमत छोटे और कमजोर देशों को कहीं अधिक भारी रूप में चुकानी पड़ती है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए अब ठोस और साहसिक कदम जरूरी हैं। आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कर सुधार, व्यय नियंत्रण और कर्ज को जीडीपी के 100 प्रतिशत से नीचे लाने की सलाह दे रही हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी सबसे बड़ी बाधा है।

डिजिटल मुद्राएं और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें उधार प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती हैं, जबकि सस्टेनेबल और ग्रीन बॉन्ड भविष्य के विकास को अधिक जिम्मेदार दिशा दे सकते हैं। विकासशील देशों के लिए ऋण राहत, पुनर्गठन और निवेश प्रवाह बेहद आवश्यक है।

यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह कर्ज संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट का रूप ले सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा।

डिजिटल संसार में सेहत के जोखिम

डॉ विजय गर्ग

यह मानव स्वभाव है कि हर पीढ़ी अपने बच्चों को खुद से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करती है। मगर ऐसा लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सौंप दी है। बच्चे अब पहाड़, समुद्र, युद्ध, महामारी और उत्सव सब कुछ अंगुलियों के एक स्पर्श से देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया को समझ भी पा रहे हैं या फिर सिर्फ देख रहे हैं, बिना याद रखे, बिना गहराई से

'बेड किए इसी प्रश्न के बीच दो नई आदतें उभरकर सामने आती और स्क्रॉलिंग संस्कृति, जो बच्चों की दृश्य स्मृति मानसिक सक्रियता को प्रभावित कर रही 'हैं। 'बेड-राटिंग' का अर्थ है- लंबे समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहना और मोबाइल चलाते रहना। पढ़ाई, मोबाइल, आराम सब कुछ एक ही जगह पर यह आदत अकसर थकान उदासी के नाम पर शुरू होता है रू होती है, लेकिन धीरे-धीरे जीवनशैली बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब बिस्तर केवल सोने की जगह न रहकर जागने और स्क्रीन देखने का केंद्र बन जाता है, तो दिमाग को स्पष्ट संकेत नहीं मिलते।। इसका सीधा असर नींद की गुणवत्ता और स्मृति निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है।" बच्चों के मामले में यह स्थिति और भी संवेदनशील है। उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। 'विजुअल प्रोसेसिंग' यानी दृश्य प्रसंस्करण वह क्षमता है, जिससे बच्चा आकार, रंग, दूरी, दिशा और गति को समझता है। दृश्य स्मृति वह शक्ति है, जिससे वह देखी हुई जानकारी को याद रखता है, चाहे वह शब्दों का रूप हो, किसी का चेहरा हो या रास्ते की पहचान। इन क्षमताओं का विकास केवल किताबों या स्क्रीन से नहीं होता, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभवों से होता है, जैसे खुली जगह, खेल, दौड़ना, चेहरे पड़ना, , और वस्तुओं को छूकर समझना आदि। लगातार बिस्तर पर रहकर एक सीमित दूरी से स्क्रीन देखना दृश्य अनुभव को संकुचित कर देता है। ऐसे में बच्चा तेज, चमकीली और लगातार बदलती तस्वीरों का आदी हो जाता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान से जुड़े शोध बताते हैं कि इस तरह के एकरूप दृश्य अनुभव से मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और दृश्य विशेष "कौशल कमजोर हो सकता है। इसका असर आगे चलकर पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता पर भी दिखता है। इसी सीमित दृश्य संसार में प्रवेश करती है 'इम स्क्रॉलिंग' यानी नकारात्मक, डराने वाली और संकट से भरी सूचनाओं को बिना रुके देखते जाना महामारी, युद्ध, अपराध और आपदाओं की लगातार तस्वीरें बच्चों और किशोरों के मन में यह भावना बैठा देती हैं कि दुनिया असुरक्षित और भयावह है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, इस तरह की आदत चिंता, अवसाद और मानसिक थकान बढ़ाती है। चिंतित दिमाग न तो ध्यान केंद्रित कर पाता है और न ही नई जानकारी को ठीक से याद रख पाता है। इसके विपरीत हाल के वर्षों में 'ब्लूम-स्क्रॉलिंग' की अवधारणा सामने आई है।

विचार

जहाँ अक्षर उँगलियों से बोलते हैं: ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल

सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 4 जनवरी को 'विश्व ब्रेल दिवस' (वर्ल्ड ब्रेल डे) के रूप में मनाया जाता है, क्यों कि आज ही के दिन ब्रेल लिपि(नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए एक लिपि) के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा और उनके लिए समान अवसरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रेल कोई भाषा नहीं, बल्कि यह एक लिपि है, जिसे दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अपनाया जा सकता है। केवल छह उभरे बिंदुओं के संयोजन से अक्षर, अंक, गणितीय चिह्न, संगीत संकेत और यहां तक कि कंप्यूटर कोड भी पढ़े-लिखे जा सकते हैं। जानकारी मिलती है और लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का विकास मात्र 15 वर्ष की उम्र में किया था। आज ब्रेल केवल कागज तक सीमित नहीं है। डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल नोट-टेकर और स्मार्ट डिवाइसों ने इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया है, जिससे आज शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। भारत में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए मानकीकृत ब्रेल उपलब्ध है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति के अधिकार को सुदृढ़ करना, समाज में समावेशन (इन्क्लूजन) की भावना को बढ़ावा देना और सुलभ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ब्रेल साक्षरता आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन की आधारशिला है और वास्तव में यही संदेश विश्व ब्रेल दिवस के केंद्र में रहता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि (2026 की थीम के संदर्भ में) उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कोई अनिवार्य/स्थायी आधिकारिक थीम घोषित नहीं करता है तथा 2026 में भी यह दिवस व्यापक रूप से सुलभता, समावेशी शिक्षा और दृष्टिबाधितों के अधिकारों जैसे संदेशों के साथ मनाया जाएगा। कुल मिलाकर, विश्व ब्रेल दिवस हमें याद दिलाता है कि सुलभता कोई सुविधा नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकार है, और ब्रेल लिपि इस अधिकार को साकार करने का सशक्त माध्यम है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस में जन्मे लुईस ब्रेल नेत्रहीनों (अंधों) के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने-लिखने के योग्य बनाया। सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि जिसे ब्रेल के नाम से जाना जाता है, छोटी उम्र में ही विकसित की। पाठकों को यहां जानकारी देना चाहूंगा कि लुई ब्रेल का पारिवारिक जीवन अत्यंत साधारण, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था।उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को कूपव्रे, फ्रांस में हुआ था तथा उनके पिता साइमन-रेने ब्रेल पेशे से चमड़े का काम (हार्नेस बनाने) करते थे, जबकि माता मोनीक ब्रेल एक गृहिणी थीं। जानकारी मिलती है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन माता-पिता ने बच्चों को संस्कार, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया।लुई ब्रेल अपने परिवार के चार बच्चों में सबसे छोटे थे। कहते हैं कि मात्र तीन वर्ष की उम्र में पिता की कार्यशाला में खेलते समय एक औजार से उनकी आंख में चोट लगी, जो संक्रमण के कारण धीरे-धीरे पूर्ण दृष्टिहीनता में बदल गई। इस दुर्घटना के बाद परिवार ने उन्हें बोझ नहीं समझा, बल्कि हर संभव सहयोग दिया। माता-पिता ने उनके आत्मविश्वास को बनाए रखा और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया।लुई ब्रेल का विवाह नहीं हुआ तथा उनका पूरा जीवन शिक्षा, अध्ययन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी लेखन प्रणाली के विकास को समर्पित रहा। परिवार का भावनात्मक सहारा और बचपन में मिले संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने ऐसी लिपि विकसित की, जिसने दुनिया भर के करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन को रोशन किया।पिता के साथ काम करने के दौरान एक हादसे में पहले उनकी एक ही आंख खराब हुई थी, लेकिन बाद में उनकी दूसरी आंख की रौशनी भी चली गई थी तथा आर्थिक तंगी के कारण उन्हें सही से इलाज भी न मिल सका और 8 साल की उम्र में ही लुईस ब्रेल को दिखाई देना बंद हो गया था।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)

'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

जीवन की हकीकत से दूर बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी

मनोज कुमार अग्रवाल

आज की नई पीढ़ी सपनों में जी रही है सोशल मीडिया रील ओटीटी पर परोसी जा रही लिव-इन रिलेशनशिप लव अफेयर्स सुसाइड हिंसा की काकटेल यूथ लाइफ पर इस तरह हावी हो रही है कि बिना सोचे समझे जस्ट डिसीजन जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। उस पर मल्टी अफेयर्स विवाह पूर्व और विवाहेत्तर स्वछंद सेक्स रिलेशन युवा जोड़ों के वैवाहिक जीवन को त्रास रहे हैं। एक ओर स्वछंद जीवन जीने की ललक है दूसरे ओर वर्जित संबंधो से बचाव की वर्जना इन दोनों का एक साथ संयोग बनाने की कवायद में बहुत सारे कपल अंकंफर्ट हो रहे हैं और नतीजा कभी मेरठ की मुस्कान के नीले ड्राम तो कभी हनीमून ट्रिप पर राजा रघुवंशी के कत्ल के बतौर सामने आ रहा है। वहीं तमाम समाज और परिवार की परंपराओं को तोड़ कर लव मैरिज कर रहे कपल भी फास्टफूड की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं और एक दूसरे को समझने परखने समझौता करने का आत्मविश्वास खो कर पलक झपकते ही सुसाइड जैसे आत्मघाती फैसले ले रहे हैं दरअसल पेरेंट्स के प्रति सम्मान कम हो रहा है बुजुर्गों के पास समय देना पल भर बैठना भी आज के यूथ को बेकार लगता है ऐसे में उसे जीवन बोध से कौन अवगत करा सकता है वह सिर्फ रील देखता है इंसटा चलाता है फास्ट फूड खाता है और जिंदगी को अपने मुताबिक जीने की ललक में लगातार जिंदगी से दूर होता जा रहा है इस सब जीवन द्वंद को दो दिन में सामने आई दो घटनाओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु में शादी के बाद हनीमून से लौटे एक जोड़े ने झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। पत्नी गानवी की मौत के दो दिन बाद पति सूरज ने नागपुर के एक होटल में फांसी लगा ली। गानवी के परिवार ने सूरज और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सूरज की मां ने भी आत्महत्या का प्रयास किया और उनकी हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के दो दिन बाद नागपुर के एक होटल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक पत्नी के माता-पिता ने सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।

चुनौतियों के बावजूद भारत आर्थिक विकास की ओर

संजीव

भारत विश्व के उन विशिष्ट राष्ट्रों में है जहाँ भौगोलिक विविधता एक ओर गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है तो दूसरी ओर वही विविधता उसकी सामरिक और आर्थिक शक्ति का आधार भी बनती है, उत्तर में हिमालय की दुर्गम और हिमाच्छादित पर्वतमालाएँ प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं परंतु साथ ही सीमावर्ती अवसंरचना, परिवहन और संचार के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं, दक्षिण में फैला विशाल हिंद महासागर भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनाता है लेकिन समुद्री सुरक्षा, तटीय आपदाएँ और अंतरराष्ट्रीय नौवहन की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ाता है, पश्चिम का थार मरुस्थल जल संकट, सीमित कृषि और जीवन की कठोर परिस्थितियों की चुनौती देता है तो पूर्व का गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, बाढ़ और भूमि क्षरण जैसी समस्याओं से जूझता है, इसके बावजूद भारत ने इन भौगोलिक विषमताओं को रणनीतिक अवसरों में परिवर्तित करते हुए निरंतर प्रगति की है, लगभग 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा ने भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका दी है जहाँ वैश्विक व्यापार का बड़ा भाग संचालित होता है और भारतीय नौसेना ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है, हिमालयी क्षेत्रों में अटल सुरंग, सीमावर्ती सड़कों और ऑल-वेदर परियोजनाओं ने सामरिक गतिशीलता के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी गति दी है, भौगोलिक स्थिति के कारण भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला स्वाभाविक सेतु बनता है और इसी कारण अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा तथा भारतझ्रमध्य पूर्वझ्रयूरोप आर्थिक गलियारे जैसी पहलें भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को सुदृढ़ करती हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत की यात्रा आसान नहीं रही है क्योंकि विशाल जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, अविकसित अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ लंबे समय तक विकास में बाधक रहीं।

कहानी

तीन मछलियां

एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता हैं, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत-सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लम्बी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार हैं करने कराने से कुछ नहीं होता जो किस्मत में लिखा है, वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिकाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके । एक ने अनुमान लगाया 'दोस्तो! लगता हैं झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय हैं, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। ' मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे।

एक मछुआरा बोला 'अहा! इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा।' 'यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी।' दूसरा बोला। तीसरे ने कहा 'आज तो शाम घिरने वाली हैं। कल सुबह ही आकर यहां जाल डालेंगे। ' इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछि्लयों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा 'साथियो! तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं हैं। खतरे की सूचना हमें मिल गई हैं। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूं। उसके बाद मछुआरे सुबह आएं, जाल फेंके, मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होऊंगी।' प्रत्यु मछली बोली 'तुम्हें जाना हैं तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहां हैं, जो इतना घबराने की जरूरत है हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों का यहां आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है, हो सकता हैं रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है। उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता हैं या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती हैं और बाढ में उनका गांव बह सकता हैं। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं हैं। जब वह आएंगे, तब की तब सोचेंगे। हो सकता हैं मैं उनके जाल में ही न फंसूं। ' यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही 'भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना हैं तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना हैं तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा हैं तो क्या किया जा सकता हैं? ' इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने । प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने । उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आस-पास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही हैं। वह उसके बचाव के काम आ सकती हैं। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी।

कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक

इंडिगो प्रकरण की ही बात करें तो विमानन नियामक ने इस कंपनी को ऐसी गुंजाइश ही क्यों दी कि वह बाजार के 65 प्रतिशत हिस्से पर काबिज हो सके। उसे परिचालन विस्तार के लिए ऐसी अनुमति कैसे मिलती गई कि वह नियामक को ही अपनी अंगुलियों पर नचा सके? ऐसे में डीजीसीए के ढांचे और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्या उसके अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं या महज उसमें नियुक्ति पाने वाले नौकरशाह ही हैं। दिसंबर की शुरुआत में विमान सेवाओं के एक बड़े हिस्से के करीब-करीब ठप पड़ने के कई सप्ताह बाद भी इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं।

जहां तक अरावली मुद्दे का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने उस फैसले पर स्थगन का निर्णय किया। नवंबर में अदालत ने सरकार द्वारा गठित 'विशेषज्ञ पैनल' द्वारा दी गई एक अजीब परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। इसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। जहां मंत्रालय ने अपनी तथाकथित 'विशेषज्ञ समिति' की इस राय का जोरदार बचाव किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में इसके विपरीत रुख अपनाया। सरकार की 'विशेषज्ञ समिति' की बात करें तो उसमें अधिकांश सदस्य

नए साल में कुछ नई चुनौतियां भी साथ आई हैं। देश और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को इन चुनौतियों का सामना करना है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चुनौतियों के कुछ तार कहीं न कहीं पिछले साल से भी जुड़े हुए हैं। अस्थिरता के शिकार वैश्विक ढांचे में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जो अनिश्चितता बढ़ाई, उससे उपजी चुनौतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता से संभाला। हालांकि इंडिगो संकट, अरावली खनन, प्रदूषण से कराहती राष्ट्रीय राजधानी के मुद्दे बेहद परेशान करने वाले रहे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक को मिली राहत जैसी घटना भी चौंकाने वाली रही। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना में जिंदा जले लोग भी राज्य सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार के शिकार बने। यह भी एक दुर्योग रहा कि ऐसे सभी मामले साल की अंतिम तिमाही के दौरान सामने आए, जो कहां न कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के पास न केवल केंद्रीय, बल्कि राज्यों के स्तर पर भी सक्षम मंत्रियों एवं नौकरशाहों का अभाव है, जो एक पारदर्शी एवं प्रभावी सरकार की योजनाओं को लागू करने में सहायक बन सकें। इंडिगो प्रकरण की ही बात करें तो विमानन नियामक ने इस कंपनी को ऐसी गुंजाइश ही क्यों दी कि वह बाजार के 65 प्रतिशत हिस्से पर काबिज हो सके। उसे परिचालन विस्तार के लिए ऐसी अनुमति कैसे मिलती गई कि वह नियामक को ही अपनी अंगुलियों पर नचा सके? ऐसे में डीजीसीए के ढांचे और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्या उसके अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं या महज उसमें नियुक्ति पाने वाले नौकरशाह ही हैं। दिसंबर की शुरुआत में विमान सेवाओं के एक बड़े हिस्से के करीब-करीब ठप पड़ने के कई सप्ताह बाद भी इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जहां तक अरावली मुद्दे का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने उस फैसले पर स्थगन का निर्णय किया। नवंबर में अदालत ने सरकार द्वारा गठित 'विशेषज्ञ पैनल' द्वारा दी गई एक अजीब परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। इसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। जहां मंत्रालय ने अपनी तथाकथित 'विशेषज्ञ समिति' की इस राय का जोरदार बचाव किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में इसके विपरीत रुख अपनाया। सरकार की 'विशेषज्ञ समिति' की बात करें तो उसमें अधिकांश सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ न होकर नौकरशाह ही थे। इस मामले को लेकर रुख बदलने में मीडिया के सवालों की अहम भूमिका रही है। मीडिया के माध्यम से ही यह हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने दर्जनों खनन पट्टों को त्वरित गति से स्वीकृति प्रदान की। यदि यह सच है तो एक बड़ी विडंबना को ही दर्शाता है कि खनन माफिया पूरे परिदृश्य को किस हद तक प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार इस मामले में समय से स्पष्टता नहीं दिखा सकी, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई। यह किसी से छिपा नहीं रह गया है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में नए कीर्तिमान बनाती जा रही है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के पास इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिहाज से कुछ उल्लेखनीय नहीं है। बीते साल कुछ दिनों के दौरान एक्यूआइ का आंकड़ा 500 से 1,000 तक पहुंचता दिखा, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने किसी निदान के बजाय दोषारोपण का सहारा लेने को ही प्राथमिकता दी। कभी पराली को लेकर अंगुली उठाई गई तो कभी आम आदमी पार्टी पर। प्रदूषण से निपटने में किसी कारगर कार्ययोजना के मामले में दिल्ली सरकार भी अकर्मण्य ही नजर आई। इसका ही परिणाम है कि दिल्ली रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक शहर बन गया है। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। गुजरे हुए साल के अंतिम दिनों में उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत भी चर्चा के केंद्र में रही। सीबीआइ की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट भी दिया। कुछ वर्ष पूर्व यह मामला सामने आने के बाद सेंगर को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे व्यक्ति को पहले-पहल भाजपा में शामिल ही क्यों किया गया? इस पूरे मामले में कई कानूनी सवाल भी उठते हैं, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर जेल में बंद है। सेंगर पर सख्ती के मामले में भी मीडिया के रुख की अहम भूमिका रही। गोवा का नाइट क्लब भी शासन-प्रशासन के स्तर पर घोर लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण रहा।

सम्पादकीय

कॉलेज में रैगिंग-एक छात्रा, कई आरोपी और एक असफल व्यवस्था

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाने के सपनों के साथ किसी कालेज में दाखिला ले और वहां परिचय के नाम पर होने वाली प्रताड़ना की वजह से उसकी जान चली जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की रैगिंग के चलन पर पाबंदी है, लेकिन आज भी इसके बहाने अलग-अलग रूप में विद्यार्थियों को जानलेवा शक्ल में प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा के साथ रैगिंग का जैसा मामला सामने आया है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि किसी भी रूप में इस चलन का जारी रहना शिक्षा से लेकर समाज तक के कितने हित में है। साथ ही, तमाम सख्ती के बावजूद आज भी इस पर रोक क्यों नहीं लग सकी है? गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित एक कालेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर के विरुद्ध पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले के मुताबिक, बीते 18 सितंबर को पिटाई और प्रताड़ना की वजह से पीड़ित छात्रा की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस घटना में शर्मनाक यह भी है कि कालेज के जिस प्राध्यापक को उत्पीड़न की घटना को रोकना चाहिए था, वह खुद भी छात्रा को प्रताड़ित करने में शामिल हो गया। इस घटना में संस्थान भी कठघरे में है, क्योंकि वहां का प्रबंधन रैगिंग के नाम पर होने वाली ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। हिमाचल प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी विद्यार्थी को रैगिंग की वजह से जानलेवा हद तक यातना दी गई। करीब डेढ़ दशक पहले राज्य में कांगड़ा के एक कालेज में मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र अमन काचरू के साथ वहीं के चार वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग के दौरान मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। ऐसी कई घटनाओं के जैसे त्रासद नतीजे सामने आए, उससे एक व्यापक बहस खड़ी हुई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नवागंतुक विद्यार्थियों की रैगिंग को क्यों नहीं तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इसी क्रम में कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाए गए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी। यह समझना मुश्किल है कि कालेज में कुछ वरिष्ठ कहे जाने वाले विद्यार्थियों के भीतर नए विद्यार्थी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करने के मानसिक ढांचे के स्रोत क्या हैं! क्या इसके पीछे किसी नवागंतुक विद्यार्थी के मनोबल को तोड़ देने की मंशा काम करती है? आपसी परिचय या सहजता के नाम पर किसी विद्यार्थी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि वह उसके लिए जानलेवा साबित हो, क्या एक सामंती कुंठा का परिचायक नहीं है? अगर परिचय के नाम पर यातना देने के चलन को आपस में सहज होने के लिए सिर्फ मनोविनोद के रूप में देखा-जाना जाता है, तो क्या यह एक आपराधिक तरीका नहीं है, जिसमें कालेज में आए एक नए विद्यार्थी के मन पर गहरी चोट पहुंचती है, वह खुद को अपमानित महसूस करता है, उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है?

पूर्वोत्तर भारत की पीड़ा समझें

पूर्वोत्तर भारत का सबसे मनोरम, प्राकृतिक सुषमा से युक्त वीरों और प्रज्ञावान युवाओं का क्षेत्र है, जिसको राममनोहर लोहिया ने यक्ष प्रदेश कहा था। आठ प्रदेशों की पांच हजार किमी सीमाएं चीन, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से मिलती हैं। सर्वाधिक संख्या में प्रतिबंधित संगठन पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं। मोदी शासन आने से पूर्व यहां असम के अलावा अन्य राज्यों में रेल, हवाई अड्डे नामालूम थे। 2024-25 के बजट में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का बजट 74.4 प्रतिशत बढ़ाया गया। 2014-15 की तुलना में मोदी शासन में पूर्वोत्तर के लिए कुल बजट 179 प्रतिशत बढ़ाया गया। हवाई अड्डे, राजमार्ग, ईटानगर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बेहतर शिक्षा एवं खेल सुविधाएं, इन सबका अनंत और असीम विस्तार हुआ है, पर इससे भारत के शत्रु तत्व और बौखला गए हैं। पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की षड्यंत्रकारी योजनाएं ब्रिटिश

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में कुछ गुंडों के हमले में मौत की हृदयद्रावक घटना की पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। पूर्वोत्तर के सामाजिक संगठन, नेता इस घटना से काफी रोष में हैं। इस समय मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ही हूं, क्योंकि मुझे एंजेल चकमा के स्वजनों से मिलना है। इस घटना ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं।

कुछ लोग इस घटना पर गिद्ध राजनीति कर दुर्भाग्यपूर्ण शोकांतिका का असम एवं अन्य क्षेत्रों में आसन्न चुनावों के लिए जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, उससे समाज में विष बढ़ने का भय है। मृतक चकमा समाज का होनहार युवक था। चकमा मूलतः चटगांव निवासी, बौद्ध मतावलंबी एवं शांतिप्रिय लोग हैं। पंडित नेहरू की दुर्नीति के कारण चटगांव को गैर-मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध बहुल होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में जाने दिया गया। तब हजारों चकमाओं का नरसंहार हुआ।

उन्हें शरण के लिए भारत आना पड़ा, लेकिन भारत के ईसाई बहुल पूर्वोत्तर राज्यों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मिजोरम के ईसाई छात्र संगठनों ने 1990 के दशक में चकमाओं के घर जलाए और उन्हें त्रिपुरा सीमा के पार धकेल दिया। तब चकमाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री भेजी थी। आज जो लोग एंजेल चकमा की हत्या को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, उन्होंने कभी चकमाओं की विपत्ति समय में सहायता नहीं की। चकमा लोग पूरे भारत में मात्र साढ़े पांच लाख हैं और मुख्यतः मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। जहां वे ईसाई बहुल राज्यों में हैं, वहां उनके साथ भेदभाव होता है। उनके क्षेत्रों में सड़कें नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। चकमा गांवों के नाम भी बदले गए हैं। इसलिए वे शिक्षा हेतु अपने बच्चे देहरादून, दिल्ली, बेंगलुरु आदि भेजने पर विवश होते हैं। पूर्वोत्तर

भारत का सबसे मनोरम, प्राकृतिक सुषमा से युक्त वीरों और प्रज्ञावान युवाओं का क्षेत्र है, जिसको राममनोहर लोहिया ने यक्ष प्रदेश कहा था। आठ प्रदेशों की पांच हजार किमी सीमाएं चीन, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से मिलती हैं। सर्वाधिक संख्या में प्रतिबंधित संगठन पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं। मोदी शासन आने से पूर्व यहां असम के अलावा अन्य राज्यों में रेल, हवाई अड्डे नामालूम थे। 2024-25 के बजट में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का बजट 74.4 प्रतिशत बढ़ाया गया। 2014-15 की तुलना में मोदी शासन में पूर्वोत्तर के लिए कुल बजट 179 प्रतिशत बढ़ाया गया।

हवाई अड्डे, राजमार्ग, ईटानगर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बेहतर शिक्षा एवं खेल सुविधाएं, इन सबका अनंत और असीम विस्तार हुआ है, पर इससे भारत के शत्रु तत्व और बौखला गए हैं। पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की षड्यंत्रकारी योजनाएं ब्रिटिश काल में क्राउन कालोनी के नाम से चलीं। ब्रिटिश काल में ही सादुल्लाह के नेतृत्व में असम की मुस्लिम लीग ने अपील जारी कर युवकों से ज्यादा बच्चे पैदा करने और असम में ज्यादा मुस्लिम भेजने का अभियान चलाया। असम तथा पूर्वोत्तर भारत पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसका षड्यंत्र रचा गया।

एंजेल चकमा का परिवार एक देशभक्त और बौद्ध मतावलंबी है। वातावरण के कारण वहां कुछ परिवारों में पश्चिमी नाम रखने का अजीब फैशन है। इसलिए माइकल या एंजेल नाम सुनने में आते हैं। यह समय हर परिस्थिति में पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ खड़े होने का है और उन्हें अपनेपन का अहसास कराना राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा का सवाल

यह ठीक है कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य सामान की डिलीवरी करने वाले अस्थायी कामगारों यानी गिग वर्करों की ओर देश का ध्यान गया, लेकिन ऐसा तब हो पाया, जब विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। गिग वर्करों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्यदशाएं काफी कठोर हैं। आज जब क्विक कामर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तब उनके लिए काम की बेहतर दशाएं सुनिश्चित की ही जानी चाहिए। यह संतोषजनक तो है कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन बात तब

बनेगी, जब इस प्रस्ताव के प्रविधानों को सही तरह लागू करने में सफलता मिलेगी। गिग वर्करों की समस्या यह है कि वे जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। उनके काम के घंटे भी तय नहीं हैं। वे जितने समय काम करते हैं, उतने ही वक्त का उन्हें पैसा मिलता है। उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। चूंकि उनकी स्थिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसी है, इसलिए उनकी कार्यदशाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि उनके साथ कुछ अनहोनी जाए तो संबंधित कंपनी की जवाबदेही नहीं होती। यह समझा जाना चाहिए कि गिग वर्कर आधारित उद्योग बेहतर नियमन की मांग कर रहा है। गिग वर्करों की समस्याएं इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि दस मिनट में भी सामान की डिलीवरी करने का चलन जोर पकड़ गया है। इस चलन पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे गिग वर्करों के साथ दुर्घटनाएं होने का जोखिम बढ़ गया है। कई बार गिग वर्कर शीघ्र सामान पहुंचाने के फेर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखते हैं। निःसंदेह गिग वर्कर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाले मेहनताने को आकर्षक नहीं कहा जा सकता। नीति आयोग के अनुसार 2020-21 में जो गिग वर्कर 77 लाख के करीब थे, उनकी संख्या 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सरकार के साथ उन कंपनियों को भी उनकी सुधि लेनी होगी, जिनके लिए वे काम करते हैं। उन्हें केवल सामाजिक सुरक्षा के ही दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए, जिससे उनका शोषण न हो सके और वे अपने भरणपोषण लायक आय अर्जित कर सकें।

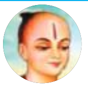

तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुं ओर।
बसीकरन इक मंत्र है, परिहरू बचन कठोर।।

संत तुलसीदास कहते हैं, मीठे बोल से हम सब तरफ सुख फैला सकते हैं। किसी को भी वश में करने के लिए मिठास भरे शब्द मंत्र सरीखे होते हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर बातें छोड़कर मीठा बोलने की कोशिश करे और अनजानों को भी अपना बना लें।

भारतीयों की रुचि पर्यटन के बजाय तीर्थाटन में निहित

भारत का मन उत्सवी है। भारतीयों की रुचि पर्यटन के बजाय तीर्थाटन में रही है। पर्यटन और तीर्थाटन में मूलभूत अंतर है। पर्यटन में अच्छा खाना, अच्छे होटल और अच्छी सुख-सुविधाएं जरूरी होती हैं, लेकिन तीर्थाटन में इन कारकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती। तीर्थाटन में प्राय: किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जहां नदियां आपस में मिलती हैं। जहां प्रकृति खिलती है, जहां किसी न किसी देवता के दर्शन की अभिलाषा रहती है। प्रयागराज इसका जीवंत उदाहरण है।

भारतीय संस्कृति उत्सवधर्मा है। यहां बारहों महीने उत्सव चलते हैं। 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक ऋतु के अपने उत्सव हैं। वर्षा और बसंत प्रकृति प्रायोजित उत्सव हैं। शिशिर और हेमंत का क्या कहना। होली सनातन उल्लास है। व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र की भी ऊर्जा होती है। जैसे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही समाज और राष्ट्र को स्वस्थ रखने के प्रयास जरूरी हैं और यह प्रयास संस्कृतिधर्मा लोगों द्वारा किया जाता रहता है। उत्स का अर्थ होता है मूल। उत्सव का अर्थ है देश के मूल से जुड़ी सामाजिक सक्रियता।

संस्कृति मनुष्य की रचना है। संस्कृति का निर्माण सतत् प्रवाही प्रक्रिया है। भारत के मन की संस्कारमय संस्कृति प्राचीन ज्ञान परंपरा में निहित है। भारत की संस्कृति का जन्म और विकास ज्ञान व दर्शन की परंपरा से हुआ है। भारतीय दर्शन में बुध और जैन को मिलाकर आठ दार्शनिक धाराएं हैं। भारत के राष्ट्र जीवन के सभी धाराओं ने प्रभावित किया है। कपिल का सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी माना जाता है। बुद्ध व जैन दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अद्वैत वेदांत का प्रभाव काफी बड़ा है। अद्वैत की धारा शंकराचार्य के पहले से थी, लेकिन शंकराचार्य ने उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र के तत्वों के आधार पर ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा है। वे घर बैठ तर्क का आनंद उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे।

शंकराचार्य ने देश की एकता को देखते हुए चार धामों की घोषणा की। उन्होंने उत्तर में ऊंचे पहाड़ों पर बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और पश्चिम में द्वारका की। पूरब में जगन्नाथ पुरी की और दक्षिण में रामेश्वरम् की। चारों स्थान पहले बहुत प्रतिष्ठित नहीं थे, लेकिन शंकर की घोषणा के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गए। भारत का मन उत्सवी है। भारतीयों की रुचि पर्यटन के बजाय तीर्थाटन में रही है। पर्यटन और तीर्थाटन में मूलभूत अंतर है। पर्यटन में अच्छा खाना, अच्छे होटल और अच्छी सुख-सुविधाएं जरूरी होती हैं, लेकिन तीर्थाटन में इन कारकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती। तीर्थाटन में प्रायः किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जहां नदियां आपस में मिलती हैं। जहां प्रकृति खिलती है, जहां किसी न किसी देवता के दर्शन की अभिलाषा रहती है। प्रयागराज इसका जीवंत उदाहरण है।

ऋषिकेश की गगनचुंभी पहाड़ियों के दरश परश से मन संगीतमय हो जाता है। ऋग्वेद में नदियों से पार उतरने के लिए उथले स्थल को तीर्थ बताया गया है। जहां से हम आसानी से नदी पार कर सकते हैं। उपासना परंपरा में किसी देवता के नाम से चले आ रहे पुण्य स्थान तीर्थ कहलाते हैं। कुंभ (प्रयागराज) में सारी दुनिया के लोग आते हैं। करोड़ों लोगों का यह एकत्रीकरण गंगा, जमुना व सरस्वती का संगम बनता है।

हृदय नारायण दीक्षित
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश

प्रयागराज दुनिया का आकर्षण है। ऐसे ही हरिद्वार, रामेश्वरम्, तिरुपति, कांचीपुरम् आदि अनेक स्थलों पर तीर्थ यात्री भूखे-प्यासे चले जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी ऐतिहासिक तीर्थ हैं। काशी में शिव दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। वैसे भारतीय दर्शन में तीर्थाटन की तुलना में दर्शन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को सत्य मानते हुए कर्मकांड को भी उचित बताया है। उन्होंने काशी के प्रवास में अपना दर्शन सबको बताया था। ब्रह्म को एकमात्र सत्य और संसार को मिथ्या बताने वाले आचार्य शंकर के दर्शन ने परवर्ती संतों का ध्यान भी आकर्षित किया था। शंकराचार्य जगत् को मिथ्या बताते थे।

भारत स्वयं में एक तीर्थ है। सारी दुनिया को परिवार बताने वाला यह राष्ट्र शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। आवागमन के साधन बढ़े हैं। शंकराचार्य के समय न साइकिल थी न रेल। आश्चर्य है कि आचार्य ने कैसे भारत भ्रमण किया होगा? अब आवागमन के द्रुतगामी साधन बढ़े हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी अल्प समय में तय की जा सकती है। आधुनिक सभ्यता के दबाव में देश के लोगों का एक वर्ग तनाव में रहता है। वह तीर्थाटन का मजा नहीं लेता। पर्यटन को महत्व देता है।

पर्यटन से मानसिक शांति नहीं मिलती। तीर्थाटन से लौटे परिवार आनंद से भरे-पूरे दिखाई पड़ते हैं। भारत राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मविश्वास से भरा पूरा है। पर्यटन उद्योग बन गया है। पर्यटन की दृष्टि से महात्मा गांधी के जन्म और कर्म स्थान साबरमती जाना अपने आप में जीवंत अनुभव है। सरदार पटेल की प्रतिमा केवड़िया, गुजरात में दर्शनीय है। डॉक्टर आंबेडकर के दिल्ली सहित कई स्थानों पर बने स्मारक दर्शनीय हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणास्थल भी दर्शनीय है।

यज्ञ में काफी धन लगता था, इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ का विकल्प तीर्थ यात्रा बताया गया है। महाभारत वन पर्व के 42वें अध्याय में यज्ञ के विकल्प की चर्चा की गई है। पुलस्त्य भीष्म से कहते हैं, 'ऋषियों के अनुसार यज्ञ करने से इस लोक और परलोक में फल मिलता है।' परंतु गरीब मनुष्य यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते। उनके पास साधन नहीं होते, इसलिए जो साधनहीन हैं, वे तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा को यज्ञ के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, 'मनुष्य तीर्थ यात्रा से जो फल पाता है, वह बड़े से बड़े यज्ञों से नहीं मिलता।'

महाभारत के रचनाकाल में ज्यादातर तीर्थ कुरुक्षेत्र के आसपास थे। पुष्कर तीर्थ का महत्व बताते हुए कहते हैं, 'पुष्कर में दस सहस्त्र कोटि तीर्थ का निवास रहता है।' यहां पुष्कर तीर्थ का महत्व बताने कि लिए दस खरब तीर्थों की उपस्थिति बताई गई है। बताते हैं कि पुष्कर में ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। यहां स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का दस गुना फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है।

महाकाल (उज्जैन) में शिव के दर्शन से हजार गोदान का फल मिलता है। ऐसी बहुत सी नदियां हैं, जिनमें स्नान करने से यज्ञ के फल मिलते हैं। नर्मदा सहित अनेक नदियों में स्नान से यज्ञों के फल मिलते हैं। महाभारत के रचनाकाल में सरस्वती पर्याप्त जल से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये बाद में सूखीं। सिंधु और सागर के मिलन स्थल पर स्नान करने से वरुण लोक मिलता है। सरस्वती ऋग्वेद के ऋषियों की प्रिय नदीतमा हैं। पुलस्त्य कहते हैं कि वायु द्वारा उड़ा कर लाई गई कुरुक्षेत्र की धूल से मनुष्य को परम गति मिल जाती है। जो यहां नहीं रहते कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा करें। तीर्थ की प्रशंसा मजेदार है। बताते हैं, भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र तीर्थ है।

देवी उपासना भारत में वैदिक काल से स्पष्ट दिखाई देती है। ऋग्वेद में जल माताएं हैं। वन देवी हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल देवी उपासना का महत्वपूर्ण केन्द्र है। मध्य प्रदेश का दतिया और असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शनार्थ पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। तीर्थाटन से मिलने वाले लाभ व हानि पर आग्रही बहस चलना जरूरी नहीं है। मुख्य बात है देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भारत भक्तों का आवागमन। शंकराचार्य ने इसीलिए चारों धामों की स्थापना की थी। प्रत्येक तीर्थ के साथ अविश्वसनीय कथाएं चलती हैं। इन्हें बड़े सरल ढंग से अंधविश्वास कहा जा सकता है, लेकिन पर्यटन का विकल्प तीर्थाटन ही है।

मशीन बनते कर्मचारी और उनकी मुश्किलें

इंटरनेट युग ने मनुष्य की जीवन शैली को 'हैक' कर के उन्हें मशीन बना दिया है। कोरोना काल में सुरक्षा के मद्देनजर सहूलियत के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जब शुरुआत हुई, तो घर और कार्यालय के मध्य सूक्ष्म मानसिक और शारीरिक सीमाओं का अतिक्रमण हुआ। उसके पश्चात से सरकारी, निजी व बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान में अब एक धारणा आम हो गई है कि आप 24 घंटे के नौकर हैं। हर समय घर में कार्य अवधि के पश्चात या अवकाश में यदि आपको ऑफिस से कॉल या मेल आता है, तो आपकी त्वरित प्रतिक्रिया अपेक्षित है, जिससे कई बार व्यक्ति सुकून भरे अवकाश के क्षणों में भी तनाव, चिंता और मानसिक थकान का अनुभव करता है। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी अवकाश में होता है, लेकिन मानसिक रूप से वह कार्यालय संबंधी काम की चिंता में होता है।

बीना नयाल
शिक्षिका

इसी तनाव के चलते कार्यस्थल पर होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष पुणे की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबस्टियन की काम के दबाव के कारण मौत हो गई थी, जिसका मुख्य कारण काम व निजी जिंदगी में उचित प्रबंधन न कर पाना बताया गया। स्वतंत्रतोत्तर भारत में संविधान निर्माण के दौरान जो छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, वह उस दौर की मांग थी, जो आज परिपक्व हो चुके हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट वर्तमान समय की मांग है।

निजी और खास तौर से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अब एक धारणा आम हो गई है कि आप 24 घंटे के नौकर हैं। कार्य अवधि के पश्चात घर में या अवकाश में यदि आपको ऑफिस से कॉल या मेल आता है, तो आपकी त्वरित प्रतिक्रिया अपेक्षित है। यह बातें जीवन में तनाव पैदा करती हैं।

आवश्यकतानुसार तकनीक से डिस्कनेक्ट होकर हम अपने पर्सनल स्पेस को सुकून से जी सकते हैं और वास्तविक दुनिया में अपने परिवार, दोस्तों व प्रकृति से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक हमें न केवल कार्य के पश्चात मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सदैव हाथ में रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर जरूरी सूचनाओं के मस्तिष्क में अवशोषण व सोशल मीडिया में घुमक्कड़ी पर भी युक्ति संगत प्रतिबंध लगाएगा। इस बिल की वर्तमान समय में भारत के लिए प्रासंगिकता और भी अधिक इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रांस, पुर्तगाल, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित राष्ट्र पहले से ही इस अधिकार को अपने देश में लागू कर चुके हैं। साथ ही देश में ईमानदार, निष्ठावान और समर्पित कार्यशैली का भी होना आवश्यक है, जहां कर्मचारी आवंटित कार्य को नियत समय सीमा में पूरा करें, जिससे न संस्थान के सुचारु संचालन में दिक्कत हो और न ही कर्मचारियों का पर्सनल स्पेस बाधित हो।

अधिकारियों में भी यह संस्कृति विकसित की जानी चाहिए कि पर्सनल संबंध और प्रोफेशनल संबंधों को अलग रखें। पर्सनल संबंध खराब होने पर कर्मचारियों को कार्य संबंधित तनाव और दबाव न दें और आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसरों को बनाए रखें। कर्मचारियों की खुशहाल जिंदगी, बेहतर मानसिक और शारीरिक स्थिति कार्य स्थल में उनकी दक्षता व गुणवत्ता में वृद्धि कर उनके बेहतर निष्पादन की राह सुनिश्चित करनी चाहिए।

समुद्र की गहराइयों में नारी शक्ति की गूंज

पिछले दिनों जब भारत की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी 'आईएनएस वाघशीर' पर सवार होकर समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया, वह क्षण भारत के सैन्य इतिहास में एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर बन गया। उनकी यह यात्रा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह भारत की समुद्री शक्ति, रक्षा आत्मनिर्भरता, महिला नेतृत्व और हिंद महासागर क्षेत्र में देश की निर्णायक भूमिका का सशक्त प्रदर्शन थी। राष्ट्रपति मुर्मू न केवल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पनडुब्बी यात्रा की बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि भारत अब तकनीकी, रणनीतिक और नेतृत्व, तीनों स्तरों पर नया आत्मविश्वास अर्जित कर चुका है।

योगेश गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

लगभग 19 वर्ष पहले फरवरी 2006 में भारत के राष्ट्रपति 'मिसाइल मैन' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने आईएनएस सिंधु रक्षक में समुद्री यात्रा की थी। तब से लेकर अब तक भारत का रक्षा परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। जो राष्ट्र तब विदेशी प्रणालियों पर निर्भर था, वह आज आत्मनिर्भरता और उन्नत तकनीकी क्षमता के साथ समुद्र की गहराइयों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा इस ऐतिहासिक निरंतरता को नया आयाम देती है। यह केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रपति की एक सक्रिय, संलग्न और रणनीतिक भूमिका का प्रतीक है, जहां सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं उन चुनौतियों और अवसरों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, जिनसे हमारे सशस्त्र बल प्रतिदिन जूझते हैं।

'आईएनएस वाघशीर' प्रोजेक्ट-75 स्कॉर्पीन कार्यक्रम की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना में जनवरी 2025 में शामिल हुई थी। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने फ्रांस की कंपनी 'नेवल ग्रुप' के तकनीकी सहयोग से किया। यह सहयोग अब केवल तकनीक हस्तांतरण का मॉडल नहीं रहा, बल्कि 'मेक इन इंडिया' की वास्तविक सफलता का उदाहरण बन चुका है। भारत आज न केवल जटिल नौसेना प्रणालियों को जोड़ने में सक्षम है, बल्कि उनमें नवाचार करने की दिशा में भी अग्रसर है। तकनीकी रूप से वाघशीर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में गिनी जाती है। लगभग 67 मीटर लंबी और 1,565 टन वजनी यह पनडुब्बी 350 मीटर तक गोता लगाने और पानी के नीचे 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है।

आईएनएस वाघशीर का उन्नत स्टील्थ डिजाइन इसे दुश्मन के सोनार और रडार से लगभग अदृश्य बनाता है। वायर-गाइडेड टॉरपीडो और एंटी-शिप मिसाइलें इसे दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता देती हैं। उच्च-संवेदनशील सोनार और रडार प्रणालियां इस पनडुब्बी को खुफिया जानकारी, निगरानी और विशेष अभियानों के लिए आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती हैं। 50 दिनों तक समुद्र में तैनाती की क्षमता से यह लंबी अवधि के मिशन संचालित कर सकती है।

मौत का पानी व जवाबदेही की सूखी टोटियां

इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यह कोई अचानक आया तूफान नहीं था। यह मौतें धीरे-धीरे आईं, चेतावनी देती रहीं, शिकायतों की शक्ल में दस्तक देती रहीं, लेकिन जलदाय विभाग और जिम्मेदार तंत्र ने उन्हें सुना ही नहीं।

देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा पाने वाला इंदौर आज एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा है, जो किसी एक गली, एक कॉलोनी या एक हादसे तक सीमित नहीं है। भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह 14 घरों में पसरे सन्नाटे की गिनती है, 14 चिताओं की राख है और सैकड़ों बीमार शरीरों की कराह है। जिन शहरों को हम विकास, स्वच्छता और आधुनिक व्यवस्था का मॉडल बताते नहीं थकते, वहीं अगर नल से ज़हर बहने लगे, तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता नहीं तो और क्या है!

भागीरथपुरा की संकरी गलियों में बीते कई दिनों से मातम पसरा है। अरविंद, उम्र 43 वर्ष, कुलकर्णी भट्टा निवासी, इस त्रासदी का 14वां शिकार बना। उससे पहले 21 से 31 दिसंबर के बीच 13 जिंदगियां बुझ चुकी थीं। यह कोई अचानक आया तूफान नहीं था। यह मौतें धीरे-धीरे आईं, चेतावनी देती रहीं, शिकायतों की शक्ल में दस्तक देती रहीं, लेकिन जलदाय विभाग और जिम्मेदार तंत्र ने उन्हें सुना ही नहीं। दो साल से लोग कह रहे थे कि नलों से बदबूदार, गंदा पानी आ रहा है। दो साल से बच्चे बीमार पड़ रहे थे। बुजुर्ग उल्टियां कर रहे थे। घरों में दवाइयों की बोतलें जमा हो रही थीं। अगर तब सुना जाता, तो शायद आज 14 चिताएं न जल रही होतीं।

कांतिलाल मांडोत
वरिष्ठ पत्रकार

पानी जीवन है, यह वाक्य हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब वही पानी मौत बन जाए, तो सवाल सीधे उस विभाग पर जाता है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों तक सुरक्षित जल पहुंचाने की है। जलदाय विभाग की पाइप लाइनों में लीकेज था, यह बात अब सरकारी रिपोर्ट भी मान चुकी है। सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि पाइपलाइन में रिसाव के कारण पानी दूषित हुआ और उसी पानी को पीने से लोग बीमार पड़े और मरे। सांसद ने भी स्वीकार किया कि पानी के सैंपल में जानलेवा बैक्टीरिया मिले हैं, लेकिन यह स्वीकारोक्ति तब आई, जब कई घर उजड़ चुके थे। क्या किसी विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ रिपोर्ट आने के बाद बयान देना है, या समय रहते खतरे को रोकना भी उसका दायित्व है?

स्वास्थ्य विभाग ने करीब आठ हजार घरों का सर्वे किया, ढाई हजार से ज्यादा लोग संक्रमित या संदिग्ध पाए गए, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हुए। यह संख्या बताती है कि समस्या कितनी व्यापक थी। फिर भी जलदाय विभाग की तरफ से न समय पर सप्लाई रोकी गई, न वैकल्पिक व्यवस्था की गई, न ही बड़े स्तर पर चेतावनी जारी की गई। जिन नलों से पानी आता है, वही नल मौत का फंदा बन गए और लोग मजबूरी में वही पानी पीते रहे, जिनके पास बोतलबंद पानी खरीदने की हैसियत नहीं थी, उनके लिए इससे ज्यादा कठिनाई और क्या हो सकती थी?

जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा पहुंचे और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये के चेक देने की कोशिश की गई, तो वह दृश्य अपने आप में व्यवस्था के प्रति लोगों के गुस्से का आईना था। परिजनों ने चेक लेने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए। महिलाओं ने मंत्री को घेरकर कहा कि दो साल से शिकायत कर रहे थे, अगर तब सुन लिया गया होता तो आज इतने लोग नहीं मरते। यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, यह एक मां, एक पत्नी, एक बहन की पीड़ा थी, जिसे चेक से नहीं खरीदा जा सकता।

मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के बयान इस त्रासदी में और नमक छिड़कते नजर आए। कहीं कहा गया कि जांच होगी, कहीं कहा गया कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, कहीं यह बताया गया कि आंकड़े जल्द जारी किए जाएंगे। सवाल यह है कि जब लोग मर रहे थे, तब ये बयान कहां थे? जब बदबूदार पानी की शिकायतें दर्ज हो रही थीं, तब जलदाय विभाग की मशीनरी क्यों नहीं जागी? क्या हर हादसे के बाद यही रटी-रटाई पंक्तियां सुनना ही जनता की नियति है? इंदौर की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। यह उस पूरे देश का आईना है, जहां आजादी के इतने वर्षों बाद भी साफ पानी की गारंटी नहीं दी जा सकी। शहरों में स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं, करोड़ों की परियोजनाएं गिनाई जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग आज भी नल खोलते वक्त डरता है कि पता नहीं आज पानी आएगा भी या नहीं और अगर आएगा तो कैसा आएगा। भागीरथपुरा के लोग आज यही डर जी रहे हैं। पानी की सप्लाई कोई विलासिता नहीं, बल्कि मूलभूत अधिकार है।

जरूरी है कि मन की पांचों ज्ञानेंद्रियों पर नियुक्त रहे 'पहरेदार'

धनाढ्य घरों एवं कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए पहरेदार रखे जाते हैं, जो रात भर जागते हैं तथा चोर-डाकुओं से घर की रक्षा करते हैं। ये पहरेदार लोगों को सजग करते हुए 'जागते रहो' की आवाज़ तथा सीटी बजाते रहते हैं। पहरेदार के 'जागते रहो' की आवाज़ और सीटी बजाने का आशय यह है कि घर तथा कॉलोनी के लोगों को यह एहसास होता रहे कि चौकीदार खुद जाग रहा है तथा सजग स्थिति में है, न कि खुद सो गया है।

सलिल पांडेय
मिर्जापुर

यही स्थिति निजी जीवन की है। घर का मतलब आंतरिक जगत से है, जहां घर का मालिक मन रहता है। मन के पास ही बहुमूल्य संपदा होती है। मन बादशाह की तरह है, तो जीवन में बादशाहियत झलकती है, जबकि यदि मन में बुरी आदतें हैं, तो वह भी बाहरी दुनिया में झलक कर रहेगी ही, क्योंकि मन के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है। अब सवाल उठता है कि मन उत्कृष्ट भाव में रहे तो सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि मन जिन पांच ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित होता हैं, उसमें मुख (जिह्वा), नेत्र, कान, नासिका एवं त्वचा शामिल है।

मन को प्रभावित करने वाले इन पांचों द्वार की हिफाज़त के लिए इन द्वारों पर पहरेदार बैठाना जरूरी होता है, वरना मन तो क्षुद्र चीजों के लिए अधिक लालायित होता है। इन पांचों द्वारों के पहरेदार में मुख का पहरेदार है सात्विक भोजन, क्योंकि आहार की शुद्धता नहीं रहेगी तो मन में विकृतियां पैदा होती रहेंगी। मसलन शराब पीने वाले का मन हमेशा बहका-बहका रहेगा और उसका मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी तरह अखाद्य वस्तुओं के खाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अस्वस्थ व्यक्ति सकारात्मक भाव-विचार का रहे, इसमें संशय है। मुख पर पहरेदार बैठाने पर आहार की शुद्धता के साथ शब्दों की भी शुद्धता रहेगी। अश्लील एवं अशोभनीय शब्द नहीं निकलेंगे।

नेत्र पर पहरेदार बैठाने से नेत्रों में भी अश्लीलता नहीं आएगी और नेत्र बाह्य जगत की सुंदरता एवं प्रकृति की भव्यता पर ही जाएगी। कान पर पहरेदार बैठाने से निंदा, चुगली और अशोभनीय शब्दों से परहेज होगा। नासिका पर पहरेदार बैठने से सुगंधित वातावरण में जीने की आदत पड़ेगी। त्वचा की स्पर्श की शुद्धता से घटियापन का भाव नहीं पैदा होगा। खुद के हाथ में है कि हम उन्नत अवस्था में रहें या निकृष्ट अवस्था में।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाएं

भारत विविध भाषाओं का देश है। हिंदी भारतीय संविधान की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है और उत्तर भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है, किंतु दक्षिण भारत में इसके प्रसार की प्रक्रिया एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। दक्षिण भारत में हिंदी का प्रसार केवल भाषाई प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हालांकि यह प्रक्रिया भाषाई अस्मिता और राजनीतिक चुनौतियों से प्रभावित रही है, लेकिन भविष्य में शिक्षा, मीडिया, डिजिटल मंचों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से हिंदी का महत्व और बढ़ेगा।

द्रविड़ भाषा परिवार (Dravidian Language Family) का मुख्य केंद्र दक्षिण भारत है। यह क्षेत्र भाषाई विविधता और गहरी साहित्यिक परंपराओं का संगम है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चार प्रमुख भाषाएं प्रचलन में हैं, जो अपने-अपने राज्यों की आधिकारिक भाषाएं हैं। राज्य स्तर पर इन भाषाओं का प्रचलन बहुत अधिक है, जो क्षेत्र की भाषाई पहचान को मजबूत करता है। केरल में मलयालम (96.69%) और तमिलनाडु में तमिल (86.89%) का क्षेत्रीय प्रभुत्व बहुत मजबूत है।

प्रो. मीना यादव
शिक्षाविद्

कर्नाटक में कन्नड़ मातृभाषा बोलने वालों का प्रतिशत लगभग 66.24% है, जो इसे भारत का एक महत्वपूर्ण बहुभाषी राज्य बनाता है, जहां उर्दू, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाएं भी अच्छी संख्या में बोली जाती हैं। तेलुगु बोलने वालों की संख्या (मातृभाषा के रूप में 8.11 करोड़) अन्य सभी द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक है, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर चौथी सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। इन प्रमुख भाषाओं के अलावा, तटीय क्षेत्रों में तुलू और कोंकणी जैसी अन्य द्रविड़ और इंडो-आर्यन भाषाएं भी बोली जाती हैं।

बड़े शहरी केंद्रों में, हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग भी व्यापक रूप से होता है। संक्षेप में, दक्षिण भारत की भाषाएं इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास की अमूल्य निधि हैं, जो न केवल संचार का माध्यम हैं, बल्कि एक समृद्ध साहित्यिक विरासत को भी दर्शाती हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि समाज की संस्कृति, पहचान और परंपरा की वाहक होती है। यह राष्ट्र की आत्मा को जोड़ती है और उसकी विरासत को सुरक्षित रखती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय बनाए रखने के लिए एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी संदर्भ में हिंदी का प्रचार एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत के अनेक क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत में, अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के प्रति लोगों का आकर्षण घटने लगा था। गांधीजी का मानना था कि यदि कोई भाषा कमजोर पड़ती है, तो उसका प्रभाव उस भाषा के समाज, इतिहास और चिंतन पर भी पड़ता है। इसी चिंता से प्रेरित होकर उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का संकल्प लिया। उनका स्पष्ट विचार था कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा और प्रांतीय भाषाओं को उनके उचित स्थान पर नहीं प्रतिष्ठित करेंगे, तब तक स्वराज्य की भावना अधूरी रहेगी। गांधीजी ने मातृभाषा के अनादर को 'मां के अनादर' के समान बताया और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए स्वयं आगे आए।

1918 में गांधीजी ने इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन (स्थापनाः 1910) के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहीं से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दक्षिण भारत में प्रचारित करने की दिशा में संगठित प्रयास आरंभ हुआ। गांधीजी का उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं था, बल्कि हिंदी को भारत के विभिन्न प्रांतों के बीच संपर्क भाषा बनाना था। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और परस्पर समझ को सुदृढ़ करना चाहते थे।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाप्लिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- अनिल त्रिगुणायत***
0522-4008111 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-50986/1989 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।

बाओबाब
एक अनोखा पेड़
आदिवासियों का संरक्षक और देवतुल्य साथी

बाओबाब मात्र एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समुदाय के जीवन जीने का प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। यह लोगों का आश्रय ही नहीं, बल्कि पानी का भी स्रोत है?

अफ्रीका की विशाल और कठोर धरती पर जीवन आसान नहीं है। तपता सूरज, महीनों तक न बरसने वाली बारिश और दूर-दूर तक फैले सूखे मैदान, इन सबके बीच अगर किसी पेड़ ने सदियों से इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा है, तो वह है 'बाओबाब पेड़'। अफ्रीका के आदिवासी समुदायों के लिए बाओबाब केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवनदायी संरक्षक और देवतुल्य साथी है।

इतिहास और रहस्य

बाओबाब को अक्सर 'जीवन का पेड़' या 'उल्टा उगा हुआ पेड़' कहा जाता है, क्योंकि इसका मोटा तना और ऊपर की ओर फैली जड़ जैसी शाखाएं इसे अनोखा रूप देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकता है। अफ्रीकी लोककथाओं में मान्यता है कि देवताओं ने इसे उल्टा गाड़ दिया था, इसलिए इसकी जड़ें आसमान की ओर दिखती हैं। यही रहस्यमयी छवि इसे आदिवासी संस्कृति में विशेष स्थान दिलाती है।

पानी का प्राकृतिक भंडार

अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में बाओबाब एक प्राकृतिक जल टंकी की तरह काम करता है। इसका विशाल तना बारिश के पानी को सोखकर महीनों तक संचित रखता है। जब आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं होता, तब आदिवासी इसके तने से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। यही कारण है कि सूखे के समय बाओबाब जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन जाता है।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व

अफ्रीकी आदिवासियों के लिए यह पेड़ पवित्र माना जाता है। कई जन जातियां इसे पूर्वजों की आत्माओं का वास स्थल मानती हैं। इसके नीचे धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और निर्णय सभाएं होती हैं। यह पेड़ उनके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। यह आदिवासियों के लिए सचमुच एक वरदान है, जो पानी, भोजन, छाया और आश्रय देता है और संस्कृति को जीवित रखता है। अब जब जंगल कट रहे हैं, तब यह पेड़ हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व ही जीवन की असली कुंजी है।

आश्रय और सामुदायिक केंद्र

कुछ बाओबाब पेड़ों का तना इतना चौड़ा होता है कि उसके भीतर कई लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अफ्रीका के कई आदिवासी इन पेड़ों को अस्थायी घर, सभा स्थल या विश्राम स्थान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहीं-कहीं तो इसके अंदर स्कूल, अनाज भंडार और यहां तक कि छोटी दुकानें भी बनाई गई हैं।

फल, भोजन और औषधि

बाओबाब का फल पोषण का भंडार है। इसमें विटामिन-सी, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। आदिवासी इसे भोजन के रूप में तो खाते ही हैं, साथ ही इससे औषधियां भी बनाते हैं। इसकी पत्तियां सब्जी की तरह उपयोग होती हैं और बीजों से तेल निकाला जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में यह पेड़ बुखार, पेट की बीमारियों और त्वचा रोगों के इलाज में काम आता है।

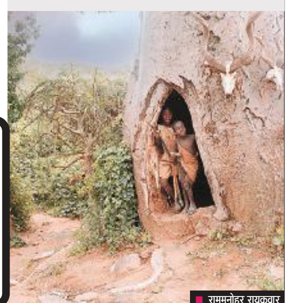

▪ राममनोहर रायकवार

वेर्डफोर्ट डोम
पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय टकराव की अमिट छाप

पृथ्वी का इतिहास केवल पहाड़ों, नदियों और महासागरों में नहीं, बल्कि उन ब्रह्मांडीय घटनाओं में भी दर्ज है जिन्होंने इसकी दिशा बदली। दक्षिण अफ्रीका का वेर्डफोर्ट डोम ऐसी ही एक अद्भुत प्राकृतिक विरासत है।

दुनिया रहस्यमयी और रोमांचकारी प्राकृतिक संरचनाओं से भरी है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी के अतीत की असाधारण कहानी खुद में समेटे हुए हैं। वेर्डफोर्ट डोम उन्हीं में से एक है, जिसे आज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उल्कापिंड प्रभाव स्थल माना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट और नॉर्थ वेस्ट प्रांत में फैला हुआ है और लगभग 300 किलोमीटर व्यास में विस्तृत है।

क्या कहते हैं भू-वैज्ञानिक

भू-विज्ञानियों के अनुसार, लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस उल्कापिंड का अनुमानित व्यास 10 से 15 किलोमीटर के बीच था और इसकी गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति सेकंड रही होगी। इतनी तीव्र और शक्तिशाली टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह लाखों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर मानी जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ऊपरी परत पिघल गई, चट्टानें वाष्पीकृत हो गईं और गहराई में स्थित चट्टानें सतह की ओर उछल आईं।

मिलती हैं दुर्लभ चट्टानें

इस घटना के बाद एक विशाल गड्ढा बना, जिसके केंद्र में दबाव के कारण चट्टानों का उभार हुआ और गोलाकार डोम जैसी संरचना अस्तित्व में आई। अत्यधिक तापमान और दबाव ने चट्टानों की आंतरिक संरचना को बदल दिया। आज यहां शॉक्ड क्वाट्र्ज जैसी दुर्लभ चट्टानें मिलती हैं, जो केवल क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड टकराव से ही बन सकती हैं। करोड़ों वर्षों के दौरान हवा, पानी और मौसम के प्रभाव से क्रेटर का ऊपरी हिस्सा क्षरित हो गया, लेकिन केंद्रीय डोम आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

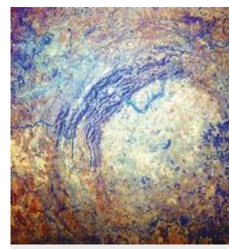

विश्व धरोहर घोषित

वैज्ञानिक दृष्टि से वेर्डफोर्ट डोम का महत्व वैश्विक है। यहां पृथ्वी की गहरी परतों की चट्टानें सतह पर देखी जा सकती हैं, जिससे प्लेट टेक्टॉनिक्स से पहले की पृथ्वी की संरचना को समझने में मदद मिलती है। यही कारण है कि वर्ष 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

घटना का जीवंत उदाहरण

वेर्डफोर्ट डोम केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच हुए हुई घटना का जीवंत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की घटनाएं कैसे हमारे ग्रह के भूगोल, जलवायु और संभवत: जीवन की दिशा तक को बदल सकती हैं।

▪ जसवंत सिंह राजपूत

किसानों की तकदीर बदल देगी
दुर्लभ किस्म के काले बीजों की खेती

खेतों में उगने वाले बीज आमतौर पर तेल, मसाले या दालों से जोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं जो सीधे लग्जरी और हाई-प्रोफाइल इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं। देखने में साधारण लगने वाले ये काले-काले बीज कीमत के मामले में सोने-चांदी से रेस लगा रहे हैं। इनका एक किलो दाम सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी रकम में कई लोगों का साल भर का खर्च निकल जाए। आखिर क्या है इनकी खासियत, और क्यों इन्हें उगाने वाला किसान देखते ही देखते मालामाल बन जाता है?

काले रंगे के ये छोटे-छोटे बीज कोई साधारण फसल नहीं हैं। दावा किया जाता है कि इनकी बाजार कीमत 1,50,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। यानी सिर्फ एक किलो बीज बेचकर कोई भी लखपति बन सकता है। पहली नजर में ये बीज काले तिल जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये खास किस्म के दुर्लभ काले जंगली बीज होते हैं, जिन्हें प्रीमियम ग्रेड में तैयार किया जाता है।

टैटू इंक का खजाना

इन बीजों की सबसे बड़ी मांग टैटू इंडस्ट्री में है। टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गहरी काली इंक इन्हीं बीजों से तैयार की जाती है। इनसे निकाला गया प्राकृतिक पिगमेंट बेहद गहरा, टिकाऊ और चमकदार होता है, जो टैटू को लंबे समय तक काला बनाए रखता है। यही वजह है कि पेशेवर टैटू आर्टिस्ट्स के बीच इस इंक की जबरदस्त मांग रहती है।

तिल की प्रीमियम वैरायटी

टैटू इंक के लिए इस्तेमाल होने वाले ये बीज ऑर्गेनिक, केमिकल-फ्री और हाई पिगमेंट वाले होते हैं। इन्हें चुनिंदा इलाकों में उगाया जाता है और हाथ से छांटकर, साफ करके प्रोसेस किया जाता है। यही वजह है कि इनकी कीमत आसमान छूती है।

महंगे क्यों

इन बीजों की ऊंची कीमत के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण इनकी दुर्लभता है। ये विशेष जलवायु में ही उगते हैं, जैसे उत्तर भारत या नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में। दूसरा कारण मेहनत और प्रोसेसिंग है। एक किलो बीज तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तीसरा कारण है टैटू और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनकी लगातार बढ़ती मांग।

किसानों के लिए सुनहरा मौका

अब कई किसान और सप्लायर इन बीजों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। सही जानकारी, सही बाजार और गुणवत्ता बनाए रखी जाए, तो एक सीजन में लाखों रुपये की कमाई संभव है। यही वजह है कि ये काले बीज आज खेती की दुनिया में काली कमाई का नया रास्ता बनते जा रहे हैं।

▪ धर्मेंद्र सिंह कर्ण

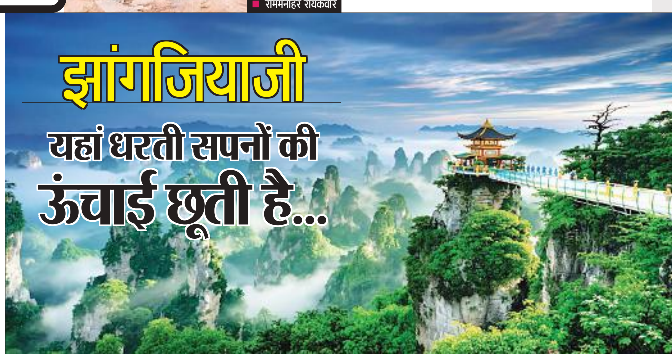

झांगजियाजी
यहां धरती सपनों की ऊंचाई छूती है...

चीन का झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क ऐसा संसार है, जहां बादलों से बातें करते पत्थर स्तंभ, हरी घाटियां और धुंध मिलकर प्रकृति का अनूठा सौंदर्य रचते हैं।

चीन के हुनान प्रांत में बसा झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क प्रकृति की उन विरल कृतियों में से है, जिसे देखकर मन विस्मय से भर उठता है। यहां पहुंचते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने स्वयं आकाश को छूने की आकांक्षा कर ली हो। बादलों से घिरे स्तंभनुमा पर्वत, गहरी घाटियां और अनंत हरियाली मिलकर इस स्थान को किसी स्वप्नलोक में बदल देते हैं। यही कारण है कि झांगजियाजी को दुनिया भर में 'धरती पर तैरता स्वर्ग' कहा जाता है।

बादलों को छूते पत्थर के स्तंभ

झांगजियाजी की सबसे अनोखी पहचान हैं इसके क्वार्ट्ज और सैंडस्टोन से बने हजारों ऊंचे-ऊंचे पहाड़, जो सीधे धरती से उठकर आकाश को छूते प्रतीत होते हैं। सुबह की पहली किरण जब इन पर्वतों पर पड़ती है और बादल धीरे-धीरे इनके चारों ओर लिपटते हैं, तब दृश्य किसी जादुई चलचित्र जैसा बन जाता है। कई बार घने बादल पहाड़ों को आधा ढंक लेते हैं, जिससे वे हवा में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यह दृश्य प्रकृति की उस विराट कल्पना को बताता है, जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है।

मौसम और हरियाली का जादू

यहां का मौसम झांगजियाजी की सुंदरता को और भी गहराई प्रदान करता है। बारिश के बाद उठती हल्की धुंध, हरी-भरी घाटियां और दूर-दूर तक फैले घने जंगल मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच खड़े होकर इंसान खुद को प्रकृति की विराटता के सामने बेहद छोटा, लेकिन सौभाग्यशाली महसूस करता है।

रोमांच का प्रतीक ग्लास ब्रिज

झांगजियाजी की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देने वाला आकर्षण है यहां स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा कांच का पुल। लगभग 430 मीटर लंबा और 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बना यह ग्लास ब्रिज दो पहाड़ों को जोड़ता है। पारदर्शी कांच से बने इस पुल पर चलते समय नीचे गहरी घाटी साफ दिखाई देती है, जो रोमांच और भय का अनोखा संगम रचती है। कई पर्यटक पहले कदम पर ही ठिठक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए यह अनुभव जीवनभर की याद बन जाता है।

हॉलीवुड से जुड़ी कल्पना की उड़ान

झांगजियाजी की प्राकृतिक भव्यता ने हॉलीवुड को भी प्रेरित किया है। प्रसिद्ध फिल्म 'अवतार' में दिखाए गए तैरते पहाड़ों की प्रेरणा यहीं से ली गई मानी जाती है। इस कारण यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि कल्पना और यथार्थ के अद्भुत संगम का जीवंत प्रतीक बन जाता है। कुल मिलाकर, झांगजियाजी वह स्थान है जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ सामने आती है, जहां पहाड़ बादलों से संवाद करते हैं और इंसान प्रकृति की गोद में स्वयं को एक विनम्र दर्शक के रूप में पाता है।

एटलांटिस ऑफ द ईस्ट
पानी में डूबा शेरों का शहर

जब भी पानी में डूबे शहरों की बात होती है, तो लोगों के जहन में अटलांटिस की रहस्यमयी कहानी उभर आती है। लेकिन चीन में वास्तव में एक ऐसा शहर है, जिसे 'एटलांटिस ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि इतिहास की एक सच्ची और चौंकाने वाली घटना है। इस शहर का नाम है शीचेंग, जिसे 1970 के दशक में एक डैम परियोजना के तहत जानबूझकर पानी में डुबो दिया गया।

शहर का इतिहास

शीचेंग की स्थापना लगभग 1400 साल पहले, यानी ईस्वी सन् 621 में तांग राजवंश के समय हुई थी। यह शहर झेजियांग प्रांत में स्थित था और अपने शानदार वास्तुकला, मजबूत किलों, भव्य द्वारों और नक्काशीदार इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। शहर के आसपास पांच पहाड़ थे, जिनकी आकृति शेर जैसी लगती थी, इसी कारण इसे शेरों का शहर कहा गया। यह शहर न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध माना जाता था।

क्यों डुबोया पूरा शहर?

1959 में चीन सरकार ने शिनआन नदी पर जलविद्युत डैम बनाने की योजना बनाई, जिससे कियानदाओ झील का निर्माण हुआ। इस परियोजना से बिजली उत्पादन और सिंचाई के बड़े फायदे होने थे। लेकिन इसकी कीमत बेहद भारी थी- लगभग 2.9 लाख लोगों का विस्थापन और शीचेंग समेत कई प्राचीन बस्तियों का पूरी तरह जलमग्न होना। सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बजाय विकास को प्राथमिकता दी और शहर को बिना तोड़े-फोड़े पानी के नीचे छोड़ दिया।

पानी के नीचे सुरक्षित शहर

हैरान करने वाली सच्चाई

शीचेंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह शहर पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में पानी के नीचे मौजूद है। करीब 30 से 40 मीटर गहराई में स्थित इस शहर की इमारतों की दीवारों में आज तक न काई जमी है और न ही दरारें पड़ी हैं।

इसका मुख्य कारण है

- झील का शांत और स्थिर पानी
- धूप, हवा और ऑक्सीजन का अभाव
- मजबूत पत्थरों और पारंपरिक चीनी निर्माण तकनीक का उपयोग

यही वजह है कि लकड़ी के दरवाजे, पत्थर की नक्काशी, शेरों की मूर्तियां और प्राचीन द्वार आज भी लगभग वैसे ही मौजूद हैं, जैसे सदियों पहले थे।

रहस्य और पर्यटन

जब गोताखोरों ने पहली बार इस डूबे शहर की तस्वीरें दुनिया के सामने रखीं, तो शीचेंग वैश्विक चर्चा का विषय बन गया। आज यह अंडरवॉटर आर्कियोलॉजी और एडवेंचर डाइविंग का केंद्र बन चुका है। शीचेंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की कीमत क्या सिर्फ वर्तमान चुकाता है या इतिहास भी? एटलांटिस ऑफ द ईस्ट सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता के फैसलों का मौन साक्ष्य है।

▪ हरिनारायण मिश्रा